2025

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष

सहकारी समितियाँ एक बेहतर
दुनिया का निर्माण करती हैं

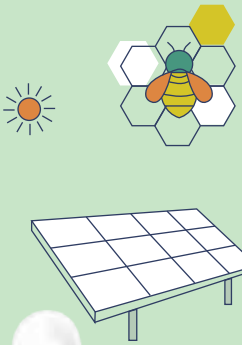

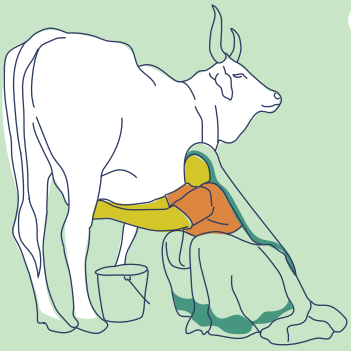

राष्ट्रीय
डेरी
विकास
बोर्ड

60 वर्ष

सहकारिता के माध्यम से सतत् एवं समावेशी डेरी

वार्षिक रिपोर्ट

2024-25

विषय सूची

बोर्ड के सदस्य	01
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड	02
अध्यक्ष का संदेश	04
डेयरी क्षेत्र के रुझान	10
भारतीय डेयरी क्षेत्र में बदलाव	12
उत्पादकता वृद्धि	20
अनुसंधान एवं विकास द्वारा प्रौद्योगिकीय प्रगति	36
सस्टेनेबिलिटी एवं सर्कुलैरिटी	42
डेयरी विकास के लिए सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन	48
श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत सहकारी कवरेज का विस्तार- "सहकार- से- समृद्धि" के विज़न को साकार करना	68
डेयरी सहकारिताओं का पेशेवर प्रबंधन एवं समर्थन	76
भारतीय डेयरी क्षेत्र का डिजिटलीकरण	94
डेयरी अवसंरचना का विस्तार	98
विकास हेतु रणनीतिक साझेदारियां	104
मानव संसाधन का प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास	110
डेयरी क्षेत्र के लिए विज़न 2047	116
एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रीशन	120
राजभाषा का प्रगामी प्रयोग	122
प्रमुख कार्यक्रमों की झलकियां	124
एनडीडीबी के प्रयासों को बढ़ावा देना – एनडीडीबी की सहायक कंपनियां	130
डेयरी सहकारिताओं की प्रगति	140
आगंतुक	150
लेखा-जोखा	156
एनडीडीबी के अधिकारी	184
शब्दावली	192
कृतज्ञता ज्ञापन	197

निम्नलिखित वेबसाइट पर इस रिपोर्ट को देखें

nddb.coop

बोर्ड के सदस्य

डॉ. मीनेश सी शाह
अध्यक्ष[1] एवं प्रबंध निदेशक
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

सुश्री वर्षा जोशी
अपर सचिव (मवेशी एवं डेयरी विकास)
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी
मंत्रालय, भारत सरकार

डॉ. एन विजया लक्ष्मी
अध्यक्ष
बिहार राज्य सहकारी डेयरी महासंघ
लिमिटेड, पटना

श्री विकेयी केन्या
अध्यक्ष
नागालैण्ड राज्य डेयरी सहकारी महासंघ
लिमिटेड, कोहिमा

डॉ. जी एस राजोरिया
पूर्व अध्यक्ष
इंडियन डेयरी एसोसिएशन

[1]अध्यक्ष, एनडीडीबी का अतिरिक्त प्रभार

31 मार्च 2025 की स्थिति

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की स्थापना वर्ष 1965 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में हुई। तत्पश्चात् संसद द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से वर्ष 1987 में इसे एक सांविधिक निगमित निकाय के रूप में गठित किया गया, जिसमें इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन के उपक्रम का समावेश किया गया। लगभग छह दशकों से एनडीडीबी भारत के डेयरी क्षेत्र की प्रगति के आधारस्तंभ के रूप में कार्यरत है तथा उत्पादक-स्वामित्व वाले संस्थानों (POI) को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे लाखों दूध उत्पादकों, विशेषकर भूमिहीन, सीमांत तथा छोटे किसानों की आजीविका में सुधार हुआ है।

एनडीडीबी ने अपनी स्थापना के समय से ही, सहकारिता के सिद्धांतों को आधार बनाकर ऐसे कार्यक्रमों की संकल्पना कर उनको क्रियान्वित किया है, जिनसे डेयरी को ग्रामीण विकास तथा राष्ट्रीय पोषण संबधी मानकों में सुधार का सशक्त साधन बनाया जा सके। इस प्रयास की एक ऐतिहासिक उपलब्धि ऑपरेशन फ्लड (1970–1996) रहा, जिसे डेयरी सहकारिताओं के माध्यम से तीन चरणों में क्रियान्वित किया गया। इस क्रांतिकारी कार्यक्रम ने वर्ष 1998 तक भारत को विश्व के अग्रणी दूध उत्पादक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभाई।

एनडीडीबी ने राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण–I (NDP I) तथा राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) जैसे महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय पहलों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है और सदैव किसान केंद्रित रणनीतियों एवं सहकारी विकास के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता बनाए रखी है। राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण–I (NDP I) को विश्व बैंक से 'अत्यंत संतोषजनक (Highly Satisfactory)' रेटिंग प्राप्त हुई, जो उसके वित्त पोषित परियोजनाओं को प्रदान की जाने वाली सर्वोच्च मान्यता है। सतत् वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय नवाचारों को अपनाकर एनडीडीबी डेयरी इको सिस्टम को सुदृढ़ बना रही है, किसानों की आय में वृद्धि कर रही है तथा सहकारी मॉडल को सतत् डेयरी विकास के लिए सर्वाधिक प्रभावी फ्रेमवर्क के रूप में और भी सशक्त बना रही है।

एनडीडीबी ने डेयरी सहकारिताओं को तकनीकी विशेषज्ञता, वित्तीय सहायता और इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान कर कई पहलें भी क्रियान्वित की हैं। इन पहलों में प्रॉमिसिंग दूध संघों का पुनरुत्थान, डेयरी सहकारिताओं के सुदृढ़ीकरण के लिए रणनीतिक विपणन सहयोग तथा एथनोवेटरिनरी मेडिसिन (EVM) और वन हेल्थ पहलों के माध्यम से रोग नियंत्रण कार्यक्रम शामिल हैं।

भावी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, एनडीडीबी दूध उत्पादक किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के अपने मिशन के प्रति प्रतिबद्ध है। नवाचार को आत्मसात करते हुए, प्रौद्योगिकी का उपयोग कर तथा सहयोग एवं सहभागिता को बढ़ावा देकर, एनडीडीबी भावी चुनौतियों का सामना अटूट संकल्प के साथ करने के लिए तत्पर है।

अध्यक्ष का संदेश

वर्ष 2024-25 डेयरी क्षेत्र के लिए अनुकूल रहा, जिसे सहायक जलवायु परिस्थितियों, दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए लाभकारी मूल्यों तथा सुदृढ़ उपभोक्ता मांग का निरंतर समर्थन मिला।

मुझे राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है जो भारतीय डेयरी क्षेत्र में सतत् विकास, नवाचार तथा सुदृढ़ीकरण का प्रतीक है।

वर्ष के दौरान, डेयरी क्षेत्र को अनेक अनुकूल परिस्थितियों के लाभ मिले हैं। अनुकूल जलवायु, स्थिर दूध मूल्य व्यवस्था तथा विशेषकर वर्ष के उत्तरार्ध में अधिकांश पशु आहार सामग्रियों के मूल्य में उल्लेखनीय कमी होने से डेयरी क्षेत्र की प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित हुआ। भारत सरकार के रणनीतिक उपायों, विशेषकर डी-ऑयल्ड राइस ब्रान (DoRB) के निर्यात पर प्रतिबंध लगने से पशु आहार की कीमतों को स्थिर करने में महत्त्वपूर्ण योगदान मिला । इस पहल ने दूध उत्पादन लागत को प्रभावी ढंग से स्थिरता प्रदान की है, जिससे डेयरी व्यवसाय की आर्थिक व्यवहार्यता और सुदृढ़ हुई है।

भारत में दूध का उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है और वर्ष 2024–25 में इसके लगभग 250 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे भारत की स्थिति विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश के रूप में और सुदृढ़ हो रही है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता लगभग 490 ग्राम प्रतिदिन तक पहुंचने की संभावना है, जो देशव्यापी पोषण स्तर और खाद्य सुरक्षा सुधार में सहायक है।

इस प्रगति की आधारशिला डेयरी सहकारिताएं ही हैं, जिन्होंने संरक्षित कमोडिटी के विशाल भंडार के बावजूद उल्लेखनीय दृढ़ता प्रदर्शित की है। सहकारिताओं द्वारा दूध संकलन बढ़कर 676 लाख किलोग्राम प्रतिदिन (LKgPD) तक पहुंच गया, जबकि तरल दूध की औसत बिक्री 444 लाख लीटर प्रतिदिन (LLPD) रही। दूध संकलन सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के साथ-साथ किसानों को इनपुट सेवाएं, जिनमें पशु-चिकित्सा सेवा, कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं, टीकाकरण तथा उच्च गुणवत्ता वाला पशु आहार एवं हरा-चारा सम्मिलित हैं, उपलब्ध कराते हुए हमारी सहकारिताएं सतत् रूप से कृषि क्षेत्र को महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रही हैं। इन प्रयासों ने सतत् विकास के लाभ को जमीनी स्तर तक पहुंचाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की नींव को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

एनडीडीबी सतत् डेयरी विकास को सहयोग प्रदान करने वाले वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों को आगे बढ़ाने में निरंतर अग्रणी है। जीनोमिक चयन एवं प्रजनन संबधी जैव-प्रौद्योगिकियों के माध्यम से आनुवंशिक सुधार तथा देशी नस्लों के संरक्षण पर हमारा विशेष ध्यान उत्पादकता में वृद्धि के ठोस परिणाम प्रदान कर रहा है। हमने आहार संतुलन तथा संपूर्ण मिश्रित आहार (TMR) तकनीकों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित कर उन्नत आहार पद्धतियों को बढ़ावा दिया है, जिससे पशु पोषण और पशु आहार की दक्षता में सुधार हुआ है।

हमारे पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम वन हेल्थ फ्रेमवर्क के अनुरूप रणनीतिक रूप से संचालित हैं, जो समग्र रूप से रोग नियंत्रण उपायों को अपनाते हुए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) के जोखिम को कम करते हैं। स्वदेशी अनुसंधान में हुई प्रगति से निदान क्षमताओं और जैव-सुरक्षा मानकों का सुदृढ़ीकरण हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और फार्म जैव-सुरक्षा में सुधार हुआ है। इन समन्वित प्रयासों से न केवल उत्पादकता में वृद्धि हुई है, बल्कि डेयरी उद्योग की दीर्घकालिक स्थिरता भी सुनिश्चित हुई है।

वर्ष 2024–25 में भारत का दूध उत्पादन 250 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है तथा प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता लगभग 490 ग्राम प्रतिदिन होने की संभावना है।

वर्ष के दौरान, एनडीडीबी द्वारा समर्थित प्रमुख सरकारी योजनाओं का अधिक सुदृढ़ीकरण हुआ। राष्ट्रीय गोकुल मिशन देशी गोवंशीय नस्लों के आनुवंशिक सुधार को गति प्रदान करता है, जबकि राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) दूध की गुणवत्ता, प्रसंस्करण तथा अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि (DIDF) ने सुविधाओं के आधुनिकीकरण को संभव बनाया, वहीं 'डेयरी सहाकारिताओं एवं किसान उत्पादक संगठनों को सहयोग' (SDC & FPO) योजना ने कार्यशील पूँजी ऋणों पर ब्याज सहायता के माध्यम से आवश्यक वित्तीय सहयोग प्रदान किया। राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के अंतर्गत पशु आहार उत्पादन को बढ़ावा देने तथा गुणवत्तायुक्त बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास और तेज किए गए। 10,000 एफपीओं योजना के अंतर्गत 100 फॉडर प्लस एफपीओ की स्थापना पशु आहार आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ बना रही है तथा डेयरी पशुओं के लिए सतत् पशु आहार उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है।

हमें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी ने ओडिशा के रायरंगपुर से वर्चुअल माध्यम द्वारा महत्त्वपूर्ण डेयरी विकास पहलों का शुभारंभ किया। इनमें गौ – समावेश कार्यक्रम, स्कूली बच्चों हेतु गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम तथा ओमफेड के लिए सुदृढ़ विपणन सहयोग शामिल हैं। एनडीडीबी की एक गैर-लाभकारी सहायक कंपनी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के माध्यम से हम उत्पादकता वृद्धि परियोजना कार्यान्वित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मयूरभंज जिले में 3,000 उच्च आनुवंशिक गुण वाली गायों एवं बछड़ों को शामिल किया जा रहा है। साथ ही, ओमफेड को दूध संकलन एवं विपणन प्रयासों को सुदृढ़ बनाने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है।

महाराष्ट्र के वाशीम में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एनडीडीबी द्वारा विकसित गौसॉर्ट (GauSort) — एक किफायती, स्वदेशी सीमन सेक्स सॉर्टिंग तकनीक तथा गौचिप (GAUCHIP) और महिषचिप (MAHISHCHIP) का शुभारंभ किया। ये जीनोमिक चिप्स गाय एवं भैसों में आनुवंशिक चयन की गति को तीव्र करने हेतु विकसित की गई हैं। इनके साथ ही, अन्य किसान केंद्रित पहलों का भी आरंभ किया गया। ये तकनीकी उपलब्धियां पशुधन की गुणवत्ता एवं दूध उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि का आश्वासन देती हैं और ये उपलब्धियां आत्मनिर्भर एवं तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ डेयरी क्षेत्र की परिकल्पना को साकार करने में सहायक सिद्ध होंगी।

वर्ष 2024–25 महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्ष रहा है क्योंकि एनडीडीबी ने अपने हीरक जयंती वर्ष में प्रवेश किया है, जो भारत के

अध्यक्ष का संदेश

डेयरी उद्योग के प्रति उसकी साठ वर्षों की अटूट प्रतिबद्धता का उत्सव है। इस उत्सव की शुरुआत हीरक जयंती लोगो के अनावरण से हुई, जो एनडीडीबी की 'सहकारिताओं के माध्यम से सतत् एवं समावेशी डेयरी विकास' के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

निरंतर उत्सवों के एक भाग के रूप में, माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी तथा माननीय केन्द्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन सिंह जी ने 22 अक्तूबर 2024 को आणंद में अनेक किसानोन्मुख पहलों का शुभारंभ किया। इसकी प्रमुख उपलब्धियों में आणंद स्थित एनडीडीबी के नए कार्यालय भवन, वडोदरा के इटोला में मदर डेयरी के फल एवं सब्जी प्रसंस्करण संयंत्र तथा दिल्ली के नरेला में आईडीएमसी के पॉलीफिल्म संयंत्र की आधारशिला रखना शामिल है। इस कार्यक्रम के दौरान, मदर डेयरी द्वारा गिर घी तथा उत्तराखंड कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा बद्री घी का शुभारंभ भी किया गया, जिनमें भारत पशुधन प्लेटफार्म के अंतर्गत ट्रेसबिलिटी विशेषताओं को शामिल किया गया है। इस अवसर पर कई महत्त्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) भी किए गए। इन पहलों ने डेयरी सहकारिताओं के सतत् सुदृढ़ीकरण की आधारशिला रखी है, साथ ही हीरक जयंती वर्ष के दौरान अनेक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के आयोजन की योजना बनाई गई है।

वर्ष के दौरान, मुझे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से भेंट करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर एनडीडीबी एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा संचालित अनेक नवोन्मेषी पहलों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही, उन्हें पशु उत्पादकता में सुधार, डेयरी सहकारिताओं के सुदृढ़ीकरण तथा राजस्थान में फलों एवं सब्जियों के संकलन से संबंधित संचालित एवं प्रस्तावित गतिविधियों की जानकारी भी प्रदान की गई।

सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में सहकारिता मंत्रालय के साथ सहयोग निर्णायक रहा है। इस वर्ष की एक ऐतिहासिक पहल श्वेत क्रांति 2.0 है, जिसे सहकारिता मंत्रालय एवं मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आरंभ किया गया है, जिसमें एनडीडीबी एक प्रमुख कार्यान्वयन सहयोगी की भूमिका निभा रही है।

इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियों (DCS), बहुउद्देशीय डेयरी सहकारी समितियों (MDCS) तथा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (MPACS) की स्थापना करना है, जिससे गांव स्तर पर दूध उत्पादन, संकलन एवं विपणन की पहुंच को मजबूत किया जा सके।

इसके अलावा, लगभग 46,000 मौजूदा सहकारिताओं को स्वचालित दूध संकलन इकाइयों, डाटा प्रसंस्करण प्रणालियों, परीक्षण उपकरणों तथा बल्क मिल्क कूलर्स के माध्यम से सुदृढ़ किया जाएगा। इन पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु एनडीडीबी ने राज्य सरकारों और डेयरी महासंघों के सहयोग से एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है।

एनडीडीबी अपनी सक्रिय भागीदारी को तीन नई राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्यीय सहकारी समितियों—राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL), भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) तथा राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) के साथ जारी रखे हुए है, जिनका उद्देश्य क्रमशः ऑर्गेनिक कृषि, स्वदेशी

भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ रायरंगपुर, मयूरभंज, ओडिशा में प्रमुख डेयरी विकास कार्यक्रमों के वर्चुअल उद्घाटन के दौरान

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी वाशीम, महाराष्ट्र में गौसॉर्ट तथा गौचिप एवं महिषचिप का शुभारंभ के दौरान, जिसमें माननीय राज्यपाल, महाराष्ट्र श्री सी पी राधाकृष्णन जी; माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे जी; माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी; माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी; माननीय उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी; माननीय उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र श्री अजित पवार जी; माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव जी तथा अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे

बीज विकास तथा डेयरी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। यह पहल डेयरी क्षेत्र से परे जाकर, ग्रामीण सहकारिता विकास में एनडीडीबी की भूमिका के रणनीतिक विस्तार का प्रतिनिधित्व करती है।

एनडीडीबी की पहलों को प्रमुख देशीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों —सुजुकी आरएंडडी सेंटर इंडिया, खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO), डेयरी सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क तथा सस्टेन प्लस एनर्जी फाउंडेशन (टाटा ट्रस्ट से संबद्ध) के साथ रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से और सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

एनडीडीबी राष्ट्रव्यापी स्तर पर संचालित इकाइयों के रूप में कार्यरत डेयरी सहकारिताओं को निरंतर प्रबंधन सहयोग प्रदान कर रही है, जिनमें वाराणसी, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर, लद्दाख और महाराष्ट्र शामिल हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारों एवं दूध संघों के अनुरोध पर एनडीडीबी ने मध्य प्रदेश, गोवा, औरंगाबाद, बनासकांठा, हिमाचल प्रदेश, एर्नाकुलम तथा दिल्ली दुग्ध योजना को निःस्वार्थ जनशक्ति सहयोग भी उपलब्ध कराया।

एनडीडीबी की सहायक कंपनियां सहकारिता को बढ़ावा देने और डेयरी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के एनडीडीबी के मिशन को आगे बढ़ाने में निरंतर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रत्येक सहायक कंपनी अपनी विशिष्ट कार्यक्षमताओं के माध्यम से हमारे सामूहिक प्रयासों की पूरक है, जिनका उद्देश्य ग्रामीण आजीविका में सुधार लाना, सतत् डेयरी विकास सुनिश्चित करना और देशभर के किसानों को सशक्त बनाना है।

मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रा. लि. (MDFVPL) ने दूध उत्पादकों को लाभकारी बाजार उपलब्ध कराने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं उच्च गुणवत्ता वाले डेयरी और खाद्य उत्पाद प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस वित्त वर्ष में एमडीएफवीपीएल ने 17,386 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

आईडीएमसी लिमिटेड ने टर्नकी डेयरी संयंत्र स्थापनाओं, उन्नत रेफ्रिजरेशन एवं फार्म उपकरण समाधानों तथा विस्तारित पैकेजिंग एवं निर्यात क्षमताओं के माध्यम से सतत् विकास को गति दी है। रणनीतिक अवसंरचना विस्तार एवं नयी डेयरी कल्चर उत्पादन सुविधा ने 'आत्मनिर्भरता' और 'मेक इन इंडिया' को और अधिक सुदृढ़ किया है। आईडीएमसी ने 882.00 करोड़ रुपये की कुल आय दर्ज की, जो डेयरी क्षेत्र में इसके निरंतर योगदान को प्रदर्शित करता है। वर्ष के दौरान, एनडीडीबी द्वारा विकसित 'रेडी टू यूज़ कल्चर (RUC)' तकनीक व्यावसायिक उत्पादन हेतु आईडीएमसी लिमिटेड को हस्तांतरित की गई।

इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड (IIL), जो विश्व की एक सबसे बड़ी टीका उत्पादक कंपनी है, ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष में 1,453 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया। आईआईएल, भारत सरकार के प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे ASCAD, UIP तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रमुख टीका आपूर्तिकर्ता है, साथ ही 60 से अधिक देशों को निर्यात भी कर रहा है। आईआईएल ने देश में टीका उत्पादन में आत्मनिर्भरता को और मजबूत किया है, जिसके अंतर्गत स्वदेश में विकसित एवं निर्मित उत्पाद शामिल हैं, जैसे FMD, रेबीज़, पेंटावैलेंट, पीपीआर, हेपाटाइटिस ए एवं बी आदि के टीके। इसके अलावा, आईआईएल इंफेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकाइटिस (IBR), खसरा-रूबेला, लंपी स्किन डिज़ीज़ तथा मत्स्य रोगों के लिए टीकों के विकास हेतु निरंतर प्रयासरत है।

एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज़ (NDS), जो एनडीडीबी की एक गैर-लाभकारी सहायक कंपनी है, ने समावेशी एवं सतत् डेयरी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देना निरंतर जारी रखा है। वर्ष के दौरान, एनडीएस ने 23 दूध उत्पादक संगठनों (MPOs) को सहयोग प्रदान किया, जिन्होंने संयुक्त रूप से 9,637 करोड़ रुपये का कारोबार किया। विशेष रूप से, इन एमपीओ में से 16 एमपीओ महिलाओं के नेतृत्व में संचालित हैं, जिनके 74 प्रतिशत सदस्य महिलाएं हैं तथा 65 प्रतिशत सदस्य लघुधारक उत्पादक हैं। ये एमपीओ 32,000 से अधिक गांवों से प्रतिदिन 60 लाख किलोग्राम से अधिक दूध संकलित कर रहे हैं।

आनुवंशिक सुधार के क्षेत्र में, एनडीएस के चार वीर्य केन्द्र संचालित हैं। इन्होंने 426 लाख हिमीकृत वीर्य डोजों का वितरण किया, जिसमें

देशी नस्लों का भी उल्लेखनीय योगदान शामिल है। डेयरी क्षेत्र से परे, एनडीएस ने आम, सरसों एवं मक्का में मूल्य श्रृंखला संबंधी हस्तक्षेप प्रारम्भ किए, जिससे आय विविधीकरण को बढ़ावा मिला और ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिली।

एनडीडीबी मृदा लिमिटेड ने खाद प्रबंधन, बायोगैस उत्पादन तथा ऑर्गेनिक उर्वरक समाधान पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सस्टेनेबल ग्रामीण ऊर्जा एवं डेयरी प्रणालियों को समर्थन प्रदान किया। सुज़ुकी आरएंडडी सेंटर इंडिया के सहयोग से एनडीडीबी मृदा ने देशभर में बायोगैस संयंत्रों के विकास को प्रोत्साहित किया। एमएनआरई बायोगैस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में, इस कंपनी ने 13 राज्यों में 7,000 से अधिक घरेलू बायोगैस इकाइयों की स्थापना की, जिससे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की उपलब्धता में सहयोग मिला और किसानों पर पूंजीगत व्यय का बोझ कम हुआ।

एनडीडीबी काफ लिमिटेड ने दूसरे वर्ष में 18.63 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया और खाद्य, पशु आहार तथा डेयरी उत्पादों के लिए विविध विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान कीं। आणंद स्थित इस प्रयोगशाला ने गायों एवं भैंसों हेतु अनुवांशिक परीक्षण, रोग-निदान तथा नस्ल मूल्यांकन की क्षमताओं का विस्तार किया। इस प्रयोगशाला को एनएबीएल तथा बीआईएस, एपीईडीए, ईआईसी और एफएसएसएआई की मान्यता प्राप्त है। यह दूध एवं दूध उत्पादों हेतु राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में अपनी भूमिका निभाती है। वर्ष के दौरान, 100,000 से अधिक सैपलों एवं 420,000 पैरामीटर का विश्लेषण किया गया।

आज, भारत न केवल दूध उत्पादन में 'आत्मनिर्भर' है, बल्कि वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दूध उत्पादक देश के रूप में भी प्रसिद्ध है, जो वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग 25 प्रतिशत का योगदान देता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी हस्तक्षेपों के निरंतर तथा व्यवस्थित प्रयोग और केंद्र एवं राज्य सरकारों के सहयोग से भारत शीघ्र ही निर्विवाद रूप से 'डेयरी टू द वर्ल्ड' बनने की कगार पर है।

भविष्य को गढ़ने के लिए एनडीडीबी ने 'विज़न 2047' तैयार किया है, जो अगले दो दशकों में भारत के डेयरी क्षेत्र के सतत् एवं समावेशी बदलाव का रणनीतिक रोडमैप है। अगले दो दशकों में, इस क्षेत्र का लक्ष्य डेयरी पशु उत्पादकता को मौजूदा 2,080 किलोग्राम से बढ़ाकर प्रतिवर्ष प्रति पशु 5,200 किलोग्राम करना है। संगठित डेयरी क्षेत्र की पहुँच को दोगुना करते हुए 1.7 लाख गाँवों से बढ़ाकर 3.5 लाख गाँवों तक विस्तारित करने की योजना है। सहकारी क्षेत्र में मूल्य संवर्धित दूध उत्पादों की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। 'विज़न 2047' के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रमुख हस्तक्षेपों में डेयरी सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण,

श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री; श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी और पंचायती राज मंत्री; प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल जी, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी और पंचायती राज राज्य मंत्री; श्री जॉर्ज कुरियन जी, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी और अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री; श्री राघवजीभाई पटेल जी, माननीय कृषि, पशुपालन, गौ-प्रजनन और मत्स्यपालन मंत्री, गुजरात सरकार; श्री जगदीश विश्वकर्मा जी, माननीय सहकारिता राज्य मंत्री, गुजरात सरकार और एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ मीनेश शाह एनडीडीबी के हीरक जयंती समारोह के अवसर पर एनडीडीबी, आणंद में आयोजित एक कार्यक्रम में दीप प्रज्ज्वलन समारोह के दौरान

प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल जी, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी और पंचायती राज राज्य मंत्री; श्री पियरक्रिस्टियानो ब्रेज़ाले, आईडीएफ अध्यक्ष; सुश्री लॉरेंस रेकेन, महानिदेशक, आईडीएफ; डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी और सदस्य सचिव, आईएनसी-आईडीएफ; श्री लॉरेंट डेमियंस, आईडीएफ बोर्ड सदस्य; श्री एस रघुपति, कार्यपालक निदेशक, एनडीडीबी; श्री मनीष बंदलिश, प्रबंध निदेशक, मदर डेयरी और अन्य गणमान्य व्यक्ति कोच्चि, केरल में आयोजित प्रथम एशिया पैसिफिक आईडीएफ क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन 2024 के दौरान

प्रसंस्करण, अवसंरचना का विकास, दूध की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना, विपणन सुधार, पशु उत्पादकता में वृद्धि तथा सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलैरिटी संबंधी पद्धतियों को आगे बढ़ाना शामिल है।

एनडीडीबी के समग्र रोग नियंत्रण मॉडल, जो 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण पर आधारित हैं, एंटीमाइक्रोबियल उपयोग (AMU) में कमी लाने और एंटीमाइक्रोबियल रेज़िस्टेंस (AMR) को कम करने में सहायक हैं, जो पशु एवं मानव स्वास्थ्य के लिए एक मौन महामारी के रूप में उभर रही है। 'वन हेल्थ' सिद्धांत को एकीकृत करके, ईवीएम के उपयोग को बढ़ावा देकर तथा जन-जागरूकता निर्मित करने पर विशेष बल देकर एनडीडीबी ने भारतीय डेयरी क्षेत्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और ग्रामीण समुदायों का समावेशी विकास एवं उत्थान सुनिश्चित किया है।

वर्ष के दौरान, एनडीडीबी की प्रगति में योगदान देने वाले सभी हितधारकों के निरंतर प्रयासों की हम हृदय से प्रशंसा व्यक्त करते हैं।

आइए, हम अटूट संकल्प और सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ इस यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाएं, ताकि भारत के लिए एक समृद्ध, सस्टेनेबल एवं समावेशी डेयरी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सके।

श्री जॉर्ज कुरियन जी, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री, श्रीमती जे. चिंचुरानी जी, माननीय पशुपालन, डेयरी विकास एवं दुग्ध सहकारिता मंत्री, केरल सरकार और डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी एवं आईआईएल, सीएडब्ल्यूए टीम को विशेष रूप से अनुकूलित रेबीज टास्क फोर्स वाहन की चाबी सौंपते हुए

डेयरी क्षेत्र के रुझान

घरेलू डेयरी परिदृश्य

पिछले 10 वर्षों में, देश में दूध का उत्पादन लगभग 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से निरंतर बढ़ रहा है, जबकि प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में 4 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2024-25 में देश में दूध का उत्पादन लगभग 250 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता लगभग 490 ग्राम प्रतिदिन तक पहुंचने की संभावना है।

अनुकूल जलवायु परिस्थितियों और वर्ष के उत्तरार्ध में, अधिकांश आहार सामग्री के मूल्य में कमी और डेयरी किसानों को लाभकारी मूल्य की प्राप्ति के कारण, यह वर्ष डेयरी व्यवसाय के लिए अनुकूल साबित हुआ।

भारत सरकार ने इनपुट लागत, विशेषकर पशु आहार की लागत को स्थिर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए। डी-ऑयल्ड राइस ब्रान (DoRB) के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहने से पशु आहार के मूल्य स्थिर बने रहे और इस प्रकार दूध उत्पादन की लागत तथा उपभोक्ताओं के स्तर पर दूध के मूल्य भी नियंत्रित रहे।

भले ही, डेयरी सहकारिताओं के पास अधिक मात्रा में संरक्षित कमोडिटी उपलब्ध थीं, उन्होंने फिर भी डेयरी किसानों से दूध संकलन जारी रखा। डेयरी सहकारिताओं द्वारा दूध संकलन 676 लाख किलोग्राम प्रतिदिन (LKgPD) तक बढ़ गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है।

डेयरी सहकारिताएं तकनीकी इनपुट और विस्तार सेवाओं के माध्यम से, लगातार डेयरी किसानों का समर्थन करती रहीं, जिनमें पशु चिकित्सा देखभाल, कृत्रिम गर्भाधान (AI), टीकाकरण, संतुलित पशु आहार, चारा बीज, खनिज मिश्रण आदि शामिल हैं। डेयरी

सहकारिताओं की औसत तरल दूध की बिक्री 444 लाख लीटर प्रतिदिन (LLPD) रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है।

स्किम्ड मिल्क पाउडर (SMP) और व्हाइट बटर जैसी संरक्षित डेयरी कमोडिटी की घरेलू बाजार कीमतों में वर्ष के दौरान मिला-जुला असर देखा गया। मार्च 2025 के अंत तक एसएमपी की कीमतें 5 प्रतिशत बढ़कर 247 रुपये प्रति किलोग्राम हो गईं। वहीं दूसरी ओर, व्हाइट बटर की कीमतें 21 प्रतिशत बढ़कर मार्च 2025 के अंत तक 414 रुपये प्रति किलोग्राम हो गईं।

अंतरराष्ट्रीय डेयरी क्षेत्र परिदृश्य

संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, वैश्विक दूध उत्पादन 2024 में 982.5 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2023 से 1.6 प्रतिशत अधिक है, जिसका मुख्य कारण भारत में दूध उत्पादन में वृद्धि है।

2024 में डेयरी उत्पादों का वैश्विक व्यापार 86.2 मिलियन टन (दूध के समतुल्य) होने का अनुमान है, जो वर्ष 2023 की तुलना में 2 प्रतिशत अधिक है। सबसे बड़े आयातक, चीन ने 14.2 मिलियन टन (दूध के समतुल्य) डेयरी उत्पादों का आयात किया, जो आयातित डेयरी उत्पादों के बढ़े हुए स्टॉक के कारण पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत कम है। चीन के आयात में यह कमी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, अफ्रीकी देशों तथा मध्य अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के देशों से आयात में वृद्धि द्वारा संतुलित की गई।

यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूज़ीलैंड से दूध के समतुल्य निर्यात में क्रमशः 4 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 1 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके विपरीत, ऑस्ट्रेलिया के निर्यात में वर्ष-प्रति-वर्ष 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो अनुकूल व्यापार समझौतों और बेहतर निर्यात प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ।

वैश्विक डेयरी व्यापार में वर्ष 2024-25 के दौरान स्किम्ड मिल्क पाउडर (SMP) और व्हाइट बटर के मूल्य में मामूली वृद्धि देखी गई। SMP का औसत मूल्य अप्रैल 2024 में लगभग 2,546 USD प्रति मीट्रिक टन से बढ़कर मार्च 2025 में 2,737 USD प्रति मीट्रिक टन हो गया। इसी तरह, बटर का मूल्य अप्रैल 2024 में 6,569 USD प्रति मीट्रिक टन से बढ़कर मार्च 2025 में 7,622 USD प्रति मीट्रिक टन तक पहुंच गया।

भारतीय डेयरी क्षेत्र में बदलाव

एनडीडीबी ने देश में डेयरी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए किसान-केंद्रित और नवाचार-आधारित दृष्टिकोण को और सुदृढ़ किया। विभिन्न देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोगात्मक पहलों के माध्यम से, एनडीडीबी ने न केवल राष्ट्रीय डेयरी क्षेत्र को सशक्त बनाया, बल्कि समान लघुधारक डेयरी प्रणाली वाले देशों, विशेषकर दक्षिण एशिया और अफ्रीका में अपनाने योग्य मॉडल भी प्रस्तुत किए।

भारत द्वारा प्रथम एशिया पैसिफिक आईडीएफ क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन 2024 की मेजबानी

भारत के लिए यह गर्व की बात है कि 26 से 28 जून 2024 को कोच्चि में एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए प्रथम IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन की मेजबानी की गई। इस सम्मेलन का विषय "डेयरी क्षेत्र में किसान-केंद्रित नवाचार" था और इसे इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन (IDF) के भारतीय राष्ट्रीय समिति के नेतृत्व में आयोजित किया गया। यह समिति पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव के अध्यक्षता में संचालित हुई और एनडीडीबी को इसके सचिवालय के रूप में शामिल किया गया। इस समिति में विभिन्न डेयरी सहकारिताएं, प्रमुख निजी क्षेत्र के संगठन और शैक्षणिक संस्थान शामिल थे। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में भारत सहित 25 देशों से 1,200 से अधिक लीडर, विशेषज्ञ और किसान उपस्थित हुए। इस अवसर पर डेयरी उद्योग की गंभीर चुनौतियों पर चर्चा की गई, जिसमें विशेष रूप से एशिया-पैसिफिक क्षेत्र और वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन 26 जून 2024 को कोच्चि, केरल में किया गया, जिसमें केरल सरकार के पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री श्रीमती जे. चिंचुरानी जी और अरुणाचल प्रदेश सरकार के कृषि, बागवानी, पशुपालन, पशु चिकित्सा और डेयरी विकास मंत्री श्री गैब्रियल डेनवांग वांगसू जी उपस्थित रहे। उपस्थित प्रमुख अतिथियों में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग की सचिव एवं आईडीएफ (आईएनसी- आईडीएफ) के भारतीय राष्ट्रीय समिति की अध्यक्ष श्रीमती अलका उपाध्याय; श्रीलंका की उच्चायुक्त

श्रीमती जे. चिंचुरानी जी, माननीय पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री, केरल सरकार; श्री गेब्रियल डेनवांग वांगसू जी, माननीय कृषि, बागवानी, पशुपालन, पशु चिकित्सा और डेयरी विकास मंत्री, अरुणाचल प्रदेश सरकार; श्री पियरक्रिस्टियानो ब्राज़ाले, आईडीएफ अध्यक्ष; सुश्री लॉरेंस रेकेन, महानिदेशक, आईडीएफ; श्रीमती अलका उपाध्याय, सचिव, डीएएचडी, भारत सरकार और अध्यक्ष आईएनसी-आईडीएफ; डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी और सदस्य सचिव, आईएनसी-आईडीएफ और अन्य गणमान्य व्यक्ति कोच्चि, केरल में प्रथम एशिया पैसिफिक आईडीएफ क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन 2024 के उद्घाटन के दौरान

डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी, आईडीएफ आरडीसी 2024 के अपने दौरे के दौरान प्रदर्शनी में माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल जी को जानकारी देते हुए

महामहिम श्रीमती क्षेनुका सनेविरत्ने; भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग की अपर सचिव सुश्री वर्षा जोशी; एनडीडीबी के अध्यक्ष एवं आईडीएफ के भारतीय राष्ट्रीय समिति के सदस्य सचिव डॉ. मीनेश शाह; केरल सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव श्री प्रणबज्योति नाथ; एफएओ इंडिया के श्री ताकायुकी हागिवारा; अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ (IDF) के अध्यक्ष श्री पिएरक्रिस्टियानो ब्राज़ाले; एवं आईडीएफ की महानिदेशिक श्रीमती लॉरेंस रेकेन शामिल रहे।

इस सम्मेलन में डेयरी और नवाचार पर वैश्विक और क्षेत्रीय दृष्टिकोण को शामिल करते हुए 11 सत्र आयोजित किए गए, जिनका मुख्य उद्देश्य किसान-केंद्रित हस्तक्षेपों के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने, दूध संकलन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सस्टेनेबल पद्धतियों को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित था। जलवायु चुनौतियों से निपटने से लेकर, वन हेल्थ (One Health) सिद्धांतों के प्रचार तक, इन सत्रों में सार्थक संवाद और व्यावहारिक जानकारियां प्रदान की गईं। इस विचार-विमर्श से एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में डेयरी क्षेत्र के विकास और उत्थान हेतु नवाचारी विपणन दृष्टिकोणों के बारे में भी जानकारी मिली। इसके अलावा, 22 प्रदर्शनी पवेलियन में डेयरी फार्म, प्रसंस्करण उपकरण और संबंधित तकनीकों का प्रदर्शन किया गया, जबकि
17 अलग-अलग स्टार्ट अप्स ने डेयरी और संबद्ध उद्योगों में अपनी नवाचार पहलें प्रस्तुत कीं। इस कार्यक्रम के दौरान NDERP प्रोजेक्ट, SAG–Slow Release (SAG-SR) सीमेन स्ट्रॉ और SAG MinVit एवं MinRich खनिज मिश्रण; AMUL का प्रोटीन युक्त दूध और चॉकलेट; और मिल्मा का रेडी-टू-ड्रिंक पलाडा पायसम भी लॉन्च किया गया।

FAO – IDF – NDDB द्वारा दूध उत्पादन संबंधी चुनौतियों का समाधान; सतत् क्षेत्रीय परिवर्तन के लिए नवाचार; DSF-NDDB द्वारा मिल्कशेड में स्थिरता फ्रेमवर्क का क्रियान्वयन; पर साइड इवेंट आयोजित किए गए तथा अंतर्राष्ट्रीय ऊँट परिवार (Camelids) वर्ष के अवसर पर साइड इवेंट भी आयोजित किए गए।

IDF विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन, 2024 में भागीदारी

11-18 अक्तूबर 2024 के दौरान फ्रांस के पेरिस में आयोजित IDF डेयरी शिखर सम्मेलन, 2024 और संबंधित बैठकों में भारत के एक प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया, जिसका नेतृत्व भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी विभाग की सचिव एवं INC-IDF की अध्यक्ष श्रीमती अलका उपाध्याय ने किया। श्रीमती उपाध्याय ने महिला राउंड-टेबल, मंत्रियों के पैनल-परिचर्चा और सस्टेनेबिलिटी पर डेयरी लीडर्स फोरम में भाग लिया। सस्टेनेबिलिटी पर डेयरी लीडर्स फोरम के दौरान, श्रीमती उपाध्याय और डॉ. मीनेश शाह, सदस्य सचिव, INC-IDF एवं अध्यक्ष, एनडीडीबी ने भारत का दृष्टिकोण साझा किया और 'पेरिस डेयरी डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबिलिटी' पर हस्ताक्षर किए।

श्रीमती उपाध्याय को IDF के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणपत्र भी प्रदान किया गया, जिसमें इस बात की घोषणा है कि भारत IDF WDS 2027 की मेज़बानी करेगा। भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी विभाग की अपर सचिव सुश्री वर्षा जोशी ने IDF स्थायी समितियों और महिला राउंडटेबल की विभिन्न बैठकों में भाग लिया। एनडीडीबी के अध्यक्ष ने भी IDF बिजनेस मीटिंग्स, जिनमें IDF बोर्ड बैठकें और राष्ट्रीय समितियों की बैठकें शामिल थीं, में भाग लिया। एनडीडीबी के अधिकारियों ने 'राउंड-टेबल परिचर्चा – 'फार्म स्तर पर सिद्धांत से क्रियान्वयन तक – डेयरी क्षेत्र में पशु कल्याण के लिए किन-किन-बातों को ध्यान में रखा जाए' और IDF बिजनेस मीटिंग्स में भागीदारी की।

एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज द्वारा प्रोमोट की गई आशा महिला दूध उत्पादक संगठन को 'डेयरी क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण में नवाचार' श्रेणी में प्रतिष्ठित IDF इनोवेशन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही, एनडीडीबी ने सुंदरबन कोऑपरेटिव मिल्क एंड लाइवस्टॉक प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड के साथ 'सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेज (सामाजिक-आर्थिक विकास) में नवाचार' श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किया।

आईडीएफ के अध्यक्ष श्री पियरक्रिस्टियानो ब्रेज़ाले ने भारत सरकार की डीएएचडी सचिव एवं आईएनसी-आईडीएफ की अध्यक्ष श्रीमती अलका उपाध्याय और एनडीडीबी के अध्यक्ष एवं आईएनसी-आईडीएफ के सदस्य सचिव डॉ. मीनेश शाह को एक प्रमाण पत्र प्रदान किया। उन्होंने घोषणा की कि पेरिस में आयोजित आईडीएफ डब्ल्यूडीएस 2024 के दौरान भारत आईडीएफ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी करेगा। इस अवसर पर आईडीएफ बोर्ड के सदस्य श्री गाइल्स फ्रॉमेंट, आईडीएफ बोर्ड के सदस्य श्री लॉरेंट डेमियंस और भारत सरकार की डीएएचडी की अपर सचिव सुश्री वर्षा जोशी भी उपस्थित रही

एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज द्वारा प्रवर्तित आशा महिला दूध उत्पादक संगठन 'डेयरी क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण में नवाचार' के लिए आईडीएफ नवाचार पुरस्कार 2024 प्राप्त करते हुए

नॉर्वे में आयोजित IDF चीज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिम्पोजियम, भारत की प्रतिभागिता

एनडीडीबी, अमूल, बनास डेयरी, मदर डेयरी और कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (नंदिनी) का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिष्ठित डेयरी प्रोफेशनल के एक प्रतिनिधि मंडल ने 4 से 6 जून 2024 को बर्गेन, नॉर्वे में आयोजित IDF चीज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिम्पोजियम में भाग लिया।

इस सिम्पोजियम का एजेंडा डेयरी क्षेत्र में वैज्ञानिक क्षेत्र में हुई नवीनतम प्रगति को समर्पित था, जिसमें विशेष रूप से संपूर्ण चीज़ उत्पादन मूल्य श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन सत्रों में महत्वपूर्ण विषयों की व्यापक रूप से चर्चा की गई, जिनमें दूध और चीज़ की गुणवत्ता, स्टार्टर कल्चर्स, माइक्रोबायोटा, बकरी और मेमनी दूध के चीज़ की गुणवत्ता, चीज़ निर्माण प्रक्रियाओं में नवाचार, सतत् उत्पादन और पैकेजिंग, और चीज़ की जटिल संरचना और मैट्रिक्स विषय शामिल थे।

यह सिम्पोजियम 30 से अधिक देशों के लगभग 200 वैज्ञानिकों के लिए एक समागम स्थल साबित हुआ, जिसने महत्त्वपूर्ण जानकारी के आदान-प्रदान और चीज़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवोन्मेषी विकास की सामूहिक खोज को संभव बनाया।

एनडीडीबी प्रतिनिधिमंडल द्वारा न्यूज़ीलैंड में पशुधन सुधार और डेयरी नवाचारों का अन्वेषण

एनडीडीबी के एक प्रतिनिधिमंडल ने न्यूज़ीलैंड का दौरा किया, जिसका मुख्य उद्देश्य वहां की उन्नत डेयरी फार्मिंग प्रणालियों का अध्ययन करना और जानकारी हासिल करना था। इस दौरे का उद्देश्य उन उन्नत पद्धतियों का पता लगाना था जिन्हें भारत में डेयरी क्षेत्र की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपनाया जा सके।

एनडीडीबी टीम ने अपने दौरे के दौरान कई क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग पर ध्यान केन्द्रीत किया, जिसमें पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, उन्नत चारागाह आधारित आहार प्रणाली और सतत् कृषि पद्धतियां शामिल थीं। उनकी गतिविधियों का एक प्रमुख हिस्सा लाइवस्टॉक इंप्रूवमेंट कार्पोरेशन (LIC) के साथ संवाद करना था, जो न्यूज़ीलैंड का एक प्रमुख कृषि-प्रौद्योगिकी सहकारी संस्थान है और अपने व्यापक योगदान, विशेषकर पशु सुधार और डेयरी फार्म प्रबंधन में योगदान के लिए मशहूर है। इसके अलावा, प्रतिनिधिमंडल ने फार्म प्रबंधन में डिजिटल समाधानों के एकीकरण का भी अध्ययन किया, जिन्होंने न्यूज़ीलैंड में संचालन को सुगम बनाने और दूध उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस दौरे के उपरांत, एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह ने एनडीडीबी और एनडीएस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर न्यूज़ीलैंड के माननीय कृषि मंत्री श्री टॉड मैक्ले से भेंट की। उनकी चर्चाएं पशु आहार और पोषण, भ्रूण एवं सीमन तकनीकों में प्रगति, तथा उत्सर्जन के मापन और शमन की विधियों जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में तकनीकी विशेषज्ञों के आदान-प्रदान पर केंद्रित रहीं। डॉ. शाह ने न्यूज़ीलैंड के मिनिस्ट्री फॉर प्राइमरी इंडस्ट्रीज की उप महानिदेशक सुश्री जूली कॉलिन्स के साथ भी भेंट वार्ता की, जिसमें भावी सहयोगात्मक परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें व्यावसायिक एक्पोजर विजिट, एथनो-वेटरिनरी दवाओं को एंटीबायोटिक्स के विकल्प के रूप में तलाशना तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सस्टेनेबल डेयरी से जुड़े विषयों पर एकीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करना जैसी पहलें शामिल थीं।

डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी, न्यूजीलैंड के माननीय कृषि मंत्री श्री टॉड मैक्ले के साथ

एनडीडीबी और एनडीएस के अधिकारी न्यूजीलैंड के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय, न्यूजीलैंड डेयरी कंपनी एसोसिएशन और वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में डेयरी न्यूजीलैंड के अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए

एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. के. आनंद कुमार और जीसीएमएमएफ के प्रबंध निदेशक श्री जयेन मेहता के साथ केन्या गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति, महामहिम श्री विलियम्स समोई रुटो से मुलाकात करते हुए

केन्या के डेयरी क्षेत्र के सशक्तिकरण हेतु समझौता

पिछले वर्ष की उन पहलों को आगे बढ़ाते हुए, एनडीडीबी के अध्यक्ष ने जीसीएमएमएफ के प्रबंध निदेशक के साथ मिलकर केन्या का दौरा किया, जिनका उद्देश्य केन्या में डेयरी मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना था। इस दौरे का उद्देश्य सहयोग के संभावित अवसरों का पता लगाना था, ताकि भारतीय विशेषज्ञता का उपयोग कर केन्या के डेयरी क्षेत्र को सशक्त बनाया जा सके। प्रतिनिधिमंडल ने केन्या सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, इंटरनेशनल लाइवस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट (ILRI) के प्रतिनिधियों और केन्या में भारत के उच्चायोग के सदस्यों सहित कई प्रमुख हितधारकों के साथ संवाद किया। चर्चाएं तकनीकी जानकारी के आधान-प्रदान, दूध उत्पादन बढ़ाने की रणनीतियां, किसानों के लिए उचित भुगतान प्रणालियों का कार्यान्वयन तथा सस्टेनेबल डेयरी कृषि पद्धतियों के विकास जैसे विषयों पर केंद्रित रहीं।

केन्या दौरे के दौरान, डॉ. शाह एवं भारतीय प्रतिनिधिमंडल को केन्या गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति श्री विलियम्स समोई रूटो से भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस बैठक में अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों पर सार्थक विचार-विमर्श हुआ। प्रमुख चर्चा क्षेत्रों में टीकों की आपूर्ति एवं टीका-निर्माण इकाइयों की स्थापना, आनुवंशिक सुधार की रणनीतियाँ (विशेष रूप से भैंसों के परिचय पर बल), दुग्ध उपकरणों एवं नवीन पैकेजिंग समाधानों की उपलब्धता, किसान-केंद्रित सहकारी डेयरी मॉडल का संवर्धन, बायोगैस एवं गोबर प्रबंधन संबंधी प्रौद्योगिकियाँ, परीक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, विभिन्न कार्यक्षेत्रों में व्यापक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, तथा दोनों सरकारों के मध्य औपचारिक सहयोगी ढाँचे का विकास के विषय सम्मिलित थे।

भारत द्वारा थाईलैंड में FAO क्षेत्रीय मंच पर पशुधन क्षेत्र में नवाचारों का प्रदर्शन

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में सतत् पशुधन बदलाव को समर्थन प्रदान करने हेतु क्षेत्रीय नवाचार मंच का आयोजन थाईलैंड के खोन केन में किया गया। इस अवसर पर, एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह तथा भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD) के आयुक्त डॉ. अभिजीत मित्रा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ (IDF) के साथ हुए समझौते से, एनडीडीबी ने इस मंच पर अनेक नवोन्मेषी एवं किसान-केंद्रित पहलों का प्रदर्शन किया। ये पहलें विशेष रूप से सस्टेनेबल डेयरिंग को बढ़ावा देने, दूध उत्पादकता में सुधार लाने, लाभप्रदता में वृद्धि करने तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं। इस प्रकार, ये प्रयास प्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) की प्राप्ति में योगदान करते हैं। प्रतिभागियों को एनडीडीबी, आणंद में 29 मार्च से 4 अप्रैल, 2025 तक आयोजित किए जाने वाले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (ICAR) के आगामी वार्षिक सम्मेलन तथा IDF/ISO Analytical Week 2025 के बारे में भी अवगत कराया गया।

डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी और डॉ. अभिजीत मित्रा, आयुक्त, डीएएचडी, भारत सरकार एफएओ के सहायक महानिदेशक डॉ. थानावत टिएनसिन को टोकन ऑफ़ एप्रिसिएशन प्रदान करते हुए

प्रदर्शनी में एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह, आयुक्त, डीएएचडी, भारत सरकार डॉ. अभिजीत मित्रा तथा एनडीडीबी के अधिकारी मौजूद रहे

वैश्विक स्वास्थ्य संबंधों को सुदृढ़ करना : वियतनाम में टीका साझेदारी के 15 वर्ष

एनडीडीबी के अध्यक्ष एवं आईआईएल के प्रबंध निदेशक डॉ. मीनेश शाह ने Dalat Pasteur Vaccine Company Limited (DAVAC), वियतनाम सरकार द्वारा आयोजित एक समारोह में सहभागिता की। यह आयोजन DAVAC, All for Medical Vietnam (AMV) Group एवं आईआईएल के बीच 15 वर्षों की सफल साझेदारी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस समझौते के अंतर्गत वियतनाम में आईआईएल के Vero cell-आधारित एंटी-रेबीज़ टीके – 'अभयरब' की सफलतापूर्वक शुरूआत की गई।

आईआईएल ने वियतनाम के पांच प्रोविंस में आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए 10,000 डोज एंटी-रेबीज़ वैक्सीन भी दान किए। इस समझौते से अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन समझौते में भारत की भूमिका उजागर होती है तथा यह सुलभ प्रौद्योगिकियों और जनस्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से "वन हेल्थ" दृष्टिकोण के समर्थन में भारतीय संस्थानों के योगदान को रेखांकित करता है।

एनडीडीबी और आईआईएल के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह, आईआईएल के प्रबंध निदेशक डॉ. के. आनंद कुमार के साथ वियतनाम में वियतनामी सरकार के रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम की प्रमुख डॉ. त्रान थी गियांग हुआंग को एंटी-रेबीज वैक्सीन की 10,000 डोज डोनेट करते हुए

उत्पादकता वृद्धि

एनडीडीबी ने सतत् डेयरी विकास के समर्थन में पशु प्रजनन, पोषण, स्वास्थ्य एवं निदान के क्षेत्रों में वैज्ञानिक हस्तक्षेपों को आगे बढ़ाने के अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखा। प्रमुख हस्तक्षेपों में जीनोमिक चयन के माध्यम से आनुवंशिक सुधार, प्रजनन जैव-प्रौद्योगिकियों का उपयोग तथा नस्लों का संरक्षण शामिल है। संस्था ने बेहतर आहार पद्धतियों को प्रोत्साहित करते हुए आहार संतुलन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया तथा संपूर्ण मिश्रित आहार (TMR) तकनीक को अपनाने की आवश्यकता व्यक्त की। पशु स्वास्थ्य संबंधी रणनीतियों को वन हेल्थ फ्रेमवर्क के अनुरूप बनाया गया, जिसमें रोग नियंत्रण एवं एंटीमाइक्रोबियल रेज़िस्टेंस (AMR) को कम करने पर विशेष बल दिया गया। निदान के क्षेत्र में प्रगति तथा जैवसुरक्षा उपायों को सुदृढ़ बनाने में स्वदेशी अनुसंधान ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समन्वित प्रयास उत्पादकता वृद्धि, जैवसुरक्षा को मजबूत करने और भारत के डेयरी क्षेत्र की समग्र स्थिरता को सुदृढ़ करने में सहायक रहे है।

पशु प्रजनन

एनडीडीबी ने व्यवस्थित प्रजनन हस्तक्षेपों के माध्यम से बोवाइन आबादी की आनुवंशिक क्षमता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। इन प्रयासों का उद्देश्य गायों एवं भैंसों दोनों में उत्पादकता को बढ़ाना तथा डेयरी व्यवसाय की सस्टेनेबिलिटी को समर्थन प्रदान करना रहा।

आनुवंशिक सुधार को दो प्रमुख रणनीतियों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया– उत्कृष्ट जर्मप्लाज्म की पहचान तथा श्रेष्ठ आनुवंशिकता का व्यापक स्तर पर वितरण। एनडीडीबी ने आनुवंशिक प्रगति को गति प्रदान करने के लिए जीनोमिक चयन, सेक्स-सॉर्टेड सीमन के उपयोग तथा भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का क्रियान्वयन किया।

भारत सरकार की राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के अंतर्गत एनडीडीबी ने देशी नस्लों के आनुवंशिक मूल्यांकन में नेतृत्व किया, जिसे निम्नलिखित कार्यक्रमों के माध्यम से क्रियान्वित किया गया—

- एनडीडीबी ने व्यवस्थित प्रदर्शन रिकॉर्डिंग और अधिक उत्पादक पशुओं की पहचान करने के लिए संतति परीक्षण (PT), वंशावली चयन (PS) और राष्ट्रीय दुग्ध रिकॉर्डिंग कार्यक्रम (NMRP) को क्रियान्वित किया।
- एनडीडीबी ने उन्नत प्रजनन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से श्रेष्ठ जर्मप्लाज़्म का तीव्र गुणन करने के लिए तीव्र नस्ल सुधार कार्यक्रम (ABIP-IVF) लागू किया।
- एनडीडीबी ने भ्रूण प्रत्यारोपण प्रौद्योगिकी (ETT) कार्यक्रम के अंतर्गत स्वदेशी कल्चर मीडिया विकसित किया, जिससे इन-विट्रो भ्रूण उत्पादन एवं प्रत्यारोपण की सफलता दर में सुधार हुआ।
- एनडीडीबी ने ABIP-SSS के अंतर्गत सेक्स-सॉर्टेड सीमन के उपयोग को बढ़ावा दिया, जिससे मादा बछड़ों की संख्या में वृद्धि हुई और प्रतिस्थापन दर एवं दीर्घकालिक पशु उत्पादकता में सुधार हुआ।

इन कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रमुख देशी एवं संकर नस्ल डेयरी पशु गाय एवं भैंस नस्लों को शामिल किया गया। एनडीडीबी ने सटीक चयन निर्णयों हेतु जीनोमिक चयन का उपयोग किया। प्रजनन जैव-प्रौद्योगिकियां श्रेष्ठ आनुवंशिक गुणों के तीव्र प्रसार में सहायक रहीं।

इन प्रयासों ने सतत् आनुवंशिक प्रगति एवं नस्ल संरक्षण की आधारशिला को सुदृढ़ किया तथा राष्ट्रीय प्रजनन नीति के उद्देश्यों के अनुरूप परिणाम सुनिश्चित किए।

जीनोमिक चयन – गोवंशीय पशुओं में तीव्र आनुवंशिक सुधार की पद्धति

युवा सांड़ों का जीनोमिक चयन

एनडीडीबी ने गौवंशीय आबादी में आनुवंशिक सुधार को तीव्र करने के लिए अपने जीनोमिक चयन कार्यक्रम का विस्तार किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संदर्भ आबादी का विस्तार करना तथा देशी एवं संकर डेयरी नस्लों में कवरेज बढ़ाना है।

एनडीडीबी ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) तथा गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर (GBRC) द्वारा समर्थित परियोजनाओं के अंतर्गत सत्यापित प्रदर्शन रिकार्ड वाले 18,005 गायों एवं भैंसों का जीनोटाइपिंग किया। साथ ही, GCMMF ने भी एनडीडीबी के सहयोग से जीनोटाइपिंग हेतु प्रदर्शन-रिकार्डेड गायों से सैंपल उपलब्ध कराए, जिससे संदर्भ आबादी को और अधिक सुदृढ़ किया जा सका।

एनडीडीबी ने विभिन्न नस्लों—गिर, साहिवाल, कांकरेज, मुर्रा, महेसाना, क्रॉसब्रेड होल्सटीन फ्रीज़ियन (HFCB) तथा क्रॉसब्रेड जर्सी (JYCB)—के 1,612 युवा सांड़-बछड़ों का जीनोटाइपिंग किया। ये बछड़े संतति परीक्षण (PT) एवं वंशावली चयन (PS) कार्यक्रमों के अंतर्गत पैदा किए गए थे। इनका मूल्यांकन GAUCHIP (गायों के लिए) एवं MAHISHCHIP (भैंसों के लिए) का उपयोग करके किया गया। जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यूज़ (GBV) के आधार पर वीर्य केन्द्रों हेतु सांडों का चयन किया गया, जिससे कृत्रिम गर्भाधान (AI) के माध्यम से आनुवंशिक लाभप्रदता के उद्देश्य से हिमीकृत वीर्य का उत्पादन संभव हुआ।

जीनोमिक चयन को किसानों एवं प्रजनन संस्थाओं के बीच व्यापक जन स्वीकृति प्राप्त हुई। एनडीडीबी काफ लिमिटेड ने 11,835 गाय एवं भैंस के सैम्पलों का जीनोटाइपिंग किया तथा उच्च आनुवंशिक क्षमता वाली बछिया एवं सांड़ों के चयन में सहयोग हेतु जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यूज़ (GBV) साझा किए। जीनोटाइप-आधारित नस्ल शुद्धता आकलन की मांग में वृद्धि हुई, जिससे शुद्ध नस्लीय पशुओं की पहचान एवं संरक्षण को समर्थन प्राप्त हुआ।

एनडीडीबी ने 30 देशी नस्लों, 2 संकर नस्लों (क्रॉसब्रेड होल्सटीन फ्रिज़ियन एवं क्रॉसब्रेड जर्सी) तथा 2 विदेशी नस्लों (जर्सी एवं होल्सटीन फ्रिज़ियन) की 1,28,826 जीनोटाइप की गई गायों का डीएनए रिपोजिटरी बनाए रखा। इस रिपोजिटरी में 12 भैंस नस्लों, जिनमें स्वैम्प भैंसें भी सम्मिलित हैं, के 98,979 डीएनए सैंपल भी उपलब्ध हैं। इनमें से 61,632 गायें एवं 62,928 भैंसें रेफरेंस डीएनए बायोबैंकिंग सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत संपूर्ण-जीनोम स्तर पर जीनोटाइप की गईं। इस वर्ष हिमाचली पहाड़ी, लद्दाखी एवं बारगुर जैसी गाय नस्लों तथा गोजरी एवं बारगुर जैसी भैंस नस्लों का भी जीनोटाइपिंग किया गया।

ओवम पिक-अप, इन-विट्रो भ्रूण उत्पादन एवं भ्रूण प्रत्यारोपण (OPU-IVEP-ET)

ओवम पिक-अप एवं इन-विट्रो भ्रूण उत्पादन (OPU-IVEP) को श्रेष्ठ गौवंशीय डेयरी आनुवंशिकी के प्रसार हेतु व्यापक मान्यता प्राप्त हुई है, विशेष रूप से उन देशों में जहां डेयरी क्षेत्र विकसित हैं। यह प्रौद्योगिकी, उत्कृष्ट जर्मप्लाज्म के तीव्र गुणन के माध्यम से गाय एवं भैंसों के आनुवंशिक वृद्धि को तीव्र गति प्रदान करने की अपनी विशिष्ट क्षमता के कारण, भारत के डेयरी परिदृश्य में बदलाव करने तथा डेयरी व्यवसाय की पद्धतियों को पुनः अभिमुख करने में अत्यंत आशाजनक सिद्ध हो रही है।

एनडीडीबी OPU-IVEP-ET सुविधा ने गाय एवं भैंस दोनों के लिए इस तकनीक की दक्षता बढ़ाने के प्रयासों को निरंतर जारी रखा। तकनीकी अपनाने के अलावा, इस सुविधा ने कुशल जनशक्ति के विकास पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया, जो गौवंशीय प्रजनन प्रौद्योगिकियों की प्रगति के साथ-साथ एक सक्षम कार्यबल सुनिश्चित करने के प्रति एनडीडीबी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। साथ ही, इसमें स्वदेशी OPU-IVEP-ET कल्चर मीडिया विकसित कर इस प्रौद्योगिकी की लागत में कमी लाने पर भी बल दिया गया है।

1,812

जीवनक्षम भ्रूण श्रेष्ठ गोवंश डोनर से उत्पादित किए गए

790

भ्रूण प्रत्यारोपण किए गए, जिनमें 173 गर्भधारण की पुष्टी हुई

72

वर्ष के दौरान, OPU-IVEP-ET प्रोटोकॉल के माध्यम से 72 बछड़ों का जन्म हुआ

एनडीडीबी ने अमूल डेयरी, बनास डेयरी तथा असम कृषि विश्वविद्यालय को OPU-IVEP-ET सुविधाएं स्थापित करने और उन्हें क्रियान्वित करने हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

एनडीडीबी ने किसानों के घर तक OPU-IVEP-ET तकनीक पहुंचाने के लिए प्रमुख 'हब एंड स्पोक' मॉडल को कार्यान्वित किया, जिसे डेयरी संघों के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से लागू किया गया। इस मॉडल का उद्देश्य जिम्मेदारियों के व्यवस्थित विभाजन के माध्यम से भारत में भ्रूण प्रत्यारोपण की दीर्घकालिक व्यवहार्यता स्थापित करना। इस ढांचे के तहत, एनडीडीबी प्रयोगशाला 'हब' के रूप में कार्य करती है, जो भ्रूण उत्पादन और क्षेत्र में OPU एवं ET प्रक्रियाओं के लिए प्रारंभिक आवश्यक सहयोग प्रदान करने की जिम्मेदारी निभाती है। वहीं, दूध संघ 'स्पोक' के रूप में कार्य करते हैं, जिनका काम श्रेष्ठ डोनर पशुओं की पहचान करना, ग्राही पशु का समन्वयन करना, पशु के गर्मी में आने का पता लगाना, क्षेत्र में भ्रूण प्रत्यारोपण करना और किसानों के बीच जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना है।

यह 'हब एंड स्पोक' मॉडल गुजरात के पांच प्रमुख दूध संघों — अमूल, बनास, साबर, महेसाणा तथा सुमुल द्वारा अपनाया गया। इस मॉडल का संचयी परिणाम निम्नानुसार हैः

1,800

भ्रूण किसानों के घर पर ही प्रत्यारोपित किए गए

280

पशु गाभिन हुए

194

बछड़ों का जन्म हुआ

इसमें कम से कम 25 पशुचिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया, जो अब स्वतंत्र रूप से भ्रूण प्रत्यारोपित कर रहे हैं, जिससे इस क्षमता-विकास प्रयास की सफलता परिलक्षित होती है।

किसानों के बीच इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए, अमूल डेयरी ने अपनी प्रयोगशाला स्थापित की, जबकि बनास, साबर और महेसाणा दुग्ध संघ की उनकी प्रयोगशालाएं निर्माणाधीन हैं। इन पहलों का समर्थन करने में एनडीडीबी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इन प्रयोगशालाओं की प्रभावी स्थापना और संचालन हेतु विशेषज्ञता एवं सहयोग उपलब्ध कराया गया। ये प्रयास पशु अनुवांशिकी के सुदृढ़ीकरण, उत्पादकता में सुधार तथा OPU-IVEP-ET के व्यापक उपयोग द्वारा किसानों की आय बढ़ाने पर केन्द्रित रहे।

साइलेज बनाने के लिए चारे की कटाई

पशु आहार

एनडीडीबी ने किफायती तरीके से डेयरी पशुओं के दूध उत्पादन और गुणवत्ता, आहार दक्षता और प्रजनन प्रदर्शन में सुधार के लिए पशु पोषण कार्यक्रम लागू किए।

आहार संतुलन कार्यक्रम (RBP) के माध्यम से संतुलित आहार को बढ़ावा देना

एनडीडीबी ने डेयरी पशुओं के लिए वैज्ञानिक पोषण पद्धतियों को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा। एनडीडीबी ने आहार संतुलन कार्यक्रम (RBP) के माध्यम से किसानों के घर तक आहार परामर्श सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित किया। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, एनडीडीबी ने डेयरी सहकारिताओं एवं अन्य कार्यान्वयन साझेदारों को तकनीकी सहायता प्रदान की, ताकि पशु उत्पादकता में स्थायी रूप से सुधार लाने हेतु आरबीपी को अच्छे से लागू किया जा सके।

आगा खां फाउंडेशन (AKF), जो एक गैर-लाभकारी संस्था है, के सहयोग से एनडीडीबी ने बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में आहार संतुलन कार्यक्रम (RBP) का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया। इस साझेदारी के अंतर्गत 4,089 किसानों के स्वामित्व वाले 5,491 पशुओं को आहार परामर्श सेवाएं प्रदान की गईं। वैज्ञानिक आहार विधियों को अपनाने से दूध उत्पादन में प्रति पशु प्रतिदिन औसतन 0.26 लीटर की वृद्धि हुई, फैट कंटेंट में 0.11 यूनिट का सुधार हुआ, तथा प्रति किलोग्राम दूध पर आधारित आंतरिक मीथेन उत्सर्जन में 8 से 15 प्रतिशत तक की कमी देखी गई।

कोल्हापुर दूध संघ ने भी अपने संकलन क्षेत्र में आहार परामर्श सेवाएं प्रदान करना निरंतर जारी रखा। संघ ने कुल 23,548 किसानों के 45,817 पशुओं को इस कार्यक्रम के तहत सेवाएं प्रदान कीं। वैज्ञानिक आहार व्यवस्था के माध्यम से दूध उत्पादन में प्रति पशु प्रतिदिन औसतन 0.32 लीटर की वृद्धि तथा फैट कंटेंट में 0.29 यूनिट का सुधार दर्ज किया गया।

राष्ट्रीय दूध रिकार्डिंग कार्यक्रम (NMRP) के क्रियान्वयन को सुगम बनाने हेतु, एनडीडीबी ने 27 कार्यान्वयन एजेंसियों के पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया, ताकि वे कार्यक्रम में पंजीकृत पशुओं को आहार परामर्श सेवाएं प्रदान कर सकें। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान 1,259 पशुओं को ये सेवाएं प्रदान की गईं।

इसके अलावा, एनडीडीबी ने विभिन्न राज्यों के पशुपालन विभागों के 156 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। यह प्रशिक्षण पशु पोषण के मूल सिद्धांतों तथा 'भारत पशुधन' प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आहार संतुलन पर केंद्रित रहा।

परंपरागत संपूर्ण मिश्रित आहार (TMR) को बढ़ावा देना

एनडीडीबी ने एक नया आहार वितरण समाधान विकसित किया, जिसमें पूरे वर्ष डेयरी पशुओं को संतुलित और तैयार-खाने योग्य आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परंपरागत पैक्ड टीएमआर के उत्पादन का विकास और मानकीकरण किया गया।

सहकारी क्षेत्र में पहला संपूर्ण मिश्रित आहार (TMR) संयंत्र अमूल में भारत सरकार के राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) की वित्तीय सहायता और एनडीडीबी की तकनीकी विशेषज्ञता की मदद से स्थापित किया गया। वित्त वर्ष 2024–25 में लगभग 550 मीट्रिक टन पैक्ड टीएमआर का उत्पादन किया गया और इसे डेयरी किसानों में वितरित किया गया।

इस पहल का विस्तार करने के लिए, एनडीडीबी ने अन्य डेयरी सहकारिताओं को राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के तहत टीएमआर संयंत्रों के लिए प्रस्ताव तैयार करने और प्रस्तुत करने में सहायता प्रदान की। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, बनासकांठा और जयपुर दूध संघों द्वारा दो टीएमआर संयंत्रों के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। वर्ष के दौरान, बनासकांठा दूध संघ ने अपने टीएमआर संयंत्र की स्थापना पूरी की और 2025–26 में इसकी कमीशनिंग होने की योजना है।

पारंपरिक टीएमआर संयंत्र

पशु आहार एवं संपूरक उत्पादन के लिए तकनीकी सहयोग

एनडीडीबी ने डेयरी सहकारिताओं को सुरक्षित एवं संतुलित मिश्रित पशु-आहार के उत्पादन में सहयोग प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाई। मिश्रित पशु-आहार डेयरी पशुओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। डेयरी सहकारिताओं द्वारा संचालित पशु आहार संयंत्रों (CFP) ने देश में उत्पादित कुल मिश्रित पशु-आहार का लगभग आधा भाग निर्मित किया।

एनडीडीबी ने पशु आहार संयंत्रों (CFP) को न्यूनतम लागत पर पशु आहार निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा नए फीड वैरिएंट के विकास जैसे क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग प्रदान की। वित्त वर्ष 2024–25 में एनडीडीबी के तकनीकी मार्गदर्शन से सूरत एवं जयपुर पशु आहार संयंत्रों में तीन नए मिश्रित पशु फीड वैरिएंट — प्रेग्नेंसी फ़ीड, अर्ली लैक्टेशन फ़ीड तथा काफ स्टार्टर की सफलतापूर्वक शुरूआत की गई।

वित्त वर्ष 2024–25 में, एनडीडीबी ने सीएफपी के कार्मिकों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास में सहयोग प्रदान किया। इस अवधि में 18 सीएफपी के 22 गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारियों को आहार निर्माण तकनीकों, गुणवत्ता आश्वासन तथा मिश्रित पशु आहार निर्माण से संबंधित नए रुझानों पर प्रशिक्षित किया गया।

नियमित पशु आहार उत्पादन के अलावा, एनडीडीबी ने सीएफपी को विशिष्ट पोषण संबंधी एवं मौसमी आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष आहार संपूरक उत्पादन में सहयोग प्रदान किया। वर्ष 2023–24 के दौरान एनडीडीबी के मार्गदर्शन से 11 पशु आहार संयंत्रों में लगभग 959 मीट्रिक टन समृद्धि (दूध में फैट एवं एसएनएफ की मात्रा बढ़ाने हेतु विकसित आहार संपूरक) का उत्पादन किया गया। इसके अतिरिक्त, दो सीएफपी द्वारा 3 मीट्रिक टन पशु शीतवर्धक (अत्यधिक गर्म जलवायु परिस्थितियों में डेयरी पशुओं में हीट स्ट्रेस को कम करने हेतु विकसित आहार संपूरक) का उत्पादन किया गया।

पशु पोषण हेतु वैकल्पिक आहार संसाधन

पारंपरिक पशु आहार कच्चे माल की बढ़ती लागत के मद्देनज़र, एनडीडीबी ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अपारंपरिक खाद्य सामग्रियों के उपयोग की संभावनाओं का परीक्षण किया। यह पहल मिश्रित पशु-आहार की किफ़ायती उपलब्धता बनाए रखने तथा डेयरी व्यवसाय की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई।

एनडीडीबी ने वैकल्पिक आहार सामग्रियों जैसे कलौंजी की खल, अनार छिलका तथा संतरे के अवशेष का मूल्यांकन किया और इन्हें मिश्रित पशु-आहार में सम्मिलित करने की संभावनाओं का आकलन किया। इन सामग्रियों के इन-विट्रो विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि इन्हें सुरक्षित रूप से पशु आहार में शामिल किया जा सकता है — कलौंजी की खल एवं अनार छिलका 2 प्रतिशत तक तथा संतरे का अवशेष 4 प्रतिशत तक, जिससे पाचन तंत्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

इसके अलावा, एनडीडीबी ने बेकरी अपशिष्ट पर आहार परीक्षण प्रारंभ किया, ताकि मिश्रित पशु-आहार में इसके उपयुक्त उपयोग स्तर एवं संभावना का पता लगाया जा सके। इस प्रकार की पहलें देशभर के दूध उत्पादकों के लिए किफ़ायती, क्षेत्र विशिष्ट एवं पोषण संबंधी संतुलित आहार समाधान उपलब्ध कराने के प्रति एनडीडीबी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

दुधारू भैंसों हेतु गेहूं के भूसे के विकल्प के रूप में हरे धान की पराली से साइलेज का मूल्यांकन

एनडीडीबी ने मिल्कफेड, पंजाब तथा गुरु अंगद देव पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (गडवासु), लुधियाना के सहयोग से पंजाब में हरे धान की पराली को साइलेज के रूप में उपयोग करने की संभावना पर प्रायोगिक अध्ययन किया। इस पहल का उद्देश्य सूखे चारे, विशेष रूप से गेहूं के भूसे, के विकल्प के रूप में व्यावहारिक समाधान उपलब्ध कराना तथा फसल अवशेष जलाने से उत्पन्न पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करना है, जो श्रमिकों की कमी और कटाई से बुवाई के अल्प समयांतराल के कारण क्षेत्र में प्रचलित है।

भारत में पशु आहार का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा सूखे चारे से प्राप्त होता है तथा इसकी उपलब्धता में कमी निरंतर चिंता का विषय बनी हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में व्यापक मूल्यांकन हेतु धान की पराली से दो

गेहूं के भूसे के विकल्प के रूप में धान की पराली से बना साइलेज : एक व्यावहारिक एवं सुरक्षित विकल्प

प्रकार का साइलेज तैयार किया गया— पहला बिना उपचार का तथा दूसरा कल्चर और एंजाइम से समृद्ध।

इन विट्रो तथा इन विवो दोनों प्रकार के आकलन और प्रायोगिक परीक्षण लुधियाना स्थित गडवासु डेयरी फ़ार्म में सम्पन्न किए गए। साथ ही, क्षेत्रीय परीक्षण कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), बरनाला एवं कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), मोहाली में आयोजित किए गए।

इन विट्रो विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि अनट्रीटेट धान की पराली को साइलेंज में, ट्रीटेट वैरिएंट की तुलना में, शुष्क पदार्थ पाचन क्षमता, कार्बनिक पदार्थ पाचन क्षमता, न्यूट्रल डिटर्जेंट फ़ाइबर पाचन क्षमता तथा सूक्ष्मजीवी बायोमास उत्पादन सहित पाचन क्षमता से संबंधित मापदंड उल्लेखनीय रूप से श्रेष्ठ पाए गए।

अठारह दूधारू भैंसों पर किए गए इन विवो परीक्षणों में ट्रीटमेंट ग्रुप के बीच पाचन क्षमता संबंधी मापदंडों में कोई महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित नहीं हुआ। तथापि, गेहूं का भूसा ग्रुप में औसत दुग्ध उत्पादन (10.47 किग्रा/पशु/दिन) अनट्रीटेड साइलेज ग्रुप (9.99 किग्रा/पशु/दिन) एवं ट्रीटेट साइलेज ग्रुप (9.94 किग्रा/पशु/दिन) की तुलना में अधिक पाया गया।

दूध में फैट का प्रतिशत, गेहूं का भूसा ग्रुप (6.74 प्रतिशत) एवं ट्रीटेट साइलेज ग्रुप (7.26 प्रतिशत) के बीच सांख्यिकीय दृष्टि से समतुल्य पाया गया, जबकि यह अनट्रीटेट साइलेज ग्रुप (6.63 प्रतिशत) में उल्लेखनीय रूप से काफी कम पाया गया। इसके विपरीत, प्रोटीन, लैक्टोज़ तथा एसएनएफ के प्रतिशत ट्रीटेट साइलेज ग्रुप में गेहूं का भूसा ग्रुप की तुलना में अधिक पाए गए।

रक्त और हीमेटोलॉजिकल पैरामीटर्स में किसी भी समूह में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं पाई गई, सभी मापदंड सामान्य फीजियोलॉजिकल रेंज के भीतर रहे।

आर्थिक विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि गेहूं का भूसा पर आधारित आहार सबसे अधिक किफ़ायती रहा, जिससे प्रति पशु प्रतिदिन 269 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ, जबकि ट्रीटेट साइलेज से 255 रुपये तथा अनट्रीटेट साइलेज से 213 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन का शुद्ध लाभ मिला।

क्षेत्रीय परीक्षणों से पुष्टि हुई कि डेयरी पशुओं को प्रतिदिन 7–8 किलोग्राम धान की पराली से बना साइलेज खिलाना सुरक्षित है। इन परिणामों से यह प्रदर्शित हुआ है कि यद्यपि गेहूं की भूसी की आर्थिक लाभप्रदता बरकरार रही, परन्तु धान की पराली से बना साइलेज भी एक व्यावहारिक और सुरक्षित विकल्प है, जो चारे की कमी की समस्या का समाधान प्रदान करने के साथ-साथ पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में योगदान दे सकता है।

चारा उत्पादन एवं संरक्षण को बढावा देना

एनडीडीबी ने डेयरी सहकारिताओं को हरे एवं सूखे चारे तथा कृषि-औद्योगिक उपोत्पादों के उत्पादन, संरक्षण एवं उपयोग में सुधार हेतु सहयोग प्रदान किया। हरा चारा एक किफायती और पोषक तत्वों से भरपूर संसाधन है, जो दूध उत्पादन में सुधार और चारे की लागत को कम करने के लिए आवश्यक है।

निम्नलिखित उपाय किए गए :

- अधिक उपज देने वाली चारा फसलों की किस्मों के प्रजनक बीज की व्यवस्था ICAR/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से की गई।
- सहकारी नेटवर्क के माध्यम से गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन एवं वितरण में सहयोग प्रदान किया गया।
- किसानों को चारा उत्पादन एवं पोषण-वृद्धि हेतु उन्नत कृषि-तकनीकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- हरे चारे के संरक्षण के लिए साइलेज एवं हेलेज़ जैसी वैज्ञानिक विधियों तथा सूखे चारे के भंडारण को बढ़ावा दिया गया।
- कृषि-औद्योगिक अवशेषों एवं कार्बनिक उप-उत्पादों (जैसे, फल एवं सब्ज़ियों के अपशिष्ट) के क्षेत्र-विशिष्ट उपयोग एवं संरक्षण को प्रोत्साहित किया गया।

इन उपायों से दूधारू पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता में वृद्धि हुई तथा सदस्य दूध संघों में सस्टेनेबल आहार पद्धतियों को बढ़ावा मिला।

एनडीडीबी, आणंद में हीरक जयंती समारोह के अवसर पर एनडीडीबी और सैक-इसरो के बीच एमओयू का आदान-प्रदान

रिमोट सेंसिंग तकनीक के माध्यम से आहार संसाधनों का मानचित्रण

एनडीडीबी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (SAC) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत सैटेलाइट-आधारित रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग कर आहार संसाधनों का मानचित्रण किया जाना प्रस्तावित है। यह पहल चारा फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन से संबंधित विश्वसनीय राष्ट्रीय आंकड़ों की कमी, जो अब तक आहार संबंधी योजना निर्माण एवं वितरण में निरंतर बाधक रही, को दूर करने हेतु की गई है।

इस समझौता ज्ञापन (MoU) का उद्देश्य रियल टाइम पर भू-स्थानिक संदर्भित आंकड़े तैयार करना है, जिससे हरे चारे के संसाधनों के पूर्वानुमान एवं निगरानी को सुदृढ़ किया जा सके। इसके अलावा, इस पहल से चारे की अधिकता एवं चारे की कमी वाले क्षेत्रों की पहचान संभव हुई, जिसके परिणामस्वरूप चारे के अधिक न्यायसंगत वितरण को सुगम बनाने तथा आपूर्ति श्रृंखला की कार्यकुशलता में सुधार करने में सहायता मिली।

एनडीडीबी ने इसके आरंभिक चरण के भाग के रूप में बिहार और राजस्थान राज्यों में एक प्रायोगिक अध्ययन की शुरूआत की। रिमोट सेंसिंग आँकड़ों की पुष्टि हेतु ग्राउंड-ट्रुथिंग अभ्यास किए गए तथा राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन के लिए मानकीकृत प्रोटोकॉल विकसित किए गए। इस पहल ने सतत् चारा प्रबंधन में एनडीडीबी के प्रयासों को और सुदृढ़ किया तथा आँकड़ा-आधारित एवं जलवायु-अनुकूल हस्तक्षेपों के माध्यम से राष्ट्रीय डेयरी विकास उद्देश्यों में योगदान सुनिश्चित किया।

बीज गुणन श्रृंखला का विकास

एनडीडीबी ने 18 डेयरी सहकारिताओं को अपना समर्थन प्रदान किया, जिससे उनकी चारा बीज गुणन आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिली, जिनमें से 6 खरीफ मौसम के दौरान और 12 रबी मौसम में शुरू की गईं। विभिन्न आईसीएआर संस्थानों एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से कुल 17.82 मीट्रिक टन ब्रीडर बीज सफलतापूर्वक क्रय किए गए। इन बीजों का चयन उन्नत चारा किस्मों पर केन्द्रित था, जो हरे चारे एवं साइलेज उत्पादन—दोनों के लिए उपयुक्त हैं।

डेयरी सहकारिताओं एवं विशिष्ट बीज उत्पादन एजेंसियों ने इन ब्रीडर बीजों के गुणन में सहभागिता की तथा उन्हें फाउंडेशन एवं प्रमाणित बीजों में परिवर्तित किया। इससे अधिक उत्पादकता वाले चारा किस्मों की समग्र उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस रणनीतिक हस्तक्षेप से प्रति हेक्टेयर मीट्रिक टन में मापी गई चारा उत्पादकता में प्रत्यक्ष रूप से सुधार हुआ तथा किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण हरे चारे की पहुंच सुलभ हुई।

पशु आहार उत्पादन प्रौद्योगिकियों पर जागरूकता

एनडीडीबी ने दुग्ध उत्पादकों के बीच चारा उत्पादन प्रौद्योगिकियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु अनेक पहलें कार्यान्वित कीं। आणंद स्थित चारा प्रदर्शन इकाई में जई (JO 05-304, PLP-24, SFO-7, SFO-8), बरसीम (BL-45, BL-46) तथा हिम पालम राई घास-1 जैसी उन्नत चारा किस्मों का प्रदर्शन किया गया।

किसानों को साइलेज निर्माण हेतु मक्का एवं ज्वार की अधिक उत्पादकता वाली संकर किस्मों तथा हरे चारे हेतु बरसीम, लूसर्न और जई की खेती पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्षभर हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डेयरी किसानों को 78,000 से अधिक हाइब्रिड नेपियर के स्टेम की कटिंग वितरित की गई।

इसके अलावा, एनडीडीबी ने गुजरात की मुजकुवा डेयरी सहकारिता तथा कोटयार्क गौशाला को वर्षभर हरे चारे हेतु फार्म स्थापित करने एवं उनके प्रबंधन हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

पशु आहार उत्पादन में वृद्धि एवं अपारंपरिक संसाधनों के संवर्धन पर कार्यशाला

एनडीडीबी ने फरवरी 2025 में "पशु आहार उत्पादन दक्षता में वृद्धि, चारा गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा अपारंपरिक चारा संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देना" विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। एनडीडीबी के अध्यक्ष द्वारा कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर दूध संघों एवं महासंघों से जुड़े तकनीकी विशेषज्ञों, प्रबंधकों एवं गुणवत्ता नियंत्रण कर्मियों सहित लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

सत्रों में प्रक्रिया अनुकूलन, बीआईएस मानक तथा लागत में कमी एवं सस्टेनेबिलिटी संवर्धन हेतु अपारंपरिक सामग्रियों को शामिल करने पर चर्चा की गई। साथ ही, पशु उत्पादकता से संबंधित प्रमुख चुनौतियों, चारे की कमी तथा बायो फ्यूल के उत्पादन हेतु अनाजों के बढ़ते उपयोग पर भी विचार-विमर्श किया गया। प्रतिभागियों ने साबरकांठा दूध संघ के पशु-आहार संयंत्र एवं अमूल टीएमआर संयंत्र का भ्रमण कर उत्कृष्ट पद्धतियों का अवलोकन किया।

डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी "चारा उत्पादन बढ़ाने और अपरंपरागत संसाधनों के संवर्धन पर कार्यशाला" में सभा को संबोधित करते हुए

सफलता की कहानी – बनासकांठा, गुजरात में गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन के माध्यम से चारा उपलब्धता में वृद्धि

"बंजर भूमि में भी, बीज और विश्वास ने भूमि को हरित समृद्धि में बदल डाला।"

बनासकांठा के सूखे, धूप से झूलसते मैदानों में - जहां खेती का मतलब अक्सर खेत जोतने से ज्यादा प्राकृतिक आपदाओं से जूझना होता था। वहीं, चुपचाप एक प्रभावशाली क्रांति ने अपनी जड़ें जमा ली। यह क्रांति नवीनतम यंत्रों या तकनीक से नहीं, बल्कि सबसे साधारण संसाधन (बीज) से शुरु हुई।

जलवायु संबंधी चुनौतियों का सामना करते हुए, जिन्होंने हज़ारों परिवारों की डेयरी-आधारित आजीविका को खतरे में डाल दिया था, बनासकांठा दूध संघ ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाले, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध चारा बीजों की खेती पर आधारित एक आत्मनिर्भर मॉडल विकसित किया। वर्ष 2021–22 में प्रमाणित बीजों के मात्र 324 क्विंटल उत्पादन से प्रारंभ हुई यह पहल शीघ्र ही एक सुदृढ़ कार्यक्रम के रूप में विकसित हो गई। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान बीज उत्पादन बढ़कर 18,000 क्विंटल से अधिक हो गया, जबकि 2024–25 की अवधि के लिए बीज उत्पादन का 22,000 क्विंटल का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

इस कार्यक्रम का प्रभाव मात्र बीज उत्पादन तक सीमित नहीं रहा। लगभग 43,921 हेक्टेयर भूमि को उत्पादक खेतों में परिवर्तित किया गया, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख मीट्रिक टन पोषक तत्वों से भरपूर चारा उत्पन्न हुआ। बीज क्रय लागत में 15.66 करोड़ रुपये की बचत के अतिरिक्त, 41,000 से अधिक किसानों के जीवन में उल्लेखनीय आर्थिक परिवर्तन आया। किसानों को मक्का की खेती से प्रति एकड़ लगभग 32,000 रुपये तथा लूसर्न से प्रति एकड़ लगभग 66,000 रुपये तक का लाभ प्राप्त हुआ, जो पारंपरिक फसलों की उपज की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार है।

पशु स्वास्थ्य

एनडीडीबी ने पशु स्वास्थ्य संबंधी रणनीतियों को सुदृढ़ किया, ताकि वैज्ञानिक आधार पर तथा किफ़ायती हस्तक्षेपों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप परिणाम प्राप्त किए जा सकें। इसका प्रमुख ध्यान उत्पादकता में वृद्धि, रोग में कमी तथा सस्टेनेबल पशुधन पद्धतियों को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित रहा।

एंटीमाइक्रोबियल उपयोग (AMU) को कम करने एवं एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) से जुड़े जोखिमों का समाधान करने के लिए वन हेल्थ आधारित दृष्टिकोण अपनाए गए। इन प्रयासों से पशुओं एवं मनुष्यों—दोनों के लिए बेहतर जैव सुरक्षा एवं स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित हुए।

एनडीडीबी के तकनीकी सहयोग से किसान-केंद्रित पशु स्वास्थ्य सेवाओं का कार्यान्वयन संभव हुआ, जिससे पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि, दूध की गुणवत्ता में सुधार तथा दीर्घकालिक क्षेत्रीय उत्थान सुनिश्चित हुआ।

प्रमुख उपलब्धियां:

ईवीएम पद्धतियां:

एनडीडीबी ने डेयरी सहकारिताओं के माध्यम से EVM (Ethno Veterinary Medicine) को बढ़ावा दिया। इससे एलोपैथिक दवाओं पर निर्भरता कम हुई, जिसके परिणामस्वरूप दूध में एंटीबायोटिक अवशेषों में कमी आई तथा पशु-देखभाल की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

क्षमता विकास:

एनडीडीबी ने पशु चिकित्सकों एवं किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें औषधियों के तार्किक उपयोग एवं एएमआर नियंत्रण, वन हेल्थ, खुर प्रबंधन तथा वैज्ञानिक डेयरी पशुपालन पद्धतियों पर बल दिया गया।

रोगों की निगरानी:

राज्य पशुपालन विभागों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे WOAH और APHA, UK के सहयोग से रोग निगरानी एवं नैदानिक सेवाओं को सुदृढ़ किया गया, जिससे रोगों की समयपूर्व पहचान एवं त्वरित समाधान संभव हुआ।

रोग-निवारक प्रोटोकॉल:

एनडीडीबी ने किफायती रोग-निवारण एवं प्रबंधन उपायों तथा पशु झुंड स्वास्थ्य निगरानी हेतु फील्ड वेलिडेशन में सहयोग प्रदान किया।

गोवंशीय रोगों की जांच

गोवंशीय रोगों की जांच एवं निगरानी

एनडीडीबी ने 10 राज्यों से प्राप्त 12,575 गोवंशीय सैंपलों की छह रोगों हेतु जांच की। इनमें से 10,273 सैंपल (81.7 प्रतिशत) उच्च-आनुवंशिक क्षमता वाले नर बछड़ों से प्राप्त हुए थे, जिन्हें राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के अंतर्गत एकत्र किया गया। आरजीएम परियोजनाओं से प्राप्त सैंपलों की जांच पर कुल 34.38 लाख रुपये व्यय हुए। जांच किए गए सीरा सैंपलों में से ब्रुसेलोसिस के लिए 5,036 सैंपलों में 1.49 प्रतिशत, संक्रामक गोवंशीय राइनोट्रेकाइटिस (IBR) के लिए 4,504 सैंपलों में 14.28 प्रतिशत तथा गोवंशीय वायरल डायरिया (BVD) के लिए 2,568 सैंपलों में 0.25 प्रतिशत की पॉज़िटिविटी पाई गई। बोवाइन जेनिटल कैम्पिलोबैक्टीरियोसिस (BGC) एवं ट्राइकोमोनोसिस हेतु परीक्षण किए गए किसी भी जेनिटल वॉश सैंपलों में संक्रमण नहीं पाया गया। इसी प्रकार, एन्ज़ूटिक बोवाइन ल्यूकोसिस (EBL) के लिए जांचे गए किसी भी सीरा सैंपल में पॉज़िटिविटी नहीं पाई गई।

वैकल्पिक विधियों के माध्यम से रोग नियंत्रण (DCAM) परियोजना : एथनोवेटरिनरी मेडिसिन (EVM) के माध्यम से एएमआर से मुकाबला

एनडीडीबी ने एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस (AMR) की चुनौती से निपटने हेतु वैकल्पिक उपायों से रोग नियंत्रण (DCAM) परियोजना कार्यान्वित की। इस परियोजना के अंतर्गत एथनोवेटरिनरी मेडिसिन (EVM) के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया। यह परियोजना रणनीतिक रूप से आठ राज्यों—केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के 16 दूध संघों में कार्यान्वित की गई।

डीसीएएम परियोजना व्यापक वन हेल्थ फ्रेमवर्क के अनुरूप कार्यान्वित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य एंटीबायोटिक उपयोग का अनुकूलन करना। इसके अंतर्गत, ईवीएम पद्धतियों को पशुधन स्वास्थ्य देखभाल प्रोटोकॉल में शामिल किया गया। इन केंद्रित हस्तक्षेपों का लक्ष्य एंटीबायोटिक के अनुचित उपयोग को नियंत्रित करना तथा डेयरी पशुपालन में रोग नियंत्रण के लिए सतत् एवं वैकल्पिक तरीकों को प्रोत्साहित करना है।

मार्च 2025 तक, एनडीडीबी ने 11 लाख से अधिक ईवीएम हस्तक्षेपों का दस्तावेजीकरण किया, जिनकी सफलता दर 80 प्रतिशत से अधिक रही। यह आंकड़ा पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए ईवीएम की प्रभावशीलता को दर्शाता है और साथ ही पारंपरिक एंटीबायोटिक पर निर्भरता को कम करने में भी सहायक रहा।

वन हेल्थ पहल

एनडीडीबी ने डीसीएएम परियोजना के अंतर्गत 14 दूध संघों और उत्पादक संगठनों से किसानों के परिसर में कुल 491 सैंपल एकत्रित किए, जिनमें थनैला प्रभावित दूध, हैंडलर्स, थनेला प्रभावित गायों के स्वैब और पर्यावरणीय स्वैब शामिल थे, ताकि रोगजनकों का एएमआर प्रोफाइलिंग किया जा सके। इन सैंपलों से वन हेल्थ दृष्टि से महत्वपूर्ण रोगजनक जैसे E. coli, S. aureus, Klebsiella spp., और S. agalactiae पृथक किए गए। इन रोगजनकों के मल्टी लोकेस सिक्वेंस टाइपिंग (MLST) का कार्य जारी है, जिससे उनके संक्रमण की स्थिति और संभावित उत्पत्ति (मानव या पशु) का पता लगाया जा सके।

आसानी से ईवीएम फ़ॉर्मूलेशन की उपलब्धता

जूनोटिक रोगों से निपटने हेतु 'वन हेल्थ' आधारित मॉडल

ब्रुसेलोसिस नियंत्रण – वन हेल्थ दृष्टिकोण पर केंद्रित

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP) अब मादा गोवंशीय बछड़ों के लिए ब्रुसेलोसिस टीकाकरण की निगरानी करता है। एनडीडीबी का वन हेल्थ-अनुकूलित मॉडल इस ज़ूनोटिक रोग से संबंधित है, जो मानवों में अक्सर कम निदान होने के कारण कार्य क्षमता को प्रभावित करता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बोझ डालता है। एक चिकित्सा संस्थान के सहयोग से, एनडीडीबी ने 6,000 से अधिक किसानों और पशु स्वास्थ्य कर्मचारियों का परीक्षण किया। इनमें से 140 सिंप्टोमैटिक व्यक्तियों का उपचार किया गया और वे पूर्णतः स्वस्थ हुए। संक्रमण के खतरे को रोकने हेतु टीकाकरण के साथ-साथ हितधारक जागरूकता निर्माण, उचित निपटान, सफाई/डिसइन्फेक्शन तथा संभावित मामलों में पशुओं का पृथक्करण जैसी प्रक्रियाएं भी अपनाई गईं। इन एकीकृत प्रयासों ने वन हेल्थ फ्रेमवर्क के अनुरूप पशु और मानव दोनों के स्वास्थ्य परिणामों को मजबूत करने में योगदान दिया।

थनैला एवं एएमआर की निगरानी

वैकल्पिक उपायों द्वारा रोग नियंत्रण (DCAM) परियोजना क्षेत्रों में थनैला से प्रभावित गायों के कुल 126 दूध सैंपलों को कल्चर एवं पृथक्करण के लिए जांचा गया तथा एंटीबायोटिक संवेदनशीलता परीक्षण स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से किया गया। सैंपलों में Staphylococcus spp. (27 प्रतिशत) और Streptococcus spp. (13 प्रतिशत) प्रमुख पाए गए, इसके बाद Enterococcus spp. (5 प्रतिशत) और E. coli (1.4 प्रतिशत) पाए गए। सभी पृथक किए गए रोगजनकों ने बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशीलता दिखाई, जो परियोजना क्षेत्रों में एथनोवेटरिनरी मेडिसिन (EVM) के उपयोग के माध्यम से एएमआर नियंत्रण की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

गुणवत्ता आश्वासन और जैव-सुरक्षा

एनडीडीबी की अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने अपनी ISO 9001:2015 प्रमाणन और ISO/IEC 17025:2017 मान्यता बनाए रखी। IBR, ब्रुसेलोसिस, BVD और EBL के अंतरराष्ट्रीय प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रमों में प्रयोगशाला ने 100 प्रतिशत अनुरूपता पाई। जैव-सुरक्षा प्रोटोकॉल को अद्यतन किया गया और अर्धवार्षिक जोखिम मूल्यांकन किए गए। इसके साथ ही, एक संस्थागत जैव-सुरक्षा समिति (IBSC) का गठन किया गया और इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग में पंजीकृत किया गया, जिससे राष्ट्रीय जैव-सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित हुआ।

स्वदेशी परीक्षण विधि (ASSAY) का विकास

एनडीडीबी की अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने PCR-RFLP परीक्षण विकसित किया, जिससे Bovine Herpesvirus-1 (BoHV-1), Bovine Herpesvirus-5 (BoHV-5), और Bubaline Herpesvirus-1 (BuHV-1) में अंतर किया जा सके, और मौजूदा सिरोलॉजिकल विधियों में मौजूद क्रॉस-रिएक्टिविटी की समस्याओं का समाधान हुआ। इसके अलावा, Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV) के लिए एक रीयल-टाइम RT-PCR परीक्षण भी विकसित और इन-हाउस मान्य किया गया, जो आयातित किटों के मुकाबले किफ़ायती विकल्प प्रदान करता है। इन परीक्षण विधियों ने राष्ट्रीय स्तर पर BVDV निगरानी प्रयासों को बढ़ावा देते हुए सस्टेनेबिलिटी को सुदृढ़ किया।

डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी "एफएमडी फ्री ज़ोन इन गुजरात" पर सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान

'एफएमडी फ्री ज़ोन इन गुजरात' पर सम्मेलन

पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD), भारत सरकार, ने एनडीडीबी के सहयोग से आणंद में "गुजरात में एफएमडी मुक्त क्षेत्र: संकल्पना से वास्तविकता" विषयक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीमती अलका उपाध्याय, सचिव, डीएएचडी ने की। इसमें डॉ. अभिजित मित्रा, पशुपालन आयुक्त, भारत सरकार; डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी; श्रीमती सरिता चौहान, संयुक्त सचिव (पशु स्वास्थ्य), डीएएचडी; श्री जयेन मेहता, प्रबंध निदेशक, अमूल; श्रीमती फाल्गुनी ठाकुर, निदेशक (पशुपालन), गुजरात सरकार; डॉ. भूषण त्यागी, संयुक्त आयुक्त, डीएएचडी; डॉ. के आनंद कुमार, प्रबंध निदेशक, आईआईएल; डॉ. सी.पी. देवनंद, प्रबंध निदेशक, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज; साथ ही गुजरात राज्य पशुपालन विभाग, GCMMF, एनडीडीबी, क्षेत्रीय दूध संघ और माही मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सम्मेलन में हितधारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा की गई, ताकि गुजरात में एफएमडी मुक्त क्षेत्र स्थापित करने हेतु ठोस रणनीति विकसित की जा सके। एफएमडी से घरेलू दुग्ध उत्पादन और दूध एवं पशुधन उत्पादों के निर्यात में उत्पन्न चुनौतियों को उजागर किया गया। एनडीडीबी की केरल में सफल प्रायोगिक पहलों के अनुभवों के आधार पर, गुजरात में एफएमडी नियंत्रण और एफएमडी मुक्त क्षेत्रों के निर्माण के लिए उपयुक्त रणनीतियों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

पशुमित्र कॉल सेंटर

एनडीडीबी पशुमित्र कॉल सेंटर को संचालन करती है, जो देश के 25 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में किसानों को सहायता प्रदान करता है। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को पशु स्वास्थ्य और पशुपालन प्रबंधन पर समयोचित मार्गदर्शन प्रदान किया गया। यह पहल एनडीडीबी के किसान-केंद्रित समर्थन पर प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है।

सफलता की कहानी – ईवीएम के एकीकरण के माध्यम से एंटीमाइक्रोबियल उपयोग में कमी

एंटिमाइक्रोबियल एजेंट्स पशुओं के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक हैं और ये मानव चिकित्सा में महत्वपूर्ण हैं। लेकिन पशुधन में एंटीबायोटिक्स का अनियंत्रित और सही तरीके से उपयोग न करना खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है और वैश्विक एंटिमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) की समस्या को बढ़ाता है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए, एनडीडीबी ने लगभग 30 सामान्य गौवंशीय रोगों के उपचार के लिए एथनोवेटरिनरी मेडिसिन (EVM) को एक सुरक्षित और प्रभावी उपाय मानते हुए इसको बढ़ावा देने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है।

दूध संघों, उत्पादक संगठनों (PO) और विभिन्न अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से, एनडीडीबी की पहलों ने महत्वपूर्ण परिणाम दिए हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण कर्नाटक स्थित बेंगलुरु दूध संघ है, जिसने 2017-18 और 2022-23 के बीच खरीदी गई विभिन्न एंटीबायोटिक क्लास और कांबिनेशन डोज में 70 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की है। इसी प्रकार, महाराष्ट्र का कोल्हापुर दूध संघ ने उसी अवधि में एंटीबायोटिक उपयोग में 68 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की। ये उपलब्धियां ईवीएम पद्धतियों को जमीनी स्तर पर व्यापक रूप से अपनाने, रणनीतिक क्षमता विकास कार्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण, जन जागरूकता अभियानों और ईवीएम के नियमित पशु स्वास्थ्य सेवाओं में एकीकरण के माध्यम से संभव हुईं।

इस सफल पहल से स्पष्ट होता है कि एथनोवेटरिनरी मेडिसिन (EVM) किसानों को न केवल स्थानीय सुलभ और किफ़ायती उपचार उपलब्ध कराती है, बल्कि एंटिमाइक्रोबियल्स के उपयोग को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और एंटिमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) से निपटने के वैश्विक प्रयासों में भी योगदान देती है।

अनुसंधान एवं विकास द्वारा प्रौद्योगिकीय प्रगति

एनडीडीबी ने वर्ष के दौरान लक्षित अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसने विशेष रूप से डेयरी एवं पशुपालन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित किया और उत्पादकता, आनुवंशिक क्षमता और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से सहयोगात्मक साझेदारियां विकसित कीं। ये प्रयास पद्धतियां और उत्पादों के विकास के सहायक रहे, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं और 'मेक इन इंडिया' तथा 'आत्मनिर्भर भारत' के विज़न के साथ मेल खाते हैं।

श्री मोहन चरण माझी जी, माननीय मुख्यमंत्री, ओडिशा; श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री; प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल जी, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज राज्य मंत्री और श्री जॉर्ज कुरियन जी, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री, ओडिशा में मानसून मीट 2024 में स्वदेशी आईवीएफ मीडिया सूट 'षष्ठी' के शुभारंभ के दौरान

स्वदेशी IVF मीडिया सूट का विकास

अपनी परिचालन क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए, एनडीडीबी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था आईआईएल के सहयोग से OPU-IVEP-ET प्रोटोकॉल में उपयोग हेतु एक स्वदेशी कल्चर मीडिया सूट सफलतापूर्वक विकसित किया। इस सूट में पांच अलग-अलग मीडिया फ़ॉर्म्युलेशन शामिल हैं, जिन्हें इन विट्रो भ्रूण उत्पादन और भ्रूण प्रत्यारोपण की प्रत्येक विशिष्ट अवस्था के अनुरूप तैयार किया गया है।

इस रणनीतिक पहल का मुख्य उद्देश्य संगठन की महंगी आयातित मीडिया पर निर्भरता को कम करना है, जिससे भारत के डेयरी किसानों के लिए आईवीएफ प्रौद्योगिकियों की किफ़ायत और उपलब्धता बढ़ाई जा सके। इस सूट को 'षष्ठी' नाम से ब्रांड किया गया है, जिसका औपचारिक शुभारंभ ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी जी तथा भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन सिंह जी द्वारा किया गया। यह समारोह भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित मॉनसून मीट 2024 के दौरान सम्पन्न हुआ, जिसमें माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल जी, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन जी तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भी सहभागिता की।

'षष्ठी' के उपयोग से भ्रूण उत्पादन की लागत में कमी आई और उन्नत प्रजनन प्रौद्योगिकियों तक पहुंच का दायरा बढ़ा। यह उपलब्धि आनुवंशिक विकास के माध्यम से नस्ल सुधार के लिए एनडीडीबी के सस्टेनेबल प्रयासों को सशक्त बनाती है।

रेडी-टू-यूज़ कल्चर (RUC) प्रौद्योगिकी और अनुसंधान

एनडीडीबी ने रेडी-टू-यूज़ कल्चर (RUC) प्रौद्योगिकी का विकास किया और इसे मैसर्स IDMC Ltd को व्यावसायिक निर्माण हेतु सफलतापूर्वक हस्तांतरित किया, जो नए स्थापित आरयूसी संयंत्र में लागू की गई। एनडीडीबी और IDMC Ltd के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह ने इस सुविधा का शिलान्यास किया। यह संयंत्र मुख्यतः स्वदेशी स्रोतों से प्राप्त मशीनरी से सुसज्जित है और यह प्रतिदिन लगभग एक मिलियन लीटर फर्मेंटेड दूध के उत्पादन में सहयोग प्रदान करने की क्षमता रखता है।

एनडीडीबी ने उपकरण चयन, स्थापना, प्रोटोकॉल डिज़ाइन, प्रशिक्षण और समस्या निवारण में व्यापक तकनीकी समर्थन प्रदान किया। इस समर्थन ने प्रौद्योगिकी के सफल हस्तांतरण और व्यावसायिक स्तर पर उसका विस्तार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह पहल, जो भारत की समृद्ध माइक्रोबियल विविधता का लाभ उठाती है, 'मेक इन इंडिया' विज़न के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।

अनुसंधान एवं विकास प्रयासों का उद्देश्य फर्मेंटेड दूध उत्पादों के लिए कल्चर के विकास पर केंद्रित है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया स्ट्रेन का उपयोग करते हुए छह नए फ़ॉर्म्युलेशन विकसित किए गए। प्रत्येक ने एसीडिफिकेशन एवं शुगर टॉलरेंस के विशिष्ट गुण प्रदर्शित किए और इनका सफल परीक्षण अनेक डेयरियों में किया गया।

एनडीडीबी ने सात नए मेसोफिलिक स्टार्टर स्ट्रेन जोड़कर अपने कल्चर डिपॉजिटरी का भी विस्तार किया। ये स्ट्रेन विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए गए और भविष्य के अनुसंधान तथा व्यावसायिक उपयोग के लिए आनुवंशिक और फंक्शनल बेस को बढ़ाया। ये गतिविधियां एनडीडीबी के नवाचार को मजबूत करने, डेयरी प्रसंस्करण में सुधार लाने और सहकारी विकास का समर्थन करने की रणनीति के अनुरूप हैं।

आईडीएमसी लिमिटेड, आणंद में आरयूसी संयंत्र का शिलान्यास कार्यक्रम

डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी तथा श्री केनिचिरो टोयोफुकु, निदेशक, एसआरडीआई, आणंद स्थित आईडीएमसी लिमिटेड के परिसर में मोबाइल मिल्क कलेक्शन एवं कूलिंग सिस्टम को झंडी दिखा कर रवाना करते हुए

मोबाइल मिल्क कलेक्शन, टेस्टिंग और कूलिंग सिस्टम

एनडीडीबी ने सुजुकी आरएंडडी सेंटर इंडिया प्रा. लि. (SRDI) और आईडीएमसी के सहयोग से आणंद में मोबाइल मिल्क कलेक्शन, टेस्टिंग और कूलिंग सिस्टम लॉन्च किया। डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी और श्री केनिचिरो टोयोफुकु, निदेशक, SRDI ने इस मोबाइल मिल्क कलेक्शन, टेस्टिंग और कूलिंग सिस्टम का उद्घाटन किया। यह सिस्टम दूध की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्वचालित दूध संकलन, परीक्षण और चिलिंग तकनीकों को एकीकृत करता है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों के डेयरी किसानों से दूध संकलन की कार्यक्षमता बढ़ती है। लद्दाख दूध मंहासंघ के साथ इसका संचालन परीक्षण क्षेत्रीय परिस्थितियों में प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जा रहा है।

गोबर प्रबंधन और ऑर्गेनिक उर्वरक उत्पादन में नवाचारों के लिए पेटेंट पंजीकरण

एनडीडीबी ने वर्ष के दौरान गोबर प्रबंधन और ऑर्गेनिक उर्वरक उत्पादन से संबंधित तीन पेटेंट पंजीकृत किए। ये नवाचार मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने और उप-उत्पाद उपयोग में गुणवत्ता को मानकीकृत करने के लिए विकसित किए गए। पेटेंट में शामिल हैं:

- गोबर की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए एक परीक्षण प्रणाली;
- बायो-स्लरी गुणवत्ता का आकलन करने की विधि;
- डाइजेस्टेड पशु गोबर से दानेदार ऑर्गेनिक उर्वरक उत्पादन की प्रक्रिया।

पेटेंट की गई यह प्रक्रिया गोबर और स्लरी के संकलन परिचालनों के लिए एक विस्तार योग्य एवं मानकीकृत ढांचा प्रदान करती है। यह वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पद्धतियों के माध्यम से किसानों के लिए गुणवत्ता-आधारित भुगतान प्रणाली को सुचारू बनाती है। दानेदार उर्वरक उत्पादन विधि अपशिष्ट को उच्च-मूल्यवान ऑर्गेनिक इनपुट में परिवर्तित करने में सहायक है, जो जलवायु-अनुकूल और सस्टेनेबल फार्मिंग के अनुरूप है। ये पेटेंट वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन और डेयरी किसानों की आय में विविधता लाने के प्रति एनडीडीबी की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

‘हब एंड स्पोक’ मॉडल का संतति परीक्षण कार्यक्रम के साथ एकीकरण

एनडीडीबी ने उच्च आनुवंशिक गुण (HGM) वाले सांड़ों के उत्पादन हेतु OPU-IVEP-ET तकनीक का उपयोग करते हुए ‘हब एंड स्पोक’ मॉडल को संतति परीक्षण कार्यक्रम के साथ एकीकृत करने के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत की है। यह पहल राष्ट्रीय गोकुल मिशन के व्यापक ढांचे के अंतर्गत SAG HFCB संतति परीक्षण कार्यक्रम (PT-ET) का हिस्सा है।

पारंपरिक रूप से, संतति परीक्षण (PT) कार्यक्रमों में वीर्य उत्पादन के लिए सांड़ बछड़ों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु बड़ी संख्या में श्रेष्ठ मादाओं की नोमिनेटेड मेटिंग की आवश्यक होती है। इस पायलट परियोजना को OPU-IVEP-ET तकनीक का उपयोग करके सीमित संख्या में श्रेष्ठ डोनर से आवश्यक सांड़ों का उत्पादन करने के लिए डिजाइन किया गया। इस दृष्टिकोण ने चयन की तीव्रता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया और परिणामस्वरूप आनुवंशिक प्रगति की दर में सुधार किया।

इस मॉडल में, एनडीडीबी मुख्य रूप से ‘हब’ के रूप में कार्य करती है, जो भ्रूण उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, जबकि साबर, सूरत और गोधरा जैसे दूध संघों ने ‘स्पोक’ के रूप में संचालन किया। इन दूध संघों की जिम्मेदारी ग्राही पशुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और क्षेत्र स्तर पर भ्रूण प्रत्यारोपण को सुगम बनाना है।

एनडीडीबी में श्रेष्ठ डोनर पशुओं से प्राप्त भ्रूणों का प्रत्यारोपण भागीदार दूध संघों के ग्राही पशुओं में सफलतापूर्वक किया गया। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कुल 400 भ्रूणों का उत्पादन एवं प्रत्यारोपण किया गया, जिससे 124 पशु गाभिन हुए। इस पायलट परियोजना ने क्षेत्रीय स्तर पर ‘हब एंड स्पोक’ मॉडल की परिचालन क्षमता को प्रभावी रूप से प्रदर्शित किया और उन्नत प्रजनन तकनीकों के माध्यम से आनुवंशिक सुधार की प्रक्रिया को गति देने की इसकी संभावनाओं को उजागर किया।

BuHV-1 सीरोप्रिवेलेंस अध्ययन

एनडीडीबी ने भारत में बुबलाइन हर्पीसवायरस टाइप-1 (BuHV-1) की सीरोप्रिवेलेंस का आकलन करने हेतु एक लक्षित अनुसंधान अध्ययन प्रारंभ किया। यह अध्ययन विशेष रूप से भैंस आबादी पर केंद्रित है, जिन्हें इस वायरस का नेचुरल होस्ट माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य BuHV-1 और बोवाइन हर्पीसवायरस टाइप-1 (BoHV-1) के बीच क्रॉस-रिएक्टिविटी से उत्पन्न होने वाली निदान संबंधी चुनौतियों को सामना करना है, जहां BoHV-1 आईबीआर का कारक एजेंट है।

भैंस के सांड बछड़ों के चयन में फॉल्स-पॉज़िटिव परिणामों की समस्या को कम करने के लिए एनडीडीबी ने BoHV-1 पॉज़िटिव पाए गए। 677 सैंपलो का रिट्रोस्पेक्टिव विश्लेषण किया। दोनों प्रकार के वायरय संक्रमणों में अंतर करने हेतु एक डिफ़रेंशियल ELISA टेस्ट का उपयोग किया गया। अध्ययन में पाया गया कि भैंसों में BuHV-1 सीरोप्रिवेलेंस 29.6% तथा गायों में 6.6% है।

ये निष्कर्ष IBR निगरानी और नियंत्रण कार्यक्रमों के अंतर्गत BuHV-1 और BoHV-1 में सटीक अंतर करने हेतु उन्नत नैदानिक प्रोटोकॉल की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि राष्ट्रीय प्रजनन रणनीति के अंतर्गत एनडीडीबी साक्ष्य-आधारित निर्णय प्रक्रिया और आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है।

सहयोगात्मक और नवोन्मेषी सैंपलिंग

एनडीडीबी ने वन हेल्थ फ्रेमवर्क के अंतर्गत एक समेकित निगरानी कार्यक्रम संचालित किया, जिसका उद्देश्य थैनेला रोगजनकों से जुड़े एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) और जूनोटिक जोखिमों का आकलन करना है। विश्लेषण के लिए कुल 220 सैंपल विभिन्न निर्दिष्ट परियोजना स्थलों से एकत्र किए गए, जिनमें पशुधन, फार्म कर्मचारी और जल तथा सीवेज जैसे पर्यावरणीय स्रोत शामिल हैं।

तत्काल ट्रैकिंग को सुदृढ़ करने के लिए एक डिजिटल रिपोर्टिंग सिस्टम लागू किया गया, जिससे संभावित ट्रांसमीशन रूट की विशेष निगरानी संभव हुई और समय पर, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सहायता मिली।

इसके अलावा, एफएमडी एंटीबॉडी पहचान हेतु Whatman® फ़िल्टर पेपर का उपयोग कर कोल्ड चैन फ्री सैंपलिंग पद्धति विकसित की गई, जिसके परिणाम सीरम के समतुल्य पाए गए। यह क्षेत्र-अनुकूल सैंपल कंलेक्शन विधि NADCP के अंतर्गत प्रभावी और विश्वसनीय सीरोमॉनिटरिंग और सीरोसर्विलांस को सुगम बना सकती है।

मल्टीप्लेक्स डायग्नोस्टिक्स

एनडीडीबी की आरएंडडी प्रयोगशाला ने गौवंशीय ब्लड सैंपल में Theileria annulata, Babesia spp. और Anaplasma marginale का एक साथ पता लगाने के लिए मल्टीप्लेक्स PCR परीक्षण विकसित किया। इस परीक्षण को 264 क्षेत्रीय सैंपलों से जांचा गया और इसके परिणाम मानक PCR प्रोटोकॉल के साथ नैदानिक अनुरूपता दर्शाते हैं।

यह मॉलिकुलर टूल प्रमुख हिमोप्रोटोज़ोअन संक्रमणों की जांच के लिए एक प्रभावी और किफायती उपाय प्रदान करता है, जिससे समय पर रोग नियंत्रण हस्तक्षेप को समर्थन मिलता है।

डेयरी पशुओं का प्रिसीजन आहार प्रबंधन

एनडीडीबी ने आणंद में एक क्षेत्रीय परीक्षण आयोजित किया ताकि प्रिसीजन आहार के डेयरी पशुओं की उत्पादकता पर प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य आहार संतुलन से आगे बढ़कर उन्नत पोषक तत्वों के मापदंडों को शामिल करना है, ताकि डेयरी पशुओं की आनुवंशिक क्षमता और शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।

इस अध्ययन में 16 दुधारू गायों को शामिल किया गया, जिनके मौजूदा आहार कार्यक्रमों का प्रारंभिक विश्लेषण कर उनके पोषण संबंधी प्रोफ़ाइल का आकलन किया गया। इस मूल्यांकन के आधार पर उनके आहार का अनुकूलन किया गया, ताकि न केवल मूलभूत पोषक तत्वों—जैसे कि क्रूड प्रोटीन, कुल पाचन पोषक तत्व (TDN), कैल्शियम और फ़ॉस्फ़ोरस का संतुलन स्थापित हो, बल्कि उन्नत

पोषक तत्त्वों के मानकों जैसे स्टार्च, चयापचय ऊर्जा, चयापचय प्रोटीन, लाइसीन, मेथियोनीन, न्यूट्रल डिटर्जेंट फ़ाइबर (NDF), सूक्ष्म खनिज, विटामिन A, D_3 और E तथा बफ़रिंग एजेंट्स का भी ध्यान रखा जा सके।

इस परीक्षण से पशु-प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया। प्रिसीजन आहार ग्रुप की गायों में दूध उत्पादन में औसतन 1.2 किलोग्राम प्रतिदिन प्रति पशु की वृद्धि पाई गई। यद्यपि नियंत्रण और उपचार ग्रुपों के बीच पोषक तत्वों का सेवन एवं पाचन समान रहा फिर भी उचित आहार प्राप्त करने वाले पशुओं ने बेहतर फ़ीड रूपांतरण दक्षता और उन्नत नाइट्रोजन उपयोग क्षमता प्रदर्शित की।

यद्यपि उपचार ग्रुप के लिए आहार लागत अपेक्षाकृत अधिक रही, किन्तु दूध उत्पादन और संरचना में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रतिपशु प्रतिदिन 32 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार, प्रिसीजन आहार पद्धति की आर्थिक व्यवहार्यता सफलतापूर्वक प्रदर्शित हुई।

इन निष्कर्षों से एनडीडीबी के आहार संतुलन सॉफ़्टवेयर के सुदृढ़ीकरण हेतु मूल्यवान जानकारियां प्राप्त हुईं और क्षेत्र-विशिष्ट आहार के विकास को भी समर्थन मिला, जिन्हें क्षेत्रीय पोषण आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाता है।

नए दूध उत्पाद और प्रक्रिया विकास

एनडीडीबी ने सहकारी दूध संघों का उत्पाद विकास और प्रक्रिया सुधार में अनुप्रयुक्त अनुसंधान के माध्यम से समर्थन किया। इन प्रयासों का उद्देश्य बाज़ार की प्रवृत्तियों, उपभोक्ता की अपेक्षाओं और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है।

नेचुरल स्वीट की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, एनडीडीबी ने आइसक्रीम और मीठा दही विकसित किया, जिनमें चीनी का आंशिक प्रतिस्थापन शहद से किया गया। इस आंशिक प्रतिस्थापन से न केवल स्वाद और पोषण मूल्य में वृद्धि हुई बल्कि यह कैलोरी के प्रति जागरूक उपभोक्ता वर्ग के बीच भी लोकप्रिय सिद्ध हुआ। इन उत्पादों के औद्योगिक परीक्षण पश्चिम असम दूध उत्पादक संघ लिमिटेड (वामूल – पूरबी डेयरी) में किए गए तथा अंतिम विधियां वाणिज्यिक उपयोग हेतु साझा की गईं।

एनडीडीबी ने फंक्शनल बेवरेजेस में बनावट और गाढ़ेपन में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया। रागी-आधारित दूध पेय का एक फॉर्मूलेशन विकसित किया गया, जिससे तलछट जमने और असमान बनावट की पहले की समस्याएं दूर हो गईं।

एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह घोघा-हजीरा समुद्री मार्ग पर माही एमपीओ दूध टैंकरों के लिए रो-रो फेरी सेवा को झंडी दिखा कर रवाना करते हुए

सहकारी दुग्ध संघों में उत्पाद अनुकूलन और नवाचार के लिए तकनीकी समर्थन

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, एनडीडीबी ने सहकारी डेयरियों को उनके उत्पाद पोर्टफोलियो के विस्तार और नए उत्पादों के परिचय हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान किया। केरल को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (मिल्मा) को टेंडर कोकोनट आइसक्रीम के फ़ॉर्म्युलेशन को अनुकूलित करने में सहयोग दिया गया, जिसमें उत्पाद की स्थिरता और संवेदी गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। वामूल (पूरबी डेयरी) को नए फ्लेवर्ड मिल्क वैरिएंट के विकास में सहायता दी गई, जिसमें शेल्फ लाइफ़ बढ़ाने और स्वाद की स्थिरता बनाए रखने पर बल दिया गया। जयपुर डेयरी को बाजरा-आधारित पौष्टिक आहार के विकास में सहयोग दिया गया, जिसका उद्देश्य पोषण मूल्य में वृद्धि करना और क्षेत्रीय आहार आवश्यकताओं को पूरा करना। इन सभी हस्तक्षेपों को कार्यात्मक दक्षता सुनिश्चित करने, खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन और उपभोक्ता स्वीकृति को मज़बूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया। ये पहलें सहकारी डेयरी उद्यमों में नवाचार और गुणवत्ता संवर्धन को बढ़ावा देने के एनडीडीबी के रणनीतिक उद्देश्य के अनुरूप हैं।

भारत की पहली रो-रो दूध परिवहन फेरी सेवा

एनडीडीबी ने माही मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर समुद्री मार्ग द्वारा दूध के परिवहन में नवाचार किया, जिससे यात्रा समय कम हुआ और परिवहन लागत में कमी आई, जो भारत के डेयरी उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ। यह पहल माननीय प्रधानमंत्री जी के आंतरिक जलमार्गों के विकास के दृष्टिकोण और आर्थिक विकास से मेल खाती है। एनडीडीबी के अध्यक्ष ने माही एमपीओ के दूध टैंकरों को घोगा-हजीरा समुद्री मार्ग पर से परिवहन करने के लिए रो-रो फेरी सेवा का उद्घाटन किया।

सस्टेनेबिलिटी एवं सर्कुलैरिटी

एनडीडीबी ने सस्टेनेबिलिटी, प्रौद्योगिकी और किसान सहभागिता पर केंद्रित पहलों के माध्यम से भारत के डेयरी एवं संबद्ध क्षेत्रों को सुदृढ़ किया। प्रमुख हस्तक्षेपों में विकेन्द्रीकृत और केन्द्रीकृत गोबर प्रबंधन, कार्बन क्रेडिट भुगतान, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग तथा फ़ीड एडिटिव्स के माध्यम से मीथेन में कमी लाना शामिल है।

बोर्ड ने व्यवस्थित साझेदारियों और प्रायोगिक इकाइयों के माध्यम से सर्कुलैरिटी, जैव विविधता संरक्षण और क्षमता विकास को प्रोत्साहित किया। ये प्रयास जलवायु-अनुकूल और ग्रामीण विकास संबंधी राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप हैं तथा सहकार-आधारित सस्टेनेबल विकास के प्रति एनडीडीबी की प्रतिबद्धता को पुष्टि करते हैं।

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी तथा माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन जी की उपस्थिति में एनडीडीबी और नाबार्ड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलैरिटी पर कार्यशाला

भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD) द्वारा नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलैरिटी विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डेयरी संचालन के सभी चरणों में सर्कुलर इकोनामी के सिद्धांतों के एकीकरण को प्रोत्साहित करना। कार्यशाला का उद्घाटन माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा किया गया। इस अवसर पर, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस पी सिंह बघेल जी, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन जी तथा अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे।

कार्यशाला में संसाधन दक्षता बढ़ाने, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने तथा डेयरी उत्पादकों के लिए सकारात्मक आर्थिक परिणाम सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। मुख्य विषयों में परिचालन सर्कुलैरिटी, छोटे डेयरी किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट के अवसर तथा सस्टेनेबल डेयरी पद्धतियों को प्रोत्साहित करने में कार्बन मार्केट की भूमिका शामिल रही।

एनडीडीबी ने 15 राज्यों के 25 डेयरी सहकारी संस्थानों के साथ विकेन्द्रीकृत एवं केंद्रीकृत गोबर प्रबंधन मॉडलों को अपनाने हेतु समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए। सस्टेनेबल डेयरी अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक अलग समझौता ज्ञापन नाबार्ड के साथ किया गया। इस कार्यशाला के दौरान "डेयरी क्षेत्र में सुर्कुलैरिटी हेतु मार्गदर्शिका" का विमोचन किया गया, एनडीडीबी की बायोगैस वित्तपोषण योजना तथा सस्टेनेबल डेयरी हस्तक्षेपों के वित्तपोषण हेतु NDDB-SPEF साझेदारी के दूसरे चरण का शुभारंभ भी किया गया।

यह कार्यशाला सस्टेनेबल बदलाव के प्रति पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD) के सतत प्रयासों का प्रतिबिंब है और इसने जलवायु अनुकूलता, सहकारी विकास तथा ग्रामीण समृद्धि संबंधी राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

संपूर्ण भारत में बायोगैस संयंत्रों के विस्तार हेतु सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन और एनडीडीबी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर

सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सुजुकी आरएंडडी सेंटर इंडिया प्रा. लि. (SRDI) ने एनडीडीबी के साथ संपूर्ण भारत में बायोगैस संयंत्रों के विस्तार के लिए समझौता किया। इस समझौते के तहत, एसआरडीआई, एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनडीडीबी मृदा लि. में निवेश करेगी। एनडीडीबी और एसआरडीआई की संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में, एनडीडीबी मृदा से दोनों संस्थाओं की साझा उद्देश्य को आगे बढ़ाने की संभावना है, जिसके अंतर्गत गोबर आधारित बायोगैस मॉडलों के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा के विविध रूप उपलब्ध कराना और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने हेतु जैविक उर्वरकों की आपूर्ति शामिल है।

सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्री तोशुहिरो सुजुकी तथा एनडीडीबी और एनडीडीबी मृदा लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में एनडीडीबी, एनडीडीबी मृदा लिमिटेड और एसआरडीआई के बीच समझौते पर हस्ताक्षर

खाद प्रबंधन पहल

एनडीडीबी ने डेयरी क्षेत्र में गोबर के बेहतर उपयोग और संसाधन दक्षता को बढ़ाने के लिए विकेन्द्रीकृत और केन्द्रीकृत दोनों मॉडल लागू किए। विकेन्द्रीकृत मॉडल ने छोटे दूध उत्पादक किसानों को गोबर से बायोगैस तैयार करने में सक्षम बनाया, जिसका उपयोग खाना पकाने में किया गया। इससे श्रम की बचत हुई, घर के भीतर धुएं के संपर्क में कमी आई, पर्यावरणीय प्रभाव में कमी आई तथा बायोगैस स्लरी को ऑर्गेनिक उर्वरक के रूप में बेचकर किसानों के लिए आय का नया स्रोत सृजित हुआ।

केन्द्रीकृत मॉडल के तहत, दो बड़े बायोगैस संयंत्र ढाँचे विकसित किए गए। बनास मॉडल में उच्च क्षमता वाले संयंत्रों में गोबर का उपयोग कर कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) और ऑर्गेनिक उर्वरक का उत्पादन किया गया। दूसरी ओर, वाराणसी मॉडल में डेयरी संयंत्र के लिए भाप और बिजली का उत्पादन किया गया तथा साथ ही ऑर्गेनिक उर्वरक भी तैयार किया गया।

इन प्रणालियों से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, जीवाश्म ईंधनों की खपत में कमी आती है तथा डेयरी मूल्य शृंखला में सर्कुलैरिटी को प्रोत्साहन मिलता है। सस्टेनेबल ग्रामीण विकास के उद्देश्य को आगे बढ़ाने हेतु एनडीडीबी के अध्यक्ष ने माननीय जल शक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल जी तथा गुजरात विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी जी से मुलाकात की और गोबर-आधारित सीबीजी संयंत्रों की स्थापना पर चर्चा की। इस चर्चा के दौरान, हरित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु कार्य-योजना संबंधी रणनीतियां प्रस्तुत की गईं, जो सस्टेनेबल ग्रामीण विकास की दृष्टि के अनुरूप हैं। अध्यक्ष, एनडीडीबी ने खाद प्रबंधन से कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने संबंधी एनडीडीबी की पहलों पर भी प्रकाश डाला और इस क्षेत्र में उपलब्ध प्रासंगिक सहायक योजनाओं के अंतर्गत अवसरों की खोज के लिए सरकार के साथ सहयोग का प्रस्ताव रखा।

सस्टेनेबल कृषि प्रबंधन पद्धतियों के लिए प्रदर्शन इकाई

एनडीडीबी ने डेयरी पशुपालकों और अन्य हितधारकों के बीच सस्टेनेबल कृषि प्रबंधन पद्धतियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक सक्रिय पहल की। सस्टेनेबल डेयरिंग के लिए नवोन्मेषी एवं समग्र दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने हेतु सस्टेनेबल कृषि प्रबंधन पद्धतियों की एक प्रदर्शन इकाई की स्थापना कार्य एनडीडीबी, आणंद में किया गया।

एनडीडीबी की OPU-IVEP-ET सुविधा से प्राप्त गोबर का उपयोग 40 घन-मीटर क्षमता वाले फ्लेक्सी बायोगैस संयंत्र में किया गया, जिसे एनडीडीबी मृदा लि. और Sistema.bio के संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया। इस इकाई से उत्पन्न बायोगैस को नवीकरणीय विद्युत में परिवर्तित किया गया, जिसका उपयोग गौशालाओं को ऊर्जा आपूर्ति हेतु किया गया। इस प्रकार पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता में कमी आई।

डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी, श्री सी आर पाटिल जी, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और श्री शंकरभाई चौधरी, अध्यक्ष, गुजरात विधानसभा के साथ एक बैठक के दौरान

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी तथा माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी द्वारा वामूल (WAMUL) की एक महिला दूध उत्पादक सदस्य को पहली बार कार्बन क्रेडिट भुगतान प्रदान करते हुए

बायोगैस संयंत्र की डाइजेस्टेड स्लरी के कुशल प्रबंधन हेतु एक सर्कुलर उपयोग मॉडल अपनाया गया। इसके अंतर्गत ठोस अंश को संसाधित कर ऑर्गेनिक उर्वरक बनाया गया और एनडीडीबी की चारा प्रदर्शन इकाई तथा चारा अनुसंधान केंद्र, इटोला में हरे चारे की खेती हेतु उपयोग किया गया। तरल अंश को रिसाइकल कर ताज़े गोबर से स्लरी तैयार करने में उपयोग किया गया, जिससे संसाधन उपयोग दक्षता में समग्र रूप से वृद्धि हुई।

इन हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप खाद प्रबंधन में सुधार से ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में 41.4% की कमी तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन म से 17.5% की कमी आई। पोषण की दृष्टि से संतुलित आहार सुनिश्चित करने हेतु चारा और दाना को मिलाकर संपूर्ण मिश्रित आहार (TMR) तैयार किया गया। इसके लिए 5 घन मीटर क्षमता वाला टीएमआर मिक्सर, जो आईडीएमसी लि. द्वारा विकसित किया गया है, उपयोग में लाया गया। इस पहल से डेयरी पशुओं का कुशल एवं वैज्ञानिक पोषण सुनिश्चित हुआ।

इस एकीकृत मॉडल में वैज्ञानिक चारा उत्पादन, संतुलित आहार, खाद प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और ग्रीनहाउस गैस (GHG) में कमी जैसी गतिविधियों को समाहित किया गया। यह पहल एक प्रदर्शन और अधिगम केंद्र के रूप में कार्य कर रही है, जो दूध संघों, दूध महासंघों, किसानों और अन्य हितधारकों को मूल्यवान जानकारियां प्रदान करती है। यह परियोजना एनडीडीबी की अपनी सहायक कंपनियों और भागीदारों के साथ मिलकर भारत के डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबल एवं सर्कुलर पद्धतियों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है।

डेयरी किसानों के लिए पहली बार कार्बन क्रेडिट सम्मान

एनडीडीबी के हीरक जयंती समारोह के एक भाग के रूप में, आणंद में आयोजित कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा राजस्थान और असम के दूध उत्पादक किसानों को पहली बार कार्बन क्रेडिट भुगतान प्रदान किए गए। इस अवसर पर, राजस्थान की एक महिला दूध उत्पादक को 63,000 रुपये तथा असम की एक महिला दूध उत्पादक को 52,000 रुपये की राशि प्राप्ति इस बात का प्रतीक है कि पारंपरिक पद्धतियों को सस्टेनेबल आजीविका में बदला जा रहा है।

इस अवसर पर अपने उद्बोधन में, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि यह उपलब्धि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के उस विज़न को प्रतिपादित करती है, जिसके अंतर्गत 'गोबरधन योजना' के माध्यम से "अपशिष्ट से समृद्धि" करने की परिकल्पना की गई है। इस विज़न के सफलता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां कभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ईंधन के रूप में प्रयुक्त गोबर, अब स्वच्छ ऊर्जा, जैविक खाद और कार्बन क्रेडिट आय का स्रोत बन रहा है।

एनडीडीबी का बायोगैस-आधारित खाद प्रबंधन कार्यक्रम सस्टेन प्लस एनर्जी फाउंडेशन (SPEF) – जो टाटा ट्रस्ट से संबद्ध है – के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस पहल में पहले सात राज्यों के नौ स्थलों पर एक हजार से अधिक दूध उत्पादक किसान भागीदारी कर रहे हैं। यह पहल कार्बन क्रेडिट के मुद्रीकरण के माध्यम से बायोगैस संयंत्रों को वित्तीय रूप से सक्षम बना रही है। यह कार्यक्रम देशभर में व्यापक स्तर पर इसे अपनाने और विस्तारित करने की ठोस नींव रखता है।

आईडीएमसी लिमिटेड द्वारा विकसित टीएमआर मिक्सर

यह पहल इस बात का सशक्त उदाहरण है कि किस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न, जो एनडीडीबी के नवाचार और सहकारिता की भावना से समर्थित है, किसानों की समृद्धि को बढ़ाते हुए पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी में भी योगदान दे रहा है।

आंतरिक मीथेन कम करने हेतु फीड एडिटिव्स

एनडीडीबी का मानना है कि मीथेन, जो एक सशक्त ग्रीनहाउस गैस है, फार्म-स्तरीय ग्रीन हॉउस गैस उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है और मुख्य रूप से एंटरिक फर्मेंटेड प्रक्रिया के दौरान जुगाली करने वाले पशुओं में उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में पशु द्वारा खाए गए आहार की कुल ऊर्जा का लगभग 8–12 प्रतिशत की हानि होती है तथा फार्म-स्तरीय कुल उत्सर्जन का लगभग दो-तिहाई भाग इसके कारण होता है। इन उत्सर्जनों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में आहार ग्रहण की मात्रा, पाचन क्षमता और पशु आहार का पोषण संतुलन शामिल हैं।

इस चुनौती का समाधान करने के लिए एनडीडीबी ने वैज्ञानिक आहार पद्धतियों को बढ़ावा दिया, जैसे कि संतुलित आहार और संपूर्ण मिश्रित आहार (TMR) का उपयोग। इन उपायों से रूमेन में पोषक तत्वों के उपयोग की क्षमता में सुधार हुआ और कुल दूध उत्पादन दक्षता बढ़ी। इसके परिणामस्वरूप मीथेन उत्सर्जन में 10–15 प्रतिशत तक कमी दर्ज की गई।

इसके अलावा, एनडीडीबी ने नया फीड एडिटिव्स (मीथेन अवरोधक) के विकास की पहल की, जिनका उद्देश्य रूमेन फर्मेंटेशन प्रक्रियाओं में परिवर्तन करके मीथेन उत्पादन को कम करना है। एनडीडीबी द्वारा किए गए इन-विट्रो परीक्षणों में यह पाया गया कि इन एडिटिव्स से मीथेन उत्सर्जन में 16–18 प्रतिशत तक की कमी आई और पाचन क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। इन-विवो वेलिडेशन में सफल होने के उपरांत, इन फीड एडिटिव्स को मिश्रित पशु आहार में सम्मिलित करने हेतु पशु आहार संयंत्रों अथवा डेयरी किसानों द्वारा संपूरक के रूप में उपयोग के लिए प्रस्तावित किया गया।

यह पहल उत्पादकता वृद्धि और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों को संबोधित करते हुए, भारत में सस्टेनेबल एवं जलवायु-अनुकूल डेयरी फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के प्रति एनडीडीबी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

असम में क्षमता विकास और सस्टेनेबिलिटी पहल

एनडीडीबी ने असम में डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना को सुदृढ़ करने और सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए दो प्रमुख पहलें संचालित कीं। एनडीडीबी ने वामूल को तकनीकी और परिचालन सहयोग प्रदान किया, जिससे पूरबी डेयरी की प्रसंस्करण क्षमता दोगुनी की जा सके। इस सुविधा के विकास में नए मूल्य संवर्धित प्रोडक्ट लाइनों का भी समावेश किया गया, जिससे उत्पादों में विविधता आई और बाजार पहुंच में सुधार हुआ। यह पहल बढ़ती उपभोक्ता मांग को पूरा करने के साथ-साथ स्थानीय डेयरी किसानों के लिए खरीदारी और आय बढ़ाने के उद्देश्य से डिज़ाइन की गई है।

इसके अलावा, एनसीओएल ने नॉर्थ ईस्ट डेयरी एंड फूड्स लिमिटेड (NEDFL) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ऑर्गेनिक प्रसंस्करण इकाई और प्रदर्शन फार्म स्थापित करने का प्रावधान है। इस पहल के तहत 1,000 से अधिक किसानों को ऑर्गेनिक पद्धतियों में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिनका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार, रासायनिक इनपुट्स में कमी और प्रमाणन सहायता है। इसका लक्ष्य स्थानीय ऑर्गेनिक मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना और ग्रामीण रोजगार सृजित करना है।

ये पहलें एनडीडीबी के सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य के अनुरूप हैं। इनसे प्रसंस्करण क्षमता में सुधार और सस्टेनेबल कृषि पद्धतियों के व्यापक अपनाने में योगदान मिला है।

मुजकुवा गांव का कार्बन पदचिह्न आकलन

एनडीडीबी ने मुजकुवा गांव के लिए एक व्यापक कार्बन पदचिह्न आकलन किया। इस अध्ययन में 1,008 घरों एवं स्थानीय संस्थानों का विस्तृत सर्वेक्षण शामिल रहा, जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन का आधार-स्तर निर्धारित किया गया। आकलन में परिवहन, खाना पकाने में उपयोग होने वाली ऊर्जा, कृषि, विद्युत खपत, पशुधन और अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित उत्सर्जन को शामिल किया गया। एकत्रित आंकड़ों के आधार पर प्रमुख उत्सर्जन स्रोतों की पहचान की गई है, जिनके आधार पर लक्षित नियंत्रण एवं शमन रणनीतियां तैयार की जाएंगी।

इस आकलन से प्राप्त निष्कर्षों से गांव में कार्बन न्यूट्रैलिटी हस्तक्षेपों की योजना बनाने में सहयोग मिलेगा। यह रिपोर्ट समान ग्रामीण कार्बन न्यूट्रैलिटी परियोजनाओं के लिए एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में भी कार्य करेगी। यह पहल ग्रामीण एवं डेयरी इकोसिस्टम में आंकड़ा-आधारित पर्यावरणीय योजना निर्माण को बढ़ावा देने के प्रति एनडीडीबी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाएं

वर्ष के दौरान, दो सौर ऊर्जा परियोजनाओं की कमीशनिंग की गई: बरौनी, बिहार में 300 KWp की स्थापना और फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी (FES), आणंद में 60 KWp का सिस्टम। इसके अलावा, चार परियोजनाएं वर्तमान में निष्पादन के अधीन हैं: (i) भुखला–वडगाम, गुजरात में 300 KWp (ii) अगथला–लखानी, गुजरात में 300 KWp (iii) इरमा, आणंद में 25 KWp (iv) एनसीडीएफआई कार्यालय, वघासी, आणंद में 50 KWp।

विद्या डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट, आणंद की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट

एनडीडीबी ने विद्या डेयरी, आणंद पर एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में ऊर्जा दक्षता एवं वाटर इफिसिएंसी में सुधार, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, अपशिष्ट प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण संबंधी पहलों का दस्तावेजीकरण किया गया। इसमें सस्टेनेबिलिटी के प्रति विद्या डेयरी के दृष्टिकोण को व्यावहारिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से भी प्रस्तुत किया गया। यह पहल पर्यावरणीय, सामाजिक एवं सुशासन (ESG) पद्धतियों के लिए एक मानक स्थापित करती है और उत्तरदायी डेयरी संचालन को बढ़ावा देने हेतु एनडीडीबी के प्रयासों को सशक्त बनाती है।

एनडीडीबी परिसर का बायो डायर्वसिटी मैपिंग

एनडीडीबी ने अपने परिसर में देशी वनस्पति और पक्षियों का दस्तावेजीकरण करने हेतु एक बायो डायर्वसिटी मैपिंग परियोजना लागू की। इस पहल का उद्देश्य पारिस्थितिक जागरूकता बढ़ाना और देशी प्रजातियों का संरक्षण करना है। एक विस्तृत सूची तैयार की गई और प्रजाति-सूचना सहित वेदर रेजिस्टेंट प्रदर्शन बोर्ड लगाए गए। इन बोर्डों को एनडीडीबी की वेबसाइट पर QR कोड के माध्यम से डिजिटल बायो डायर्वसिटी मैपिंग से जोड़ा गया। इस परियोजना ने परिसर को एक जीवंत बायो डायर्वसिटी रिपोजिटरी के रूप में स्थापित किया, जिससे एनडीडीबी के पर्यावरणीय जागरूकता प्रयासों को मजबूती मिली।

डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी; डॉ. सुनीता पिंटो, अध्यक्ष, विद्या डेयरी; और डॉ. अमित व्यास, प्रबंध निदेशक, कैरा जिला सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड तथा विद्या डेयरी के बोर्ड सदस्य, विद्या डेयरी की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के विमोचन के दौरान

डेयरी विकास के लिए सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

एनडीडीबी कई वर्षों से विभिन्न सरकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्यरत है। इन योजनाओं में गौवंश के आनुवंशिक सुधार, वैज्ञानिक चारा उत्पादन, आहार प्रबंधन, डेयरी अवसंरचना विकास, गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, डिजिटलीकरण सहित अनेक महत्वपूर्ण पहलें शामिल हैं। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि करना और किसानों की आय सुदृढ़ करना है।

गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल जी ने बनास डेयरी के दामा वीर्य उत्पादन इकाई, डीसा में एनडीडीबी द्वारा विकसित स्वदेशी सेक्स्ड-सॉर्टेड सीमन मशीन, गौसॉर्ट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गुजरात विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और बनास डेयरी के अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी जी और एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह भी उपस्थित रहे

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)

एनडीडीबी ने भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग की पहल, केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के तहत कई परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी को निरंतर जारी रखा। ये गतिविधियां राज्य पशु विकास बोर्डों, दूध महासंघों, दूध संघों, गैर-सरकारी संगठनों और एनडीडीबी की सहायक कंपनियों के सहयोग से संचालित की गईं। इनका उद्देश्य गौवंश के आनुवंशिक सुधार को तेज करना और कुल उत्पादकता में वृद्धि करना था।

गौसॉर्ट: आनुवंशिक सुधार के लिए देशी सेक्स-सॉर्टिंग तकनीक

गौसॉर्ट, एक देशी सेक्स-सॉर्टिंग तकनीक, मादा बछडे के उत्पादन में वृद्धि करने और फार्म स्तर पर लाभप्रदता सुधारने के उद्देश्य से एनडीडीबी की आरएंडडी पहल के तहत विकसित की गई और इसे एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज द्वारा लागू किया गया।

इस तकनीक के वाणिज्यिक विकास के लिए वित्तीय सहायता भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग की राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत प्रदान की गई। इस नवाचार का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 5 अक्तूबर 2024 को वाशीम, महाराष्ट्र में किया गया।

गौसॉर्ट ने सेक्स-सॉर्टेड सीमन से मादा बछड़े का उत्पादन लगभग 90 प्रतिशत शुद्धता के साथ किया। इससे पहले भारत बहुराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर था और सेक्स-सॉर्टेड सीमन की कीमत लगभग 1,000 रुपये प्रति डोज थी। स्वदेशीकरण के बाद यह लागत लगभग 250 रुपये प्रति डोज हो गई, जिससे यह डेयरी किसानों के लिए अधिक सुलभ और किफायती हो गया।

गौसॉर्ट कार्यान्वयन के उद्देश्य :

- उच्च आनुवंशिक गुण वाली मादा बछडों के जन्म द्वारा दूध की उत्पादकता बढ़ाना।
- डेयरी पशु संख्या बढ़ाकर किसानों की आय में सुधार करना।
- समय के साथ अप्रयुक्त नर बछडों की संख्या में कमी लाना।

एनडीडीबी ने इस तकनीक को निम्नलिखित स्थानों पर लागू किया:

- अलामाढी वीर्य केन्द्र, चैन्नई, तमिलनाडु
- केन्द्रीय हिमीकृत वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान (CFSP&TI), हेसारघट्टा, बेंगलुरु
- दामा वीर्य केन्द्र, बनास डेयरी

गौसॉर्ट का परिनियोजन प्रजनन तकनीकों में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह राष्ट्रीय लक्ष्य – आनुवंशिक सुधार और पशुपालन उत्पादकता बढ़ाने के अनुरूप है।

जीनोमिक चयन में समेकित प्रयासों के लिए एकीकृत जीनोटाइपिंग चिप्स

एनडीडीबी, आईसीएआर-राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (ICAR-NBAGR), राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (NIAB) और बीएआईएफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन (BAIF) ने दो एकीकृत जीनोटाइपिंग चिप्स के उत्पादन के लिए सहयोगात्मक समझौते पर हस्ताक्षर किए: गायों के लिए "GAUCHIP" और भैंसों के लिए "MAHISHCHIP"। ये चिप्स, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग की राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत विकसित किए गए हैं और किसानों को किफायती जीनोटाइपिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से डिज़ाइन किए गए हैं। इस पहल के माध्यम से युवा गायों और सांड़ों का शीघ्र चयन संभव हो सकेगा। "GAUCHIP" और "MAHISHCHIP" का औपचारिक शुभारंभ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 5 अक्तूबर, 2024 को वाशिम, महाराष्ट्र में किया गया।

दूध उत्पादन के लिए जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू (GBV) का उपयोग करते हुए जीनोमिक चयन इस पहल का एक प्रमुख घटक रहा। इस पद्धति ने कृत्रिम गर्भाधान के लिए उच्च-गुणवत्ता, रोग-मुक्त वीर्य के उत्पादन हेतु सांड़ बछड़ों के चयन में सहायता प्रदान की, साथ ही भविष्य में प्रजनन उद्देश्यों के लिए मादा बछड़ों के चयन की प्रक्रिया को भी सुलभ बनाया।

वर्ष के दौरान, कांकरेज नस्ल के लिए जीनोमिक चयन की शुरुआत की गई। इस प्रकार, गिर, साहिवाल, कांकरेज, HFCB और JYCB गायों तथा मुर्रा और महेसाना भैंसों के नर और मादा बछड़ों के लिए जीनोमिक चयन सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। विकसित जीनोमिक डेटाबेस का उपयोग नस्ल की शुद्धता का मूल्यांकन, अनुवांशिक रोगों की पहचान और दूध प्रोटीन जैसे A1/A2 की पहचान के लिए एकल जीन परीक्षण के माध्यम से किया गया, जिससे श्रेष्ठ पशुओं के चयन की लागत में कमी आई।

वीर्य केन्द्रों के साथ-साथ स्वामिनारायण मंदिर और अनुसूया गौधाम जैसी गौशालाओं और व्यक्तिगत किसानों ने GBV और नस्ल शुद्धता सेवाओं के आधार पर पशुओं के चयन की प्रक्रिया अपनाई है। इससे उन्हें श्रेष्ठ पशुओं के चयन और अपने स्थायी ब्रीड का विकास करने में सहायता मिली है। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए www.genomics.coop नामक एक वेब पोर्टल विकसित किया गया। यह पोर्टल एक एकीकृत पहुंच बिंदु के रूप में कार्य करता है, जिससे किसान और विभिन्न संगठन जीनोटाइपिंग सेवाओं और राष्ट्रीय जीनोमिक डेटाबेस का लाभ उठा सकते हैं। जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू (GBV) की सटीकता बढ़ाने और किसानों के लिए जीनोमिक परीक्षण की लागत कम करने के प्रयास में, एनडीडीबी ने विभिन्न संगठनों के साथ साझेदारी कर संदर्भ आबादी का विस्तार भी किया है।

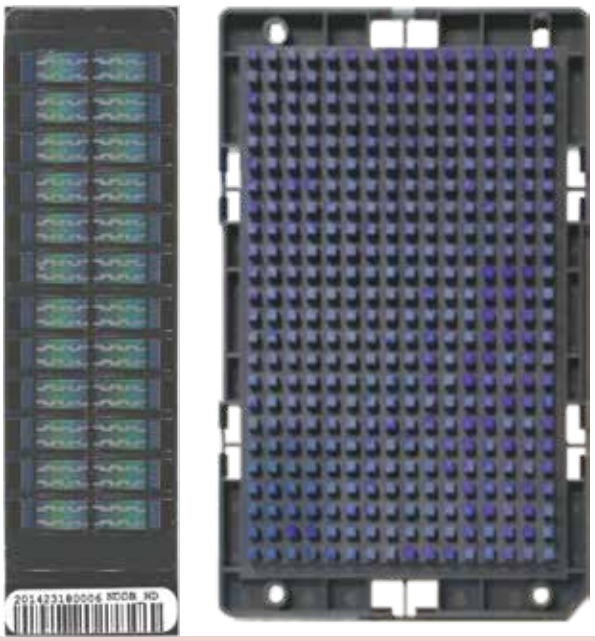

स्वदेशी एकीकृत जीनोटाइपिंग चिप्स गाय के लिए "गौचिप" और भैंसों के लिए "महिषचिप"

देशीय नस्लों के लिए राष्ट्रीय बोवाइन जीनोमिक केंद्र (NBGC-IB)

पीटी और पीएस परियोजनाओं के तहत फीनोटाइप रिकॉर्डिंग का उपयोग जीनोमिक चयन प्रयासों के समर्थन के लिए किया गया। मिल्क रिकॉर्डेड पशुओं के रक्त और टिश्यू सैंपल एकत्रित किए गए, ताकि जीनोमिक मूल्यांकन के लिए एक मजबूत संदर्भ आबादी का निर्माण जारी रखा जा सके।

कुल 18,363 प्रदर्शन रिकॉर्डेड पशुओं और सांड़ो के रक्त/टिश्यू सैंपल एकत्रित किए गए और डीएनए एक्सट्रेक्शन के लिए संसाधित किए गए। इनमें से 14,433 पशुओं के सैंपलों का नवीनतम संस्करण GAUCHIP और MAHISHCHIP का उपयोग कर जीनोटाइपिंग किया गया।

गिर, साहिवाल, होल्स्टीन फ्रीजियन क्रॉसब्रीड, जर्सी क्रॉसब्रीड गायों और मुर्रा तथा महेसाना भैंसों के नर बछड़े उनके GBV के आधार पर चुने गए, जिससे उच्च आनुवंशिक गुण वाले पशुओं के चयन की सटीकता में सुधार हुआ।

सेक्स्ड सीमन के साथ इन-विट्रो निषेचित भ्रूणों द्वारा तीव्र नस्ल सुधार कार्यक्रम

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के अंतर्गत संचालित इस परियोजना का उद्देश्य अधिक उत्पादन वाले पशुओं की आबादी को बढ़ाकर उत्पादकता में सुधार करना है, जिसे भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के माध्यम से हासिल किया गया। इस परियोजना को विभिन्न हितधारकों के सहयोग से लागू किया गया, जिनमें दूध संघ/महासंघ, दूध उत्पादक कंपनियां, राज्य पशुपालन विभाग और राज्य पशुधन विकास बोर्ड शामिल हैं।

मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में एनडीडीबी ने दो सेवा प्रदाताओं—एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (NDS) के राहुरी वीर्य केन्द्र और ट्रॉपिकल एनिमल जेनेटिक्स (TAG) के साथ समझौते किए। ये सेवा प्रदाता, भ्रूणों का उत्पादन और लक्षित लाभार्थियों में प्रत्यारोपण के लिए उत्तरदायी हैं और परियोजना का वार्षिक लक्ष्य लगभग 66,000 गर्भधारण निर्धारित किया गया है।

इस प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने के समर्थन के लिए, भारत सरकार ने सेक्स्ड सीमन से उत्पादित IVF भ्रूणों का उपयोग करके प्राप्त प्रत्येक निश्चित गर्भधारण पर 5,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की। मार्च 2025 तक, 16,390 पशुओं को निश्चित रूप से गाभिन करने के लिए कुल 28 कार्य योजनाओं को अनुमोदित किया गया।

निश्चित गर्भधारण के लिए सेक्स-सॉर्टेड सीमन द्वारा तीव्र नस्ल सुधार कार्यक्रम

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के अंतर्गत स्वीकृत तीव्र नस्ल सुधार कार्यक्रम की शुरुआत सेक्स-सॉर्टेड सीमन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई, जिससे मादा बछड़े उत्पन्न होने की संभावना 90 प्रतिशत होती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पांच वर्षों में कुल 51.63 लाख पशुओं का निश्चित गर्भधारण करना है।

इस पहल के लिए एनडीडीबी को नोडल निगरानी एजेंसी के रूप में नामित किया गया। इस भूमिका में एनडीडीबी सेक्स्ड सीमन की कीमतें तय करने, चयनित आपूर्तिकर्ताओं के साथ दर अनुबंध करने और विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजना के निष्पादन की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। मार्च 2025 तक, इस कार्यक्रम के तहत कुल 20.06 लाख सेक्स्ड सीमन डोज़ उपलब्ध कराए जा चुके हैं। भारत पशुधन एप्लिकेशन में दर्ज आंकड़ों के अनुसार, कार्यान्वयन एजेंसियों ने सेक्स्ड सीमन का उपयोग करके क्षेत्र में 3.65 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए हैं।

संतति परीक्षण (PT) और वंशावली चयन (PS) कार्यक्रम

पीटी और पीएस कार्यक्रमों का ध्यान डेयरी पशुओं के वैज्ञानिक चयन पर केंद्रित रहा, ताकि अनुवांशिक सुधार को बढ़ावा दिया जा सके।

संतति परीक्षण (PT)

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के अंतर्गत फील्ड आधारित संतति परीक्षण नौ राज्यों में आयोजित किया गया, जिसमें गिर, साहिवाल, जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन क्रॉसब्रीड, जर्सी क्रॉसब्रीड गायों तथा मुर्रा और महेसाना भैंसों को शामिल किया गया। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, 250 सांड़ों का संतति परीक्षण किया गया और 50,354 पशुओं की दुग्ध रिकॉर्डिंग की गई।

कुल 496 उच्च आनुवंशिक गुण वाले सांड का चयन अनुमानित GBV और DNA आधारित पितृत्व सत्यापन के आधार पर किया गया और इन्हें वीर्य केन्द्रों में वितरित किया गया। सभी चयनित सांड़ों का अनुवांशिक रोगों और संक्रामक बीमारियों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार परीक्षण किया गया। दुग्ध उत्पादन, फैट प्रतिशत, सॉलिड्स-नॉट-फैट (SNF), प्रोटीन उत्पादन और प्रजनन गुणों के लिए आनुवंशिक मूल्यांकन किया गया। एनिमल टाइप वर्गीकरण और आनुवंशिक मूल्यांकन गतिविधियां कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है, जिससे एनडीडीबी के उद्देश्य सटीक और डेटा-आधारित चयन पद्धतियों के माध्यम से सतत् आनुवंशिक प्रगति को बढ़ावा देने को समर्थन मिला।

आरजीएम योजना के अंतर्गत क्रियान्वित पीटी परियोजनाओं का विवरण नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है:

क्र. सं	राज्य	ईआईए के नाम	नस्ल
1	आंध्र प्रदेश	एपीएलडीए	जर्सी क्रॉसब्रीड
2	गुजरात	एसएजी	मुर्रा
3	गुजरात	एसएजी	एचएफसीबी
4	गुजरात	महेसाणा दूध संघ	महेसाना
5	गुजरात	बनास दूध संघ	महेसाना
6	गुजरात	एसएजी	गिर
7	हरियाणा	एचएलडीबी	मुर्रा
8	हिमाचल प्रदेश	एचपीएलडीबी	जर्सी
9	केरल	केएलडीबी	एचएफसीबी
10	पंजाब	पीएलडीबी	मुर्रा
11	पंजाब	पीएलडीबी	सहिवाल
12	राजस्थान	श्री गंगानगर दूध संघ	साहिवाल
13	तमिलनाडु	टीसीएमपीएफ	जर्सी क्रॉसब्रीड
14	उत्तर प्रदेश	एबीआरओ	मुर्रा

वंशावली चयन (PS)

वंशावली चयन (PS) कार्यक्रमों को देशी गाय और भैंस नस्लों के आनुवंशिक सुधार को आगे बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किया गया है, जिनमें उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता, अनुकूलनशीलता, गर्मी के प्रति सहनशीलता और रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसी लाभकारी विशेषताएं शामिल हैं। ये कार्यक्रम उन क्षेत्रों में, जहां कृत्रिम गर्भाधान (AI) कवरेज कम है, ट्रांजिशनल स्ट्रेटजी के रूप में कार्य करते हैं, ताकि पीटी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से पहले एआई कवरेज में पर्याप्तता सुनिश्चित की जा सके।

इस कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का हिस्सा हैं, ने पशु के मूल स्थान में संरक्षण और आनुवंशिक संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह कार्य श्रेष्ठ जर्मप्लाज्म की पहचान और चयन के माध्यम से पूरा किया गया, साथ ही कृत्रिम गर्भाधान (AI) सेवाओं की पहुंच का विस्तार सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा, इन कार्यक्रमों ने स्थानीय स्तर पर सस्टेनेबल प्रजनन पद्धतियों के जानकारी के प्रचार-प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, निम्नलिखित नस्लों के लिए नौ पीएस परियोजनाओं को लागू किया गया: गावलाओ, हरियाना, कांकरेज, थारपारकर और राठी (गाय); बन्नी, जाफराबादी, नीली-रावी और पंढ़रपुरी (भैंस)। इस कार्यक्रम में कुल 69,673 कृत्रिम गर्भाधान (AI) किए गए और 7,965 पशुओं को दुग्ध रिकॉर्डिंग के तहत नामांकित किया गया। इन पहलों ने देशी नस्लों की आनुवंशिक आधार और उत्पादकता को मजबूत करने में योगदान दिया, जिससे उनकी दीर्घकालिक क्षमता और डेयरी क्षेत्र में भूमिका को सुदृढ़ किया गया।

आरजीएम योजना के अंतर्गत क्रियान्वित पीएस परियोजनाओं का विवरण नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है:

इन प्रयासों ने देशी नस्लों की आनुवंशिक क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाया और लक्षित क्षेत्रों में सस्टेनेबल डेयरी विकास का समर्थन किया।

क्र. सं.	राज्य	ईआईए के नाम	नस्ल
1	गुजरात	एसएजी	जाफराबादी
2	गुजरात	बनास दूध संघ	कांकरेज
3	गुजरात	कच्छ दूध संघ	बन्नी
4	हरियाणा	एचएलडीबी	हरियाना
5	महाराष्ट्र	एमएलडीबी	गावलाओ
6	महाराष्ट्र	एमएलडीबी	पंढ़रपुरी
7	पंजाब	पीएलडीबी	नीली-रावी
8	राजस्थान	आरएलडीबी	थारपारकर
9	राजस्थान	उरमूल ट्रस्ट	राठी

स्मार्ट वेइंग स्केल का उपयोग करके दूध की रिकॉर्डिंग और भारत पशुधन एप्लिकेशन में डेटा कैप्चर करते हुए

राष्ट्रीय दुग्ध रिकॉर्डिंग कार्यक्रम (NMRP)

एनएमआरपी को एक सुव्यवस्थित प्रदर्शन रिकॉर्डिंग पहल के रूप में लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य अल्प विकसित क्षेत्रों में डेटा गैप को कम करना और गाय एवं भैंस आबादी में उत्पादकता वृद्धि का समर्थन करना है। सीमित भौगोलिक कवरेज वाले पीटी और पीएस कार्यक्रमों के पूरक के रूप में विकसित, एनएमआरपी व्यापक नस्ल और भौगोलिक कवरेज सुनिश्चित करता है और राष्ट्रीय जीनोमिक संदर्भ आबादी के विस्तार में भी योगदान देता है।

यह कार्यक्रम 40 दुग्ध रिकॉर्डिंग इकाइयों के माध्यम से संचालित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक में 45 दुग्ध रिकॉर्डिंग केंद्र शामिल हैं और इसका वार्षिक लक्ष्य 1.5 लाख पशुओं का रिकॉर्डिंग करना है। इस डेटा संग्रह का कार्य मानक परिचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का सख्ती से पालन करते हुए किया जाता है। ग्राम स्तर के मिल्क रिकॉर्डर दूध उत्पादन और दूध की संरचना संबंधी जानकारी जैसे फैट प्रतिशत, एसएनएफ और प्रोटीन प्रतिशत को भारत पशुधन मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके दर्ज करते हैं, ताकि रीयल टाइम डेटा कैप्चर सुनिश्चित किया जा सके।

एनएमआरपी में वे नस्लें शामिल हैं जो वर्तमान में पीटी और पीएस पहलों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, जिससे क्षेत्रीय नस्लों में व्यापक प्रदर्शन मूल्यांकन, आनुवंशिक रूप से श्रेष्ठ पशुओं की पहचान और चयन और आनुवंशिक लक्षणों का अनुमान संभव होता है। ये गतिविधिया राष्ट्रीय जीनोमिक डेटाबेस को सुदृढ़ करने में योगदान करती हैं और डेयरी क्षेत्र के सस्टेनेबल विकास के लिए सूचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करती हैं।

आरजीएम योजना के अंतर्गत लागू एनएमआरपी इकाइयों का विवरण नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है:

क्र. सं.	राज्य	एमआर की संख्या		शामिल की जाने वाली प्रमुख गाय और भैंस नस्लें
		इकाइयां	केन्द्र	
1	आंध्र प्रदेश	2	90	गाय: ओंगोल, जेवाईसीबी और भैंस: मुर्रा
2	असम	1	45	गाय: लाखिमी
3	बिहार	2	90	गाय: बाचौर और पूर्णिया
4	गोवा	1	45	गाय: श्वेता कपिला, एचएफसीबी, जेवाईसीबी और भैंस
5	हरियाणा	2	90	गाय: बेलाही, हरियाना
6	जम्मू और कश्मीर	2	90	गाय: एचएफसीबी और जेवाईसीबी
7	झारखंड	1	45	गाय: एचएफसीबी और जेवाईसीबी
8	कर्नाटक	2	90	गाय: शुद्ध एचएफ और भैंस: धारवाड़ी
9	मध्य प्रदेश	5	225	गाय: मालवी, निमाड़ी, केनकाथा और भैंस: भदावरी
10	महाराष्ट्र	4	180	गाय: खिल्लर, रेड कंधारी, एचएफ, एचएफसीबी और भैंस: मुर्रा, जाफराबादी, पंढरपुरी
11	मणिपुर	1	30	गाय: एचएफसीबी और जेवाईसीबी
12	मेघालय	1	45	गाय: एचएफसीबी और जेवाईसीबी
13	ओडिशा	1	45	गाय: बिझरपुरी
14	पंजाब	3	135	गाय: शुद्ध एचएफ,एचएफसीबी और भैंस: नीली रावी
15	राजस्थान	4	180	गाय: नागोरी, नारी, गिर, कांकरेज, राठी, थारपारकर
16	तमिलनाडु	3	135	गाय: अलम्बाड़ी, कंगायम और अंब्लाचेरी
17	उत्तर प्रदेश	2	90	गाय: खेरीगढ़, गंगातीरी और पोनवार
18	उत्तराखंड	1	45	गाय: बद्री, एचएफसीबी, साहिवाल और भैंस: मुर्रा
19	पश्चिम बंगाल	2	60	गाय: गिर, एचएफसीबी, जेवाईसीबी

नस्ल गुणन फार्म (BMF)

एनडीडीबी को नस्ल गुणन फार्म (BMF) परियोजना के कार्यान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के तहत संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे उद्यमियों का विकास करना है जो देशी गाय और भैंस नस्लों से रोग-मुक्त, उच्च उत्पादकता वाले श्रेष्ठ मादा बछड़ों और गायों का उत्पादन करने वाले बीएमएफ स्थापित करें। यह कार्य वैज्ञानिक प्रजनन तकनीकों जैसे सेक्स-सॉर्टेड सीमन और इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) तकनीक के माध्यम से किया गया, ताकि किसानों को आनुवंशिक रूप से श्रेष्ठ मादा पशु किफायती रूप में उपलब्ध कराए जा सकें।

मार्च 2025 तक, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने कुल 169 बीएमएफ प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें से 132 परियोजनाएं सक्रिय हैं। इसके साथ ही, 119 परियोजना लाभार्थियों को कुल 83.43 करोड़ रुपये की अनुदान राशि वितरित की गई। सभी स्वीकृत बीएमएफ परियोजनाओं ने स्थिर प्रगति दिखाई है, और विभिन्न पहलें अपने-अपने क्रियान्वयन चरणों में आगे बढ़ रही हैं, जिसे एनडीडीबी द्वारा प्रदान की जाने वाली निरंतर निगरानी और मार्गदर्शन द्वारा समर्थित किया गया।

वीर्य उत्पादन में सहयोग– मौजूदा वीर्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण

कृत्रिम गर्भाधान (AI) के लिए गुणवत्तायुक्त हिमीकृत वीर्य डोज़ की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानक के पशु प्रजनन अवसंरचना का विकास करने हेतु, भारत सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के अंतर्गत वीर्य केन्द्र सुदृढ़ीकरण परियोजना को स्वीकृति दी। इस परियोजना का उद्देश्य देशभर में गुणवत्ता वाले वीर्य के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मौजूदा वीर्य केन्द्रों को सहयोग करना है।

एनडीडीबी ने विभिन्न वीर्य केन्द्रों को परियोजना प्रस्ताव तैयार करने और प्रस्तुत करने में सहायता प्रदान की। मार्च 2025 तक, एनडीडीबी द्वारा किए गए मूल्यांकन के सफल समापन के बाद, भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD) ने कुल 47 परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान अवसंरचना

पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) में एआई तकनीशियनों के प्रशिक्षण हेतु सुदृढ़ अवसंरचना विकसित करने के उद्देश्य से, असम पशुधन विकास एजेंसी (ALDA) के अनुरोध पर एनडीडीबी द्वारा खानापारा, गुवाहाटी में एक अत्याधुनिक एआई प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। इस संस्थान का जून 2023 में उद्घाटन किया गया तथा इसमें भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यापक एआई प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

एनडीडीबी ने पूर्वोत्तर राज्यों में एआई नेटवर्क की सक्रिय निगरानी एवं पर्यवेक्षण किया। इस पहल के अंतर्गत कुल 1,683 बहुउद्देशीय एआई तकनीशियन (MAITRI) की तैनाती की गई, जिन्होंने सामूहिक रूप से 46.62 लाख से अधिक कृत्रिम गर्भाधान (AI) निष्पादित किए। क्षेत्र में एआई सर्विस डिलीवरी को सुदृढ़ करने हेतु एनडीडीबी द्वारा भारत पशुधन ऐप पर व्यापक प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर डेटा संकलन एवं सर्विस ट्रैकिंग की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सका।

प्रजनन प्रौद्योगिकियों की पहुंच का विस्तार

बापूधाम (बिहार), विदर्भ-मराठवाड़ा (महाराष्ट्र) तथा वाराणसी (उत्तर प्रदेश) जैसे प्रमुख डेयरी क्षेत्रों में दूध उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से एनडीडीबी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज़ के माध्यम से विभिन्न डेयरी विकास परियोजनाओं का नेतृत्व किया। इन पहलों का मुख्य फोकस डेयरी पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने तथा दूध की कमी वाले क्षेत्रों में संपूर्ण डेयरी तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर केंद्रित रहा।

इन परियोजनाओं के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियों में अधिक दूध उत्पादक क्षमता वाले पशुओं का समावेशन, मैत्री (बहुउद्देश्यीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन) के माध्यम से एआई वितरण नेटवर्क की स्थापना तथा प्रजनन प्रौद्योगिकियों का उपयोग शामिल है। इन प्रौद्योगिकियों में परंपरागत एवं सेक्स-सीमन के माध्यम से गर्भाधान तथा आईवीएफ भ्रूणों द्वारा भ्रूण प्रत्यारोपण सम्मिलित हैं। इन हस्तक्षेपों ने संबंधित परियोजना क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन तंत्र की सतत् वृद्धि एवं विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

प्रजनन प्रौद्योगिकियों की पहुंच बढ़ाने के लिए वीर्य केंद्र को सुदृढ़ करना

इन प्रयासों के अलावा, वर्ष के दौरान कई नई परियोजनाएं आरंभ की गईं। इनमें श्योपुर (मध्यप्रदेश), हरित प्रदेश दूध उत्पादक कंपनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश), मयूरभंज (ओडिशा), यवतमाल एवं वाशिम (महाराष्ट्र), रायलसीमा (आंध्र प्रदेश), गोरखपुर एवं रोहिलखंड-ब्रज (उत्तर प्रदेश) तथा झारखंड जैसे क्षेत्रों में एआई नेटवर्क की स्थापना शामिल रही।

इसके अलावा, एनडीडीबी ने उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में एक गौ अभयारण्य तथा तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्, तिरुपति में देशी गोवंश के आनुवंशिक विकास हेतु एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की पहल की। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सस्टेनेबल डेयरी विकास को प्रोत्साहित करना तथा अपने-अपने क्षेत्रों में देशी गोवंशीय नस्लों के संरक्षण एवं आनुवंशिक संवर्धन को बढ़ावा देना है।

परियोजना के नाम	शामिल पशुओं की संख्या	स्थापित कृत्रिम गर्भाधान (AI) केन्द्रों की संख्या (मैत्री)	निष्पादित एआई की संख्या
प्रोजेक्ट गिर वाराणसी	485	122	194540
बापूधाम दूध उत्पादक कंपनी लिमिटेड में उत्पादकता वृद्धि गतिविधियां	300	106	138643
विदर्भ- मराठवाड़ा में उत्पादकता वृद्धि गतिविधियां	2000	465	319974
श्योपुर में एआई नेटवर्क की स्थापना	-	100	54693
हरित प्रदेश दूध उत्पादक कंपनी लिमिटेड में उत्पादकता वृद्धि सेवाएं	-	170	48297
मयूरभंज, ओडिशा में उत्पादकता वृद्धि सेवाएं	3000	51	4684
रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में सेक्स्ड सीमन के माध्यम से एआई सेवाएं	-	106	23155
उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड-ब्रज क्षेत्र में AI नेटवर्क की स्थापना	-	503	190599
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र में एआई नेटवर्क की स्थापना	-	230	75086
झारखंड में एआई नेटवर्क की स्थापना	-	330	56789
वाशीम-यवतमाल, महाराष्ट्र में AI नेटवर्क की स्थापना	4000	59	10806
विदर्भ- मराठवाड़ा, महाराष्ट्र (चरण-।।) में महिला दुग्ध उत्पादक किसानों के पशुओं हेतु सेक्स्ड सीमन द्वारा एआई सेवाएं	-	-	16583
वाशीम-यवतमाल, महाराष्ट्र (चरण-।।) में पशु समावेश	3000	-	-

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत चारा बीज उत्पादन

दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए गुणवत्तायुक्त चारा बीज की उपलब्धता बढ़ाने हेतु, राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के अंतर्गत चारा बीज उत्पादन संबंधी गतिविधियां जारी रहीं। कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में, एनडीडीबी ने बीज उत्पादन में संलग्न डेयरी सहकारिताओं को कार्यान्वयन एवं निगरानी समर्थन प्रदान किया।

वित्त वर्ष 2024–25 में, खरीफ मौसम के दौरान चार राज्यों की छह डेयरी सहकारिताओं ने कुल 20,923 क्विंटल प्रमाणित चारा बीज का उत्पादन किया, जिसकी अनुमानित मूल्य राशि 1,829 लाख रुपये रही। इसी प्रकार, रबी मौसम में सात राज्यों की 10 डेयरी सहकारिताओं ने बीज उत्पादन गतिविधियां संचालित कीं, जिसके अंतर्गत लगभग 55,129 क्विंटल चारा बीज का उत्पादन होने की संभावना है, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 4,851 लाख रुपये आँका गया है।

उत्पादित प्रमाणित चारा बीजों का वितरण दूध उत्पादकों को दूध महासंघों, दूध संघों तथा अन्य दूध उत्पादक संगठनों के माध्यम से किया गया। इस पहल से बड़े पैमाने पर हरे चारे की खेती को प्रोत्साहन मिला और दूध उत्पादकों को गुणवत्तायुक्त चारे की सतत उपलब्धता सुनिश्चित हुई।

बेहतर हरे चारे की पैदावार के लिए गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन

2024–25 में डेयरी सहकारिताओं द्वारा चारा बीज का उत्पादन

एनएलएम के तहत खरीफ 2024-25 में उत्पादित चारा बीज

क्रम सं.	राज्य	डेयरी सहकारी संस्था के नाम	उत्पादित चारा बीज (क्विंटल में)	व्यय निधि (लाख रुपये में)
1	राजस्थान	कोटा दूध संघ	898.50	76.74
2		आरसीडीएफ इकाई, बीकानेर	6223.50	628.84
3	पंजाब	मिल्कफेड, पंजाब	37.35	2.79
4	गुजरात	बनासकांठा दूध संघ	7763.61	676.82
5	कर्नाटक	बेंगलुरु दूध संघ	4000.00	296.00
6		हावेरी दूध संघ	2000.00	148.00
कुल			**20922.96**	**1829.18**

एनएलएम के तहत रबी 2024-25 में अनुमानित चारा बीज उत्पादन

क्रम सं.	राज्य	डेयरी सहकारी संस्था का नाम	अनुमानित चारा बीज उत्पादन (क्विंटल में)	अनुमानित निधि व्यय (लाख रुपये में)
1	राजस्थान	कोटा दूध संघ	253.00	26.45
2		आरसीडीएफ इकाई, बीकानेर	5302.83	422.41
3	पंजाब	मिल्कफेड, पंजाब	6147.40	539.51
4	उत्तर प्रदेश	लखनऊ दूध संघ	2380.40	213.12
5	गुजरात	बनासकांठा दूध संघ	13590.32	1102.03
6	बिहार	बरौनी दूध संघ	4618.04	348.30
7		मिथिला दूध संघ	2966.49	223.14
8		पटना दूध संघ	638.40	47.88
9	आंध्र प्रदेश	श्रीजा दूध उत्पादक कंपनी	123.93	12.39
10	तेलंगाना	मूलुकानूर दूध संघ	19108.00	1916.20
कुल			55128.81	4851.43

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) घटक–ए

एनडीडीबी को एनपीडीडी योजना के घटक 'ए' को लागू करने के लिए दुग्ध उत्पादक संगठनों (MPO) और किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के लिए एक राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका संचालन भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आवश्यक सेवाओं हेतु अवसंरचना का निर्माण अथवा सुदृढ़ीकरण करना है, जिसमें गुणवत्ता आधारित दूध परीक्षण उपकरण तथा प्राथमिक चिलिंग सुविधाएं सम्मिलित हैं। मार्च 2025 तक, भारत सरकार ने दूध उत्पादक कंपनियों से प्राप्त तीन परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की, जिनका कुल व्यय 49.39 करोड़ रुपये है। इसमें 30.98 करोड़ रुपये की केंद्रीय अनुदान राशि सम्मिलित है। इसके अलावा, एनडीडीबी दूध संघों एवं महासंघों को परियोजना प्रस्तावों के निर्माण तथा स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करा रही है।

एनपीडीडी घटक– ए के अंतर्गत पूर्व-परियोजना आधारभूत सर्वेक्षण एवं डेयरी विकास योजना

एनडीडीबी ने राजसमंद जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के अनुरोध पर राजस्थान के राजसमंद ज़िले में एक पूर्व-परियोजना आधारभूत सर्वेक्षण आयोजित किया। घाटी, जैतावास तथा ओड़ा गांवों के 966 परिवारों को सम्मिलित करते हुए यह सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण में परिवारों की जनसांख्यिकी, दूधारु पशुओं की संख्या, दैनिक दूध उत्पादन, कुल उत्पादन तथा विक्रेय अधिशेष से संबंधित आंकड़े संकलित किए गए। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर एक आधारभूत रिपोर्ट तैयार कर दूध संघ को प्रस्तुत किया गया, ताकि एनपीडीडी घटक – ए के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव तैयार करने में उसे सहयोग प्राप्त हो सके।

एनडीडीबी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा गोवा की राज्य सरकारों के अनुरोध पर डेयरी विकास योजनाएं तैयार कीं। इन योजनाओं का उद्देश्य वैज्ञानिक प्रजनन, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी हस्तक्षेपों के साथ-साथ कैटल इंडक्शन के माध्यम से पशुधन की उत्पादकता बढ़ाना है। उत्पादकों को उचित मूल्य उपलब्ध कराने तथा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण दूध सुनिश्चित करने हेतु सहकारिताओं को सुदृढ़ करना प्राथमिकता रही। प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एनडीडीबी ने परिचालन संबंधी जिम्मेदारी अपने हाथ में ली।

एनपीडीडी घटक–ए के अंतर्गत वामूल, ईअमूल, पीसीडीएफ, एलडीसीएफ एवं टीसीएमपीएफ हेतु भी पूर्व-परियोजना सर्वेक्षण एवं प्रस्ताव तैयार किए गए। ये प्रस्ताव संबंधित प्राधिकरणों को प्रस्तुत किए गए तथा स्वीकृत भी हुए। असम में, प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से डिब्रूगढ़, जोरहाट, सिलचर और धेमाजी में नए डेयरी संयंत्रों की स्थापना हेतु एनडीडीबी ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार किए, जिन्हें सरकारी सहयोग प्राप्त है।

एनपीडीडी घटक- बी – सहकारिताओं के माध्यम से डेयरी (DTC- JICA) – सस्टेनेबल आजीविका की कुंजी

एनडीडीबी को "सहकारिताओं के माध्यम से डेयरी (DTC)" – एनपीडीडी के घटक-बी का कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया है। यह भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य संगठित बाजारों तक किसानों की पहुंच को बेहतर बनाकर, डेयरी प्रसंस्करण एवं विपणन अवसंरचना का आधुनिकीकरण कर तथा संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ कर दूध एवं डेयरी उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करना है। सामूहिक रूप से, ये हस्तक्षेप परियोजना क्षेत्रों में दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए अभिप्रेत हैं।

यह योजना नौ राज्यों जैसे - आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में उत्पादक-स्वामित्व वाली संस्थाओं के माध्यम से लागू की जा रही है। इनमें दूध संघ, राज्य दूध महासंघ तथा दूध उत्पादक संगठनों को सम्मिलित किया गया है।

परियोजना का संक्षिप्त विवरण

विवरण	राशि (करोड़ रुपये)
कुल परियोजना व्यय	1568.28
JICA से प्राप्त ODA ऋण	924.56
भारत सरकार का अनुदान	475.54
सहभागी संस्थाओं का अंशदान	168.18

अनुमोदित उप-परियोजनाएं

विवरण	राशि (करोड़ रुपये)
35 स्वीकृत उप-परियोजनाओं का कुल व्यय	1343.00
सहभागी संस्थाओं को ऋण (1.5% वार्षिक)	821.07
अनुदान	388.54
सहभागी संस्थाओं का अंशदान	133.39

भागीदार संस्थाओं (PI) ने विभिन्न घटकों के अंतर्गत गतिविधियां आरंभ की हैं, जिनमें दूध संकलन अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना, प्रसंस्करण एवं विनिर्माण सुविधाओं का विकास, विपणन अवसंरचना, आईसीटी अवसंरचना, उत्पादकता वृद्धि से संबंधित कार्यक्रम जैसे बछड़ी पालन कार्यक्रम (CRP), पशु पोषण परामर्श सेवाएं (ANAS) एवं चारा विकास कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण शामिल हैं।

यह योजना दूध संकलन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने तथा गांव से उपभोक्ता तक की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में दूध की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसके अलावा, योजना के अंतर्गत मूल्य संवर्धित दूध उत्पादों के उत्पादन हेतु नई अवसंरचना की स्थापना का समर्थन किया जा रहा है तथा विपणन एवं आईसीटी अवसंरचना में पर्याप्त निवेश कर परिचालन को अधिक सुगम बनाया जा रहा है। उत्पादकता संवर्धन से संबंधित गतिविधियां जैसे बछड़ा पालन कार्यक्रम (CRP) एवं पशु पोषण परामर्श सेवाएं (ANAS), दूध उत्पादक पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने हेतु डेयरी किसानों में वैज्ञानिक आहार पद्धतियों को प्रोत्साहित करने पर केन्द्रित हैं। इसी प्रकार, चारा विकास गतिविधियों का उद्देश्य हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि करना तथा चारा संरक्षण प्रौद्योगिकियों एवं फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का व्यापक स्तर पर आयोजन किया जा रहा है, जिनमें दूध उत्पादक, क्षेत्रीय कर्मचारी, तकनीकी कार्मिक, अधिकारी तथा खुदरा विक्रेता जैसे विभिन्न हितधारकों को सम्मिलित किया गया है।

यह परियोजना लघु एवं सीमांत दुग्ध उत्पादकों को बेहतर आजीविका अवसर प्रदान करने, मूल्य श्रृंखला में दूध की गुणवत्ता सुधारने, सहभागी संस्थाओं के प्रसंस्करण अवसंरचना को सुदृढ़ करने, सहकारी ब्रांडों की बाजार पहुंच बढ़ाने तथा मानव संसाधन क्षमता का विकास करने में सहायक होगी।

डीटीसी की उपलब्धियां

गतिविधि / मापदंड	उपलब्धि
नई डेयरी सहकारी समितियों (DCS) का गठन	~4,900
AMCU/DPMCU की स्थापना	8,650
सदस्य के रूप में किसानों का कुल नामांकन	~1.26 लाख
महिला सदस्य	~92,000
अतिरिक्त दूध संकलन	~7.85 लाख कि.ग्रा./प्रतिदिन
ANAS के अंतर्गत शामिल पशुओं की संख्या	31,000
प्रशिक्षित किसानों की संख्या (स्वच्छ दूध उत्पादन, पशुपालन आदि में)	~2.0 लाख

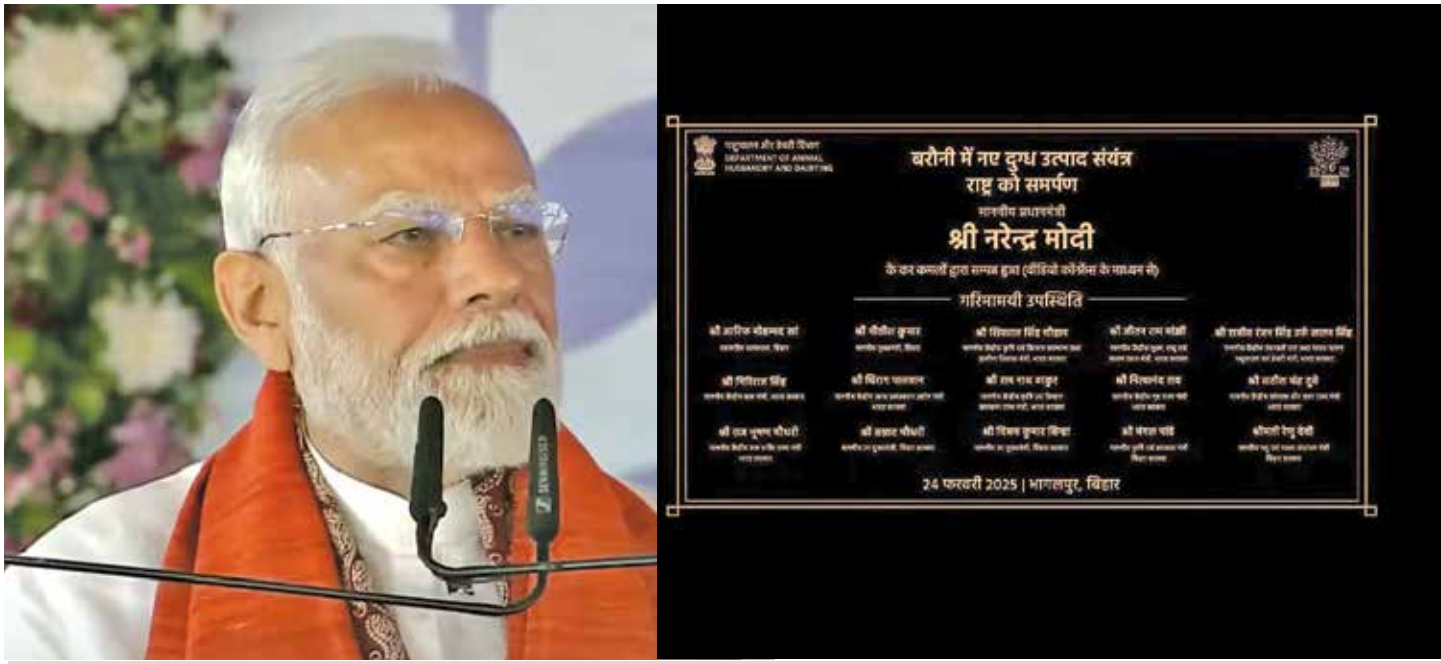

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में भारत सरकार की डीएएचडी योजना, डीआईडीएफ के अंतर्गत निर्मित बरौनी डेयरी के उत्पाद संयंत्र का उद्घाटन करते हुए

डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि (DIDF)

'डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि (DIDF)' भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की एक योजना है, जिसका कार्यान्वयन एनडीडीबी द्वारा वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक किया गया। वर्ष 2024-25 में भी प्रचलित परियोजनाओं के लिए ऋण वितरण की प्रक्रिया जारी रही। भारत सरकार, डीआईडीएफ योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों पर 2.5 प्रतिशत की दर से ब्याज सहायता उपलब्ध करा रही है।

मुख्य उपलब्धियां	प्रगति का सार
कुल वित्तीय परिव्यय	11184 करोड़ रुपये
• ऋण घटक	8004 करोड़ रुपये
• अंतिम ऋणियों का अंशदान	2001 करोड़ रुपये
• कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजना प्रबंधन एवं अधिगम योगदान	12 करोड़ रुपये
• भारत सरकार द्वारा ब्याज सहायता	1167 करोड़ रुपये
स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या (31 मार्च 2025 तक)	36 परियोजनाएं
• अनुमोदित कुल परिव्यय	6730.21 करोड़ रुपये
• स्वीकृत ऋण	4538.40 करोड़ रुपये
ऋण वितरण (वर्ष 2024–25 में)	482.37 करोड़ रुपये
संचयी ऋण वितरण (31 मार्च 2025 तक)	3599.75 करोड़ रुपये
पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या (31 मार्च 2025 तक)	17
निर्मित दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता (पूर्ण परियोजनाओं में)	10.44 मिलियन लीटर प्रतिदिन

भारत सरकार ने अवसंरचना विकास निधि (IDF) के अंतर्गत अब पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) की अवधि को 2025-26 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसमें डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि (DIDF) का भी इसमें विलय कर दिया गया है।

डेयरी सहकारिताओं को भी AHIDF योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान नमक्कल दूध संघ की एक परियोजना प्रस्ताव को AHIDF योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई, जिसके अंतर्गत एनडीडीबी ने 64 करोड़ रुपये का सावधि ऋण स्वीकृत किया। इस ऋण पर 31 मार्च 2025 तक वितरित राशि के आधार पर दूध संघ को 3 प्रतिशत की दर से 0.05 करोड़ रुपये का ब्याज सहायता का लाभ प्राप्त हुआ।

उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं को कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सहायता

कोविड-19 महामारी संबंधी प्रतिबंधों के दौरान, उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं (POI) के समक्ष आई चुनौतियों को देखते हुए, भारत सरकार के डीएएचडी ने वर्ष 2020-21 में "कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सहायता" योजना प्रारंभ की। इस योजना की अवधि को आगे बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक कर दिया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन एनडीडीबी द्वारा किया जा रहा है।

यह योजना, पात्र भागीदार एजेंसियों (PA) द्वारा बैंकों एवं वित्त संस्थानों से लिए गए कार्यशील पूंजी ऋण पर प्रतिवर्ष दो प्रतिशत ब्याज सहायता प्रदान करती है। जो एजेंसियां ऋण का समय पर और नियमित भुगतान करती हैं, उन्हें ऋण अदायगी अवधि के अंत में अतिरिक्त दो प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज सहायता दिया जाता है।

ब्याज सहायता का यह घटक योजना 'डेयरी गतिविधियों में संलग्न डेयरी सहकारी समितियों एवं किसान उत्पादक संगठनों को सहयोग (SDCFPO)' के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सहायता के माध्यम से, इस योजना ने उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं (POI) को अपने उत्पादक सदस्यों को समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाया।

प्रमुख उपलब्धियां	प्रगति सारांश
योजना का कुल परिव्यय	703.00 करोड़ रुपये
वित्त वर्ष 2024-25 तक जारी ब्याज सहायता राशि	650.75 करोड़ रुपये

एफपीओ का गठन एवं प्रोत्साहन

इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के गठन एवं प्रोत्साहन" के लिए एनडीडीबी को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, मार्च 2025 तक कुल 126 एफपीओ गठित किए जा चुके हैं, जिनमें 100 "फॉडर प्लस" एफपीओ तथा 26 मधुमक्खीपालक एफपीओ सम्मिलित हैं।

फॉडर प्लस" एफपीओ में अब तक 26,000 से अधिक किसान सदस्य जुड़ चुके हैं। एनडीडीबी द्वारा एफपीओ एवं क्लस्टर-आधारित व्यवसाय संगठनों (CBBOs) को क्षमता सुदृढ़ीकरण हेतु निरंतर तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। जानकारी एवं अनुभव के आदान-प्रदान के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए गए।

मार्च 2025 तक सीबीडीबीओ एवं एफपीओ से संबंधित 174 अधिकारियों को चारा उत्पादन एवं संरक्षण में प्रशिक्षित किया गया। 80 "फॉडर प्लस" एफपीओ ने हरे चारे, साइलेज, चारे के बीज, सूखा चारा, आहार एवं आहार संपूरक, स्टेम कटिंग इत्यादि के उत्पादन एवं विपणन संबंधी गतिविधियां प्रारंभ कर दी हैं।

एनडीडीबी द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत चारा बीज उत्पादन का प्रभावी समन्वय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के सदस्यों को उन्नत किस्मों के उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जा सके। क्षमता निर्माण की सतत् पहलों तथा क्लस्टर-आधारित व्यवसाय संगठनों (CBBO) एवं एफपीओ को प्रदान किए गए सहयोग के फलस्वरूप मार्च 2025 तक लगभग 40 करोड़ रुपये का संचयी कारोबार हुआ।

"मीठी क्रांति" को गति प्रदान करने हेतु एनडीडीबी डेयरी सहकारी नेटवर्क का उपयोग कर शहद मूल्य शृंखला स्थापित कर रही है। शहद एफपीओ में अब तक लगभग 5,500 किसान सदस्य जुड़ चुके हैं। दूध संघ सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं तथा एफपीओ सदस्यों द्वारा उत्पादित शहद के लिए अग्रिम बाज़ार संपर्क उपलब्ध कराते हुए उसे अपने स्थापित दूध ब्रांड्स के अंतर्गत लॉन्च कर रहे हैं। एनडीडीबी "राष्ट्रीय मधुमक्खीपालन एवं शहद मिशन" (NBHM) की कार्यान्वयन एजेंसी भी है और डेयरी सहकारिताओं तथा अन्य साझेदार संस्थाओं के साथ मिलकर आवश्यक मधुमक्खीपालन अवसंरचना की स्थापना कर रही है, जिसमें शहद परीक्षण प्रयोगशाला, प्रसंस्करण इकाई एवं मधुमक्खीपालन उपकरण सम्मिलित हैं। वर्तमान में कोलकाता में एक अत्याधुनिक क्षेत्रीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है।

फॉडर प्लस एवं मधुमक्खीपालन आधारित एफपीओ हेतु रणनीतिक वित्तीय सहायता योजना

किसान-उत्पादक संगठनों (FPO) को पूंजीगत निवेश को सुरक्षित करने और कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने में आने वाली गंभीर चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, एनडीडीबी ने फरवरी 2025 में एक रणनीतिक योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य पायलट के तौर पर 10-15 हाई पोटेंसियल एफपीओ को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि सस्टेनेबल और व्यवहार्य व्यावसायिक मॉडल विकसित किए जा सकें, जिन्हें बाद में देशभर में दोहराया जा सके।

इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता इस प्रकार से की गई है कि पूंजीगत संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए 50% अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, यह योजना विशेष रूप से चारे और मधुमक्खीपालन से संबंधित कार्यों के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराती है। योजना अन्य प्रासंगिक गतिविधियों के लिए, जो सीधे चारे या मधुमक्खीपालन से संबंधित नहीं हैं, ब्याजयुक्त ऋण के माध्यम से भी वित्तीय समर्थन प्रदान करती है।

इस योजना के लिए वित्तीय व्यय में अधिकतम एक बार अनुदान सहायता 100 लाख रुपये, अधिकतम एक बार बिना ब्याज का ऋण 100 लाख रुपये और अधिकतम ब्याजयुक्त ऋण 200 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।

इस पहल से उम्मीद है कि किसान-उत्पादक संगठन (FPO) अपने व्यावसायिक संचालन का विस्तार करेंगे और सफलतापूर्वक दोहराए जा सकने वाले व्यावसायिक मॉडल स्थापित करेंगे।

भारत पशुधन

भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग और एनडीडीबी ने राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (NDLM) के अंतर्गत देश में विभिन्न संगठनों द्वारा पशुपालन प्रबंधन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एंड-टू-एंड किसान-केंद्रित, प्रौद्योगिकी-सुलभ पूर्ण इको सिस्टम भारत पशुधन की स्थापना संयुक्त रूप से की गई है।

यह एक क्लाउड-बेस्ड इको सिस्टम है, जो क्षेत्रीय कर्मचारियों को, किसानों को प्रदान की गई सेवाओं को अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है, जैसे कि पशु पंजीकरण, किसान पंजीकरण, स्वामित्व में परिवर्तन, कृत्रिम गर्भाधान (AI), गर्भावस्था निदान, बछडे का जन्म, टीकाकरण, उपचार/ई-प्रिस्क्रिप्शन, रोग रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट, दूध रिकॉर्डिंग आदि। यह एप्लिकेशन पशुधन बाजार, क्लोज्ड लूप ब्रीडिंग, रोग निगरानी प्रणाली और पशु व पशु उत्पादों की पहचान और ट्रेसबिलिटी में सुधार पर भी विशेष ध्यान देता है।

यह एप्लिकेशन वर्तमान में देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियाशील है। भारत सरकार की पशुधन डेटा ट्रेसबिलिटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एनडीडीबी और हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान (NRCM) ने देश के पशुधन डेटाबेस की ट्रेसबिलिटी स्थापित करने, निगरानी करने और सत्यापित करने हेतु भारत पशुधन डेटाबेस का उपयोग करने से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस आवश्यकता को पूरा करने हेतु, कसाईघरों के लिए भारत पशुधन एप्लिकेशन में प्रावधान किया गया है, ताकि वे पशुओं के एंटिमॉर्टेम (ante-mortem) परीक्षण, पोस्टमॉर्टेम (post-mortem) परीक्षण, पशु वध आदि से संबंधित जानकारी अपलोड कर सकें।

भारत पशुधन एप्लिकेशन का क्रियान्वयन

एनडीएलएम / भारत पशुधन एप्लिकेशन का चरण- II प्रगति पर है, और इसके प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

- भारत पशुधन एप्लिकेशन के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 15 राज्यों (कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, केरल, ओडिशा, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू, कश्मीर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिज़ोरम, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना) द्वारा राज्य-स्तरीय परियोजना निगरानी इकाइयां स्थापित की गई हैं। शेष राज्यों के लिए यह प्रक्रिया प्रगति पर है।
- देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों में भारत पशुधन एप्लिकेशन के क्रियान्वयन के लिए तकनीकी और क्षेत्रीय समर्थन।

भारत पशुधन एप्लिकेशन को अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रभावी ढंग से अपनाया जाना सुनिश्चित करने हेतु, वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 70 क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को आयोजित किया गया।

क्र. सं.	प्रशिक्षण प्रकार	कार्यक्रमों की संख्या
1	भारत पशुधन एप्लिकेशन – ऑनलाइन प्रशिक्षण	41
2	भारत पशुधन एप्लिकेशन – ऑफलाइन प्रशिक्षण	29
3	पीएमयू प्रशिक्षण	5
4	ए-हेल्प प्रशिक्षण	10

भारत पशुधन एप्लिकेशन में कार्यात्मक सुधार

छोटे पशुधन जैसे भेड़, बकरी और सूअर के लिए प्रभावी सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित करने हेतु, भारत पशुधन एप्लिकेशन में विशेष फ्लॉक प्रबंधन कार्यक्षमता को शामिल किया गया है। यह सुविधा किसानों और सेवा प्रदाताओं दोनों के उपयोग के लिए विकसित की गई है।

भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, जैसे कि राष्ट्रीय दूध रिकॉर्डिंग कार्यक्रम (NMRP) और सुरभि चयन शृंखला (SCS), को भारत पशुधन एप्लिकेशन में सफलतापूर्वक शामिल किया गया है। ये पहलें, जिन्हें देशव्यापी स्तर पर डीएएचडी द्वारा लागू किया गया है, प्रजनन क्षेत्रों में श्रेष्ठ जर्मप्लाज्म की पहचान करने और दूध रिकॉर्डिंग के लिए प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण को संस्थागत बनाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही हैं।

राष्ट्रीय भारत पशुधन डेटाबेस, किसान और पशु संबंधी जानकारी का व्यापक कोष है, जो भारत सरकार के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए आधारभूत प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है और केंद्रीय एवं राज्य-स्तरीय योजनाओं के व्यापक डिजिटलीकरण की सुविधा प्रदान करता है।

''1962 फार्मर्स एप," जो भारत पशुधन डेटाबेस पर आधारित है, का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 2 मार्च 2024 को किया गया। यह एप्लिकेशन प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और किसान इसे अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। यह पशुधन किसानों के लिए एक केंद्रीकृत संसाधन के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें आवश्यक संसाधनों और जानकारी की सीधे पहुंच प्रदान करता है। इसमें सभी नजदीकी कृत्रिम गर्भाधान (AI) तकनीशियनों के संपर्क विवरण, आईवीएफ सेवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सीमन स्ट्रॉ की उपलब्धता, एथनोवेटनरी मेडिसिन पर जागरूकता संबंधी वीडियो और आहार संतुलन एप्लिकेशन शामिल हैं। यह एप्लिकेशन सेक्टर-विशेष योजनाओं और पहलों पर रियल टाइम अपडेट प्रदान करता है, जिससे किसान नवीनतम विकास की जानकारी सीधे प्राप्त कर सकें।

पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने देश में 25 अक्तूबर 2024 को 21वीं पशुधन आबादी गणना का शुभारंभ किया और यह पहली बार भारत पशुधन डेटाबेस पर निर्मित सेंसस ऐप के माध्यम से संपन्न हुई।

भारत पशुधन का लोगो, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के तहत डीएएचडी की झांकी में प्रदर्शित किया गया, जिसे 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ, नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया।

ये डिजिटल पहलें तकनीक-आधारित सेवा प्रदान करने और किसानों को सशक्त बनाने के प्रति एनडीडीबी की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

मुख्य सांख्यिकी

क्र.सं.	गतिविधि विवरण	कुल ट्रांजेक्शन की संख्या
1	पंजीकृत पशु	345437611
2	पंजीकृत पशु स्वामी	92942111
3	शामिल गांव	606978
4	शामिल जिले	766
5	शामिल संस्थाएं	267
6	निर्मित परियोजनाएं	398
7	उपचार ट्रांजेक्शन	2372138
8	टीकाकरण ट्रांजेक्शन	1081723918
9	निष्पादित कृत्रिम गर्भाधान (AI)	160129738
10	कार्विंग ट्रांजेक्शन	27279845
11	जन्मे बछड़े	12942079
12	शामिल वीर्य केन्द्र	82
13	कुल उपयोगकर्ता	474609
14	किसान ऐप उपयोगकर्ता	408949
15	डीवार्मिंग ट्रांजेक्शन	29247242
16	व्यक्तिगत आहर संतुलन ट्रांजेक्शन	27840446
17	दूध रिकॉर्डिंग (MR) ट्रांजेक्शन	15654756

भारत पशुधन एप्लीकेशन को प्रभावी ढंग से अपनाने पर प्रशिक्षण सत्र

गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन

एनडीडीबी डेयरी क्षेत्र में गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। 'क्वालिटी मार्क', जो गाय से उपभोक्ता तक प्रक्रिया प्रमाणन की एक राष्ट्रीय पहल है, वर्ष के दौरान जारी रही। अब तक, 118 आवेदकों में से 57 डेयरियों को गुणवत्ता चिह्न प्रदान किया जा चुका है। शेष डेयरियां, जो ISO 22000 / FSSC 22000 लागू कर चुकी हैं, सुधारात्मक उपायों को लागू करने की प्रक्रिया में हैं और अधिक डेयरी सहकारी संस्थाओं ने गुणवत्ता चिह्न अपनाने में अपनी रुचि व्यक्त की है।

एनडीडीबी ने भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) को दूध और दूध उत्पादों के लिए अनुरूपता मूल्यांकन योजना (CAS MMP) को लागू करने में तकनीकी सहायता प्रदान की। CAS MMP के तहत कुल 34 डेयरियों ने आवेदन किया, जिनमें से पांच ने स्टेज I और स्टेज II ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा कर प्रमाणन प्राप्त किया। 22 डेयरियां स्टेज I ऑडिट पूरा कर चुकी हैं और स्टेज II ऑडिट के लिए सुधारात्मक उपाय लागू कर रही हैं। गुणवत्ता चिह्न प्राप्त डेयरियों को CAS MMP अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

एनडीडीबी ने नियामक और वैज्ञानिक संस्थाओं, जिनमें डीएएचजी, एफएसएसएआई, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (CAC) और एफएओ शामिल हैं, को अपने समर्थन को जारी रखा। डेयरी बोर्ड अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन (INC-IDF) की भारतीय राष्ट्रीय समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करता है और वैश्विक डेयरी मंचों में भारत की भागीदारी का समन्वय करता है। विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व के माध्यम से BIS को तकनीकी सुझाव प्रदान किए गए। साथ ही, निर्यात अनुपालन के लिए डेयरी इकाइयों को प्रमाणित करने में निर्यात निरक्षण परिषद् को भी समर्थन प्रदान किया गया।

एनडीडीबी ने गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसमें प्रतिभागियों के रूप में दूध उत्पादक, डेयरी संयंत्र के कर्मचारी, सहकारी बोर्ड के सदस्य और नए नियुक्त कर्मचारी शामिल रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 'स्वच्छ दूध उत्पादन', 'गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा', और 'मानव सुरक्षा' शामिल थे।

एनपीडीडी की "सहकारिताओं के माध्यम से डेयरी" घटक के तहत वरिष्ठ डेयरी अधिकारियों को 5एस, Kaizen और क्वालिटी सर्किल जैसी तकनीकों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन प्रणालियों जैसे ISO 22000 (खाद्य सुरक्षा), ISO 14001 (पर्यावरण), ISO 50001 (ऊर्जा) और ISO 45001 (पेशेवर स्वास्थ्य) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इन मॉड्यूलों ने खाद्य सुरक्षा प्रणाली को अन्य प्रणालियों के साथ एकीकृत करने को बढ़ावा दिया, जिससे सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित हुई।

एनडीडीबी ने डेयरी सहकारिताओं को प्रक्रियागत सुधार, तकनीकी हस्तक्षेप और प्रणाली परिचय के माध्यम से संचालनात्मक दक्षता बढ़ाने में समर्थन जारी रखा। डेयरी संयंत्रों में किए गए अध्ययन से मिल्कफेड, पंजाब को लक्षित क्रियाकलापों के माध्यम से दूध के ठोस पदार्थ और पैकेजिंग सामग्री में होने वाली हानि को स्वीकार्य स्तर तक कम करने में मदद मिली।

एनडीडीबी ने परीक्षण में सटीकता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्नत और त्वरित परीक्षण उपकरणों के परिचय के साथ प्रयोगशाला आधुनिकीकरण पर अध्ययन किए। तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करते हुए, एनडीडीबी ने डीएएचडी को हितधारकों की सलाह के साथ त्वरित विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला उपकरणों के विनिर्देशों के निर्माण और अंतिम रूप देने में सहायता की।

इन प्रयासों ने तकनीकी हस्तक्षेप, क्षमता विकास और सहयोगों के माध्यम से सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पादन सुनिश्चित करने के प्रति एनडीडीबी की प्रतिबद्धता को दर्शाया।

गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा पर आयोजित प्रशिक्षण सत्र

श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत सहकारी कवरेज का विस्तार - "सहकार-से-समृद्धि" के विज़न को साकार करना

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने में सहकारी संस्थाओं की भूमिका केंद्रीय मानी जाती है। विशेषकर कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों में ये संस्थाएँ समावेशी और संतुलित विकास को प्रेरित करके सतत् परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करती हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग कर उन्हें कुशल एवं प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक संस्थाओं में रूपांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया है, जो 'सहकार-से-समृद्धि' के विज़न के अनुरूप है।

श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री; माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी; और श्री मुरलीधर मोहोल जी, माननीय केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री, मार्गदर्शिका (SOP) के विमोचन के दौरान

सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने तथा इसकी पहुंच को जमीनी स्तर तक ले जाने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच वर्षों की अवधि में देश के सभी पंचायतों/गांवों को कवर करते हुए 2 लाख नई बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (MPACS), डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की योजना को अनुमोदित किया है। यह पहल 'होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच' के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) तथा राज्य सरकारों के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है।

भारत सरकार के विज़न के अनुरूप, सहकारिता मंत्रालय ने मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के साथ मिलकर 'श्वेत क्रांति 2.0 (WR 2.0)' की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य एक सहकारिता-आधारित मॉडल स्थापित करना है, जो मजबूत, समावेशी एवं सस्टेनेबल डेयरी इकोसिस्टम का निर्माण करे। श्वेत क्रांति 2.0 का प्रमुख लक्ष्य सहकारी क्षेत्र द्वारा संकलित दूध की मात्रा में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि करना है, जिसे वर्तमान 660 लाख किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2028–29 तक 1,000 लाख किलोग्राम प्रतिदिन तक ले जाना है। इस राष्ट्रीय पहल के क्रियान्वयन में एनडीडीबी को प्रमुख हितधारक के रूप में नामित किया गया है।

2 लाख नई बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (MPACS) और डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों के गठन तथा सुदृढ़ीकरण हेतु सितंबर 2024 में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी तथा माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी ने मार्गदर्शिका (मानक प्रचालन पद्धति) का विमोचन किया। माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने दिसंबर, 2024 में श्वेत क्रांति 2.0 का औपचारिक शुभारंभ किया।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हितधारकों के बीच समन्वय की समग्र जिम्मेदारी एनडीडीबी को सौंपी गई है। श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत निम्नलिखित परिकल्पना की गई है:

श्वेत क्रांति 2.0 – वर्षवार विवरण:

	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	कुल
नई डीसीएस	13973	18115	13707	15136	14069	75000
सुदृढ़ीकरण	4642	13925	11607	9285	6963	46422

दूध संकलन लक्ष्य:

प्रमुख मापदंड	आधार वर्ष (2023-24)	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
सहकारी दूध प्रसंस्करण (एलकेजीपीडी)	660	720	780	847	923	1007

श्वेत क्रांति 2.0 को लागू करने हेतु, एनडीडीबी ने 1000 MPACS/MDCS की स्थापना का समर्थन करने हेतु एक योजना प्रारंभ की, जिसके तहत प्रत्येक MPACS/MDCS को 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस योजना के अंतर्गत, मार्च 2025 तक एनडीडीबी ने आठ राज्यों-असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 13 दूध संघों और एक दूध उत्पादक संगठन के लिए कुल 15 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। लक्षित 1,000 MPACS/MDCS में से कुल 893 MPACS/MDCS को समर्थन हेतु अनुमोदित किया गया, जिसकी अनुमानित कुल लागत 3.59 करोड़ रुपये है। रिपोर्टिंग अवधि तक, 388 MPACS/MDCS ने दूध संकलन संचालन आरंभ कर दिया है, और 8,653 सदस्य उत्पादकों से प्रतिदिन लगभग 46,000 लीटर दूध संकलित किया जा रहा है।

राज्यों में श्वेत क्रांति 2.0 के कार्यान्वयन को गति देने के लिए, एनडीडीबी ने सेंसिटाइज़ेशन वर्कशॉप्स आयोजित कीं और विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने में डेयरी सहकारिताओं को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। इस अवधि के दौरान, श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत 12,756 नई डीसीएस का गठन किया गया और 11,871 मौजूदा डीसीएस को सुदृढ़ किया गया।

इसके अलावा, श्वेत क्रांति 2.0 में बहुउद्देशीय डीसीएस और ग्राम सहकारी समितियों की स्थापना की परिकल्पना की गई है जो सदस्य किसानों को अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करेंगी, जिनमें माइक्रो-एटीएम सुविधाओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं, वेयरहाउसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और अन्य संबद्ध सहायक सेवाएं शामिल हैं।

श्वेत क्रांति 2.0 के देशव्यापी क्रियान्वयन से डेयरी सहकारी नेटवर्क को मजबूती मिलने की संभावना है। यह कार्यक्रम न केवल डेयरी मूल्य श्रृंखला में विकास को गति देगा, बल्कि विभिन्न स्तरों पर रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगा और उन महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को सशक्त करेगा, जो प्राथमिक डेयरी पशुपालन में अहम भूमिका निभाती हैं।

श्वेत क्रांति 2.0 का उद्देश्य छोटे डेयरी उत्पादकों के लिए व्यवस्थित बाजार पहुंच सुनिश्चित करना है, जिससे उन्हें उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारण तंत्र के साथ-साथ वर्ष भर दूध विपणन का भरोसेमंद चैनल प्राप्त हो। इन प्रयासों के माध्यम से डेयरी उद्योग में संगठित क्षेत्र का हिस्सा बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जो वर्तमान में मुख्यतः असंगठित हितधारकों के प्रभुत्व में है।

श्वेत क्रांति 2.0 को भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा क्रियान्वित संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। एनपीडीडी के अंतर्गत, ग्रामीण स्तर पर दूध संकलन प्रणालियों की स्थापना, क्रय में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु मिल्क चिलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ हितधारकों के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण पहलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

बहुउद्देशीय डेयरी सहकारी समितियों की उप विधियां

डेयरी सहकारी समितियों की मौजूदा उप विधियां केवल डेयरी और संबद्ध गतिविधियों में भागीदारी की अनुमति देती हैं। चूंकि श्वेत क्रांति 2.0 में बहुउद्देशीय डेयरी सहकारी समितियों का गठन शामिल है, इसलिए एनडीडीबी ने बहुउद्देशीय डेयरी सहकारी समितियों के लिए उप विधियां तैयार की हैं जिनमें संबद्ध किसान सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न होने के प्रावधान शामिल हैं।

इस बहुउद्देशीय डेयरी सहकारी समितियों की उप विधियों के निर्माण के पीछे की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि डेयरी व्यवसाय ही बहुउद्देशीय डेयरी सहकारी समितियों का प्राथमिक कार्य रहेगा, लेकिन इसके दायरे में इसके सदस्यों के लाभार्जन के लिए अन्य गतिविधियां भी शामिल होंगी। डेयरी सहकारी समितियों की गतिविधियों का दायरा बढ़ाकर इसमें कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन, नवीकरणीय ऊर्जा, बायोगैस, गोदाम, वेयरहाउस आदि गतिविधियां शामिल की गई हैं। बहुउद्देशीय डेयरी सहकारी समितियों में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए, सक्रिय सदस्यता, पूंजीगत निर्माण और पेशेवर प्रबंधन से संबंधित कुछ सहायक विशेषताएं शामिल की गई हैं। राज्यों को प्रसारित करने के लिए इन उप विधियां को सहकारिता मंत्रालय के साथ साझा किया गया है।

बहु-राज्यीय सहकारी समितियां

"लोकल-टू-ग्लोबल" विज़न और "सहकार-से-समृद्धि" के राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुरूप, भारत सरकार ने जनवरी 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर बहु-राज्यीय सहकारी समितियों की स्थापना की। इनमें राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) शामिल हैं।

राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL)

एनडीडीबी ने एनसीओएल को समर्थन देना निरंतर जारी रखा, जो मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 2002 के तहत पंजीकृत है और ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन में संलग्न सहकारिताओं के लिए अम्ब्रेला संगठन के रूप में कार्य करता है। एनडीडीबी, एनसीओएल की प्रमुख प्रमोटर है और एनडीडीबी के अध्यक्ष इसके भी अध्यक्ष हैं। अन्य प्रमोटरों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF), GCMMF, और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (NAFED) शामिल हैं।

वर्ष के दौरान, एनसीओएल ने प्राथमिक, जिला और राज्य स्तर पर 7,086 सदस्य समितियों को पंजीकृत किया, जो लगभग 50 लाख किसानों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऑर्गेनिक उत्पादों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को सुदृढ़ करने हेतु एनसीओएल ने प्रत्यक्ष बाजार पहुंच सुनिश्चित करने, उत्पादों को एकीकृत ब्रांड के अंतर्गत स्थापित करने तथा उनकी उपलब्धता को घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है।

'भारत ऑर्गेनिक' ब्रांड के अंतर्गत, एनसीओएल ने 13 नए प्रमाणित ऑर्गेनिक उत्पाद लॉन्च किए, जिससे कुल उत्पाद संख्या बढकर 24 हो गई। विस्तारित उत्पाद सूची में प्रमुख उपभोग्य वस्तुएं जैसे - गेहूं आटा, ब्राउन शुगर, गुड़ पाउडर, गुड़ की डली, खांडसारी शुगर, चना दाल, काला चना, काबुली चना, तूर/अरहर दाल, मूंग दाल, टुकडा मूंग, साबुत मूंग, साबुत उड़द, टुकडा उड़द, उड़द गोटा, उड़द दाल, राजमा चित्रा, मसूर मालका, साबुत मसूर, टुकडा मसूर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, साबुत धनिया और मेथी शामिल हैं।

ये उत्पाद सफल आउटलेट्स, जनरल रिटेल स्टोर और प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे Blinkit, Swiggy, Amazon, Big Basket और Flipkart पर उपलब्ध कराए गए। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रा. लि. के साथ वितरण समझौता किया गया। एनसीओएल ने उपभोक्ताओं की पहुंच बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए देशव्यापी वितरण का विस्तार करने की योजना आरंभ की।

अपनी पहुंच को मजबूत करने के लिए, एनसीओएल ने 14 राज्यों की नोडल एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इन साझेदारियों के माध्यम से 'भारत ऑर्गेनिक' ब्रांड के तहत क्षमता निर्माण, तकनीकी समर्थन और बाजार संबंध स्थापित किए गए।

निर्यात और वैश्विक ऑर्गेनिक उत्पाद संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए, एनसीओएल ने एनसीईएल के साथ रणनीतिक साझेदारी की। इसके

श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, एनसीओएल के भारत ऑर्गेनिक होल व्हीट आटे के शुभारंभ के दौरान, जिसमें श्री भूपेंद्र पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात; श्री शंकरभाई चौधरी, अध्यक्ष, गुजरात विधानसभा; श्री मुरलीधर मोहोल जी, माननीय केंद्रीय सहकारी राज्य मंत्री, सहकारिता मंत्रालय और श्री जगदीश विश्वकर्मा जी, माननीय सहकारी राज्य मंत्री, गुजरात सरकार उपस्थित रहे

साथ ही, एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनडीडीबी मृदा लि. के साथ सहयोग किया गया, ताकि ऑर्गेनिक इनपुट आपूर्ति और ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा दिया जा सके।

एनसीओएल द्वारा इंटर्नल कंट्रोल सिस्टम (ICS) का गठन और ऑर्गेनिक कृषि पद्धतियों पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इन क्षमता निर्माण पहलों से किसान स्तर पर जागरूकता बढ़ी और प्रमाणित ऑर्गेनिक क्लस्टरों के गठन में सहायता मिली। मानकीकृत ऑर्गेनिक प्रमाणन को कई राज्यों में प्रोत्साहित करने हेतु इन कार्यक्रमों का विस्तार करने की योजनाएं तैयार की गईं।

भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL)

बीबीएसएसएल भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का सहकारी संगठन है, जो विशेष रूप से बीज सेक्टर के लिए स्थापित किया गया है। इसे सहकारिता मंत्रालय द्वारा बनाया गया और इसकी स्थापना में इफको, कृभको, नेफेड, एनसीडीसी और एनडीडीबी शामिल हैं। एनडीडीबी के अध्यक्ष बीबीएसएसएल के बोर्ड के सदस्य भी हैं।

बीबीएसएसएल का लक्ष्य सहकारी नेटवर्क के माध्यम से गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन बढ़ाना है। इसका उद्देश्य आयात पर

एनडीडीबी के हीरक जयंती समारोह के अवसर पर, आणंद में एनसीओएल और मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रा. लि. के बीच समझौते का आदान-प्रदान

डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी और श्री चेतन जोशी, प्रबंध निदेशक, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL), डॉ. आशीष कुमार भूटानी, सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की उपस्थिति में एमओयू का आदान-प्रदान करते हुए

निर्भरता कम करना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करना और आत्मनिर्भर भारत में योगदान देना है।

इस वर्ष, बीबीएसएसएल ने 13 राज्यों में 76,000 क्विंटल से अधिक प्रमाणित बीज वितरित किए और 6,500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बीज उत्पादन का विस्तार किया। संगठन ने 55.25 करोड़ रुपये की आय दर्ज की। बीबीएसएसएल को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) और एनएलएम जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत केन्द्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामांकित किया गया। इसके शेयरधारक आधार में वृद्धि हुई और यह 20,000 से अधिक किसानों तक पहुंच गया है, जो मजबूत किसान सहभागिता को दर्शाता है।

बीबीएसएसएल ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (ICRISAT) और एनडीडीबी जैसी संस्थाओं के साथ रणनीतिक साझेदारी की। पारंपरिक और वेजिटेबल सीड सेगमेंट्स को बढ़ावा देने हेतु एक विशेष विभाग भी स्थापित किया गया, जिससे सस्टेनेबिलिटी और वैरायटल डाइवर्सिटी को बढ़ावा मिल सके।

एनडीडीबी के अध्यक्ष और बीबीएसएसएल के प्रबंध निदेशक ने डॉ. आशीष कुमार भूटानी, सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की उपस्थिति में, डेयरी सहकारिताओं को चारा बीजों की थोक आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य डेयरी सहकारिताओं, दूध उत्पादक संगठनों, पैक्स और फॉडर प्लस एफपीओ के नेटवर्क के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बीज के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु एक अनुकूल वातावरण सृजित करना है। इस समझौते से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी, गुणवत्ता मानकों को बनाए रखा जाएगा, डेयरी सहकारिताओं को सलाह दी जाएगी और बीबीएसएसएल की गतिविधियों तथा 'भारत बीज' ब्रांड के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी।

बीबीएसएसएल ने एनडीडीबी के स्वावलंबी, किसान-केंद्रित ग्रामीण विकास मिशन के अनुरूप, एक मजबूत सहकारी बीज इकोसिस्टम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

प्रस्तावित बहु-राज्यीय सहकारी समितियां

डीएएचडी द्वारा आयोजित "डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी एवं सर्कुलैरिटी पर कार्यशाला" के दौरान माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने महत्वपूर्ण रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान किया। उनके मार्गदर्शन के मुख्य बिंदु -सहकारी ढांचे में अधिक किसानों को शामिल करते हुए इनपुट सेवाओं की पहुंच का विस्तार करना, मृत गाय एवं भैंसों के अवशेषों के उपयोग हेतु वैज्ञानिक रोडमैप विकसित करना तथा उन्नत गोबर प्रबंधन के माध्यम से डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलैरिटी को सुदृढ़ करना है।

इस मार्गदर्शन के अनुरूप और कार्यशाला के ठोस परिणाम के रूप में, एनडीडीबी बहु-राज्यीय सहकारी समितियों की स्थापना हेतु सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। इन समितियों का उद्देश्य सहकारी समितियों के नेतृत्व वाली संस्थाओं के माध्यम से इन गतिविधियों को मूर्त रूप देना है। ये सहकारिताएं, प्राथमिक सहकारी समितियों को व्यापक तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जिसमें मौजूदा या नई सुविधाओं से अनुकूलित पशु आहार और आहार संपूरक का उत्पादन, आहार और साइलेज के लिए एक राष्ट्रीय

आपूर्ति ग्रिड का निर्माण और विभिन्न दूध शेडों में प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों और कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं की तैनाती शामिल है।

अंततः, ये सहकारिताएं ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने और सहकारी ढांचे के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में हैं।

डेयरी सहकारी समितियों (DCS) के कवरेज विस्तार पर कार्यशाला

एनडीडीबी ने "देश में डीसीएस के कवरेज का विस्तार" विषय पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया। इस अवसर पर डेयरी क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया, जिनमें भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, एनडीडीबी, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, डेयरी आयुक्त, राज्य दूध महासंघों के प्रबंध निदेशक तथा दूध उत्पादक संगठनों (MPO) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) शामिल रहे।

एनडीडीबी ने डेयरी सहकारी कवरेज के विस्तार हेतु सफल सहकारी मॉडलों को अपनाए जाने की महत्ता पर बल दिया और इसके लिए एक व्यापक कार्ययोजना विकसित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। परिचर्चा में किसानों की आय वृद्धि में डेयरी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया, विशेष रूप से महिला सदस्यों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रतिभागियों ने ग्राम-स्तरीय अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने में एनडीडीबी की योजनाओं और गतिविधियों, विशेषकर राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) के सकारात्मक प्रभाव को भी स्वीकार किया। सर्वसम्मति से यह निष्कर्ष निकला कि सभी संभावित गांवों में डेयरी सहकारिताओं का सार्वभौमिक कवरेज अनिवार्य है।

हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के अब तक अनाच्छादित क्षेत्रों में की गई पायलट पहलों की सफलताओं के आधार पर, एनडीडीबी ने आधिकारिक रूप से एक नई योजना शुरू की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दूध संघों और एमपीओ के माध्यम से 1,000 बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारी समितियों (MPAC) को समर्थन प्रदान करना है। सभी राज्यों को इस योजना में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया गया, ताकि 'सहकार से समृद्धि' के राष्ट्रीय विज़न को साकार किया जा सके।

इस कार्यशाला ने श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मार्गदर्शिका के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो डेयरी क्षेत्र में सहकारी-नेतृत्व विकास को बढ़ावा देने के एनडीडीबी के प्रयासों के अनुरूप है।

डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी, "देश में डेयरी सहकारी समितियों के कवरेज का विस्तार" विषयक कार्यशाला में अपने संबोधन के दौरान, जिसमें डॉ. आशीष कुमार भूटानी, सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार; सुश्री वर्षा जोशी, अपर सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार; और श्री पंकज बंसल, अपर सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार उपस्थित रहे

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह जी, "अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025" के लिए वार्षिक गतिविधियों के कैलेंडर का विमोचन करते हुए, जिसमें माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, सहकारिता, श्री मुरलीधर मोहोल जी; महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री, श्री एकनाथ शिंदे जी और श्री अजीत पवार जी; तथा महाराष्ट्र सरकार के सहकारिता मंत्री, श्री बाबासाहेब मोहनराव पाटिल जी उपस्थित रहे

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC) 2025 का उत्सव

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC) 2025 के उपलक्ष्य में, एनडीडीबी ने कई पहलें प्रारंभ की है। "सहकारी समितियां एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं" इस वर्ष की थीम है, जो सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहकारिता की प्रासंगिकता को रेखांकित करती है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन के दौरान आईवाईसी 2025 का औपचारिक शुभारंभ किया।

एनडीडीबी ने डेयरी किसानों में जागरूकता बढ़ाने और सहकारिता की भावना को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न आउटरीच गतिविधियों का आयोजन किया। इन पहलों का उद्देश्य ग्रामीण भारत में सहकारी ढांचे की पहुंच को और विस्तृत करना भी है। एनडीडीबी ने कुल 587 कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें लगभग 23,000 प्रतिभागियों के लिए ग्राम-स्तरीय प्रशिक्षण सत्र शामिल रहे। इन प्रयासों से समावेशी ग्रामीण विकास को गति देने में सहकारिताओं की भूमिका को सुदृढ़ करने के प्रति एनडीडीबी की प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई।

"व्हील्स ऑफ कोऑपरेशन" अभियान के माध्यम से 71वें अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह का आयोजन

एनडीडीबी ने "विकसित भारत के निर्माण में सहकारिताओं की भूमिका" विषय पर "व्हील्स ऑफ कोऑपरेशन" पहल के अंतर्गत एक सहकारी अभियान का आयोजन किया। इस अभियान में अमूल डेयरी, बड़ौदा डेयरी, सुमुल डेयरी, अमिधारा फ्रूट एंड वेजिटेबल कोऑपरेटिव लिमिटेड (वलसाड), गोदावरी-खोरे दूध संघ (कोपरगांव), और सह्याद्री फार्म्स (नासिक) जैसी संस्थाओं ने भागीदारी की। इस अभियान का उद्देश्य अंतर-क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहकारी प्रयासों के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। एनडीडीबी ने प्रतिभागियों के बीच संवाद की सुविधा प्रदान की, जिससे नॉलेज शेयरिंग, सस्टेनेबल पद्धतियों को अपनाने और सर्कुलर इकोनॉमी के समाधानों को प्रोत्साहन मिला।

इस अवधि के दौरान आयोजित प्रदर्शनों और परिचर्चाओं में संपूर्ण मिश्रित आहार(TMR) खिलाने की उत्तम पद्धतियां, सिंचाई हेतु नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, कुशल खाद कम्पोस्टिंग तकनीकें तथा ऑर्गेनिक इनपुट्स द्वारा मृदा समृद्धि पर विशेष बल दिया गया। यह रणनीतिक पहल बहु-क्षेत्रीय सहकारिताओं की उस महत्वपूर्ण क्षमता को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करती है, जो समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने, ग्रामीण आय बढ़ाने और पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने में सहायक है।

डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी, गुजरात के आणंद जिले में मुजकुवा गांव की डेयरी, खाद, ऑर्गेनिक और सौर सहकारी समितियों के लीडर और सदस्यों के साथ

मुजकुवा ऑर्गेनिक किसान सहकारी मंडली लिमिटेड का पंजीकरण एवं प्रमाणन

एनडीडीबी ने मुजकुवा गांव में मुजकुवा ऑर्गेनिक किसान सहकारी मंडली लिमिटेड के पंजीकरण की सुविधा प्रदान की और 21 किसानों को संस्थापक सदस्य के रूप में नामांकित किया। सभी सदस्यों को पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम (PGS) के अंतर्गत प्रथम वर्ष का ऑर्गेनिक प्रमाणन प्रदान किया गया।

पंजीकरण प्रमाणपत्र का वितरण एक औपचारिक कार्यक्रम में किया गया, जिसमें माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी; पशुपालन एवं डेयरी विभाग की अपर सचिव सुश्री वर्षा जोशी; तथा एनडीडीबी के अध्यक्ष श्री मीनेश शाह उपस्थित रहे।

इस पहल ने ग्राम-स्तर पर ऑर्गेनिक कृषि के लिए सहकारी ढांचे की नींव रखी। इससे प्रमाणित उत्पादों के सामूहिक विपणन, प्रीमियम बाजारों तक बेहतर पहुंच, उचित मूल्य प्राप्ति, सस्टेनेबल कृषि को बढ़ावा, मृदा स्वास्थ्य सुधार और खाद्य सुरक्षा सुदृढ़ होने की संभावना है। ये गतिविधियां उन गांवों के लिए अपनाई जा सकने वाली कार्यप्रणाली भी प्रस्तुत करती है, जो ऑर्गेनिक कृषि की ओर उन्मुख हैं और एनडीडीबी के सस्टेनेबल लक्ष्यों के अनुरूप है।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन सिंह जी, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री; सुश्री वर्षा जोशी, अपर सचिव, डीएडीएच; तथा डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी, सहकारी पंजीकरण प्रमाणपत्र उसके सदस्यों को प्रदान करते हुए

डेयरी सहकारिताओं का पेशेवर प्रबंधन और समर्थन

एनडीडीबी पिछले छह दशकों से करोड़ों डेयरी किसानों की आजीविका में सुधार लाने के लिए उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं को सहायता कर और बढ़ावा देकर देश में डेयरी क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राज्य सरकारों के विशेष अनुरोध पर, एनडीडीबी देश के विभिन्न भागों में प्रबंधन और डेयरी विकास गतिविधियां संचालित कर रही है। एनडीडीबी वर्तमान में झारखंड दूध महासंघ (JMF), वाराणसी दूध संघ, पश्चिमी असम दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (WAMUL), पूर्वी असम दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (EAMUL), नॉर्थ ईस्ट डेयरी एंड फूड्स लिमिटेड (NEDFL), विदर्भ मराठवाड़ा डेयरी विकास परियोजना (VMDDP), लद्दाख डेयरी सहकारी संघ लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित और महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित के संचालन का प्रबंधन कर रही है।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

झारखंड दूध महासंघ (JMF)

एनडीडीबी अप्रैल 2014 से झारखंड राज्य सहकारी दूध उत्पादक महासंघ लिमिटेड (JMF) के संचालन का प्रबंधन कर रही है। एनडीडीबी और झारखंड सरकार के बीच हुए समझौता ज्ञापन के पिछले ग्यारह वर्षों के दौरान, राज्य में डेयरी विकास के प्रमुख मापदंडों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

राज्य में डेयरी विकास के प्रमुख मापदंड

विवरण	इकाई	(आधार वर्ष) 2013-14	2024-25
दूध पूलिंग प्वाइंट / डेयरी सहकारी समितियां	संख्या	261	1147
शामिल किए गए गांव	संख्या	261	3409
सक्रिय दूध प्रदात्ता	संख्या	2335	64563
दूध संकलन	टीकेजीपीडी	11.48	203.24
दूध बिक्री	टीएलपीडी	11.09	177.72
दूध बिल भुगतान (डीबीटी के माध्यम से)	करोड़ रुपये	8.92	278.6
कुल कारोबार	करोड़ रुपये	-	441

महासंघ ने भारतीय डेयरी एसोसिएशन (IDA) से 2 एलएलपीडी से कम श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पैकेजिंग का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, जिसमें उसकी 1 एमएल की रबड़ी (80 ग्राम) और गुलाब जामुन (250 ग्राम) की पैकिंग की सराहना की गई। वर्ष के दौरान एनपीडीडी के तहत अत्याधुनिक केंद्रीय प्रयोगशाला की स्थापना भी पूरी की गई।

एनडीडीबी और सस्टेन प्लस की मदद से, जेएमएफ गोबर गैस संयंत्रों के 100 यूनिटों के माध्यम से एक खाद प्रबंधन परियोजना चला रहा है और सभी यूनिटें संचालित हैं। इस पहल से एक ओर ग्रामीण महिलाओं के परिश्रम में कमी आई है, वहीं दूसरी ओर नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग हो रहा है और बायोगैस स्लरी से सीधे गांव स्तर पर ऑर्गेनिक खाद का उत्पादन हो रहा है, जिसका उपयोग उनके खेतों में किया जा रहा है, जिससे कार्बन फुटप्रिंट में कमी आ रही है। अतिरिक्त स्लरी को इसके स्लरी प्रोसेसिंग प्लांट में ऑर्गेनिक उर्वरक में परिवर्तित किया जा रहा है।

जेएमएफ, भारत सरकार के आरजीएम के तहत ABIP-IVF-ET परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सेक्स-सॉर्टेड सीमन के माध्यम से 90 प्रतिशत शुद्धता के साथ उच्च आनुवंशिक क्षमता वाली मादा बछड़ों का उत्पादन करना है, जिससे

कम समय में दूध उत्पादन बढ़ाया जा सके। मार्च 2025 तक, जेएमएफ द्वारा इस नवीनतम तकनीक के माध्यम से चयनित ग्राही पशुओं में से 27 को गाभिन किया गया।

जेएमएफ द्वारा रांची और लोहारदगा जिलों में 2 चारा एफपीओ और 2 हनी एफपीओ का पंजीकरण किया गया और इनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियां 2024-25 में प्रारंभ की गई।

रांची स्थित मदर डेयरी में बची हुई मटर की फली से ईपीपी साइलेज उत्पादन के लिए एक पायलट परियोजना की शुरूआत की गई। इस पायलट परियोजना के तहत 53.76 एमटी ईपीपी साइलेज का उत्पादन किया गया और उसकी बिक्री की गई। परियोजना के अधिक विस्तार के लिए, टाटा ट्रस्ट द्वारा जेएमएफ का समर्थन करने के लिए एक परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

झारखंड राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (JSIA) ने राज्य में कृत्रिम गर्भाधान (AI) गतिविधियों को और सशक्त बनाने के लिए एआई गतिविधियों का संचालन किया। जेएमएफ ने एनडीएस के माध्यम से झारखंड के 12 जिलों में अपने 501 एआई केंद्रों में 74000 से अधिक एआई निष्पादित किए।

वाराणसी दूध संघ

वर्ष 2024–25 के दौरान, एनडीडीबी ने वाराणसी दूध संघ का प्रबंधन निरंतर जारी रखा। एनडीडीबी के प्रबंधन में, संघ ने नई डेयरी सहकारी समितियों (DCS) की स्थापना और अधिक गांवों को कवर करके दूध संकलन में लगभग 100 प्रतिशत (CAGR) वार्षिक वृद्धि दर्ज की। वित्त वर्ष 2024-25 में उत्पादकों को दिए गया औसत दूध संकलन मूल्य 43.93 रुपये प्रति किलोग्राम रहा, जो अधिग्रहण के समय निर्धारित 31.30 रुपये प्रति किलोग्राम की तुलना में उल्लेखनीय 40 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है। दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दूध संकलन और चिलिंग सुविधाओं को और सशक्त बनाया गया, जिसमें 250 डेटा प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट (DPMCU), 15 ऑटोमेटेड मिल्क कलेक्शन यूनिट (AMCU) और 15 बल्क मिल्क कूलर (BMCU) स्थापित किए गए। सदस्य किसानों को प्रदान की जाने वाली इनपुट सेवाओं में पशु आहार, क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण और आहार संपूरक की किफायती दरों पर आपूर्ति शामिल है।

डेयरी विकास के प्रमुख मापदंड

विवरण	इकाई	(आधार वर्ष) 2021-22	2024-25
दूध संकलन केंद्र / डेयरी सहकारी समितियां	संख्या	238	532
शामिल किए गए गाँव	संख्या	238	532
सक्रिय दूध प्रदाता	संख्या	6400	17350
दूध का संकलन	टीकेजीपीडी	9.7	96.7
दूध की बिक्री	टीएलपीडी	9.2	20.6
दूध बिल भुगतान (डीबीटी के माध्यम से)	करोड़ रुपये	11.07	155.1
कुल कारोबार	करोड़ रुपये	25.34	206.1

डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी, श्री मनोज कुमार सिंह, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को वाराणसी दूध संघ की प्रगति के बारे में अवगत कराते हुए

वर्ष 2024–25 के दौरान, संघ ने 'पराग' ब्रांड के तहत प्रतिदिन औसतन 20 हजार लीटर (TLPD) पैक्ड लिक्विड दूध का विपणन किया, जबकि अधिग्रहण के समय यह मात्रा 9.25 टीएलपीडी थी। इसके साथ ही पनीर, घी, दही और लस्सी जैसे मूल्यवर्धित उत्पाद भी विपणन किए गए। वर्ष 2024–25 में वार्षिक कारोबार 206 करोड़ रुपये तक बढ़ गया, जो पिछले वर्ष के 172 करोड़ रुपये की तुलना में 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, एनडीईआरपी प्रोडक्शन मॉड्यूल के कार्यान्वयन की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य संयंत्र स्तर पर संचालन को स्वचालित करना और उत्पादन को अन्य संघ-स्तरीय प्रक्रियाओं के साथ एकीकृत करना है, ताकि संचालन क्षमता में सुधार हो सके।

एनडीडीबी से संघ ने निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्राप्त की :

- नए फर्मेंटेड उत्पाद संयंत्र से संबंधित सिविल कार्यों के लिए ब्याज-मुक्त ऋण राशि 1,150 लाख रुपये।
- अवसंरचना विकास के लिए ब्याज-मुक्त ऋण राशि 97.77 लाख रुपये।
- "रिवाइटलाइजिंग प्रॉमिसिंग प्रोड्यूसर्स ओन्ड इंस्टिट्यूशन्स" योजना के तहत ब्याज-मुक्त राशि 164.67 लाख रुपये ऋण और 34.33 लाख रुपये की अनुदान राशि ।
- "उत्पादक-स्वामित्व वाले संस्थानों के विपणन परिचालनों के सुदृढ़ीकरण हेतु समर्थन" योजना के तहत अनुदान राशि 12.90 लाख रुपये।

इस निधि का उपयोग दूध संकलन लॉजिस्टिक्स को सशक्त बनाने, प्रसंस्करण अवसंरचना और ब्रांड दृश्यता बढ़ाने के लिए किया गया।

सदस्य किसानों को प्रदान की जाने वाली इनपुट सेवाओं में पशु आहार, क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण और आहार संपूरक की किफायती दरों पर आपूर्ति शामिल है। संघ ने डेयरी किसानों, रूट सुपरवाइजरों, विपणन कर्मियों और संभावित कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए।

संघ ने 'पराग' ब्रांड के तहत औसतन 16.33 हजार लीटर प्रतिदिन (TLPD) पैक्ड तरल दूध का विपणन किया, साथ ही पनीर, घी, दही और लस्सी जैसे मूल्यवर्धित उत्पाद भी विपणन किए। वर्ष 2023–24 में, वार्षिक कारोबार 172 करोड़ रुपये तक बढ़ गया, जो पिछले वर्ष के 54 करोड़ रुपये के कारोबार की तुलना में 220 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

एनडीडीबी के अध्यक्ष द्वारा नए 50 एमटीपीडी फर्मेंटेड प्रोडक्ट सेक्शन की आधारशिला रखी गई। वर्ष के दौरान डेयरी परिसर में 20 एमटीपीडी पाउडर प्लांट और स्वीट मेकिंग सेक्शन का कमीशनिंग कार्य भी जारी रहा।

डेयरी परिसर में स्थापित गोबर आधारित बायोगैस प्लांट ने ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान दिया, जिससे पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम हुई। इस पहल ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मदद की और डेयरी किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत भी सृजित किया। ये गतिविधियां स्वच्छ भारत मिशन और हरित ऊर्जा कार्यक्रम के राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप हैं।

डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी ने श्री मनोज कुमार सिंह, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, से भेंट की और उन्हें वाराणसी दूध संघ में एनडीडीबी और उसकी सहायक संस्थाओं की पहलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने एनडीडीबी और प्रादेशिक सहकारी डेयरी फेडरेशन/ दूध संघ के बीच तीन डेयरी प्लांट और एक पशु आहार प्लांट के लीज हस्तातंरण हेतु प्रस्तावित एमओयू पर भी चर्चा की।

पश्चिमी असम दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (WAMUL)

एनडीडीबी ने पश्चिमी असम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (WAMUL), जिसे पूरबी डेयरी के नाम से जाना जाता है, का प्रबंधन जारी रखा।

डेयरी विकास के प्रमुख मापदंड

विवरण	इकाई	(आधार वर्ष) 2008-09	2024-25
दूध संकलन केंद्र / डेयरी सहकारी समितियां	संख्या	65	1346
शामिल किए गए गाँव	संख्या	65	3000
सक्रिय दूध प्रदाता	संख्या	1000	51100
दूध का संकलन	टीकेजीपीडी	4.5	161
दूध की बिक्री	टीएलपीडी	4.5	136.7
दूध बिल भुगतान (डीबीटी के माध्यम से)	करोड़ रुपये	4.5	134.04
कुल कारोबार	करोड़ रुपये	3.12	307

वामूल डेयरी किसानों को अतिरिक्त दूध संकलन मूल्य के रूप में लगभग 3.00 करोड़ रुपये (1.00 रुपये प्रति किलोग्राम) की अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगा।

इस वर्ष वामूल ने अपने कार्यक्षेत्र में 56,000 लीटर की अतिरिक्त बल्क मिल्क कूलिंग क्षमता का सृजन किया। इसके लिए 08 बीएमसी केंद्र और 16 बीएमसी इकाइयां फ्रेंचाइजी आधार पर शुरू की गईं, जिन्होंने इसके डेयरी किसानों के आधार को और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2024-25 के दौरान, वामूल से जुड़े सक्रिय डेयरी किसानों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

वामूल ने विभिन्न इनपुट सेवाएं प्रदान करना निरतंर जारी रखा, जिनमें घर पर एआई सेवा की आपूर्ति, किफायती दरों पर पशु आहार और आहार संपूरक का वितरण, साथ ही अपने डेयरी किसानों के लिए फील्ड डेमोंस्ट्रेशन, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रमों का आयोजन शामिल रहा। ये सभी गतिविधियां विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित असम कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना (APART) के औपचारिक डेयरी मूल्य श्रृंखला घटक की अंतिम कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में की गईं। मार्च 2025 तक, वामूल ने 3,393 गांवों में 373 मोबाइल एआई तकनीशियनों (MAIT) के नेटवर्क के माध्यम से 10,84,665 घर पर एआई सेवाएं प्रदान कीं। इसके अलावा, मार्च

एनडीडीबी और वामूल के बीच एमओयू का आदान-प्रदान, जिसमें श्री जोगेन मोहन जी, माननीय सहकारिता मंत्री, असम सरकार; श्री पीयूष हज़ारिका जी, माननीय जल संसाधन मंत्री, असम सरकार; तथा डॉ. बी. कल्याण चक्रवर्ती, अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, असम सरकार उपस्थित रहे

2025 तक कुल 4,14,497 बछड़ों के जन्म की जानकारी दी गई, जिनमें से 2,12,228 मादा बछड़े हैं।

वर्ष 2024–25 में, वामूल ने 4,450 टन पशु आहार और 34 टन खनिज मिश्रण का विक्रय किया। इसके अलावा, वर्ष के दौरान वामूल ने खुले बाजार में अपने पशु आहार की वाणिज्यिक बिक्री और वितरण भी प्रारंभ किया। इसी अवधि में, वामूल ने अपने डेयरी किसानों को 5.30 लाख हाइब्रिड नेपियर स्लिप्स और लगभग 5 टन चारे के बीज वितरित किए। साथ ही लगभग 14 टन साइलेज की बिक्री की व्यवस्था की गई और 119 साइलेज डेमोंस्ट्रेशन आयोजित किए गए, जिनमें डेयरी किसानों द्वारा लगभग 90 प्रतिशत अपनाने की दर दर्ज की गई। वर्ष के दौरान, वामूल ने अपने क्षेत्र के 800 गांवों में लगभग 2,000 डेयरी किसानों के स्वामित्व वाले लगभग 4,000 पशुओं को आहार संतुलित कार्यक्रम (RBP) के तहत कवर किया। इसके अलावा, वामूल ने टीकाकरण और स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए, जिनमें एथनोवेटनरी शिविर भी शामिल रहे, ताकि डेयरी पशुओं को विभिन्न बीमारियों से सुरक्षित रखा जा सके।

वामूल ने पर्यावरणीय सस्टेनेबल उपायों से गांव-आधारित दूध संकलन गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए 188 सौर ऊर्जा संचालित स्वचालित दूध संकलन प्रणाली स्थापित की। एनडीडीबी, सस्टेन प्लस एनर्जी फाउंडेशन (टाटा ट्रस्ट्स की सहयोगी संस्था) और वामूल द्वारा वित्तपोषित संयुक्त पहल के रूप में, कामरूप (मेट्रोपॉलिटन) जिले के खेतरी उपखंड के मलोइबाड़ी राजस्व ग्राम में एक स्लरी प्रसंस्करण केन्द्र का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया गया। इसके अलावा, वामूल और एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनडीडीबी मृदा लि. के बीच इस स्लरी प्रसंस्करण केन्द्र के वाणिज्यिक संचालन हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल का उद्देश्य "पूरबी-सुधन" ब्रांड नाम के तहत विभिन्न स्लरी-आधारित ऑर्गेनिक खाद उत्पादों की बिक्री करना है। स्लरी सहकारी समिति "सखी जैविक खाद सहकारी समिति लिमिटेड" (100 महिला लाभार्थियों से बनी) द्वारा उपयोग की गई स्लरी, मलोइबाड़ी केंद्र को आपूर्ति की जाएगी। यह समिति खाद प्रबंधन परियोजना के हिस्से के रूप में पंजीकृत की गई थी। वर्ष के दौरान, इस गोबर सहकारी समिति को कार्बन क्रेडिट के लिए 52,000 रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ, जिसे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, वामूल ने 150 फ्लेक्सी बायोगैस यूनिटें (प्रत्येक की क्षमता 2मी^{3}) स्थापित कीं। इसके लिए भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) से 47 लाख रुपये की वित्तीय सहायता एनडीडीबी मृदा लि. के माध्यम से एमएनआरई बायोगैस कार्यक्रम के तहत प्राप्त हुई। वामूल ने एनडीडीबी के साथ एक और समझौता ज्ञापन (MoU) पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत जाकरियापुरा मॉडल पर समान क्षमता वाली फ्लेक्सी बायोगैस यूनिटों की अतिरिक्त स्थापना प्रस्तावित है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1.70 करोड़ रुपये है।

वामूल ने केंद्रीय नोडल एजेंसी (CNA) के रूप में कार्य करते हुए 11.76 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की। यह धनराशि राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) की केंद्रीय क्षेत्र योजना के घटक-ए के अंतर्गत प्रदान की गई, जिसका उद्देश्य गांव-आधारित दूध संकलन प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु गतिविधियों का कार्यान्वयन करना है। इन सुधारों को वामूल के अपने परिचालन क्षेत्रों के साथ-साथ ईअमूल के क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान वामूल को एनडीडीबी से 94 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की गई। यह ऋण पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF) की केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत ब्याज सहायता द्वारा समर्थित है। इस ऋण का मुख्य उद्देश्य गुवाहाटी स्थित वामूल के मौजूदा डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता को 150 टीएलपीडी से बढ़ाकर 300 टीएलपीडी करना है। साथ ही, इस निधि का उपयोग दही निर्माण क्षमता को 30 एमटीपीडी से बढ़ाकर 50 एमटीपीडी करने और 20 टीएलपीडी क्षमता वाले नए आइसक्रीम संयंत्र की स्थापना के लिए भी किया जाएगा।

वित्त वर्ष के अंत में, 27 फरवरी 2025 को विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर श्री ऑगस्टे टैनो कुआमे ने गुवाहाटी स्थित पूरबी डेयरी परिसर में अपार्ट के अंतर्गत वामूल के नव-विस्तारित डेयरी संयंत्र का निरीक्षण किया। उनके साथ विश्व बैंक के टास्क टीम लीडर (TTL), अपार्ट, श्री बेकज़ोड शम्सीव, लीड सोशल प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट एवं प्रोग्राम लीडर सुश्री जुनको ओनिशी, एआरआईएएस सोसाइटी के एसपीडी, श्री वीरेन्द्र मित्तल, आईएएस, होजाई के जिला आयुक्त श्री आनंद मल्होत्रा, आईएएस तथा एआरआईएएस सोसाइटी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

वित्त वर्ष के दौरान, हमारे नेटवर्क से जुड़ी एक महिला डेयरी किसान, एक डेयरी सहकारी समिति (DCS) और एक मोबाइल एआई तकनीशियन (MAIT) को राष्ट्रीय दूध दिवस पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त, मार्च 2025 में, वामूल की प्रबंधन समिति के सदस्य एवं डेयरी किसान श्री भरत चंद्र कलिता को असम के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान "अक्सोम गौरव पुरस्कार" के लिए नामित किया गया। यह सम्मान बाजली ज़िले में दूध क्रांति की शुरुआत करने वाले एक प्रगतिशील डेयरी किसान के रूप में उनकी अग्रणी भूमिका को दर्शाता है।

वामूल ने गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में 200 एमएल एसकेयू पैक में अपने नए फ्लेवर्ड मिल्क उत्पादों की शृंखला का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया। पूरे वर्ष के दौरान, वामूल ने प्रतिदिन औसतन 1,24,300 लीटर पैक्ड लिक्विड दूध और दूध-समान उत्पादों (पनीर, मीठा दही, सादा दही, लस्सी, क्रीम, घी, आइसक्रीम एवं फ्लेवर्ड मिल्क सहित) की बिक्री की। यह प्रदर्शन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 21% की वृद्धि को दर्शाता है। इसके साथ ही, दूध-समान उत्पादों का अनुपात पैक्ड लिक्विड दूध की तुलना में पिछले वर्ष की तुलना में 3% से अधिक बढ़ा। इस मजबूत प्रदर्शन से वामूल ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए लगभग 3,200 मिलियन रुपये का अस्थायी बिक्री कारोबार दर्ज किया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 19% अधिक है।

पूर्वी असम दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (EAMUL)

एनडीडीबी के प्रबंधन में, वर्ष 2023 से, पूर्वी असम दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (EAMUL) ने असम के उत्तरी तटीय मैदानों और ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी के 13 जिलों को शामिल करते हुए अपने परिचालन क्षेत्र में डेयरी विकास गतिविधियां जारी रखी हैं।

दो वर्षों की अवधि के दौरान, ईअमूल ने डेयरी सहकारी समितियों के अपने नेटवर्क का विस्तार किया है, अधिक से अधिक किसानों को डेयरी सहकारी समितियों के दायरे में नामांकित किया है, दूध संकलन प्रक्रिया में पारदर्शी और कुशल संचालन सुनिश्चित किया है और 13 बीएमसी समूहों के नेटवर्क के साथ चिलिंग इन्फ्रास्ट्रक्टर स्थापित किया है। यहां दूध उत्पादकों को नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाता है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से केवल उनके बैंक खातों में ही किया जाता है।

दूध संघ ने विभिन्न इनपुट एवं उत्पादकता वृद्धि सेवाएं निरतंर जारी रखीं, जिनमें घर पर कृत्रिम गर्भाधान (AI) की सुविधा, आहार संतुलन, ईवीएम के माध्यम से पशु स्वास्थ्य सेवाएं तथा डेयरी किसानों को उचित दरों पर पशु आहार, आहार संपूरक एवं चारा बीजों का वितरण शामिल है। इसके अलावा, संघ द्वारा फार्म स्तरीय प्रदर्शन, प्रशिक्षण सत्र एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी नियमित रूप से आयोजित किए गए।

वर्ष के दौरान, कुल 15,277 कृत्रिम गर्भाधान 1,076 गांवों में कार्यरत 103 मोबाइल एआई तकनीशियनों के नेटवर्क के माध्यम से संपन्न किए गए। किसानों को 947 मीट्रिक टन मिश्रित पशु आहार तथा 11.88 मीट्रिक टन क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण उचित दरों पर उपलब्ध कराया गया। हितधारकों की क्षमता वृद्धि हेतु बीएमसी/डीसीएस प्रबंधन, स्वच्छ दूध उत्पादन, डेयरी पशु प्रबंधन आदि विषयों पर विभिन्न प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम भी नियमित रूप से संचालित किए जा रहे हैं।

श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत, ईअमूल ने 103 बहुउद्देशीय दूध सहकारी समितियों (MDCS) का गठन कर उनके पंजीकरण हेतु आवेदन किया है।

डेयरी विकास के प्रमुख मापदंड

विवरण	इकाई	(आधार वर्ष) 2021-22	2024-25
दूध संकलन केंद्र / डेयरी सहकारी समितियां	संख्या	0	367
शामिल किए गए गांव	संख्या	0	1046
सक्रिय दूध प्रदाता	संख्या	0	8246
दूध का संकलन	टीकेजीपीडी	0	7.57
दूध की बिक्री	टीएलपीडी	0	7.35
दूध बिल भुगतान (डीबीटी के माध्यम से)	करोड़ रुपये	0	17.12
कुल कारोबार	करोड़ रुपये	0	1797

दूध संकलन परिचालन प्रारंभ करने के लिए एनडीडीबी ने ईअमूल को एनडीडीबी की "रिवाइटलाइजिंग प्रॉमिसिंग प्रोड्यूसर्स' ओन्ड इंस्टीट्यूशन को सशक्त बनाने की योजना (RPPOI) के तहत 2.99 करोड़ रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की है। यह राशि उन नि:शुल्क सेवाओं के अतिरिक्त है, जो एनडीडीबी के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर प्रदान कर रहे हैं (मार्च 2025 तक केवल ईअमूल के लिए इसका मूल्यांकन 1.30 करोड़ रुपये आंका गया है)।

असम में सहकारी डेयरी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, जनवरी 2023 में नॉर्थ ईस्ट डेयरी एंड फूड्स लिमिटेड (NEDFL) की स्थापना की गई। यह एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे असम सरकार एवं एनडीडीबी ने मिलकर गठित किया है। राज्य की शीर्ष संस्था के रूप में, एनईडीएफएल असम में डेयरी विकास को क्लस्टर आधारित सहकारी दूध संघों के माध्यम से आगे बढ़ाएगी। एनईडीएफएल "पूरबी" ब्रांड के अंतर्गत सभी दूध एवं दूध उत्पादों की बिक्री एवं विपणन का प्रबंधन करता है तथा रक्षा आपूर्ति के समन्वयन का कार्य वामूल के माध्यम से करता है। वित्त वर्ष 2024-25 में एनईडीएफएल ने औसतन 124 टीएलपीडी दूध एवं दूध उत्पादों का विक्रय दर्ज किया। "पूरबी" ब्रांड के अंतर्गत दो नई उत्पाद पोर्टफोलियो (आइसक्रीम और फ्लेवर्ड मिल्क) का शुभारंभ किया गया।

एनईडीएफएल को भूमि आवंटित की गई है तथा प्रशासनिक स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं, जिनके अंतर्गत तीन प्रमुख डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए जाएंगे - डिब्रूगढ़ में 1 एलएलपीडी का संयंत्र, जोरहाट में 1 एलएलपीडी का संयंत्र तथा धेमाजी में 50 टीएलपीडी का संयंत्र। इन तीनों परियोजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है।

इसके अलावा, शिलांग में आयोजित "पूर्वोत्तर क्षेत्र में पशुधन क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु संवाद" सम्मेलन के दौरान, एनईडीएफएल एवं असम सरकार के डेयरी विकास निदेशालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू पर हस्ताक्षर माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन सिंह जी, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन जी तथा अन्य विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस समझौते के अंतर्गत कछार जिले के सिलचर स्थित घुंगूर दूध प्रसंस्करण संयंत्र को 20 टीएलपीडी क्षमता वाले दूध प्रसंस्करण संयंत्र के रूप में पुनर्निर्मित करने का प्रावधान है। यह नई सुविधा बराक घाटी में एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज द्वारा संगठित की जाने वाली उत्पादक कंपनी के माध्यम से दूध संकलन प्रणाली को और सुदृढ़ करेगी।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री, श्री जॉर्ज कुरियन जी, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में शिलांग में एनईडीएफएल और डेयरी विकास निदेशालय, असम सरकार के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर करते हुए

लद्दाख डेयरी सहकारी महासंघ लिमिटेड

लद्दाख ओमा ब्रांड नाम से संचालित, लद्दाख डेयरी सहकारी महासंघ लिमिटेड की स्थापना अक्तूबर 2023 में लद्दाख के डेयरी क्षेत्र में बदलाव लाने और ग्रामीण किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई। इस संघ का प्रबंधन एनडीडीबी द्वारा लद्दाख प्रशासन और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDC) के साथ एक पंचवर्षीय त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के माध्यम से किया जाता है। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य एनडीडीबी की प्रबंधकीय और तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए एक पारदर्शी, संगठित और सस्टेनेबल डेयरी मूल्य श्रृंखला का निर्माण करना है।

दूध का प्रसंस्करण लेह स्थित नवीनीकृत डेयरी संयंत्र में किया जाता है तथा इसे ताज़ा पास्चुरीकृत दूध के रूप में "लद्दाख ओमा" ब्रांड नाम से बाज़ार में उपलब्ध कराया जाता है। यह महासंघ एक सहकारी रिटेल शॉप भी संचालित करता है, जिसके माध्यम से स्थानीय उपभोक्ताओं को उच्च-गुणवत्तायुक्त दूध रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही, उत्पाद श्रृंखला का विस्तार कर दही एवं पनीर को भी बाज़ार में उतारने की योजना प्रगति पर है।

वित्तीय दृष्टि से, लद्दाख महासंघ ने वर्ष 2024-25 के दौरान दूध उत्पादकों को दूध मूल्य भुगतान के रूप में 4 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया। महासंघ को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई, जिसमें प्रॉमिसिंग प्रोड्यूसर्स' ओन्ड इंस्टीट्यूशन्स को सशक्त बनाने की योजना (RPPOI) के अंतर्गत 5.80 करोड़ रुपये (अनुदान एवं ऋण), विपणन परिचालन हेतु एनडीडीबी से 61.48 लाख रुपये तथा संयंत्र विस्तार हेतु लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश सरकार से 2 करोड़ रुपये शामिल हैं। अवसंरचना विकास, महासंघ की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। प्रमुख पहलों में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) के अंतर्गत कारगिल में 10 टीएलपीडी दूध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना, कारगिल और नुब्रा में मॉड्यूलर बल्क मिल्क कूलर (BMC) की स्थापना तथा लद्दाख की प्रथम एनएबीएल-मान्यता प्राप्त गुणवत्ता आश्वासन प्रयोगशाला की स्थापना शामिल है।अन्य प्रगतियों में एक मोबाइल परीक्षण प्रयोगशाला, एनडीडीबी एवं मारुति सुज़ुकी द्वारा विकसित दूध संकलन वाहन तथा डेयरी प्रबंधन में सर्वोत्तम पद्धतियों को बढ़ावा देने हेतु स्वच्छता स्टेशन शामिल हैं।

इन एकीकृत प्रयासों के माध्यम से, महासंघ लद्दाख के डेयरी क्षेत्र को असंगठित ढांचे से संगठित इकोसिस्टम की ओर अग्रसर कर रहा है। इससे किसानों को बेहतर प्रतिफल प्राप्त हो रहा है, सेना जैसे संस्थागत खरीदारों को विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है तथा स्थानीय उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण दूध उत्पादों की उपलब्धता बढ़ रही है। उत्कृष्टता, पारदर्शिता एवं सस्टेनेबिलिटी के प्रति महासंघ की प्रतिबद्धता लद्दाख में सहकारी विकास और ग्रामीण समृद्धि के नए मानक स्थापित कर रही है।

लद्दाख में डेयरी विकास के प्रमुख मापदंड

विवरण	इकाई	(आधार वर्ष) 2023-24	2024-25
दूध संकलन केंद्र / डेयरी सहकारी समितियां	संख्या	1	24
शामिल किए गए गांव	संख्या	1	24
सक्रिय दूध प्रदाता	संख्या	100	1200
दूध का संकलन	टीकेजीपीडी	0.45	4.5
दूध की बिक्री	टीएलपीडी	0.2	6
दूध बिल भुगतान (डीबीटी के माध्यम से)	करोड़ रुपये	-	4.12
कुल कारोबार	करोड़ रुपये	0.617	1.105

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी; माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ श्री विष्णु देव साय जी और माननीय उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ श्री विजय शर्मा जी की उपस्थिति में एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह और छत्तीसगढ़ सरकार के पशुधन विकास विभाग की सचिव सुश्री शहला निगार के बीच एमओयू का आदान-प्रदान करते हुए

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

एनडीडीबी ने छत्तीसगढ़ सरकार एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित (CGCDF) के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता माननीय केंद्रीय गृहमंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी तथा माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ श्री विष्णु देव साय जी एवं श्री विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस समझौते का उद्देश्य सीजीसीडीएफ और इसकी इकाइयों के संचालन का प्रबंधन करना है।

यह साझेदारी सहकारी ढांचे और प्रसंस्करण अवसंरचना का विस्तार करने, साथ ही दूध उत्पादन और बाज़ार पहुंच को बढ़ाने पर केंद्रित है। इस पहल के अंतर्गत लगभग 3,600 नई दूध उत्पादक सहकारी समितियों (MPCS) का गठन किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच और किसानों की सहभागिता को मज़बूती मिलेगी। यह पहल समावेशी ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ सहकारी विकास के लिए एनडीडीबी के मैनडेट में भी योगदान देगी। एनडीडीबी किसानों को समय पर दूध का भुगतान सुनिश्चित करने, बकाया विपणन देयों की वसूली करने तथा एक ईआरपी प्रणाली लागू कर संचालन को सुव्यवस्थित करने की दिशा में कार्य कर रही है।

साथ ही, छह ज़िलों – कांकेर, कोंडागांव, महासमंद, सारंगढ़, जशपुर और बलरामपुर में एक पायलट प्रोजेक्ट एनिमल इंडक्शन भी प्रगति पर है, जिसका लक्ष्य लगभग 325 आदिवासी परिवारों तक पहुंचना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक आदिवासी महिला लाभार्थी को दो दूधारू गायें खरीदने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। इसमें 50 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा, 40 प्रतिशत राशि बैंक ऋण के रूप में तथा शेष 10 प्रतिशत राशि लाभार्थी योगदान के रूप में वहन की जाती है। इस पहल का क्रियान्वयन सीजीसीडीएफ द्वारा, एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनडीएस के माध्यम से किया जा रहा है।

राज्य में डेयरी विकास के प्रमुख मापदंड

विवरण	इकाई	(आधार वर्ष) 2024-25	लक्ष्य 2031-32
दूध संकलन केंद्र / डेयरी सहकारी समितियां	संख्या	636	4600
सक्रिय दूध प्रदाता	संख्या	26000	134000
दूध का संकलन	टीकेजीपीडी	70	700
दूध की बिक्री	टीएलपीडी	42	490
दूध बिल भुगतान (डीबीटी के माध्यम से)	करोड़ रुपये	85.5	-
कुल कारोबार	करोड़ रुपये	120.4	-

महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित

महाराष्ट्र सरकार एवं एनडीडीबी के बीच महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित (MRSDMM), मुंबई—जो महाराष्ट्र में दूध सहकारी क्षेत्र की शीर्ष संस्था है, के पुनरुद्धार हेतु एक समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत 2 मई 2024 से एनडीडीबी ने एमआरएसडीएमएम के प्रबंधन का कार्यभार संभाला।

कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत, कर्मचारियों के वेतन, दूध के बिल और अन्य भुगतान जैसे प्रमुख वित्तीय दायित्वों को नियमित कर दिया गया है, जिससे संगठन के संचालन में स्थिरता और नया विश्वास आया है।

डेयरी किसानों को समर्थन देने के लिए एमआरएसडीएमएम ने गाय के दूध संकलन की कीमत बढ़ा दी है, जिसमें 35% फैट व 8.5% एसएनएफ शामिल है। इसकी कीमत को 27.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 34.00 रुपये प्रति लीटर कर दिया है, जिसमें 2.50 रुपये प्रति लीटर दूध हैन्डलिंग शुल्क और परिवहन लागत शामिल है। नई दरों में 3.00 रुपये प्रति लीटर दूध हैन्डलिंग शुल्क और परिवहन लागत शामिल है जो सदस्य दूध संघों को भुगतान किया जाता है। संगठनात्मक पुनर्गठन के हिस्से के रूप में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) भी लागू की गई।

परिचालन दक्षता में और वृद्धि करते हुए, पुणे (वरवंड) स्थित 30 एमटीपीडी दूध पाउडर संयंत्र, जो पिछले एक वर्ष से निष्क्रिय था, को पुनः प्रारंभ किया गया। वर्तमान में यह संयंत्र पूर्णतः सक्रिय है और 190 टीएलपीडी दूध को सफलतापूर्वक दूध पाउडर में परिवर्तित किया गया। एमआरएसडीएमएम ने दूध संकलन और बिक्री दोनों ही क्षेत्रों में सतत् प्रगति दर्शाई है।

ये विकासात्मक कदम एमआरएसडीएमएम के पुनरुद्धार और सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाते हैं, जो महाराष्ट्र के दूध सहकारी क्षेत्र में सस्टेनेबल वृद्धि के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता हैं।

राज्य में डेयरी विकास के प्रमुख मापदंड

विवरण	इकाई	(आधार वर्ष) 2023-24	2024-25
दूध संकलन केंद्र / डेयरी सहकारी समितियां	संख्या	624	636
शामिल किए गए गांव	संख्या	13000	26000
दूध का संकलन	टीकेजीपीडी	93.6	130.51
दूध की बिक्री	टीएलपीडी	75.09	82.54
कुल कारोबार	करोड़ रुपये	215.86	199.44

माननीय मुख्यमंत्री, मणिपुर श्री एन. बीरेन सिंह जी और माननीय पशुपालन, पशु चिकित्सा और परिवहन मंत्री, मणिपुर सरकार श्री खशिम वाशुम जी की उपस्थिति में मणिपुर सरकार, मणिपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड और एनडीडीबी के बीच त्रिपक्षीय एमओयू का आदान-प्रदान करते हुए

डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी श्री राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय उपमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश और श्री लखन पटेल जी, माननीय पशुपालन मंत्री, मध्य प्रदेश की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश के लिए डेयरी विकास योजना प्रस्तुत करते हुए

मणिपुर दूध संघ

मणिपुर में सहकारी डेयरी विकास हेतु 31 जनवरी 2025 को मणिपुर सरकार, मणिपुर दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड एवं एनडीडीबी के बीच एक त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता माननीय मुख्यमंत्री, मणिपुर श्री एन बीरेन सिंह जी एवं माननीय पशुपालन, पशु चिकित्सा एवं परिवहन मंत्री, मणिपुर सरकार श्री खाशिम वाशुम जी की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस समझौते पर एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह, मणिपुर सरकार के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग के सचिव श्री माइकल आचोम तथा मणिपुर दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के प्रशासक मंडल के श्री पी सोवाचंद्र द्वारा हस्ताक्षर किए गए। एनडीडीबी, अप्रैल 2025 से इस संघ का प्रबंधन संभालेगी।

एनडीडीबी ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से संघ को निरंतर सहयोग प्रदान किया है। री-वाइटलाइज़िंग प्रॉमिसिंग प्रोड्यूसर्स ओन्ड इंस्टिट्यूशन्स (RPPOI) के अंतर्गत संघ को 3 करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्रदान की गई, जिसका उपयोग डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना के पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण हेतु किया जा रहा है। तकनीकी सहयोग भी प्रदान किया गया, जिसके अंतर्गत एक नए दूध उत्पाद का विकास एवं बाजार में लांच करना संभव हो सका। संघ ने भारतीय सेना को दूध की आपूर्ति भी प्रारंभ की है। इसके अलावा, एक कॉम्प्रिहेन्सिव डेयरी डेवलपमेंट प्लान मणिपुर सरकार को प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य व्यवहार्य गांवों में सहकारी कवरेज को सुनिश्चित करना तथा बहुउद्देशीय डेयरी सहकारी समितियां (MDCS) एवं बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (MPACS) के माध्यम से एकीकृत डेयरी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है।

मध्य प्रदेश में डेयरी व्यवसाय का सुदृढ़ीकरण

नवंबर 2024 में एनडीडीबी के अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी से भेंट की और राज्य में डेयरी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश में डेयरी सहकारी संस्थाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण करना है। एनडीडीबी ने दूध संकलन एवं विपणन में वृद्धि, डेयरी संयंत्रों की क्षमता विस्तार, प्रजनन, पोषण एवं पशु स्वास्थ्य पहलों के माध्यम से पशु उत्पादकता सुधार हेतु सहयोग प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

एनडीडीबी के अध्यक्ष ने माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी भेंट की और किसानों के समावेशी विकास के लिए एनडीडीबी एवं इसकी सहायक संस्थाओं द्वारा डेयरी एवं कृषि क्षेत्र में की जा रही किसान-केंद्रित गतिविधियों पर चर्चा की। उन्हें मध्यप्रदेश में एनडीडीबी की डेयरी विकास से संबंधित गतिविधियों के बारे में भी अवगत कराया गया।

एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह, ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड (OMFED) के प्रबंध निदेशक श्री विजय अमृत कुलंगे के साथ मार्केट सपोर्ट प्रोग्राम का शुभारंभ करते हुए

ओडिशा में डेयरी विकास हेतु सहयोग

वर्ष के दौरान, एनडीडीबी ने ओडिशा सरकार एवं ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड (OMFED) के सहयोग से संस्थागत निर्माण, कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं अवसंरचना विकास के माध्यम से डेयरी एवं पशुधन क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु अनेक रणनीतिक पहलें कीं।

13 जनवरी 2025 को, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने ओडिशा के मयूरभंज जिले में एनडीडीबी द्वारा कार्यान्वित पहलों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत, चिह्नित लाभार्थियों को 3,000 उच्च आनुवंशिक गुण वाली गायों के वितरण हेतु एक कैटल इंडक्शन प्रोग्राम शुरू किया गया। स्कूली बच्चों में पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए, गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके तहत रायरंगपुर नगरपालिका के 1,200 स्कूली बच्चों को प्रतिदिन 200 मिलीलीटर फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड मिल्क उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, राज्य की दूध संकलन क्षमता को 5 लाख लीटर प्रतिदिन से दोगुना करके 10 लाख लीटर प्रतिदिन करने हेतु संकलन, प्रसंस्करण और विपणन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने हेतु बाजार सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया। आगे, एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रीशन एवं राउरकेला स्टील प्लांट (सेल) के बीच हुए एक समझौते के माध्यम से गिफ्ट मिल्क पहल का विस्तार किया गया, जिसका लक्ष्य वर्ष 2025-26 में अतिरिक्त 1,575 बच्चों तक पहुंचना है।

भुवनेश्वर स्थित लोक सेवा भवन में आयोजित मॉनसून मीट के दौरान, एनडीडीबी ने ओडिशा सरकार एवं ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड (OMFED) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य ओडिशा के डेयरी क्षेत्र में बदलाव लाना है, जिसमें एक कॉम्प्रिहेन्सिव डेयरी डेवलपमेंट प्लान के माध्यम से डेयरी सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण एवं कवरेज का विस्तार सम्मिलित है। इस एमओयू पर एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह, ओडिशा सरकार के एएच एंड वीएस निदेशक श्री रामाशीष हजरा तथा ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड (OMFED) के प्रबंध निदेशक श्री विजय अमरुत कुलांगे ने हस्ताक्षर किए। यह हस्ताक्षर माननीय मुख्यमंत्री, ओडिशा श्री मोहन चरण माझी जी; माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी; माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल जी एवं माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन जी; 15 राज्यों के पशुपालन एवं डेयरी मंत्रियों तथा अन्य विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इसके अलावा, एनडीडीबी एवं ओमफेड के बीच एक अन्य समझौता कटक स्थित अरिलो डेयरी में बायोगैस संयंत्र की स्थापना हेतु संपन्न हुआ। यह संयंत्र वाराणसी मॉडल पर आधारित होगा तथा डेयरी संचालन का उद्देश्य सर्कुलैरिटी और सस्टेनेबल ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देना है।

गोवा में डेयरी विकास हेतु समर्थन

एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह ने माननीय मुख्यमंत्री, गोवा डॉ. प्रमोद सावंत जी से भेंट की और राज्य में डेयरी क्षेत्र को आगे बढ़ाने हेतु डेयरी विकास योजना तैयार करने में सहयोग प्रदान किया। राज्य सरकार के अनुरोध पर, एनडीडीबी ने गोवा डेयरी को उसकी गतिविधियों के सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रबंधकीय सहयोग उपलब्ध कराया। पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार की एनपीडीडी योजना के अंतर्गत एनडीडीबी के सहयोग से एक कॉम्प्रिहेन्सिव डेयरी डेवलपमेंट प्लान प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य मौजूदा डेयरी सहकारी समितियों को सुदृढ़ करना तथा नए क्षेत्रों में नई समितियों की स्थापना करना है। इस सहयोग के तहत, गोवा डेयरी एवं एनडीडीबी के बीच गोवा में बनास मॉडल के कम्प्रैस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF) के सहयोग से, राज्य में 24x7 मोबाइल पशु चिकित्सा एंबुलेंस सेवाएं प्रारंभ की गईं। पशु आहार की कमी को दूर करने के उद्देश्य से, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज़ ने राज्य में उच्च गुणवत्ता वाला पशु आहार एवं साइलेज उपलब्ध कराना प्रारंभ किया, जिसकी बाजार दरों से कम कीमत पर आपूर्ति की जा रही है।

गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत जी, एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह और एनडीडीबी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गोवा के डेयरी विकास पर चर्चा करते हुए

अन्य राज्यों को सहयोग

एनडीडीबी ने संबंधित राज्य सरकारों एवं दूध संघों के अनुरोध पर, गोवा, औरंगाबाद, बनास डेयरी, हिमाचल प्रदेश महासंघ, एर्नाकुलम दूध संघ, दिल्ली डेयरी योजना आदि में जनशक्ति सहयोग उपलब्ध कराया।

एनडीडीबी ने अपने प्रबंधनाधीन सभी इकाइयों में प्रो-बोनो आधार पर भी जनशक्ति सहयोग उपलब्ध कराया है।

विदर्भ मराठवाड़ा डेयरी विकास परियोजना (VMDDP)

विदर्भ मराठवाड़ा डेयरी विकास परियोजना (VMDDP) की संकल्पना महाराष्ट्र के विदर्भ एवं मराठवाड़ा क्षेत्रों में, जो कि सूखा-संभावित एवं किसान आत्महत्या-संभावित क्षेत्र हैं, गरीब डेयरी किसानों के बीच डेयरी विकास सुनिश्चित करने हेतु की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों के संकट को कम करना और कृषि आय में वृद्धि करना है। यह परियोजना एनडीडीबी द्वारा उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रा. लि. (MDFVPL), मराठवरहाड़ दूध उत्पादक संस्थान (MVMPO) तथा महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। इस संबंध में एनडीडीबी एवं महाराष्ट्र सरकार के बीच दिसंबर 2013 में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

तदनुसार, अक्तूबर 2016 में, एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड ने 3 एलएलपीडी दूध को संसाधित करने के लिए 30 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सरकारी डेयरी प्लांट, नागपुर का नवीनीकरण किया और क्षेत्र के डेयरी किसानों को फॉरवर्ड लिंकेज प्रदान करने के लिए 72 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक दूध संकलन नेटवर्क स्थापित किया।

परियोजना में डेयरी विकास के प्रमुख मापदंड

विवरण	इकाई	(आधार वर्ष) 2016-17	2024-25
दूध संकलन केंद्र / डेयरी सहकारी समितियां	संख्या	310	2497
शामिल किए गए गांव	संख्या	482	3396
सक्रिय दूध प्रदाता	संख्या	8396	32886
दूध का संकलन	टीकेजीपीडी	10	405
दूध की बिक्री	टीएलपीडी	3.5	63.53
दूध बिल भुगतान (डीबीटी के माध्यम से)	करोड़ रुपये	13.76	2391

इसके उपरांत, उत्पादक-स्तर की संस्थाओं को जमीनी स्तर पर सुदृढ़ करने के लिए सहकारिता मंत्रालय के उद्देश्यों के अनुरूप, एनडीडीबी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज़ (NDS) को उत्पादक-केंद्रित संस्थाओं की स्थापना में सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया। परिणामस्वरूप, एनडीएस ने 9 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक "मराठवरहाड़ दूध उत्पादक कंपनी" का पंजीकरण कराया। मदर डेयरी द्वारा पूर्व में संचालित दूध संकलन का परिचालन अब इस नवगठित दूध उत्पादक संगठन (MPO) को हस्तांतरित कर दिया गया है। इस एमपीओ के परिचालन का औपचारिक शुभारंभ 16 मार्च 2025 को माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, श्री नितिन गडकरी जी द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी; एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज़ के प्रबंध निदेशक; मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक; श्रीमती वर्षा नानासाहेब चव्हाण, अध्यक्ष, मराठवरहाड़ दूध उत्पादक संगठन; तथा अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। इस एमपीओ के गठन का उद्देश्य मदर डेयरी द्वारा स्थापित दूध संकलन नेटवर्क को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना और विदर्भ एवं मराठवाड़ा क्षेत्र के सभी 19 जिलों में इसके विस्तार को समर्थन देना है।

यह परिवर्तन किसानों को अधिक स्वामित्व, लाभांश में भागीदारी और एक सस्टेनेबल एवं आत्मनिर्भर डेयर उद्यम के रूप में सशक्त बनाएगा। वर्तमान में इस एमपीओ के 11 जिलों के 3,300 गांवों की 35,000 महिलाएं दूध उत्पादक सदस्य हैं। यह महिला-स्वामित्व एवं महिला-नेतृत्व वाला एमपीओ क्षेत्र की महिला डेयरी उत्पादक किसानों को सशक्त बनाने और डेयरी व्यवसाय को एक सस्टेनेबल आजीविका के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य करेगा। यह पहल न केवल किसानों की आय में वृद्धि करेगी, बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को भी गति प्रदान करेगी।

मराठवरहाड़ एमपीओ के शुभारंभ के दौरान धारा फूड ऑयल पैकेजिंग स्टेशन की आधारशिला भी रखी गई। विदर्भ क्षेत्र में सोयाबीन एक प्रमुख तिलहन फसल है तथा धान एक अन्य महत्वपूर्ण कृषि फसल है। क्षेत्र में तेल प्रसंस्करण की संभावनाओं को देखते हुए मदर डेयरी द्वारा स्थापित यह संयंत्र सोयाबीन एवं धान उत्पादक किसानों के साथ-साथ स्थानीय प्रसंस्करणकर्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करेगा। इस संयंत्र की प्रारंभिक उत्पादन क्षमता प्रति माह 500 मीट्रिक टन होगी, जिसे बढ़ाकर 1,500 मीट्रिक टन तक ले जाने की योजना है। उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य तेल उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु यह संयंत्र आधुनिक तकनीक से सुसज्जित होगा।

16 सितंबर 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने एक शासन-निर्देश जारी कर विदर्भ-मराठवाड़ा डेयरी विकास परियोजना (VMDDP) के द्वितीय चरण को स्वीकृति प्रदान की। इस चरण का कुल व्यय 328.42 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जिसमें से 149.26 करोड़ रुपये का वित्तीय सहयोग महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें 142.82 करोड़ रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थी डेयरी उत्पादक

माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के प्रबंध निदेशक डॉ. सी. पी. देवानंद, मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक श्री मनीष बंदलिश और मराठवरहाड़ दुग्ध उत्पादक संगठन की अध्यक्ष श्रीमती वर्षा नानासाहेब चव्हाण की उपस्थिति में नवगठित एमपीओ 'मराठवराहाड़ दुग्ध उत्पादक कंपनी' के उद्घाटन के अवसर पर

किसानों के बैंक खातों में सब्सिडी के रूप में अंतरित की जाएगी। इस चरण से क्षेत्र के लगभग 1.0 लाख डेयरी किसानों को लाभ होने की संभावना है।

द्वितीय चरण में दूध संकलन संचालन का विस्तार वर्तमान 11 जिलों से बढ़ाकर विदर्भ एवं मराठवाड़ा क्षेत्र के सभी 19 जिलों तक किए जाने की योजना है। अनुमान है कि आने वाले वर्षों में मराठवरहाड़ एमपीओ के सदस्य डेयरी किसानों की संख्या 75,000 तक पहुंच जाएगी और मार्च 2028 तक यह प्रतिदिन लगभग 10 लाख किलोग्राम दूध का संकलन करेगा।

इसी परिप्रेक्ष्य में मदर डेयरी नागपुर में अत्याधुनिक मेगा डेयरी परियोजना पर कार्य प्रारंभ कर चुकी है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर यह संयंत्र प्रतिदिन 6 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण करने में सक्षम होगा, जिसे 10 एलएलपीडी तक विस्तारित करने की सुविधा उपलब्ध होगी। इस इकाई में लस्सी, मिष्टी दोई, फ्लेवर्ड मिल्क, स्वीट एवं घी जैसे मूल्य संवर्धित दूध उत्पादों का भी उत्पादन किया जाएगा, जिससे पश्चिमी एवं दक्षिण भारत के बाजारों में विस्तार के साथ-साथ मौजूदा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी।

एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (NDS) द्वारा आरजीएम अंतर्गत परियोजना क्षेत्र में लागू घर पर कृत्रिम गर्भाधान (AI) सेवा भी प्रगतिशील रही है। वर्तमान में, परियोजना क्षेत्र के दस जिलों में 500 से अधिक एआई केंद्र कार्यरत हैं, जहां, अब तक, लगभग 3.35 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए जा चुके हैं। इसके परिणामस्वरूप 1.15 लाख पशु गाभिन हुए है और उनसे 34500 उच्च गुणवत्ता वाले बछड़े प्राप्त हुए हैं।

भारत सरकार की 100 चारा किसान उत्पादक संगठन (FPO) योजना के अनुरूप, परियोजना क्षेत्र के वर्धा जिले में "सुचरा फॉडर एफपीओ" की स्थापना की गई। इसे कमलनयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन के सहयोग से गठित किया गया, जिसने क्लस्टर बेस्ड बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन (CBBO) के रूप में कार्य किया। मात्र दस माह की अवधि में, इस एफपीओ ने लगभग 800 इक्विटी शेयरधारक सदस्य बना लिए हैं। इस एफपीओ के अंतर्गत 50 एकड़ से अधिक भूमि पर हरे चारे की विशेष खेती की जा रही है। इसके अतिरिक्त, एफपीओ ने एक उच्च प्रदर्शनशील चॉपर–बेलर मशीन भी खरीदी, जिसकी सहायता से वर्ष के दौरान लगभग 200 मीट्रिक टन साइलेज का उत्पादन किया गया।

डेयरी सहकारिताओं के सुदृढ़ीकरण हेतु हस्तक्षेप

एनडीडीबी ने लक्षित गतिविधियों के माध्यम से डेयरी सहकारी समितियों (DCS) और उत्पादक-स्वामित्व वाली संस्थाओं (POIs) को सुदृढ़ किया। इसका उद्देश्य संस्थागत क्षमता का निर्माण, संचालन की सुव्यवस्था तथा डेयरी सहाकारिताओं की सस्टेनेबल विकास यात्रा को समर्थन प्रदान करना था।

री-वाइटलाइज़िंग प्रॉमिसिंग प्रोड्यूसर्स ओन्ड इंस्टिट्यूशन्स

एनडीडीबी ने वर्ष 2022–23 में "री-वाइटलाइज़िंग प्रॉमिसिंग प्रोड्यूसर्स ओन्ड इंस्टिट्यूशन्स" योजना प्रारंभ की। यह पंचवर्षीय योजना चयनित पीओई को उनके व्यापार संचालन को मजबूत करने, बाजार हिस्सेदारी का विस्तार करने और सभी हितधारकों के हित में आत्मनिर्भर संस्थान के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से शुरू की गई।

वर्ष के दौरान, सात प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इनमें भंडारा दूध संघ, सोलापुर दूध संघ, पूर्वी असम दूध संघ लि. (EAMUL), लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश दूध महासंघ, मणिपुर दूध संघ, ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन (OMFED) और महानंद डेयरी शामिल हैं। इन परियोजनाओं की संयुक्त वित्तीय परिव्यय राशि 31.55 करोड़ रुपये है, जिसमें 11.85 करोड़ रुपये ब्याज मुक्त ऋण, 18.41 करोड़ रुपये अनुदान सहायता तथा 1.29 करोड़ रुपये संस्थागत अंशदान शामिल है।

अत: इस योजना के अंतर्गत कुल 13 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। इनकी स्वीकृत परिव्यय राशि 69.36 करोड़ रुपये है, जिसमें 29.56 करोड़ रुपये ब्याज मुक्त ऋण, 35.67 करोड़ रुपये अनुदान सहायता तथा 4.13 करोड़ रुपये संबंधित संस्थागत अंशदान शामिल है अतिरिक्त समर्थन प्राप्त करने वाली संस्थाओं में मिदनापुर दूध संघ, वाराणसी दूध संघ, एर्नाकुलम दूध संघ, पश्चिम असम दूध संघ, सुंदरबन दूध संघ और फिरोज़पुर दूध संघ शामिल रहे। इन गतिविधियों से परिचालन को पुनःप्रारंभ करने, संस्थागत क्षमता को बढ़ाने और समर्थित पीओआई के समग्र प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिली।

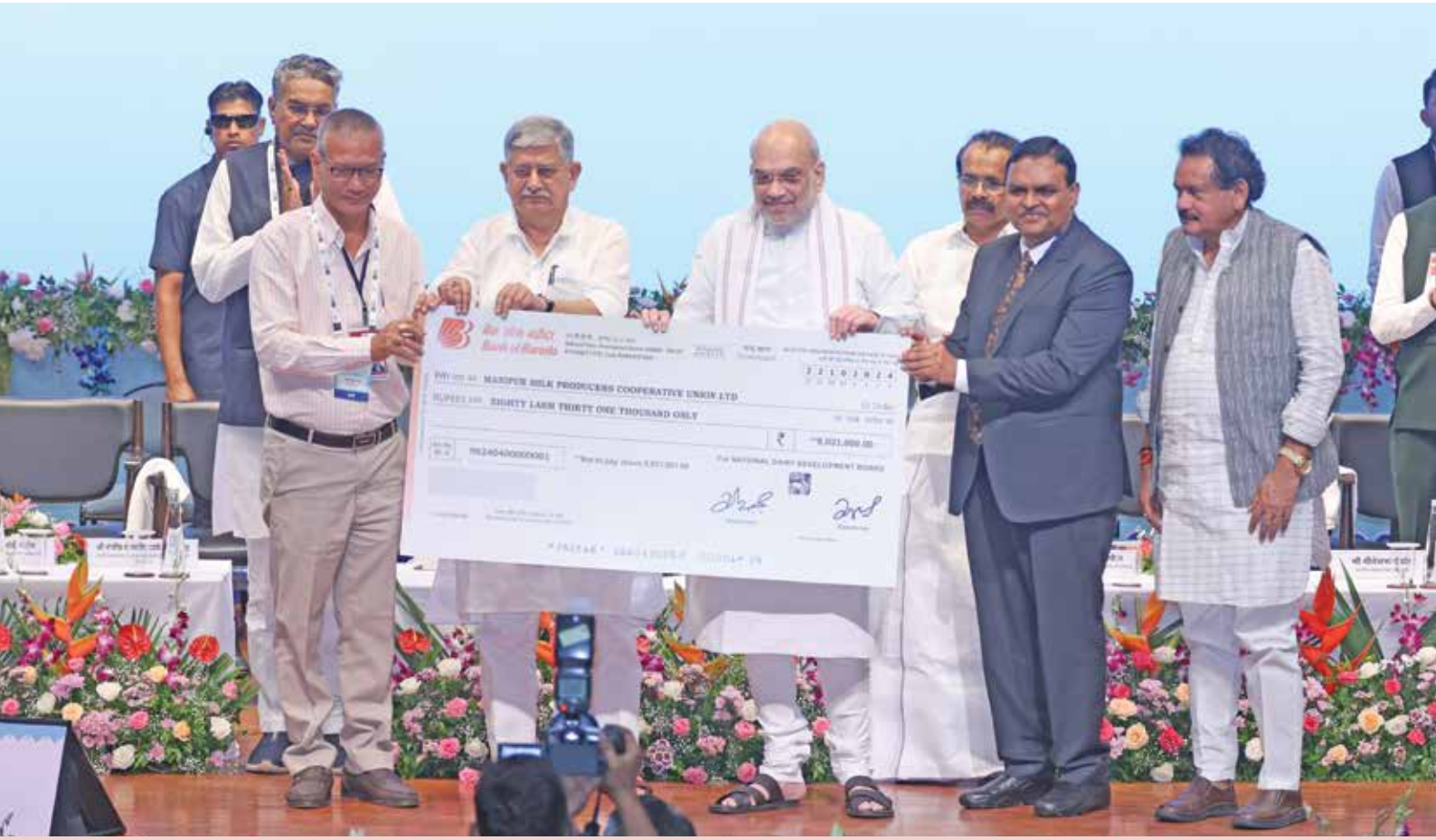

श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री और डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी, एनडीडीबी के " रिवाइटलाइजिंग प्रॉमिसिंग प्रोड्यूसर्स' ओन्ड इंस्टिट्यूशन्स " के तहत मणिपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड का समर्थन करते हुए

एनडीडीबी विपणन योजना के अंतर्गत उत्पादक-स्वामित्व वाली संस्थाओं के लिए विपणन सहायता

एनडीडीबी ने डेयरी सहकारिताओं की बाजार उपस्थिति और दक्षता में सुधार के लिए केंद्र प्रायोजित योजना 'उत्पादक- स्वामित्व वाली संस्थाओं के विपणन कार्यों के सुदृढ़करण हेतु सहायता' को क्रियान्वित किया। इस योजना को वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 30 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया।

वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक, एनडीडीबी ने 25 पीओआई को सहायता प्रदान की। कुल स्वीकृत परिव्यय 25.73 करोड़ रुपये है, जिसमें 13.72 करोड़ रुपये का पीओआई द्वारा योगदान किया गया और अनुदान सहायता के रूप में 12.01 करोड़ रुपये एनडीडीबी द्वारा जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, ब्रांड विकास और बिक्री एवं वितरण से संबंधित परामर्श सेवाओं के लिए अतिरिक्त 3 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

एनडीडीबी ने तीन नए सहकारी डेयरी ब्रांडों: 'मेदिनी' (मिदनापुर, पश्चिम बंगाल), 'मुल्कानूर' (मुलुकनूर, तेलंगाना) और 'लद्दाख ओमा' (लेह, लद्दाख) के लॉन्च करने में सहायता प्रदान की। सात मौजूदा ब्रांडों को ब्रांडिंग और पैकेजिंग के पुन: डिज़ाइन के लिए सहायता प्रदान की गई। इनमें पराग (वाराणसी), देवभोग (छत्तीसगढ़), मिल्मा (केरल), पूरबी (असम), महानंद (महाराष्ट्र), मेधा (झारखंड) और सरस (राजस्थान) शामिल हैं।

कोल्ड चेन अवसंरचना में सुधार हेतु, पीओआई ने 1,600 से अधिक मिल्क कूलर खरीदे और स्थापित किए। लगभग 6,000 इंसुलेटेड क्रेट और बॉक्स वितरित किए गए। लगभग 100 नए रिटेल बूथ और पार्लर स्थापित किए गए। छह सहकारी समितियों को बाज़ार रणनीतियों में सुधार हेतु बिक्री और वितरण पर परामर्श प्रदान किया गया।

एनडीडीबी ने इस योजना के अंतर्गत सात प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनसे लगभग 250 अधिकारी लाभान्वित हुए। क्षेत्रीय कार्यशालाओं ने सहकारी विपणन कार्यों के व्यावसायीकरण को बढ़ावा दिया। 3,000 से अधिक खुदरा विक्रेता हेतु जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। मूल्यवर्धित उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए भी सहायता प्रदान की गई, जिससे भाग लेने वाली सहकारी समितियों की दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ।

इन प्रयासों से एनडीडीबी के सस्टेनेबल एवं बाज़ारोन्मुख डेयरी संस्थानों के निर्माण संबंधी गतिविधियों को निरंतर बल मिला।

भारतीय डेयरी क्षेत्र का डिजिटलीकरण

एनडीडीबी ने डेयरी सहकारिताओं की परिचालन दक्षता एवं पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल नवाचार का लाभ उठाया। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग डेयरी उत्पादकों, समितियों और महासंघों को समय पर एवं प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने हेतु किया गया। इन पहलों ने आंकड़ा-आधारित निर्णय प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया, आपूर्ति श्रृंखला की पारदर्शिता में सुधार किया तथा ये उत्पादकता वृद्धि में सहायक सिद्ध हुईं।

किसानों की सहभागिता बढ़ाने, ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय स्तर की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए रियल-टाइम इन्फ़ॉर्मेशन सिस्टम को अपनाया गया। इन डिजिटल प्रयासों ने मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर प्रौद्योगिकी को अपनाने एवं संस्थागत क्षमता निर्माण को बढ़ावा देकर सहकारी तंत्र को और अधिक सुदृढ़ किया।

एनडीडीबी एवं एनडीएस के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह, एनडीडीबी के कार्यपालक निदेशक श्री एस. रघुपति, एनडीडीबी के कार्यपालक निदेशक श्री एस. राजीव, एनडीएस के प्रबंध निदेशक डॉ. सीपी देवानंद और झारखंड दूध महासंघ (JMF) के उप प्रबंध निदेशक श्री जयदेव विश्वास की उपस्थिति में कोच्चि में आईडीएफ आरडीसी 2024 में एनडीईआरपी परियोजना का शुभारंभ करते हुए

एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह राजस्थान के डूंगरपुर में महिला डेयरी किसानों को कार्बन क्रेडिट के लिए डिजिटल रुपये सौंपते हुए

एनडीडीबी डेयरी ईआरपी (NDERP)

एनडीईआरपी इकाई ने डेयरी क्षेत्र के लिए एक किफ़ायती एवं एकीकृत ईआरपी प्रणाली के विकास और रखरखाव पर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रयास के अंतर्गत एक ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म को शामिल किया गया तथा उसे स्वचालित दूध संकलन प्रणाली (AMCS) के साथ एकीकृत किया गया। इस प्रमुख मॉड्यूल्स में लेखा, क्रय, इन्वेंटरी, बिक्री, उत्पादन एवं गुणवत्ता तथा मानव संसाधन एवं पेरोल सम्मिलित रहे। इन वितरकों की सुविधा हेतु मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध कराए गए। साथ ही, डिजिटल वर्कफ़्लो और बिल ऑफ़ मटीरियल (BOM) एकीकरण के माध्यम से मास बैलेंसिंग और उत्पादन प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया गया। यह प्रणाली विभिन्न दूध उत्पादों हेतु जटिल बीओएम कन्फ़िग्युरेशन्स का भी समर्थन करती है, जिससे उत्पादन प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण अधिक प्रभावी और पारदर्शी हो सके।

एनडीईआरपी प्रणाली को देशभर की नौ संस्थाओं में लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य इसके डिजिटलीकृत मास बैलेंसिंग सोल्यूशन के माध्यम से फैट एवं सॉलिड-नॉट-फ़ैट (SNF) की हानि को कम करना है। यद्यपि एसएनएफ हानि में हुई विशिष्ट प्रतिशत कमी का मूल्यांकन अभी जारी है, तथापि यह प्रणाली हानियों की पहचान एवं मापन में सक्षम है। इसे अपनाने से एक किफ़ायती समाधान उपलब्ध हुआ है, जिससे परिचालन दक्षता में वृद्धि हुई है और आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। इस पहल में प्राथमिक सहयोग राज्य एवं क्षेत्रीय दूध महासंघों तथा संघों के साथ स्थापित किया गया है।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) पायलट कार्यान्वयन

एनडीडीबी ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ साझेदारी में राजस्थान के डूंगरपुर में सीबीडीसी पायलट को लागू किया। इस परियोजना के तहत ग्रामीण उपयोगकर्ताओं के लिए वॉलेट-आधारित ऑनबोर्डिंग और मोबाइल एक्सेस के माध्यम से डिजिटल रुपये, आरबीआई की आधिकारिक डिजिटल मुद्रा की शुरूआत की गई।

एनडीडीबी ने 94 महिला डेयरी किसानों को कार्बन क्रेडिट भुगतान के लिए डिजिटल रुपये के उपयोग की सुविधा दी। यह डेयरी क्षेत्र में सीबीडीसी का पहला एप्लीकेशन है जिसने पारदर्शिता और डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया। इस परियोजना ने यह प्रदर्शित किया कि कैसे डिजिटल भुगतान और सस्टेनेबल पद्धितियों को एकीकृत करके हाशिए पर रहने वाले समुदायों का समर्थन किया जा सकता है, जो एनडीडीबी के समावेशी विकास लक्ष्यों के अनुरूप है।

वीर्य केंद्र प्रबंधन प्रणाली (SSMS)

एसएसएमएस यूनिट ने एक व्यापक सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म विकसित और लागू किया है, जिसे वीर्य केंद्रों पर एफएसडी उत्पादन प्रक्रिया को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल (MSP) का पालन सुनिश्चित किया जा सके। यह प्लेटफ़ॉर्म कई मॉड्यूलों को शामिल करता है, जिनमें सांड़ लाइफ साइकल प्रबंधन, वीर्य उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, बिक्री

और सीआरएम, बायोसिक्योरिटी और फार्म व फॉडर प्रबंधन शामिल हैं। उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोगशाला उपकरणों, आईएफआईडी टैग्स, कंफ़िगरेबल वर्कफ़्लोज़ और बारकोड सिस्टम के समेकन ने पूरी प्रक्रिया में ट्रेसबिलिटी और जवाबदेही को बढ़ाया है।

वर्तमान में, भारत के 38 ग्रेडेड वीर्य केंद्र इस एसएसएमएस प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रणाली के कार्यान्वयन ने संचालन को मानकीकृत किया, एमएसपी दिशानिर्देशों के पालन को सुनिश्चित किया और एफएसडी उत्पादन की कुशलता, सटीकता और ट्रेसबिलिटी में सुधार किया। इस पहल में सहयोग के लिए पूरे देश के वीर्य केंद्र शामिल हैं, जो अक्सर राज्य पशुधन बोर्ड या कृषि विश्वविद्यालयों से जुड़े होते हैं।

इंटरनेट-आधारित डेयरी सूचना प्रणाली (i-DIS)

एनडीडीबी ने इंटरनेट-आधारित डेयरी सूचना प्रणाली (i-DIS) को लागू और विकसित करना जारी रखा, जो डेयरी सहकारी समितियों में संरचित डेटा प्रबंधन के लिए एक वेब-सक्षम प्लेटफ़ॉर्म है। इस प्रणाली ने डेटा संग्रह, सत्यापन और विश्लेषण में सुधार किया, जिससे डेयरी क्षेत्र में योजना निर्माण और नीति निर्धारण में सहायता मिली।

i-DIS का एक सरलीकृत संस्करण विकसित किया गया ताकि भाग लेने वाले संस्थानों में पहुंच और उपयोगिता बढ़ाई जा सके। 250 से अधिक दूध संघ, मार्केटिंग डेयरियां, पशु आहार संयंत्र और राज्य दूध महासंघ इस प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, जिससे प्रमुख संचालन और प्रदर्शन मीट्रिक का व्यवस्थित ट्रैकिंग संभव हुआ।

एनडीडीबी ने प्लेटफ़ॉर्म के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी और परामर्श सहायता प्रदान की। प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) कार्मिकों के लिए पुनश्चर्या कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें डेटा रिपोर्टिंग, सिस्टम उपयोग और विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

ये डिजिटल पहल डेयरी सहकारी नेटवर्क में सूचना प्रणालियों और शासन को मजबूत करने में योगदान दे रही हैं।

मिल्क रूट ऑप्टिमाइजेशन

एनडीडीबी ने मिल्क प्रोक्योरमेंट रूट ऑप्टिमाइजेशन पहल शुरू की ताकि डेयरी मूल्य श्रृंखला में संचालन कुशलता बढ़ाई जा सके और लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया जा सके। दूध परिवहन संचालन व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसके कारण रूट प्लानिंग को लागत में बचत और सस्टेनेबिलिटी उपाय के रूप में प्राथमिकता दी गई।

एनडीडीबी ने विदर्भ–मराठवाड़ा डेयरी विकास परियोजना (VMDDP) के अंतर्गत एक पायलट परियोजना लागू की, जिसमें एक मिल्क चिलिंग सेंटर को शामिल किया गया। परिणामों के आधार पर इस पहल को चार अन्य केंद्रों में भी विस्तारित किया गया। इस गतिविधियों से परिवहन लागत में प्रतिवर्ष लगभग 45 लाख रुपये की बचत हुई।

इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए एनडीडीबी ने वेब-आधारित समाधान डेयरी रूट ऑप्टिमाइज़र (DRO) विकसित किया। इस उपकरण ने स्थानिक मानचित्रण और लॉजिस्टिक एल्गोरिदम का उपयोग करके मिल्क प्रोक्योरमेंट रूटों का वास्तविक समय में ऑप्टिमाइजेशन संभव बनाया। एनडीडीबी ने दूध संघों और उत्पादक संगठनों में अपनाने को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान की।

इसके क्रियान्वयन से माही दूध उत्पादक संगठन को प्रतिवर्ष लगभग 2.2 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत हुई। पश्चिमी असम दूध संघ ने प्रतिवर्ष 23 लाख रुपये के बचत की जानकारी दी। डीआरओ के अपनाने से मार्ग दूरी, यात्रा समय, ईंधन उपयोग और उत्सर्जन कम हुआ, जिससे सस्टेनेबलिटी प्रयासों को बढ़ावा मिला।

इसके अलावा आशा, सहज, बानी, हरित प्रदेश दूध उत्पादक संगठन, औरंगाबाद दूध संघ और झारखंड दूध महासंघ द्वारा भी डीआरओ को अपनाया गया। प्रारंभिक परिणामों ने लागत में कमी और संसाधनों के बेहतर उपयोग को दर्शाया।

स्वचालित दूध संकलन प्रणाली (AMCS)

एएमसीएस इकाई ने डेयरी सहकारी समितियों (DCS) के स्तर पर दूध संकलन के स्वचालन हेतु एक स्केलेबल डिजिटल सोल्यूशन के विकास एवं परिनियोजन पर ध्यान केंद्रित किया। इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर परिचालन को एकीकृत करना, पारदर्शिता बढ़ाना, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना तथा रियल टाइम में आंकड़ों को उपलब्ध कराना है। इस प्रणाली में ओपन-सोर्स तकनीक का उपयोग किया गया, जिससे मल्टी-प्लेटफ़ॉर्म और मल्टी-लैंग्वेज कार्यक्षमता संभव हो सकी। इलेक्ट्रॉनिक मिल्क एनालाइज़र के एकीकरण द्वारा रियल टाइम में डाटा संकलन सुनिश्चित हुआ। किसानों को त्वरित एसएमएस अलर्ट भेजे गए तथा मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से लाइव डाटा उपलब्ध कराया गया।

वर्तमान में यह प्रणाली 12 राज्यों में क्रियाशील है, जहां यह 25,000 से अधिक डीसीएस का समर्थन करती है और 15 लाख से अधिक दूध उत्पादकों को जोड़ती है। प्रतिदिन 60 मिलियन से अधिक दूध का संकलन इस प्रणाली से प्रोसेस किया जाता है। कर्नाटक दूध महासंघ में पूर्ण रूप से लागू होने से इस प्रणाली का प्रभाव स्पष्ट हो गया है। एएमसीएस ने पूर्व में मैन्युअल रूप से किए जाने वाले प्रक्रियाओं को स्वचालित कर दिया है, जिससे सटीकता एवं परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके परिनियोजन से पारदर्शिता में सुधार हुआ है और किसानों को सशक्त बनाया गया है, जिससे डेयरी सहकारी संरचना में बेहतर निर्णायक क्षमता को बढ़ावा मिला है। इस पहल में 12 राज्यों के राज्य दूध महासंघों एवं जिला दूध संघों के साथ सहयोग किया जा रहा है तथा क्षेत्रीय स्तर पर निजी डीसीएस स्थलों पर इसका परिनियोजन किया गया है।

डेयरी अवसंरचना का विस्तार

एनडीडीबी देश भर की डेयरी सहकारिताओं को बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विशिष्ट इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। प्रमुख गतिविधियों में नई प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना, मौजूदा डेयरी सुविधाओं और संस्थागत अवसंरचना के विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु संकल्पना, डिज़ाइन, योजना निर्माण, कार्यान्वयन और कमीशनिंग शामिल हैं। पशु आहार संयंत्रों, जैव-सुरक्षा प्रयोगशालाओं (BSL), पशु टीका उत्पादन सुविधाओं, हिमीकृत वीर्य केंद्रों आदि के लिए भी इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं। मौजूदा संयंत्रों का अध्ययन और मूल्यांकन आधुनिकीकरण, दक्षता में सुधार, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्पाद हानि को कम करने के लिए किया जाता है। हरित पहलों और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता के तहत, नवीकरणीय ऊर्जा (सौर ऊर्जा और बायोगैस) से संबंधित कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, डीएएचडी की डीआईडीएफ योजना के तहत निर्मित साबर दूध संघ के पशु आहार संयंत्र का उद्घाटन करते हुए। इस अवसर पर गुजरात विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और बनास डेयरी के अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी जी; गुजरात सरकार के माननीय उद्योग मंत्री श्री बलवंतसिंह राजपूत जी; गुजरात सरकार के माननीय कृषि, पशुपालन, गौ-प्रजनन और मत्स्यपालन मंत्री श्री राघवजीभाई पटेल जी; गुजरात सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री श्री जगदीश विश्वकर्मा जी, संसद और विधान सभा के सदस्य, एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह; साबर डेयरी और जीसीएमएमएफ के अध्यक्ष श्री शामलभाई पटेल और जीसीएमएमएफ के प्रबंध निदेशक श्री जयेन मेहता भी उपस्थित रहे

भारत के माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी, एनडीडीबी और इरमा के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह; इरमा के निदेशक डॉ. उमाकांत दाश; इरमा बोर्ड के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति इरमा के बहुमंजिला छात्रावास भवन के उद्घाटन के दौरान

वर्ष के दौरान, छह इंजीनियरिंग परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनमें एक मूल्यवर्धित डेयरी उत्पाद संयंत्र, दो अपशिष्ट उपचार संयंत्र, एक पशु आहार संयंत्र, एक सांड़ पालन केंद्र और एक शैक्षणिक संस्थान के लिए एक बुनियादी अवसंरचना विस्तार परियोजना शामिल है। ये परियोजनाएं देश भर में विभिन्न स्थानों पर क्रियान्वित की गईं। इन इंजीनियरिंग परियोजनाओं के क्रियान्वयन में, सस्टेनेबल समाधानों के साथ ऊर्जा-दक्ष अत्याधुनिक तकनीकों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अतिरिक्त, पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी को बढावा देने हेतु दो सौर पैनल परियोजनाएं क्रियान्वित की गई।

बरौनी, बिहार में 2 एलएलपीडी क्षमता वाला दूध उत्पाद संयंत्र

यह संयंत्र देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (बरौनी डेयरी) के लिए फर्मेंटेड और विभिन्न प्रकार के स्थानीय उत्पादों का उत्पादन करता है। उत्पाद श्रेणी में फर्मेंटेड उत्पाद जैसे कि साधारण दही (20 एमटीपीडी), मीठा दही (1.6 एमटीपीडी), लस्सी (14 टीएलपीडी) शामिल हैं। साथ ही, इस संयंत्र में निम्नलिखित मूल्यवर्धित स्थानीय उत्पादों का भी उत्पादन किया जाता है: पनीर (600 किग्रा/घंटा), खोआ (3.8 एमटीपीडी), पेड़ा (2.8 एमटीपीडी), कलाकंद (1.8 एमटीपीडी), मिल्क केक (0.6 एमटीपीडी), रसगुल्ला (9 एमटीपीडी), गुलाब जामुन (9 एमटीपीडी), रसकदम (0.6 एमटीपीडी), चमचम (2 एमटीपीडी) और सुधा सुरभि रबड़ी (8 एमटीपीडी)।

इस संयंत्र की मुख्य विशेषता एससीएडीए आधारित ऑटोमेटेड प्रणाली युक्त इसका ऑटोमेटेड पनीर लाइन है।

यह अत्याधुनिक सुविधा भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा फरवरी 2024 में उद्घाटित की गई।

इरमा, आणंद, गुजरात में आधारभूत अवसंरचना का विस्तार

एनडीडीबी ने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद (इरमा) के लिए एक बहुमंजिला छात्रावास भवन के निर्माण हेतु एक इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना क्रियान्वित की है। यह भवन सुरक्षा के लिए नवीनतम अग्निशमन प्रणालियों, कई लिफ्टों और अन्य मनोरंजक सुविधाओं से सुसज्जित है। एक हरित पहल के रूप में, यहां एक सौर पीवी प्रणाली और सीवेज वाटर ट्रीटमेंट के लिए एक एसटीपी स्थापित किया गया है।

यह अत्याधुनिक सुविधा भारत के माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी द्वारा जून 2024 में उद्घाटित की गई।

मलारपुरा, खेड़ा, गुजरात में सांड पालन केंद्र की स्थापना

एनडीडीबी ने एसएजी मलारपुरा में 180 पशुओं की क्षमता वाले एक आधुनिक सांड पालन केंद्र तथा 50 पशुओं की क्षमता वाले प्री-क्वॉरन्टीन स्टेशन की स्थापना की है। इस परियोजना में सभी आवश्यक सहायक अवसंरचनाएं एवं जैव-सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस परियोजना की एक प्रमुख विशेषता प्री-इंजीनियर्ड प्रीफैब्रिकेटेड सैंडविच्ड रिजिड पॉलीयूरेथेन रूफिंग पैनल्स का उपयोग है, जो तापमान को नियंत्रित कर पशुओं को बेहतर आराम प्रदान करते हैं। यह परियोजना मई 2024 में पूर्ण की गई।

हिम्मतनगर, गुजरात में पशु आहार संयंत्र

साबर दूध संघ, हिम्मतनगर, गुजरात के लिए 800 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाले पूर्णतः स्वचालित अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र की स्थापना हेतु परियोजना का सफल क्रियान्वयन एनडीडीबी द्वारा किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत एनडीडीबी ने सिविल कार्यों का निष्पादन किया तथा यांत्रिक कार्यों हेतु तकनीकी परामर्श सेवाएं भी प्रदान कीं। इस संयंत्र को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित किया गया है, जिससे संचालन अधिक दक्षतापूर्वक हो सके और कच्चे माल की बर्बादी को कम किया जा सके।

यह संयंत्र भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा नवंबर 2024 में उद्घाटित किया गया।

जयपुर डेयरी, जयपुर, राजस्थान में टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना

एनडीडीबी ने रिड्यूस–रीयूज़–रीसायकल (3R) रणनीति को अपनाते हुए जयपुर दूध संघ, जयपुर में 500 केएलडी क्षमता वाला टर्शियरी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया है। यह संयंत्र एमबीआर, आरओ एवं एमवीआर एवापोरेशन तकनीक पर आधारित है और ज़ीरो लिक्विड अपशिष्ट उत्सर्जन नीति को सुनिश्चित करता है। इस उन्नत शोधन प्रणाली के माध्यम से अपशिष्ट जल का लगभग 90 प्रतिशत पुनः प्राप्त किया जाता है, जिससे डेयरियों के वॉटर फुटप्रिंट में कमी आती है। इस परियोजना के परिणामस्वरूप बाहरी स्रोतों से जल पर निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आई है। यह समेकित व्यवस्था उच्च स्तर की जल पुनः प्राप्ति कर, पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर तथा नियामक अनुपालन सुनिश्चित कर सस्टेनेबल वॉटर मैनेजमेंट को प्रोत्साहित करती है।

साबर डेयरी, हिम्मतनगर, गुजरात में न्यू एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (पीएच II)

साबर डेयरी, हिम्मतनगर में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP) परियोजना के द्वितीय चरण का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। इस संयंत्र की उपचार क्षमता 2000 केएलडी है, जो मौजूदा समान क्षमता वाले ट्विन-स्ट्रीम ईटीपी का विस्तार होगा। इस विस्तार से डेयरी की कुल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट क्षमता दोगुनी होकर 4000 केएलडी हो गई।

मलारपुरा, खेड़ा, गुजरात में आधुनिक सांड पालन केंद्र

बनास सुज़ुकी – गोबर आधारित सीबीजी संयंत्र, भुखला – वडगाम, गुजरात में निर्माणाधीन

डेयरी संयंत्रों की एनर्जी ऑडिट एवं परिचालन दक्षता का अध्ययन

डेयरी उद्योग में उत्पादन लागत को अनुकूलित और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करके दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के निरंतर प्रयास जारी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एनडीडीबी परिचालन दक्षता में सुधार हेतु एनर्जी ऑडिट और संयंत्र का अध्ययन कर रही है। एनडीडीबी ने हाल ही में मेगा डेयरी, बेंगलुरु कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन लिमिटेड में एनर्जी स्टडी का संचालन किया है।

वर्तमान में चल रही प्रमुख परियोजनाओं का उद्देश्य दक्षता में वृद्धि, पर्यावरणीय प्रभाव में कमी तथा डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांग को अधिक सस्टेनेबल एवं नैतिक तरीके से पूरा करना है।

जीसीएमएमएफ के लिए राजकोट में अमूलफेड–II डेयरी

राजकोट, गुजरात में 20 एलएलपीडी क्षमता वाली अत्याधुनिक पूर्णतः स्वचालित डेयरी तथा 150 एमटीपीडी क्षमता वाले पाउडर प्लांट की स्थापना की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 990 करोड़ रुपये है। इस वर्ष परियोजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु व्यापक रूप से गति प्रदान की गई है। इस परियोजना के दायरे में लगभग 4 एलएलपीडी क्षमता वाला यूएचटी प्रोसेसिंग–एसेप्टिक पैकेजिंग प्लांट, 100 एमटीपीडी क्षमता वाला बटर प्लांट तथा 40 एमटीपीडी क्षमता वाला घी निर्माण संयंत्र भी शामिल हैं। इन सभी इकाइयों का निर्माण स्वच्छ डिज़ाइनों पर आधारित ऊर्जा दक्षता हेतु अत्याधुनिक उन्नत तकनीकों का उपयोग करके किया जाएगा।

मोहाली, पंजाब में स्वचालित डेयरी संयंत्र की स्थापना

रोपड़ दूध संघ, मोहाली (पंजाब) के लिए 5 एलएलपीडी क्षमता वाला पूर्णतः स्वचालित अत्याधुनिक तरल दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इस सुविधा में 50 एमटीपीडी तक फर्मेंटेड दूध उत्पाद (जैसे दही) के उत्पादन की क्षमता भी होगी। इस परियोजना का कुल व्यय 280 करोड़ रुपये निर्धारित है। इस परियोजना के दायरे में 1500 केएलडी क्षमता वाला एफ़्लुएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल है, जो संयंत्र से उत्पन्न अपशिष्ट का दक्षतापूर्वक शोधन करेगा। इस संयंत्र का स्वचालन सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विज़िशन (SCADA) तकनीक पर आधारित है, जिसे प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे परिचालन संबंधी आंकड़ों का स्वचालित रूप से निरीक्षण, संग्रहण एवं भंडारण सुनिश्चित होता है।

अमृतसर, पंजाब में स्वचालित फर्मेंटेड उत्पाद संयंत्र

अमृतसर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ, अमृतसर (पंजाब) के लिए 2.35 एलएलपीडी क्षमता वाला स्वचालित फर्मेंटेड उत्पाद संयंत्र वर्तमान में निर्माणाधीन है। इस संयंत्र में 75 एमटीपीडी दही, 1.50 एलएलपीडी लस्सी तथा 10 टीएलपीडी मीठे एवं फ्लेवर्ड दूध उत्पाद के उत्पादन की क्षमता होगी। इस संयंत्र की एक प्रमुख विशेषता इसकी विविध प्रकार के फर्मेंटेड उत्पादों को विभिन्न एसकेयू स्वरूपों में उत्पादन करने की क्षमता है। इनमें टोंड मिल्क दही एवं डबल टोंड मिल्क दही (पाउच, कप एवं मटका पैकिंग में) तथा विभिन्न प्रकार की लस्सी जैसे मीठी लस्सी, मसाला लस्सी एवं लो-फैट लस्सी शामिल हैं। इस परियोजना का कुल परिव्यय 123.50 करोड़ रुपये निर्धारित है।

गुलाबपुरा, भीलवाड़ा में पशु आहार संयंत्र

गुलाबपुरा, भीलवाड़ा में एक आधुनिक 150 टीपीडी पशु आहार संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसे आगे चलकर 300 टीपीडी तक विस्तारित किया जा सकेगा। इस प्लांट में पूर्णत: स्वचालित संचालन प्रणाली होगी।

इस परियोजना का कुल परिव्यय 63.04 करोड़ रुपये है।

भिलाड़ी, बनास में सीओई एवं बीबीआरसी की स्थापना

अधिक उत्पादक दुधारु पशुओं की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से, वैज्ञानिक प्रजनन तकनीकों (जिसमें आईवीएफ तकनीक एवं सेक्स्ड सॉर्टेड सीमन शामिल हैं) के माध्यम से, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस – बनास बोवाइन ब्रीडिंग एवं रिसर्च सेंटर की स्थापना की जा रही है। यह केंद्र भिलाडी, बनासकांठा ज़िला, गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना का कुल परिव्यय 197.20 करोड़ रुपये है।

सीसीएसएनआईएएच बागपत में बायो-कंटेनमेंट सुविधा का विकास

यह संस्थान पशु टीकों एवं डायग्नोस्टिक्स के गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय सुविधा के रूप में कार्य करता है। इस संस्थान का प्रमुख कार्य पशुओं के बायोलोजिकल उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण का परीक्षण करना है, ताकि टीकों की प्रभावशीलता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु गुणवत्ता नियंत्रण प्रोटोकॉल के परिष्करण हेतु डेटा उपलब्ध कराया जा सके तथा पशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहयोग किया जा सके। वर्तमान नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप, संस्थान की बीएसएल–3 एवं एबीएसएल–3 सुविधाओं का विकास एवं आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इस परियोजना की कुल परिव्यय 160 करोड़ रुपये है।

निम्नलिखित चालू परियोजनाओं की सूची निम्नानुसार है:

परियोजना	क्षमता	स्थान
उत्तरी क्षेत्र		
स्वचालित डेयरी एवं ईटीपी की स्थापना	5 एलएलपीडी एलएमडी एवं 15 एलएलपीडी ईटीपी	मोहाली, पंजाब
डेयरी संयंत्र की स्थापना	50 टीएलपीडी (विस्तार योग्य 100 टीएलपीडी तक)	राजसमंद, राजस्थान
डेयरी संयंत्र का विकास एवं सुदृढ़ीकरण	50 टीएलपीडी	बांसवाड़ा, राजस्थान
पशु आहार संयंत्र	150 एमटीपीडी	भीलवाड़ा, राजस्थान
यूएचटी संयंत्र	25 टीएलपीडी	भीलवाड़ा, राजस्थान
मूल्य संवर्धित दुग्ध उत्पादों सहित स्वचालित डेयरी	1.5 एलएलपीडी (विस्तार योग्य 3 एलएलपीडी तक)	कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
हिमीकृत वीर्य केंद्र का सुदृढ़ीकरण	--	खन्ना, पंजाब
फर्मेंटेड उत्पाद संयंत्र एवं मीठे फ्लेवर्ड दूध संयंत्र का विस्तार	2.35 एलएलपीडी	अमृतसर, पंजाब
बायो कंटेनमेंट फ़ैसिलिटी का विकास एवं संबद्ध मरम्मत कार्य, सीसीएसएनआईएएच	--	बागपत, उत्तर प्रदेश
पश्चिमी क्षेत्र		
अमूलफेड-II डेयरी	एलएमपी 20 एलएलपीडी, पाउडर संयंत्र – 150 एमटीपीडी, बटर संयंत्र – 100 एमटीपीडी, घी निर्माण संयंत्र – 40 एमटीपीडी तथा यूएचटी प्रोसेसिंग-एसेप्टिक पैकेजिंग संयंत्र – 4 एलएलपीडी	राजकोट, गुजरात
पशु आहार संयंत्र (सिविल कार्य)	800 एमटीपीडी (विस्तार योग्य 1600 एमटीपीडी तक)	हिम्मतनगर, गुजरात
बनास-सुज़ुकी – गोबर आधारित सीबीजी संयंत्र	गोबर – 100 एमटीपीडी (1.5 एमटीपीडी सीबीजी)	भुखाला – वडगाम, गुजरात
बनास-सुज़ुकी – गोबर आधारित सीबीजी संयंत्र	गोबर – 100 एमटीपीडी (1.5 एमटीपीडी सीबीजी)	अगथला – लखानी, गुजरात

परियोजना	क्षमता	स्थान
साबरमती आश्रम गौशाला में इन्फ्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्ट	--	बीडज, गुजरात
एनसीडीएफआई हेतु इन्फ्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्ट	--	आणंद, गुजरात
वीर्य केंद्र का सुदृढ़ीकरण	--	एसएजी, बिडज
मदर डेयरी में मूल्य संवर्धित उत्पादों एवं पाउडर संयंत्र सहित डेयरी संयंत्र की स्थापना	एलपीडी – 6 एलएलपीडी (विस्तार योग्य 10 एलएलपीडी तक), पाउडर संयंत्र – 30 एमटीपीडी, फर्मेंटेड उत्पाद संयंत्र – 150 एमटीपीडी, पनीर संयंत्र – 3 एमटीपीडी, फ्लेवर्ड मिल्क – 5 एमटीपीडी, आइसक्रीम संयंत्र – 25 टीएलपीडी	नागपुर, महाराष्ट्र
भिलाड़ी, बनास में सीओई एवं बीबीआरसी की स्थापना	--	भिलाड़ी, बनास, गुजरात
दक्षिणी क्षेत्र		
वीर्य केंद्र का सुदृढ़ीकरण एवं संबद्ध कार्य	--	हेसारघट्टा, कर्नाटक
आईआईएल, हैदराबाद में नया पशु टीका उत्पादन संयंत्र (एफएमडी+एचएस)	--	कारकपटला, तेलंगाना
स्वचालित डेयरी संयंत्र	2 एलएलपीडी	नमक्कल, तमिलनाडु
(i) इन-विट्रो डायग्नोस्टिक री-एजेंट्स (ब्रूसेला एवं डायग्नोस्टिक्स) – जीएमपी ग्रेड सुविधा की स्थापना, आईवीपीएम, रानीपेट; (ii) औषधि विभाग (जीएमपी ग्रेड) (ऑइंटमेंट एंड लिनिमेंट फ़ैसिलिटी)	--	आईवीपीएम, रानीपेट, तमिलनाडु
पूर्वी क्षेत्र		
संयंत्र उपयोगिता सेवाओं का सुदृढ़ीकरण	--	बरौनी, बिहार
5 एलएलपीडी स्वचालित डेयरी संयंत्र में अतिरिक्त कार्य	--	अरिलो-गोविंदपुर, ओडिशा
पाउडर संयंत्र की स्थापना	20 एमटीपीडी	होटवार, रांची, झारखंड
दूध उत्पाद संयंत्र की स्थापना	--	होटवार, रांची, झारखंड
मूल्य संवर्धित उत्पादों सहित डेयरी संयंत्र की स्थापना	50 टीएलपीडी (विस्तार योग्य 1 एलएलपीडी तक)	जमशेदपुर, रांची, झारखंड
मूल्य संवर्धित उत्पादों सहित डेयरी संयंत्र की स्थापना	50 टीएलपीडी (विस्तार योग्य 1 एलएलपीडी तक)	गिरिडीह, रांची, झारखंड
गोबर आधारित बायोगैस संयंत्र	100 एमटीपीडी	बरौनी, बिहार
टीका उत्पादन सुविधा की स्थापना	एंथ्रेक्स – 5 मिलियन डोज प्रति वर्ष; एंटरोटॉक्सिमिया – 20 मिलियन डोज प्रति वर्ष	बेरहामपुर, ओडिशा

तकनीकी परामर्श सेवाएं

परियोजना	क्षमता	स्थान
मिल्क पाउडर संयंत्र	120 एमटीपीडी	महेसाणा, गुजरात
बीएसएल-4 प्रयोगशाला, जीबीआरसी	--	गांधीनगर, गुजरात
फर्मेंटेड उत्पाद संयंत्र	दही – 100 (विस्तार योग्य 150 एमटीपीडी), योगर्ट – 5 (विस्तार योग्य 10 एमटीपीडी)	रोहतक, हरियाणा
गौ अभयारण्य	--	मुज़फ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
स्वदेशी गौवंशीय नस्लों के आनुवंशिक सुधार हेतु उत्कृष्टता केंद्र	--	एसवी गौसंरक्षण शाला, तिरुपति, आंध्र प्रदेश

टीएलपीडी – प्रतिदिन हजार लीटर **टीपीडी** – टन प्रतिदिन **एलएलपीडी** – प्रतिदिन लाख लीटर

विकास हेतु रणनीतिक साझेदारियां

एनडीडीबी ने ज्ञान के आदान-प्रदान को सुगम बनाने, तकनीकी और प्रक्रिया नवाचारों को बढ़ावा देने, संस्थागत एवं मानवीय क्षमताओं को सुदृढ़ करने तथा डेयरी क्षेत्र की सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से साक्ष्य-आधारित समाधान प्रदान करने हेतु प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ साझेदारी की। इन प्रयासों से डेयरी क्षेत्र में उत्पादकता, संसाधन दक्षता और जलवायु अनुकूलता बढ़ाने में योगदान मिला, जिससे डेयरी किसानों की आजीविका में सुधार हुआ।

एनडीडीबी के हीरक जयंती समारोह, आणंद के अवसर पर श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में एनडीडीबी, एसआरडीआई और कैरा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय एमओयू का आदान-प्रदान करते हुए

गुजरात में गोबर आधारित बायो-सीएनजी संयंत्रों की स्थापना हेतु एमओयू

एनडीडीबी ने सुज़ुकी आर एंड डी सेंटर इंडिया प्रा. लि. (SRDI), कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (KDCMPUL) तथा महेसाणा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों के अंतर्गत गुजरात में दो गोबर-आधारित कम्प्रैस्ड बायोगैस (CBG) संयंत्रों की स्थापना का प्रावधान है। इस सहयोग का विस्तार अब बनास डेयरी को सम्मिलित कर और व्यापक किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य पशु गोबर को कम्प्रैस्ड बायोगैस एवं ऑर्गेनिक उर्वरक में परिवर्तित करना है। इसके माध्यम से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाई जाएगी और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।

एनडीडीबी इस परियोजना के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी, जबकि एसआरडीआई वित्तीय एवं इंजीनियरिंग विशेषज्ञता उपलब्ध कराएगी। यह साझेदारी बायोगैस संयंत्रों की डिज़ाइन एवं दक्षता में नवाचार को बढ़ावा देगी। यह परियोजना डेयरी एवं ऑटोमोबाइल क्षेत्रों के संमिलन का उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो कृषक हितैषी सर्कुलर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित कर पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देगी।

इन संयंत्रों से गोबर का बेहतर उपयोग होने, फॉर्म स्तर पर मीथेन उत्सर्जन में कमी आने, स्वच्छ ईंधन एवं उच्च गुणवत्ता वाले ऑर्गेनिक खाद के उत्पादन की संभावना है। इस प्रकार, यह परिणाम एनर्जी ट्रांज़िशन, सस्टेनेबल कृषि और अपशिष्ट-से-समृद्धि जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

एनडीडीबी, एसआरडीआई और टीईआरआई के बीच त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर

सस्टेनेबल विकास पहलों हेतु त्रिपक्षीय एमओयू

एनडीडीबी ने द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) तथा सुज़ुकी आर एंड डी सेंटर इंडिया प्रा. लि. (SRDI) के साथ डेयरी एवं संबद्ध ग्रामीण क्षेत्रों में सस्टेनेबल विकास को बढ़ावा देने हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का केंद्रबिंदु नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां, सर्कुलर अर्थव्यवस्था मॉडल तथा प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियां रहीं।

इन तीनों संगठनों की तकनीकी विशेषज्ञताओं के एकीकरण से यह संयुक्त पहल पर्यावरणीय सस्टेनेबिलटी एवं ग्रामीण विकास को सहयोग प्रदान करती है। इन प्रमुख उपलब्धियों में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा, कार्बन उत्सर्जन में कमी तथा अपशिष्ट प्रबंधन दक्षता में सुधार शामिल रहे। यह पहल नेट-ज़ीरो डेयरिंग के प्रति एनडीडीबी की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

बनासकांठा, गुजरात में पांचवें बायो-सीएनजी संयंत्र हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर

एनडीडीबी ने सुज़ुकी आर एंड डी सेंटर इंडिया प्रा. लि. तथा बनास डेयरी के साथ बनासकांठा, गुजरात में पांचवें बायो-सीएनजी संयंत्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना, पशु अपशिष्ट से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के पूर्ववर्ती सफल प्रयासों का विस्तार है। इस पहल का उद्देश्य बायोगैस संयंत्रों की दक्षता में वृद्धि करना तथा रूरल मोबिलिटी परियोजना का प्रायोगिक कार्यान्वयन करना है, जिससे डेयरी क्षेत्र में सर्कुलर जैव-अर्थव्यवस्था मॉडल को प्रोत्साहन मिलेगा।

एनडीडीबी, एसआरडीआई और बनास डेयरी के बीच पांचवें बायो-सीएनजी संयंत्र के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करते हुए, इस अवसर पर गुजरात विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और बनास डेयरी के अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी, सुज़ुकी मोटर कॉर्पोरेशन, जापान के अध्यक्ष श्री टी सुज़ुकी, सुज़ुकी मोटर कॉर्पोरेशन, जापान के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री केनिचिरो आयुकावा भी उपस्थित रहे

एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह ने एनसीआर क्षेत्र के डेयरी के लिए कार्यात्मक योजना पर हितधारक परामर्श कार्यशाला के उद्घाटन भाषण के दौरान, इस अवसर पर एनसीआरपीबी की सदस्य सचिव सुश्री अर्चना अग्रवाल, भारत सरकार की अपर सचिव सुश्री वर्षा जोशी, डीएएचडी, एनसीआरपीबी के मुख्य क्षेत्रीय योजनाकार श्री जगमोहन सिंह और एनडीडीबी के कार्यपालक निदेशक श्री एस. रघुपति भी उपस्थित रहे

एनसीआर क्षेत्रीय योजना 2041 के अंतर्गत कार्यात्मक योजना तैयार करने हेतु परामर्श कार्य

प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के उपरांत, एनडीडीबी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) द्वारा एक परामर्श परियोजना सौंपी गई। इस परामर्श कार्य का उद्देश्य एनसीआर के डेयरी क्षेत्र के लिए एक भावी कार्यात्मक योजना तैयार करना है, जिसे क्षेत्र की व्यापक क्षेत्रीय योजना 2041 में सम्मिलित किया जाएगा। प्रस्तावित एनसीआर क्षेत्रीय योजना 2041 का विज़न है:" नवीन, जीवंत भारत के तकनीक-संचालित, भविष्योन्मुख राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास हेतु एक दीर्घकालिक योजना प्रदान करना, जिसमें नागरिक-केंद्रित आधारभूत संरचना के माध्यम से एक आर्थिक रूप से समृद्ध क्षेत्र का निर्माण हो, जो सस्टेनेबल विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के विधिवत अधिसूचित घटक क्षेत्रों में संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCT of Delhi) तथा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 24 जिले सम्मिलित हैं। चूंकि इस क्षेत्र में डेयरी एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है, इसलिए कार्यात्मक योजना को एनसीआर के डेयरी क्षेत्र के लिए 15 वर्षीय रोडमैप के रूप में तैयार किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र को भविष्योन्मुख बनाना और एनसीआर में दूध एवं दूध उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। इसके साथ ही, यह योजना क्षेत्र के लाखों डेयरी किसानों को बेहतर आजीविका उपलब्ध कराने में भी सहायक सिद्ध होगी।

एनसीआर देश का सबसे बड़ा दूध बाजार है और इस प्रकार यह अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख स्तंभों कृषि और उद्योग के बीच महत्वपूर्ण संपर्क एवं समन्वय विकसित करने में सहायक होगा तथा एनसीआर की आर्थिक वृद्धि में उचित योगदान देगी। इस कार्यात्मक योजना को तैयार करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल होंगे: अध्ययन, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण एवं अंतःस्थापन, रणनीतियों का निर्माण, प्रस्तावित गतिविधियों और क्षेत्रीय, उप-क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तर पर परियोजनाओं की पहचान। यह समस्त कार्य एनसीआर मसौदा क्षेत्रीय योजना–2041 की परिधि और समग्र फ्रेमवर्क के अंतर्गत किया जाएगा।

इस कार्यात्मक योजना में समग्र रूप से रणनीतियां, दृष्टिकोण, मार्गदर्शक सिद्धांत, चिह्नित अवसंरचना परियोजनाओं की सूची अनुमानित लागत सहित, स्थान-विशिष्ट प्रस्ताव/विवरण आदि सम्मिलित होंगे, जो मसौदा क्षेत्रीय योजना 2041 की समग्र नीतियों और प्रस्तावों के अनुरूप होंगे।

यह आशा है कि इससे डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट उत्पन्न होगा, जिसके परिणामस्वरूप विकास रणनीतियों की अन्य शहरी क्षेत्रों में पुनरावृत्ति होगी। साथ ही, एनसीआर में सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना में संभावित डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

डेयरी स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को सशक्त बनाने हेतु एमओयू

एनडीडीबी ने चारुसैट इनोवेटिव वेंचर्स फाउंडेशन (CIVF), चांग, गुजरात के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य डेयरी क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देना है। यह सहयोग एनडीडीबी की डेयरी मूल्य श्रृंखला में तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाकर स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने पर केंद्रित रहा।

एनडीडीबी ने सीआईवीएफ में इनक्यूबेट किए गए स्टार्ट-अप को रणनीतिक और तकनीकी सहयोग प्रदान किया। इसमें चारा विकास, किफायती प्रसंस्करण और दूध प्रबंधन में गुणवत्ता सुनिश्चित करना जैसी पहलें शामिल थीं। इस पहल से उद्यमियों को एनडीडीबी द्वारा प्रूवन मेथड्स अपनाने में सहायता मिली, जैसे - डेयरी उत्पादकता वृद्धि, सीएफयू नियंत्रण, एसएनएफ मानक और आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन। यह एमओयू डेयरी-केंद्रित स्टार्ट-अप की वाणिज्यिक तैयारी को बेहतर बनाने में मदद करेगा, जो नॉलेज शेयरिंग, क्षमता निर्माण और व्यावहारिक समाधान के माध्यम से संभव होगा। यह सहयोग आत्मनिर्भर और सस्टेनेबल ग्रामीण विकास संबंधी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है।

एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह और चारुसैट के प्रोवोस्ट डॉ. आर. वी. उपाध्याय के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान, सीआईवीएफ के निदेशक श्री अशोक पटेल; सीआईवीएफ के निदेशक श्री गिरीश पटेल; सीआईवीएफ की निदेशक श्रीमती मधुबेन पटेल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में करते हुए

डेयरी मूल्य श्रृंखला में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना

एनडीडीबी ने टाटा पावर रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड लिमिटेड (TPRMG) के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य ग्रामीण डेयरी क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का परिचय देना है। इस साझेदारी का लक्ष्य विकेंद्रीकृत, ऊर्जा-दक्ष प्रणालियों को लागू करना और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है।

एनडीडीबी और टीपीआरएमजी ने सहमति व्यक्त की कि वे सौर ऊर्जा आधारित गतिविधियों को डीसीएस, बल्क मिल्क कूलर्स (BMC), मिल्क चिलिंग सेंटर्स और प्रसंस्करण इकाइयों में लागू करेंगे। इस योजना में गांव स्तर पर ऊर्जा की पहुंच को बढ़ाने के लिए गोबर आधारित बायोगैस सिस्टम को माइक्रोग्रिड्स में एकीकृत करना भी शामिल है।

इस एमओयू में अन्य क्षेत्रों को भी कवर किया गया, जैसे – बायोगैस-आधारित रसोई, सौर ड्रायर और दूध व पेरिशेबल्स के लिए सोलर कोल्ड सस्टोरेज। इसमें डेयरी हितधारकों के लिए सौर प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हैं। यह साझेदारी एनडीडीबी के भारतीय डेयरी क्षेत्र में नेट-ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयासों का समर्थन करती है।

एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह और टीपीआरएमजी के सीईओ श्री मनोज गुप्ता के बीच एमओयू का आदान-प्रदान, सुश्री वर्षा जोशी, अपर सचिव, डीएएचडी, भारत सरकार और डॉ. प्रवीर सिन्हा, सीईओ, टाटा पावर की उपस्थिति में

डेयरी सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क (DSF) चरण 1 का कार्यान्वयन

डेयरी सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क (DSF), डेयरी क्षेत्र की एक वैश्विक पहल है, जिसका उद्देश्य सस्टेनेबिलिटी प्रगति को सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धा-मुक्त तरीके से मॉनिटर और रिपोर्ट करना है। विकासशील डेयरी अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, डीएसएफ ने स्टेज 1 सदस्यता स्तर के तहत अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग मेथडोलॉजी में सुधार किया।

एनडीडीबी भारत में डीएसएफ चरण 1 के पायलट परीक्षण में सक्रिय रूप से शामिल थी। यह पायलट दो संगठनों में कार्यान्वित की गई: झारखंड में झारखंड राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड (JMF) और आंध्र प्रदेश में श्रीजा महिला दूध उत्पादक कंपनी लिमिटेड (श्रीजा एमएमपीसीएल)। इस पायलट के दौरान निगरानी का मुख्य मानदंड 'ग्रामीण अर्थव्यवस्था' था, जिसमें दूध के लिए किसानों को किए गए भुगतान पर विशेष ध्यान दिया गया।

मुख्य संकेतक के अलावा, दोनों संस्थाओं ने स्थानीय सस्टेनेबल कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का विकल्प चुना जो उनकी क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। जेएमएफ ने खाद प्रबंधन पहल शुरू की, जबकि श्रीजा एमएमपीसीएल ने प्रमाणित बीजों का उपयोग करके हरा चारा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया।

चरण 1 पायलट के हिस्से के रूप में, स्थानीय प्रबंधन समूह (स्थानीय सलाहकार निकाय) बनाए गए और भौतिकता मूल्यांकन पर प्रशिक्षण शुरू किया गया। एनडीडीबी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, चरण 1 पायलट में जेएमएफ और श्रीजा एमएमपीसीएल की भागीदारी ने इन संगठनों को डिमॉन्स्ट्रेट मेज़रबल सस्टेनेबिलिटी प्रोग्रेस प्रदर्शित करने और वैश्विक डेयरी क्षेत्र के सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में योगदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया।

WOAH ट्विनिंग प्रोजेक्ट और IBR पर सेमिनार

IBR निदान पर द्विवार्षिक WOAH ट्विनिंग प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हुआ, जिसमें एनिमल एंड प्लांट हेल्थ एजेंसी, यूके (APHA, UK) के साथ सहयोग था। इस परियोजना ने एनडीडीबी आर एंड डी लैब की ISO/IEC 17025 और WOAH निदान मानकों के अनुरूपता की पुष्टि की। इस परियोजना ने IBR निदान में गुणवत्ता आश्वासन को भी मजबूत किया, जिसमें भारत में उपयोग के लिए रेफरेंस सीरा पैनल का विकास शामिल था। इस परियोजना के अंतर्गत IBR नियंत्रण पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें 55 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें WOAH और डीएडीएच के प्रतिनिधि, यूके, आयरलैंड, जर्मनी और डेनमार्क के विशेषज्ञ तथा एनआईवीईडीआई, आईवीआरआई, नेपाल, और श्रीलंका के वैज्ञानिक शामिल थे। यह सेमिनार IBR नियंत्रण के लिए निदान और रणनीतिक टीकाकरण को सुव्यवस्थित करने की सिफारिशों के साथ समाप्त हुआ।

डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी, आईबीआर के नियंत्रण पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में संबोधन के दौरान, जिसमें प्रोफेसर फाल्को स्टीनबाक, प्रमुख, मैमेलियन वायरोलॉजी, एनिमल एंड प्लांट हेल्थ एजेंसी (APHA), यूके और डॉ. डेविड ग्राहम, सीईओ, ऐनिमल हेल्थ, आयरलैंड उपस्थित रहे

एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह की उपस्थिति में एनडीडीबी और पीएनबी के बीच एमओयू का आदान-प्रदान

पंजाब नेशनल बैंक के साथ डेयरी क्षेत्र के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु एमओयू

एनडीडीबी ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र की लाभार्थी संस्थाओं,जैसे- दूध संघ/महासंघ, बहुराज्यीय सहकारी समितियों, उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं और एनडीडीबी की सहायक कंपनियां को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह पंचवर्षीय समझौता एनडीडीबी को तकनीकी समर्थन देने, योग्य संस्थाओं (BO) को समर्थन देने और मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है। पीएनबी, आरबीआई के दिशानिर्देशों और आंतरिक नीतियों के अनुसार टर्म लोन और कार्यशील पूंजी सहायता उपलब्ध कराएगी। यह सहयोग उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं के लिए डेयरी अवसंरचना के विस्तार और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। डेयरी अवसंरचना में निवेश करने से डेयरी मूल्य श्रृंखला की दक्षता में वृद्धि होगी।

पशु उत्पादकता वृद्धि हेतु वैज्ञानिक साझेदारियां

एनडीडीबी ने एनआईएबी, जीबीआरसी, बीएआईएफ, एएयू, कामधेनु विश्वविद्यालय, स्वायत्त संस्थान (सेंट थॉमस कॉलेज, पलई, केरल) और आईआईएल के साथ अनुसंधान साझेदारियां बनाए रखीं। इन साझेदारियों का मुख्य फोकस जीनोमिक्स, निदान, प्रजनन, पोषण और ईवीएम फॉर्म्यूलेशन्स के वैज्ञानिक सत्यापन पर था।

एनडीडीबी के अधिकारियों ने आईसीएआर और राष्ट्रीय समितियों में वीर्य केंद्र गुणवत्ता कार्यक्रम में भाग लिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने में सहयोग मिला।

ईवीएम उत्पादन और पहुंच को सुलभ बनाना

एनडीडीबी ने साबरकांठा, कैरा, बनासकांठा और कोल्हापुर दूध संघ में एथनो-वेटनरी मेडिसिन (EVM) इकाइयों की स्थापना के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की। इन इकाइयों ने लगभग 85 लाख ईवीएम उत्पाद गैर-लाभकारी आधार पर वितरित किए, जिससे किसानों के लिए पारंपरिक पशु चिकित्सा देखभाल अधिक सुलभ और किफायती बनी।

वित्त वर्ष 2024–25 में, नई ईवीएम इकाइयां झारखंड दूध महासंघ, वाराणसी दूध संघ और एबीसी सालोन द्वारा शुरू की गईं, जिससे ईवीएम समाधानों की पहुंच और बढ़ी। साथ ही, अनुसंधान संस्थानों ने ईवीएम फॉर्म्यूलेशन का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया, जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ मस्टाइटिस, इम्यून एन्हांसमेंट और एक्सटर्नल पैरासाइट कंट्रोल शामिल हैं। इससे आधुनिक पशु स्वास्थ्य प्रणाली में पारंपरिक विधियों की वैज्ञानिक विश्वसनीयता और प्रभावशीलता मजबूत हुई।

मानव संसाधन का प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास

एनडीडीबी ने सहकारी डेयरी क्षेत्र में संस्थागत एवं व्यक्तिगत क्षमता विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। क्षमता विकास की इन पहलों का उद्देश्य तकनीकी कौशल में सुधार लाना, परिचालन प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाना तथा दीर्घकालिक सस्टेनेबिलिटी को समर्थन प्रदान करना रहा।

श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने एनडीडीबी, आणंद में आयोजित 'सक्षम : नर्चरिंग वीमेन लीडर्स' कार्यक्रम में अपने उद्घाटन संबोधन के दौरान, जिसमें डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी तथा महिला डेयरी कृषक उपस्थित रहे

'मंथन' - एनडीडीबी और उसकी सहायक कंपनियों के लिए एक लीडरशीप कॉन्क्लेव

प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास

एनडीडीबी ने उत्पादक-स्वामित्व वाली संस्थाओं के समस्त प्रमुख हितधारकों, जिनमें दूध उत्पादक, पेशेवर एवं नीतिनिर्माता सम्मिलित हैं, की क्षमता वृद्धि हेतु एक वाइब्रेंट लर्निंग इकोसिस्टम के संवर्धन को निरंतर जारी रखा। प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के प्रयासों का मुख्य उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में सुधार तथा संपूर्ण डेयरी मूल्य श्रृंखला में सस्टेनेबल विकास को प्रोत्साहित करना रहा। इन प्रयासों के अंतर्गत ऐसा दक्ष कार्यबल विकसित करने पर बल दिया गया, जो बदलते हुए डेयरी उद्योग परिदृश्य के अनुरूप स्वयं को ढाल सके और उद्योग की निरंतर सफलता में सार्थक योगदान दे सके।

दूध उत्पादकों के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया। इसके अलावा, पहली बार लद्दाख के दूध उत्पादकों ने एनडीडीबी, आणंद में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवधि में 5,600 से अधिक किसानों को उन्नत पशुपालन पद्धतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसके माध्यम से उन्हें आधुनिक डेयरी तकनीकों द्वारा पशु उत्पादकता में सुधार हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई। विशेष रूप से, इन प्रशिक्षुओं में महिलाओं की भागीदारी 45 प्रतिशत से अधिक रही, जो एनडीडीबी की महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता तथा डेयरी व्यवसाय में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

वर्ष के दौरान लगभग 300 बोर्ड सदस्यों को सुशासन तथा नीतिनिर्माताओं की भूमिका पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इन प्रतिभागियों में 10 एफपीओ के लगभग 80 निदेशक मंडल के सदस्य सम्मिलित रहें।

उत्पादक-स्वामित्व वाली संस्थाओं में पेशेवरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः एनडीडीबी ने इन पेशेवरों के कौशल विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रों जैसे व्यवसाय एवं प्रशासन, संकलन एवं इनपुट, प्रसंस्करण, विपणन, संयंत्र संचालन, वित्तीय एवं रणनीतिक योजना आदि में प्रदान किया गया। भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों (EIA) के अधिकारियों - डीटीसी जीका तथा ए-हेल्प (स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार की मान्यता प्राप्त एजेंट) से संबद्ध को एनडीडीबी, आणंद में उन्नत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके बाद, उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में योगदान दिया। इस अवधि में 450 से अधिक अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनर्स को डीटीसी जीका एवं ए-हेल्प परियोजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया। साथ ही, 700 से अधिक डेयरी संयंत्र संचालकों को डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं के संचालन एवं रखरखाव पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

ए-हेल्प कार्यक्रम का देशव्यापी क्रियान्वयन विस्तृत होकर 15 राज्यों तक पहुंच गया। इस अवधि में लगभग 100 ए-हेल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनके अंतर्गत 3,000 से अधिक पशुसखियों को ए-हेल्प के रूप में मान्यता दी गई। ये मान्यता प्राप्त व्यक्ति अब अपने गांवों में डेयरी किसानों के लिए संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करते हैं।

साथ ही, एनडीडीबी ने विदर्भ क्षेत्र तथा सुंदरबन दूध संघ में माइक्रो प्रशिक्षण केंद्रों (MTC) को सहयोग प्रदान किया। इस वर्ष, इन एमटीसी के माध्यम से 3,000 से अधिक किसानों को वैज्ञानिक पशुपालन पद्धतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

समावेश और महिला सशक्तिकरण की भावना के अनुरूप 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' तथा 'अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025' के अवसर पर तीन दिवसीय कार्यक्रम 'सक्षम – नर्चरिंग वीमेन लीडरशिप' का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण आयोजन में विभिन्न डेयरी सहकारिताओं एवं दूध उत्पादक संगठनों से आईं 60

महिला लीडरों ने भाग लिया। उनके लिए यह कार्यक्रम नेटवर्किंग, जानकारी के आदान-प्रदान और नेतृत्व कौशल विकास का एक साझा मंच रहा।

एनडीडीबी ने पहुंच और सुगमता को बढ़ाने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म की शक्ति का उपयोग करते हुए, विदर्भ–मराठवाड़ा क्षेत्र के किसानों के लिए विशेष 'एनडीडीबी संवाद' कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह शृंखला हाइब्रिड मोड (डिजिटल एवं कक्षा आधारित) में संचालित की गई, जिसमें 400 से अधिक प्रतिभागियों को शामिल किया गया। इस प्रशिक्षण में उन्हें मूलभूत पशुपालन पद्धतियों एवं गुणवत्ता आश्वासन के विषय में आवश्यक जानकारी प्रदान की गई।

भारत पशुधन प्लेटफॉर्म के प्रभावी रूप से अपनाने एवं उपयोग को सुगम बनाने के लिए एनडीडीबी द्वारा 70 से अधिक डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से 4,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंच बनाई गई। इस पहल का उद्देश्य हितधारकों एवं नीतिनिर्माताओं को आवश्यक कौशल प्रदान करना है, जिससे वे डिजिटल संसाधनों का उपयोग करके उन्नत पशुधन प्रबंधन, डेटा-आधारित निर्णय-निर्माण तथा उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित कर सकें।

इस बहुआयामी एवं प्रभावी दृष्टिकोण के माध्यम से प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को आगे बढ़ाते हुए एनडीडीबी निरंतर सहकारी डेयरी इकोसिस्टम से जुड़े व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सशक्त बना रही है। यह प्रयास निरंतर सुधार की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है तथा डेयरी क्षेत्र को अधिक दक्ष, सस्टेनेबल और समृद्धि की दिशा में अग्रसर करता है।

आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी

पारंपरिक / स्व-स्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. सं.	विषय क्षेत्र	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
क	सहकारिता सेवाएं		
	बोर्ड अभिमुखन कार्यक्रम	16	229
	एफपीओ हेतु व्यवसाय विकास	2	31
	किसानों का इंडक्शन /अभिमुखन कार्यक्रम	150	5651
	सहकारी व्यवसाय मॉडल द्वारा डेयरी विकास पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	2	25
	प्रबंधन समिति के सदस्यों का अभिमुखन कार्यक्रम	6	113
	डेयरी सहकारी अधिकारियों (पी एंड आई, एग्जीक्यूटिव्स) का प्रशिक्षण	39	467
	डेयरी सहकारी समिति के सचिव हेतु प्रशिक्षण / पुनश्चर्या	18	443
ख	पशुपालन पर डेयरी उद्यमिता कार्यक्रम	2	52
ग	दूध विपणन	6	93
घ	राष्ट्रीय दूध रिकॉर्डिंग कार्यक्रम (एनएमआरपी)	12	142
ङ	डेयरी संयंत्रों का संचालन एवं रखरखाव	36	734
च	जेम: गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस	1	12
छ	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण: ए-हेल्प/रेग्युलर	14	263
ज	डिजिटल पोर्टल और सॉफ्टवेयर		
	भारत पशुधन/एनडीएलएम टीओटी	36	1267
	एनडीडीबी ईआरपी/एएमसीएस/एसएसएमएस/डेयरी सर्वेयर/ आईडीआईएस पर प्रशिक्षण	33	452
झ	उत्पादकता वृद्धि		
	उन्नत वैज्ञानिक पशुपालन पद्धतियां और प्रबंधन पद्धतियां	2	15
	एआई बेसिक / पुनश्चर्या	35	993
	पशु स्वास्थ्य प्रबंधन	6	217
	डेयरी पशु प्रबंधन	105	3206
	ओपीयू-आईवीईपी ईटी / जीनोमिक चयन और रिकॉर्डिंग	6	77
	उन्नत पशु प्रबंधन पद्धतियों का प्रशिक्षण	2	53
	उत्पादकता वृद्धि पर पशु पोषण पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण	1	11
	एएन, सीआरपी चारा उत्पादन और संरक्षण पर प्रशिक्षण	3	60
	पशु आहार उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण पर प्रशिक्षण	1	19
ञ	डेयरी संयंत्रों में गुणवत्ता आश्वासन एवं प्रबंधन प्रणालियां	21	385

पारंपरिक / स्व-स्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम			
क्र. सं.	**विषय क्षेत्र**	**कार्यक्रमों की संख्या**	**प्रतिभागियों की संख्या**
ट	अन्य (कार्यशाला और सेमिनार)		
	राष्ट्रीय दूध दिवस कार्यशाला	1	50
	सक्षम – नर्चरिंग वीमेन लीडरशिप	1	60
	कुल	557	15120
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित कार्यक्रम			
	भारत पशुधन / एनडीएलएम टीओटी	41	2791
	एनडीडीबी संवाद – विदर्भ- मराठवाड़ा क्षेत्र	4	427
	एनडीडीबी ईआरपी/एएमसीएस/एसएसएमसी/डेयरी सर्वेक्षक/आई-डीआईएस पर प्रशिक्षण	41	236
	कुल योग	643	18574

प्रजनन एवं जीनोमिक प्रौद्योगिकियों में मानव संसाधन विकास

एनडीडीबी ने उन्नत प्रजनन जैव-प्रौद्योगिकियों में अठारह पशुचिकित्सकों को प्रशिक्षण प्रदान किया। इनमें ओवम पिक-अप (OPU), इन विट्रो एम्ब्रियो प्रोडक्शन (IVEP) तथा एम्ब्रियो ट्रांसफर (ET) जैसी तकनीकें सम्मिलित थीं। इन प्रतिभागियों में भारतीय संस्थाओं के 10 पेशेवर तथा केन्या सरकार के 8 प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त, एक स्नातकोत्तर अभ्यर्थी और तीन डॉक्टोरल अभ्यर्थियों को भी इन प्रौद्योगिकियों में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

एनडीडीबी ने फुलब्राइट–नेहरू विशेषज्ञ कार्यक्रम के अंतर्गत डॉ. जेनिफर बारफील्ड, एसोसिएट प्रोफेसर, कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी, के साथ सहयोग किया। डॉ. बारफील्ड ने एम्ब्रियो बायोटेक्नोलॉजी, एम्ब्रियो ग्रेडिंग, ट्रांसफर तकनीकें तथा क्रायोप्रिज़र्वेशन पर तकनीकी सत्र आयोजित किए। इसके साथ ही, एनडीडीबी द्वारा 'ग्रेडिंग एंड क्रायोप्रिज़र्वेशन ऑफ़ आईवीएफ एम्ब्रियोस' पर केंद्रित एक कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें पूरे भारत की आईवीएफ प्रयोगशालाओं से आए अधिकारियों ने भाग लिया।

एनडीडीबी ने जीनोम बायोलॉजी रिसर्च सेंटर (GBRC) के सहयोग से जीनोम-वाइड एसोसिएशन स्टडीज (GWAS) पर प्रशिक्षण आयोजित किया, जिसका उद्देश्य जीनोमिक विश्लेषण क्षमताओं को सुदृढ़ करना था। इसके साथ ही, केन्या सरकार के प्रतिभागियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम "जीनोमिक सिलेक्शन, लाइवस्टॉक आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी" भी आयोजित किया गया। इसके अलावा , आरजीएम कार्यक्रम के अंतर्गत एक्सिओम माइक्रोएरे जीनोटाइपिंग पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया, जिसमें एनडीडीबी, एसएजी, एनडीडीबी काफ लि., कामधेनु विश्वविद्यालय और बायफ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इन पहलों से तकनीकी दक्षता में सुधार हुआ और डेयरी आनुवंशिकी एवं प्रजनन के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने के एनडीडीबी के उद्देश्य को समर्थन मिला।

केन्या गणराज्य के पशु चिकित्सकों के लिए ओवम पिक-अप पर प्रशिक्षण

खुर रोग प्रबंधन की तकनीकों पर प्रदर्शन

खुर प्रबंधन प्रशिक्षण

एनडीडीबी ने बानी दूध उत्पादक कंपनी में खुर प्रबंधन पर एक विशेष कार्यशाला आयोजित की। इस अवसर पर मोबाइल खुर ट्रिमिंग क्रेट का उपयोग कर व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की गई। पशुचिकित्सकों को उन्नत खुर ट्रिमिंग की तकनीकों तथा खुर संबंधी रोग प्रबंधन में प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य लंगड़ापन कम करना, पशु कल्याण को बढ़ावा देना तथा उत्पादकता में सुधार सुनिश्चित करना था। इस गतिविधि से पशुधन के स्वास्थ्य परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ और यह एनडीडीबी की पशु देखभाल पद्धतियों पर केंद्रित प्रयासों को और सुदृढ़ करता है।

डीसीएएम के अंतर्गत ईवीएम क्षमता विकास

एनडीडीबी ने वैकल्पिक विधियों के माध्यम से रोग नियंत्रण (DCAM) संबंधी परियोजना के अंतर्गत, वर्ष 2017 से एक संरचित प्रशिक्षण शृखला प्रारंभ की। इस परियोजना के समापन (मार्च 2025) तक, ट्रांस-डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी (TDU), बेंगलुरु में कुल 276 मुख्य पशुचिकित्सकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, 1,014 क्षेत्रीय पशुचिकित्सकों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स (ToT) सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

जमीनी स्तर तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु, एनडीडीबी ने 12,694 पशु स्वास्थ्य कर्मियों को डेयरी सहकारी समितियों में एथनोवेटनरी मेडिसिन (EVM) के सिद्धांतों एवं उपयोग के बारे में अवगत कराया। इस व्यापक प्रशिक्षण नेटवर्क ने इवीएम पद्धतियों के विस्तृत प्रसार को संभव बनाया, जिससे किसानों को पशुधन स्वास्थ्य देखभाल हेतु सुलभ एवं स्वदेशी समाधान उपलब्ध हो सके।

चारा बीज उत्पादन में क्षमता विकास

एनडीडीबी ने चारा बीज उत्पादन में तकनीकी विशेषज्ञता सुदृढ़ करने के लिए केंद्रित प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किए, यह मानते हुए कि हरे चारे की उत्पादकता और डेयरी प्रदर्शन सुधारने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

इस क्रम में, एनडीडीबी ने आणंद कृषि विश्वविद्यालय में अपने 25 अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिससे उनके बीज उत्पादन संबंधी तकनीकी समझ में वृद्धि हुई।

इसके अतिरिक्त, एनडीडीबी ने भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान (IGFRI), झांसी के सहयोग से देशभर की 15 डेयरी सहकारिताओं के 25 अधिकारियों हेतु पांच दिवसीय उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें चारा बीज उत्पादन, प्रसंस्करण एवं भंडारण से संबंधित विषयों पर गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

इन पहलों का उद्देश्य एक ऐसा तकनीकी रूप से दक्ष कार्यबल तैयार करना है, जो डेयरी किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले चारा बीज का उत्पादन एवं आपूर्ति सुनिश्चित कर सके, जिससे जमीनी स्तर पर सस्टेनेबल चारा विकास को प्रोत्साहन मिल सके।

मानव संसाधन विकास

इस दिशा में, एनडीडीबी ने संरचित मानव संसाधन पहलों के माध्यम से प्रोफेसनल ग्रोथ, कर्मचारी कल्याण और संगठनात्मक एकरूपता को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया। एनडीडीबी के विभिन्न ग्रुपों की आंतरिक टीमों को फंक्शनल अपडेट्स प्रस्तुत करने, जागरूकता बढ़ाने और विभिन्न कार्यों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने हेतु नॉलेज-शेयरिंग फोरम का आयोजन किया गया।

एनडीडीबी ने अपने एनडीडीबी फ़ॉर फ़िटनेस कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य एवं कल्याण एजेंडा को आगे बढ़ाया। इसके अंतर्गत विशेषज्ञों द्वारा संचालित सत्र आयोजित किए गए, जिनमें पोषण, ऑफिस एर्गोनॉमिक्स तथा रेस्पिरेटरी हेल्थ जैसे विषय सम्मिलित थे। कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने हेतु 'हैप्पी आवर्स' कार्यक्रम के अंतर्गत हैप्पीनेस, तनाव प्रबंधन तथा समग्र कल्याण पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

'लीड' पहल के माध्यम से महिला कर्मचारियों के सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया। इस पहल के अंतर्गत सेवा (SEWA), अहमदाबाद का क्षेत्रीय दौरा तथा पर्सनल फाइनेंस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर सत्र आयोजित किए गए।

एनडीडीबी ने 'टेकटॉनिक्स' शृंखला के माध्यम से डिजिटल साक्षरता एवं साइबर जागरूकता को प्रोत्साहित किया। इन सत्रों में साइबर सुरक्षा के मूल सिद्धांत एवं डिजिटल वेल-बीइंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कर्मचारियों में पढने की आदत और प्रेरणादायी सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु मासिक प्रकाशन 'होराइज़न्स' और 'द बुक नुक' को परिचालित किया गया। इसी क्रम में, 'पुस्तकालय परिक्रमा' कार्यक्रम के अंतर्गत विषयगत पुस्तक प्रदर्शनियों और इंटरैक्टिव सत्रों का आयोजन किया गया, जिससे पढ़ने की आदत को बढ़ावा दिया जा सके।

एनडीडीबी ने एचआरडी सप्ताह को 'अवेक, ऐक्ट एंड ट्रांसफॉर्म' थीम के साथ मनाया। इस अवसर पर विशेषज्ञों द्वारा संचालित सत्र, वॉकाथॉन, सेवा अहमदाबाद का दौरा, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, आंतरिक पहलों पर प्रस्तुतिकरण तथा फिलेन्थ्रोपिक गतिविधियां आयोजित की गईं। 'मंथन' नामक लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीडीबी एवं इसकी सहायक इकाइयों के 83 अधिकारियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में रणनीतिक प्रस्तुतिकरण एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र सम्मिलित थे, जिनका उद्देश्य सहयोगात्मक एक्शन प्वाइंट की पहचान कर डेयरी किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है।

वर्ष के दौरान, प्रशिक्षण गतिविधियों के माध्यम से क्षमता विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रही। इस अवधि में एनडीडीबी, इसकी सहायक कंपनियों एवं अन्य संगठनों के कुल 666 प्रतिभागियों ने 47 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

एनडीडीबी ने शैक्षणिक संस्थानों के 53 छात्रों को इंटर्नशिप प्रदान कर व्यावहारिक अध्ययन के अवसर उपलब्ध कराए। इन इंटर्नशिप का उद्देश्य छात्रों को ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से कार्यस्थल प्रशिक्षण प्रदान करना है।

सात 'एनडीडीबी कनेक्ट – परिचय' कार्यक्रम एनडीडीबी की सहायक कंपनियों से जुड़े 157 नव-नियुक्त अधिकारियों के लिए आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में कक्षा-आधारित सत्रों और क्षेत्रीय भ्रमण को सम्मिलित किया गया, जिससे प्रतिभागियों को एनडीडीबी के मूल्यों एवं कार्यप्रणाली को समझने का अवसर मिला।

इसके अतिरिक्त, एनडीडीबी और इसकी सहायक कंपनियो के मध्यम एवं वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों हेतु एक नया प्रशिक्षण मॉड्यूल 'लीडरशिप एंड कल्चर बिल्डिंग' प्रारंभ किया गया। इस अंतर्गत दो कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे 43 प्रतिभागी लाभान्वित हुए।

साथ ही, एनडीडीबी ने 'लीडिंग ऑर्गनाइजेशनल चेंज' विषय पर आधारित दो विशेष रूप से तैयार अभिमुखन सत्र भी आयोजित किए, जिनमें बैंक ऑफ बड़ौदा और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने भाग लिया। सभी कार्यक्रमों को सकारात्मक फीडबैक प्राप्त हुआ, जो शैक्षिक सफलता को दर्शाता है। इन प्रयासों ने एनडीडीबी एवं उसके विस्तृत इकोसिस्टम में कुशल एवं संगठित कार्यबल के निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

विषय क्षेत्र	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
एनडीडीबी कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण	36	406
पीएसयू/पीएसबी/एनडीडीबी की सहायक कंपनियों के अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण	11	260
कुल योग	**47**	**666**

एससी/एसटी कर्मचारियों का कल्याण

एससी/एसटी कर्मचारियों की प्रगति हेतु शिक्षा, प्रशिक्षण और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि उन्हें नए अनुभव मिलें, नेतृत्व कौशल निखरें और विकास के व्यापक अवसर प्राप्त हों।

एससी/एसटी कर्मचारियों के लिए कुल 63 प्रशिक्षण नामांकन किए गए, जिसमें तकनीकी, कार्यात्मक और सामान्य प्रबंधन क्षेत्र शामिल रहे। इसके साथ ही, एनडीडीबी ने शैक्षणिक व्यय की प्रतिपूर्ति एवं शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता के माध्यम से एससी/एसटी कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को वित्तीय सहयोग प्रदान किया। नकद पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र देकर उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता को भी सम्मानित किया गया।

एनडीडीबी कार्यालयों में अम्बेडकर जयंती मनाई गई, जिसमें डॉ. बी आर अम्बेडकर के योगदानों का स्मरण किया गया। इस अवसर पर आयोजित औपचारिक सत्र में कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी रही। इन पहलों से कर्मचारी सहभागिता एवं कौशल विकास के प्रति एनडीडीबी की प्रतिबद्धता को बल मिला, जो इसके संगठनात्मक विकास रणनीति का अभिन्न अंग है।

एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह एचआरडी वीक 2025 के दौरान 'हेल्थॉन' को हरी झंडी दिखाते हुए

डेयरी क्षेत्र के लिए विज़न 2047

एनडीडीबी ने भारतीय डेयरी क्षेत्र के सतत् और समावेशी बदलाव के लिए विज़न 2047 निर्धारित किया है तथा वह वैश्विक डेयरी व्यापार में एक अग्रणी संस्थान बनने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्रीमती अलका उपाध्याय, सचिव, डीएएचडी, भारत सरकार, फ्यूचर रोडमैप फ़ॉर इंडियन डेयरी सेक्टर पर सम्मेलन के उद्घाटन भाषण के दौरान, जिसमें एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह और कामधेनु विश्वविद्यालय, एनडीआरआई, जीसीएमएमएफ, बनास डेयरी, इंस्टिट्यूट फ़ॉर रिसर्च ऑन बफ़ेलोज़, आईसीएआर-भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान के अधिकारियों के साथ-साथ भारतीय डेयरी क्षेत्र के अन्य पेशेवर उपस्थित रहे

भारतीय डेयरी क्षेत्र हेतु भावी रोडमैप पर सम्मेलन

भारतीय डेयरी क्षेत्र के भावी रोडमैप पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख गणमान्यों में श्रीमती अलका उपाध्याय, सचिव, डीएएचडी, डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी तथा कामधेनु विश्वविद्यालय, एनडीआरआई, जीसीएमएमएफ, बनास डेयरी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, आईसीएआर-भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान के अधिकारी और भारतीय डेयरी क्षेत्र के अन्य पेशेवर शामिल हुए।

सम्मेलन के दौरान, नीति निर्माताओं, निर्णयकर्ताओं और अनुसंधान संस्थानों के समूह ने दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने, मूल्यवर्धित डेयरी उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ाने, भारत में डेयरी उद्योग को और अधिक सस्टेनेबल बनाने, संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने और भारतीय डेयरी उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के उपायों पर विचार-विमर्श किया। इस विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप विज़न 2047 का विकास हुआ, जिसमें इस क्षेत्र को देश की विकास महत्वाकांक्षाओं के साथ जोड़ने के लिए पांच रणनीतिक लक्ष्यों की पहचान की गई।

एनडीडीबी डेयरी क्षेत्र के लिए विज़न 2047 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रगति कर रही है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में, दूधारू पशुओं की बायोलॉजिकल प्रणालियों के विकास हेतु दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, एनडीडीबी ने सक्रिय रूप से विभिन्न गतिविधियों की शुरुआत की है तथा उन्हें व्यापक स्तर पर लागू किया है, ताकि इस क्षेत्र में सस्टेनेबल विकास सुनिश्चित किया जा सके और निर्धारित उपलब्धियों को प्राप्त किया जा सके। इस दिशा में की गई प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

उत्पादकता वृद्धि

वार्षिक दूध उत्पादन को प्रति पशु 2,080 किलोग्राम से बढ़ाकर 5,200 किलोग्राम तक पहुंचाने के उद्देश्य से एनडीडीबी वैज्ञानिक प्रजनन, उन्नत आनुवंशिकी तथा नीतिगत सहयोग पर केंद्रित एक समग्र रणनीति कार्यान्वित कर रही है। एनडीडीबी दूधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि हेतु प्रजनन,स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन पर आधारित बहुआयामी पहलों को लागू कर रही है। पशु प्रजनन के क्षेत्र में संस्थान ने जीनोमिक चयन तथा असिस्टिड रिप्रोडक्टिव टेक्नॉलजीज़ (ART) जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग प्रारंभ किया है, साथ ही प्रदर्शन रिकार्डिंग प्रणालियों का भी विस्तार किया जा रहा है। प्रमुख नवाचारों में एकीकृत जीनोमिक चिप्स (गौचिप एवं महिषचिप) का विकास तथा स्वदेशी प्रौद्योगिकियों जैसे आईवीएफ मीडिया सूट "षष्ठी" और "गौसॉर्ट" सेक्स सॉर्टिंग टेक्नॉलोजी का उपयोग शामिल है।इन प्रयासों का उद्देश्य आनुवंशिक लाभ में वृद्धि करना, भ्रूण उत्पादन लागत को कम करना तथा सेक्स्ड सॉर्टेड सीमन को किसानों के लिए अधिक सुलभ बनाना है, जिससे दूध उत्पादन में वृद्धि तथा लागत में कमी सुनिश्चित हो सके। ये पहलें सस्टेनेबल डेयरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

एनडीडीबी की पशु स्वास्थ्य संबंधी पहलें टीकाकरण, निदान तथा रोग नियंत्रण पर आधारित बहुआयामी दृष्टिकोण पर केंद्रित हैं। संस्थान खुरपका-मुंहपका (FMD) और ब्रूसेलोसिस जैसी प्रमुख बीमारियों के लिए टीकाकरण कवरेज का विस्तार कर रहा है, साथ ही उन्नत निदान क्षमताओं के विकास और कम लागत वाले परीक्षण तरीकों को भी प्रोत्साहित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ साझेदारी के माध्यम से एनडीडीबी अपने निदान उपायों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त, संगठन 'वन हेल्थ दृष्टिकोण' को अपनाते हुए ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रमों और एएमआर से संबंधित हितधारक कार्यशालाओं का आयोजन कर रही है। एनडीडीबी एथनो-वेटनरी मेडिसिन को भी प्रोत्साहित कर रही है, जिससे सस्टेनेबल डेयरी विकास को समर्थन मिले। इन सभी प्रयासों का प्रमुख उद्देश्य पशु स्वास्थ्य में सुधार लाना और रोगों को कम करना है।

एनडीडीबी वैज्ञानिक आहार के माध्यम से सस्टेनेबल डेयरी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में संगठन संपूर्ण मिश्रित आहार (TMR), फीडिंग और प्रिसीजन आहार जैसी तकनीकों के माध्यम से फीड कन्वर्ज़न दक्षता में सुधार करने पर कार्य कर रही है। साथ ही चारे की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए चारा उपलब्धता को सुदृढ़ बनाने तथा विकेन्द्रीकृत साइलेज और चारा उद्यमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। एनडीडीबी डेयरी उत्पादन प्रणाली को पर्यावरणीय दृष्टि से अधिक अनुकूल बनाने हेतु फ़ीड एडिटिव्स और एकीकृत कृषि पद्धतियां के उपयोग से एंटरिक मीथेन उत्सर्जन को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। इन रणनीतिक पहलों का उद्देश्य दूध उत्पादन में वृद्धि, परिचालन लागत में कमी तथा पर्यावरण के अनुकूल डेयरी पद्धतियों को बढ़ावा देना है।

संगठित क्षेत्र का विस्तार

सहकारिताओं की पहुंच को 1.7 लाख गांवों से बढ़ाकर 3.5 लाख गांवों तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल का विशेष ध्यान अविकसित क्षेत्रों पर केंद्रित है, जहां महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्पादक-स्वामित्व वाले वैकल्पिक मॉडलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

एनडीडीबी पूरे देश में डेयरी सहकारिताओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। विशेष रूप से अविकसित क्षेत्रों में संस्थान महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने और उत्पादक-स्वामित्व वाले वैकल्पिक मॉडलों को प्रोत्साहित करने पर बल दे रहा है। श्वेत क्रांति 2.0 पहल के अंतर्गत एनडीडीबी ने वर्ष 2028-29 तक 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियों (DCS) का गठन करने तथा 46,000 मौजूदा समितियों को सुदृढ़ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही दूध संकलन क्षमता को प्रतिदिन 1,000 लाख किलोग्राम तक बढ़ाने का भी उद्देश्य रखा गया है। श्वेत क्रांति 2.0 के इन लक्ष्यों को डीएएचडी के राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) के संशोधित स्वरूप में वित्तीय सहायता हेतु सम्मिलित किया गया है।

एनडीडीबी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य स्तरीय डेयरी महासंघों और दूध संघों के साथ साझेदारी कर सहकारिताओं को पेशेवर ढंग से संचालित करने और उनके कवरेज का विस्तार करने पर कार्य कर रही है। वर्तमान में एनडीडीबी असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, लद्दाख और वाराणसी दूध संघ सहित देश के कई राज्यों में विभिन्न दूध संघों और महासंघों का प्रबंधन कर रही है। इसके अतिरिक्त, एनडीडीबी ने ओडिशा जैसे राज्यों में डेयरी विकास हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) किए हैं और महाराष्ट्र के विदर्भ-मराठवाड़ा क्षेत्र में डेयरी विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। इन पहलों के माध्यम से एनडीडीबी संगठित डेयरी क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बना रही है तथा अधिकाधिक उत्पादकों को औपचारिक सहकारी नेटवर्क से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मूल्य वर्धित उत्पादों का संवर्धन

सहकारी क्षेत्र में मूल्य वर्धित डेयरी उत्पादों की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया

गया है। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करना और प्रीमियम बाज़ारों में प्रवेश कर सहकारिताओं की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को सुदृढ़ करना है।

एनडीडीबी सहकारी क्षेत्र को मूल्य वर्धित डेयरी उत्पादों (VADP) के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु व्यापक सहयोग प्रदान कर रही है। इस सहयोग में नए उत्पादों के विकास, विश्लेषणात्मक पद्धतियों, स्टार्टर कल्चर प्रबंधन तथा नई तकनीकों को अपनाने जैसे क्षेत्रों में सहायता शामिल है। इन पहलों का उद्देश्य मूल्य वर्धित उत्पाद निर्माण में सहकारी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना तथा उनके उत्पाद पोर्टफोलियो को और अधिक सशक्त बनाना है।

एनडीडीबी की अनुसंधान एवं विकास संबंधी पहलें डेयरी क्षेत्र में नवाचार को गति प्रदान कर रही हैं। हाल के विकास कार्यों में मिलेट्स और शहद के साथ मिश्रित डेयरी उत्पादों का निर्माण, भारत की माइक्रोबियल विविधता का उपयोग कर नए प्रोबायोटिक्स और बायोमोलेक्यूल्स की पहचान तथा अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित डेयरी नवाचार केंद्र की स्थापना शामिल है। इसके अतिरिक्त, एनडीडीबी छोटे स्तर के उपकरण विकसित करके और डेयरी फार्मों या सहकारी समितियों पर सीधे एग्रो-फ्रेश उत्पादों का उत्पादन करने के लिए पायलट पहल करके फार्म-स्तर तथा सहकारी समिति स्तर पर वीएडीपी विनिर्माण को बढ़ावा दे रही है।

वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहन

भारत की हिस्सेदारी को वैश्विक डेयरी निर्यात में 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एनडीडीबी गुणवत्ता सुनिश्चित करने, स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करने तथा व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करने पर कार्य कर रही है।

इस दिशा में एनडीडीबी ने 21 मई 2024 को आणंद में "एफएमडी फ्री ज़ोन इन गुजरात – फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू रियैलिटी" विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में डीएएचडी, गुजरात पशुपालन विभाग तथा उद्योग से जुड़े प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य गुजरात में एफएमडी-मुक्त क्षेत्र की स्थापना के लिए रणनीतियों एवं नीतिगत सहयोग पर चर्चा करना था, ताकि डेयरी एवं पशुधन उत्पादों के वैश्विक व्यापार को सुगम बनाया जा सके।

भारत को एफएमडी-मुक्त बनाने की दिशा में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस व्यापक कार्यक्रम को 3,880 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ स्वीकृति प्रदान की गई है, जो देश में पशुधन स्वास्थ्य प्रबंधन को नई गति प्रदान कर रहा है। वर्तमान में नौ राज्य-पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र एफएमडी-मुक्त बनने की प्रक्रिया के प्रथम चरण में हैं।

डेयरी क्षेत्र के निर्माण और आधुनिकीकरण, जिसमें फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज दोनों शामिल हैं, से कच्चे दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, उसे प्रोसेस करने तथा विपणन करने में सहकारी समितियों को उल्लेखनीय लाभ हो रहा है। इसके अतिरिक्त, एनपीडीडी, एएचआईडीएफ, एसडीसीएफपीओ, गुणवत्ता चिह्न तथा सीएएस-एमएमपी जैसी भारत सरकार की योजनाएं डेयरी सहकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादित दूध एवं दूध उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में अत्यंत सहायक सिद्ध हो रही हैं।

सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करना

वर्ष 2047 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नेट-जीरो स्तर पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बायोगैस को अपनाने, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, उन्नत चारा पद्धतियों और कार्बन सिक्वेसट्रेशन पर विशेष बल दिया जा रहा है।

भारतीय डेयरी सहकारी क्षेत्र ने वर्ष 2047 तक नेट-जीरो बनने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक 20 वर्षीय कार्ययोजना (2026-27 से 2046-47 तक) तैयार की गई है, जिसे तीन चरणों में विभाजित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों से समय के साथ भारतीय डेयरी क्षेत्र में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है।

डेयरी क्षेत्र में ग्रामीण समृद्धि को गति देने की क्षमता है। यह न केवल किसानों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाने में सहायक है, बल्कि सस्टेनेबल विकास को आर्थिक वृद्धि के साथ एकीकृत कर भारत को वैश्विक डेयरी नेतृत्व की ओर भी अग्रसर कर सकता है। इस प्रकार डेयरी क्षेत्र "विकसित भारत 2047" के स्वप्न को साकार करने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकता है।

एनडीडीबी के सलाहकार डॉ. के.आर. त्रिवेदी, फ्यूचर रोडमैप फ़ॉर इंडियन डेयरी सेक्टर पर आयोजित सम्मेलन के दौरान डीएएचडी, एनडीडीबी के अधिकारियों और अन्य डेयरी पेशेवरों के साथ बातचीत करते हुए

एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रीशन

एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रीशन (NFN) की स्थापना अक्तूबर 2015 में आणंद, गुजरात में की गई। यह संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी तथा बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 के अंतर्गत एक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है। एनएफएन ने अपने उद्देश्य की दिशा में कार्य जारी रखा, जिसके अंतर्गत दूध एवं दूध उत्पादों के माध्यम से बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करना और कुपोषण की समस्या के समाधान में योगदान देना शामिल है। इस कार्य में एनडीडीबी की सहायक कंपनियों तथा देशभर के अन्य सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ।

एनडीडीबी और आईआईएल के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह, तमिलनाडु के कोयंबटूर के पोलाची में एनएफएन के प्रमुख गिफ्टमिल्क कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान, जिसमें तमिलनाडु के पोलाची की उप-कलेक्टर सेल्वी ए. कैथरीन सरन्या; आईआईएल के प्रबंधक निदेशक डॉ. के. आनंद कुमार और कोयंबटूर के जिला शिक्षा अधिकारी श्री आर. केशवकुमार उपस्थित रहे

गिफ्टमिल्क कार्यक्रम

एनएफएन की प्रमुख पहल गिफ्टमिल्क कार्यक्रम रही, जिसका उद्देश्य सरकारी विद्यालयों एवं आंगनवाड़ियों में बच्चों को 200 मिलीलीटर फ्लेवर्ड दूध (विशेषकर विटामिन A एवं D से युक्त) उपलब्ध कराना है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 13 राज्यों के 660 विद्यालयों के 66,900 से अधिक बच्चों को कुल 9.5 लाख लीटर दूध वितरित किया गया।

गिफ्टमिल्क कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार कवरेज

क्र. सं.	राज्य	स्कूल / आंगनवाड़ी की संख्या	बच्चों की संख्या	गिफ्ट मिल्क वितरण ('000 लीटर)
1	आंध्र प्रदेश	11	2264	7.45
2	बिहार	5	1200	30.08
3	छत्तीसगढ़	180	14412	197.64
4	गुजरात	18	2300	66.43
5	झारखंड	55	11200	205.86
6	महाराष्ट्र	45	5070	155.65
7	ओडिशा	50	2824	38.96
8	पंजाब	3	634	5.89
9	राजस्थान	108	1850	10.68
10	तमिलनाडु	43	4136	62.03
11	तेलंगाना	1	358	6.30
12	उत्तर प्रदेश	121	17115	113.43
13	पश्चिम बंगाल	20	3537	52.55
	कुल योग	**660**	**66900**	**952.96**

इस पहल को विभिन्न संगठनों के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरादायित्व (CSR) सहयोग से संभव बनाया गया। इस पहल के मुख्य समर्थकों में एनडीडीबी की सहायक कंपनियां - आईडीएमसी लिमिटेड, एमडीएफवीपीएल, आईआईएल एवं एनडीएस सहित अनेक सार्वजनिक उपक्रम जैसे सेल (SAIL), बोकारो पावर सप्लाई कंपनी (प्रा.) लिमिटेड, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, यामाहा मोटर सॉल्यूशंस इंडिया प्रा. लिमिटेड, मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तथा कई मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां शामिल रहीं।

एनएफएन ने अपनी गतिविधियों को और सुदृढ़ करते हुए 26–28 जून, 2024 को कोच्चि में आयोजित आईडीएफ रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस में अपनी पहलों का प्रदर्शन किया। इस सहभागिता ने डेयरी उद्योग तथा उससे जुड़े विभिन्न हितधारकों के बीच बाल पोषण को प्रोत्साहित करने के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता को व्यक्त किया।

शिशु संजीवनी कार्यक्रम

मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रा. लि. की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरादायित्व (CSR) पहल के अंतर्गत शिशु संजीवनी कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अहेरी ब्लॉक में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रारंभिक बाल पोषण को सुदृढ़ करना था।

इस अंतर्गत 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को रेडी-टू-इट, सेमी-सॉलिड, फॉर्टिफाइड न्यूट्रीशन सप्लीमेंट प्रदान किया गया। यह प्रत्येक 40 ग्राम में 18% प्रोटीन एवं लगभग 200 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, जो लगभग एक-तिहाई विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों की दैनिक रेकमेन्डिड डाइएटेरी अलाउअन्स (RDA) की पूर्ति करता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में, एनएफएन ने शिशु संजीवनी की 7.26 लाख यूनिटों का सफलतापूर्वक वितरण किया। इस प्रयास से 147 आंगनवाड़ी केंद्रों के 4,253 से अधिक बच्चों को लाभ हुआ, जिससे क्षेत्र के छोटे बच्चों के पोषण स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

गो-ग्रीन पहल

एनएफए स्वच्छ ऊर्जा और सस्टेनेबल कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कंपनियों की सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत 'गो-ग्रीन पहल' को आगे बढ़ा रहा है। इस वर्ष के दौरान, घरेलू स्तर पर 2 घन मीटर बायोगैस संयंत्र की स्थापना हेतु प्रमुख समझौते संपन्न किए गए, जिनका विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत है:

क्र.सं.	स्थान	डोनर एजेंसी	बायोगैस संयंत्रों की संख्या
1	बोकारो, झारखंड	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड	100
2	वडोदरा, गुजरात	आर्क्रोमा इंडिया लिमिटेड	50
3	महेसाणा एवं गांधीनगर ज़िले, गुजरात	सुज़ुकी आर एंड डी सेंटर इंडिया (SRDI)	285

ओएनजीसी, एनएफएन, एनडीडीबी एवं बरौनी दूध संघ के मध्य एक समझौता संपन्न हुआ, जिसके अंतर्गत बरौनी, बिहार में 100 एमटीपीडी क्षमता वाले गोबर-आधारित बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाएगी। यह संयंत्र ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन एवं ऑर्गेनिक उर्वरक निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान देगा।

एनएफएन अपने पोषण एवं स्वच्छ ऊर्जा को एकीकृत करने वाले दृष्टिकोण के माध्यम से न केवल समुदाय की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, बल्कि दीर्घकालीन एवं सस्टेनेबल विकास को भी सुदृढ़ बना रहा है।

राजभाषा का प्रगामी प्रयोग

वर्ष के दौरान, एनडीडीबी कार्यालयीन पत्राचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत रही, जिससे विभिन्न पहलों में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल हुई और राष्ट्रीय स्तर पर विशेष सम्मान प्राप्त हुआ।

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी नई दिल्ली में एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह को 2023-24 के लिए प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (प्रथम पुरस्कार) प्रदान करते हुए

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

नराकास, आणंद, एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह को राजभाषा स्तंभ पुरस्कार से सम्मानित करते हुए

एनडीडीबी को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (प्रथम पुरस्कार) 2023–24 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 14 सितंबर 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन और हिंदी दिवस समारोह के दौरान प्रदान किया गया। यह पुरस्कार माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह को समारोह के दौरान प्रदान किया गया।

इसके अलावा, एनडीडीबी, आणंद को राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए दो वार्षिक राजभाषा पुरस्कार प्राप्त हुए - प्रथम पुरस्कार 2022–23 और द्वितीय पुरस्कार 2024–25। इसके अतिरिक्त, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, आणंद द्वारा अध्यक्ष, एनडीडीबी को दो 'राजभाषा स्तंभ' पुरस्कार व प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए गए।

वित्त वर्ष 2024–25 में राजभाषा के क्रियान्वयन को गति देने वाली निम्न प्रमुख गतिविधियां शामिल रहीं:

- तिमाही राजभाषा कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें एनडीडीबी के कर्मचारी, क्षेत्रीय कार्यालय और प्रशिक्षण केंद्रों ने भाग लिया।
- तिमाही राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) बैठकें आयोजित की गईं, जिनके निर्णयों पर ठोस कार्रवाई की गई।
- ग्रुपवार हिंदी समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें राजभाषा कार्यान्वयन के जांच-बिंदु का अनुपालन और अनुवाद के लिए आईसीटी उपकरणों के उपयोग पर बल दिया गया।
- 1–30 सितंबर 2024 के दौरान, सभी एनडीडीबी कार्यालयों में हिंदी उमंगोत्सव माह का आयोजन किया गया।
- हिंदी प्रतियोगिताओं, जैसे निबंध लेखन, कविता पाठ, अनुवाद, चित्र देखो मुहावरा लिखो प्रतियोगिता एवं क्विज़ का आयोजन किया गया और कर्मचारियों ने उसमें सक्रिय भागीदारी की।
- विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर दिनांक 10 जनवरी 2025 को 'हास्य संध्या' काव्य सम्मेलन को आयोजित किया गया।
- 'साहित्य संवाद' व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी व्याख्यान आयोजित किए गए, ताकि साहित्यिक जुड़ाव को प्रोत्साहन मिल सके।
- हिंदी ई-पत्रिका 'सृजन' का प्रकाशन किया गया।

एनडीडीबी ने जन सामान्य में डेयरी विकास और संबंधित गतिविधियों की पहुंच बढ़ाने के लिए, विभिन्न सामग्री हिंदी में मुद्रित और डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से तैयार और वितरित की।

एनडीडीबी ने नराकास, आणंद के साथ अपनी सक्रिय भागीदारी बनाए रखी, इसके अर्धवार्षिक बैठकों और कार्यक्रमों में मेज़बानी और सहभागिता की। एनडीडीबी के कर्मचारियों ने नराकास, आणंद की हिंदी पत्रिका 'उज्ज्वल आणंद' के लिए कविताएं और लेख भी प्रदान किए। हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति से संबद्ध विभिन्न संस्थानों के कर्मचारियों ने भाग लिया।

हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एनडीडीबी ने हिंदी टिप्पण और आलेखन प्रोत्साहन योजना जारी रखी, जिसके अंतर्गत 32 कर्मचारियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त, जिन कर्मचारियों के बच्चों ने कक्षा 10 और 12 में हिंदी में 75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किए, उन्हें भी पुरस्कृत किया गया।

प्रमुख कार्यक्रमों की झलकियां

डॉ. मीनेश शाह का IFPRI ग्लोबल पॉलिसी सेमिनार में अभिभाषण

एलएमआईसी प्राथमिकताओं पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला

डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी ने इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (IFPRI) के ग्लोबल पॉलिसी सेमिनार में अभिभाषण दिया, जिसका विषय "डेयरी एंड न्यूट्रीशन इन द ग्लोबल साउथ: पोटेंशियल, प्रोग्रेस, एंड चैलेंजेस अहेड" था। डॉ. शाह ने "भारत में डेयरी विकास और पोषण" पर महत्वपूर्ण विचार रखे और भारत को दुनिया के अग्रणी दूध उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उजागर किया। उन्होंने डेयरी क्षेत्र की जेंडर इक्विलीटी, ग्रामीण आजीविका के सुदृढ़ीकरण और कृषि अर्थव्यवस्था की मजबूती में केंद्रीय भूमिका को रेखांकित किया। डॉ. शाह ने भारत के डेयरी कॉओपरेटिव फ्रेमवर्क की सफलता का श्रेय उपभोक्ता व्यय का 75% सीधे उत्पादकों को वापस देने की इसकी क्षमता को दिया, जिससे एक बिलियन से अधिक व्यक्तियों के लिए वित्तीय स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा और पोषण संबंधी कल्याण में वृद्धि हुई। यह सेमिनार ग्लोबल साउथ में डेयरी उत्पादन और पोषण परिणामों को बढ़ाने के लिए रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने का एक महत्वपूर्ण प्लेटफोर्म के रूप में कार्य करता है, जिसने इस क्षेत्र में भारत के नेतृत्व और वैश्विक डेयरी विकास को बढ़ावा देने के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है।

एनडीडीबी ने कम और मध्यम आय वाले देशों (LMIC) की प्राथमिकताओं पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया, जिसे सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट (CSE) इंडिया द्वारा अनिल अग्रवाल एन्वायरनमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (AAETI), निमली, राजस्थान में आयोजित किया गया। एनडीडीबी के अध्यक्ष ने वैज्ञानिक गतिविधियों के माध्यम से उत्पादकता वृद्धि हेतु एडीडीबी द्वारा किए गए प्रयासों का विस्तार से वर्णन किया। इनमें पीटी प्रोटोकॉल्स, जीनोमिक चिप्स का उपयोग, ईवीएम फॉर्म्यूलेशन और बायोगैस एवं ऑर्गेनिक खाद प्रबंधन जैसी पहलें शामिल थीं, जो सस्टेनेबल डेयरी पद्धतियों को प्रोत्साहित करती हैं।

इस कार्यशाला में विशेषज्ञों ने ग्लोबल साउथ की वास्तविकताओं और प्राथमिकताओं पर चर्चा की, जिसमें वन हेल्थ के लिए वित्तपोषण, एलएमआईसी में एएमआर कार्यान्वयन, खाद्य प्रणाली में बदलाव और सस्टेनेबिलिटी हेतु निवारक दृष्टिकोण जैसे विषय शामिल थे।

अध्यक्ष, एनडीडीबी को नेशनल अकादमी ऑफ डेयरी साइंस द्वारा सम्मान

डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष , एनडीडीबी को मथुरा में आयोजित अष्टम दीक्षांत समारोह के दौरान नेशनल अकादमी ऑफ डेयरी साइंस द्वारा प्रतिष्ठित फेलोशिप से सम्मानित किया गया। समारोह की विशेषता यह रही कि इसमें प्रमुख विश्वविद्यालयों के कुलपति और डेयरी उद्योग के प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे। मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में, डॉ. शाह ने भारत के डेयरी क्षेत्र की आधारशिला के रूप में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया, साथ ही एनडीडीबी की उत्पादकता बढ़ाने, पशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और डेयरी पद्धतियों में अग्रणी डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट किया।

गोवन फीड सेक्यूरिटी एफपीओं कार्यालय का उद्घाटन

100 फ़ॉडर प्लस एफपीओ पहल के तहत, गोवा के पोंडा में गोवन फ़ीड सिक्योरिटी एफपीओ प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड के कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसके आरंभिक चरण में 317 सदस्य थे। एनडीडीबी के अध्यक्ष ने संगठन की प्रगति की सराहना की और क्षेत्रीय चारे की कमी को कम करने के लिए हरे चारे के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके बाद, एफपीओ सदस्य द्वारा प्रबंधित एक मॉडल फार्म में चारा उत्पादन पद्धतियों और उत्पादकता का मूल्यांकन करने के लिए एक तकनीकी दौरा किया गया।

अंबेडकर जयंती

एनडीडीबी में अंबेडकर जयंती मनाई गई, जिसमें कार्यपालक निदेशक, एनडीडीबी के अधिकारी और आनंदालय के बच्चे शामिल हुए। इस कार्यक्रम में डॉ. दिलीप मेहरा, प्रोफेसर एवं स्नातकोत्तर के हिंदी विभाग के प्रमुख, सरदार पटेल विश्वविद्यालय ने डॉ. आंबेडकर के जीवन और योगदान पर व्याख्यान दिया। यह पहल सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने और सामुदायिक स्तर पर शैक्षिक मूल्यों को स्थापित करने की एनडीडीबी की प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है।

विश्व पशु चिकित्सक दिवस

महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय (MAFSU), नागपुर, ने एनडीडीबी के सहयोग से विश्व पशु चिकित्सक दिवस मनाया, जिसका विषय था: "वेटरिनेरियन्स आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स"। इस कार्यक्रम में पशु चिकित्सक पेशेवरों के पशु स्वास्थ्य प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान और भारत की दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में उनकी केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया गया।

प्रमुख कार्यक्रमों की झलकियां

विश्व पर्यावरण दिवस

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, एनडीडीबी ने डेयरी क्षेत्र में पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए एक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पहल में वरिष्ठ नेतृत्व और कर्मचारियों की भागीदारी रही, जो पर्यावरण-अनुकूल पद्धतियों को अपनाने पर एनडीडीबी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

स्वतंत्रता दिवस

एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह ने एनडीडीबी आणंद परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए डॉ. शाह ने प्रत्येक किसान को सशक्त बनाने और यह सुनिश्चित करने की एनडीडीबी की प्रतिबद्धता दोहराई कि वे भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदार बनें। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि सहकारी मॉडल एक विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में सबसे प्रभावी मार्ग के रूप में उभरेगा।

एनडीडीबी ने डिकार्बोनाइजिंग पेरिशेबल सप्लाई चेन कार्यशाला में भाग लिया

एनडीडीबी ने "डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से डिकार्बोनाइजिंग द पेरिशेबल सप्लाई चेन" विषयक महत्वपूर्ण कार्यशाला में भाग लिया, जिसे द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट (TERI) ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) के सहयोग से आयोजित किया। इस कार्यशाला में मदर डेयरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ (अमूल), बनासकांठा दूध संघ लिमिटेड जैसे डेयरी उद्योग के दिग्गजों के साथ-साथ रेलवे बोर्ड और लॉजिस्टिक्स एवं इलेक्ट्रिक ट्रक निर्माताओं के प्रतिनिधियों सहित प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। इस चर्चा का मुख्य विषय आपूर्ति श्रृंखला दक्षता और पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर रोल-ऑन/रोल-ऑफ (रो-रो) सेवाओं को अपनाना है।

एनडीडीबी के हीरक जयंती लोगो के साथ दूध के टैंकरों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया

एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह ने जीसीएमएमएफ के अध्यक्ष श्री शामलभाई पटेल और कैरा जिला सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड के अध्यक्ष श्री विपुलभाई पटेल के साथ एनडीडीबी के 59वें स्थापना दिवस के दौरान एनडीडीबी के हीरक जयंती लोगो के साथ दूध के टैंकरों को झंडी दिखाकर रवाना करते हुए, हीरक जयंती समारोह की शुरुआत की।

गांधी एवं शास्त्री जयंती

एनडीडीबी कर्मचारियों ने एनडीडीबी, आणंद में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई। समारोह की शुरुआत एनडीडीबी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण के साथ हुई। आनंदालय स्कूल के छात्रों ने गांधी जी और शास्त्री जी के जीवन और शिक्षाओं पर समर्पित विशेष रूप से तैयार किए गए गीत को प्रस्तुत किया।

त्रिभुवनदास पटेल जयंती

एनडीडीबी ने भारत में सहकारी आंदोलन के दूरदर्शी नेता और अग्रदूत श्री त्रिभुवनदास पटेल की जयंती मनाई। इस अवसर पर, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने त्रिभुवनदास पटेल जयंती पर एनडीडीबी के अपने दौरे के दौरान, माननीय केन्द्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी तथा अध्यक्ष, एनडीडीबी के साथ त्रिभुवनदास पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की।

सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती

एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह और वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ ली। इस अवसर पर, उन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित किया।

केरल में डेयरी विकास पहल

श्री जॉर्ज कुरियन जी, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री, ने एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह और विशिष्ट अतिथियों के साथ, एर्नाकुलम स्थित एडापल्ली प्रोडक्ट्स डेयरी में आइसक्रीम संयंत्र के आधुनिकीकरण की औपचारिक आधारशिला रखी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने त्रिपुनिथुरा स्थित एर्नाकुलम डेयरी में 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भी किया, जो स्थायी बुनियादी ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रमुख कार्यक्रमों की झलकियां

राष्ट्रीय दुग्ध दिवस

एनडीडीबी और सहयोगी संगठनों ने आणंद स्थित अपने मुख्यालय में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर डॉ. कुरियन को श्रद्धांजलि अर्पित की। एनडीडीबी के अध्यक्ष ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए, डेयरी सहकारिताओं के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने के डॉ. कुरियन के दृष्टिकोण को दोहराया। उन्होंने सभी संस्थानों से आग्रह किया कि वे डेयरी सहकारिताओं की पहुँच को सभी अनाच्छादित ग्राम पंचायतों और गांवों तक बढ़ाकर श्वेत क्रांति 2.0 का सक्रिय रूप से समर्थन करें। इस कार्यक्रम में जीवंत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया।

सस्टेनेबल कृषि पर प्रदर्शन इकाई का उद्घाटन

एनडीडीबी के अध्यक्ष ने आणंद में सस्टेनेबल कृषि प्रबंधन पद्धतियों पर एक प्रदर्शन इकाई का उद्घाटन किया। इस इकाई में उत्पादकता बढ़ाने के लिए बायोगैस उत्पादन, ऑर्गेनिक उर्वरक उपयोग और अनुकूलित टीएमआर फीडिंग को सम्मिलित किया गया। संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने के लिए सर्कुलर कृषि पद्धतियों को लागू किया गया। यह पहल पर्यावरण-अनुकूल डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए एक नॉलेज हब के रूप में कार्य करती है।

गणतंत्र दिवस

भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह ने एनडीडीबी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। डॉ. शाह ने सहकार से समृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के विज़न को साकार करने में एनडीडीबी की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया। उन्होंने सहकारिता की शक्ति के माध्यम से ग्रामीण भारत में बदलाव लाने के लिए एनडीडीबी की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

एनडीडीबी की प्राकृतिक कृषि सम्मेलन में सहभागिता

एनडीडीबी के अध्यक्ष ने साबर डेयरी में प्राकृतिक कृषि सम्मेलन में भाग लिया। इस कार्यक्रम में गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, गुजरात सरकार के माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री भीखूसिंह परमार जी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इस सम्मेलन में किसानों की आय बढ़ाने और सस्टेनेबल ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में कृषि और पशुपालन के बीच महत्वपूर्ण तालमेल पर जोर दिया गया। राज्यपाल ने स्वदेशी नस्ल विकास, जीनोमिक-आधारित बुल चयन और उन्नत प्रजनन तकनीकों, जिनमें ओपीयू-आईवीईपी-भ्रूण और गौसॉर्ट तकनीक शामिल हैं, में एनडीडीबी की पहलों पर जोर दिया, जिससे सेक्स्ड-सॉर्टेड सीमन डोज की लागत में उल्लेखनीय कमी आई है।

एनडीडीबी अध्यक्ष द्वारा डॉ. कुरियन स्मृति व्याख्यान

डॉ. मीनेश शाह ने XVII कृषि विज्ञान कांग्रेस में डॉ. वर्गीज़ कुरियन मेमोरियल व्याख्यान का उद्घाटन किया, जिसका विषय: " विकसित भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी" था।उन्होंने सहकारी डेयरी क्षेत्र में डॉ. कुरियन की केंद्रीय भूमिका को उजागर किया, जिसने नवोन्मेषी लघु डेयरी मॉडल के माध्यम से भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। डॉ. शाह ने एनडीडीबी की यात्रा की महत्वपूर्ण उपलब्धियों जैसे- ऑपरेशन फ्लड और एनडीपी–I पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त, उन्होंने किसान-केंद्रित नवाचारों जैसे गौचिप, महिषचिप और गौसॉर्ट पर चर्चा की, जो सस्टेनेबल और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने हेतु डिज़ाइन किए गए हैं और श्वेत क्रांति 2.0 के तहत् एनडीडीबी की रणनीतिक दृष्टि के अनुरूप हैं।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

एनडीडीबी ने "शी शाइनं" थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में डेयरी सहकारिताओं में महिलाओं की बढ़ती नेतृत्वकारी भूमिका और 'महिलाओं की डेयरी में भागीदारी' से 'महिलाओं के नेतृत्व वाली डेयरी' की ओर बदलाव को सम्मानित किया गया। जेंडर समावेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिताएं और जागरूकता से संबंधित गतिविधियां आयोजित की गईं।

एनडीडीबी के प्रयासों को बढ़ावा देना – एनडीडीबी की सहायक कंपनियां

मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड

मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1974 में ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत "मदर डेयरी, दिल्ली" के रूप में की गई थी। इस कंपनी की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य दिल्ली क्षेत्र में तरल दूध की बढ़ती मांग को पूरा करना है। मदर डेयरी अपनी स्थापना से ही किसानों तथा उपभोक्ताओं दोनों के हितों को साधने के प्रति प्रतिबद्ध रही है। कंपनी का विज़न है "उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य एवं पेय पदार्थ किफायती मूल्य पर उपलब्ध कराना तथा उत्पादकों को उचित लाभ सुनिश्चित करना।" वित्त वर्ष 2024-25 कंपनी के लिए एक ऐतिहासिक पड़ाव सिद्ध हुआ, जब मदर डेयरी ने विश्वास, गुणवत्ता और समावेशी विकास की पचास वर्षीय गौरवपूर्ण यात्रा का उत्सव मनाया।

वित्त वर्ष 2024-25 में, इस कंपनी ने 17,386 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत की मज़बूत वृद्धि दर्शाता है। डेयरी क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस वर्ष सहज (उत्तर प्रदेश), बानी (पंजाब), श्रीजा (आंध्र प्रदेश) और पायस (राजस्थान) सहित दूध उत्पादक संगठनों के बिक्री कार्यों में भी सुचारू रूप से बदलाव देखा गया, जिससे बाजार विस्तार के प्रयासों को बढ़ावा मिला।

अपने पोर्टफोलियो को सशक्त बनाते हुए, मदर डेयरी वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के ऑर्गेनिक उत्पादों के वितरण एवं विपणन की विशेष भागीदार बनी। यह कार्य इसके निर्धारित 'सफल' बूथों, सामान्य व्यापारिक आउटलेट्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से किया जाएगा।

श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री; श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री; प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल जी, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज राज्य मंत्री; श्री जॉर्ज कुरियन जी, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री; श्री राघवजीभाई पटेल जी, माननीय कृषि, पशुपालन, गौ-प्रजनन एवं मत्स्यपालन मंत्री, गुजरात सरकार; श्री जगदीश विश्वकर्मा जी, माननीय सहकारिता राज्य मंत्री, गुजरात सरकार; श्री मितेश पटेल जी, माननीय संसद सदस्य; श्रीमती अलका उपाध्याय, सचिव, डीएएचडी, भारत सरकार और डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी ने गुजरात के इटोला में मदर डेयरी की ग्रीनफील्ड परियोजना की आधारशिला रखते हुए

कंपनी ने सस्टेनेबल विकास के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कई पहलें की हैं, जिनमें पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग तथा सर्कुलर पैकेजिंग में पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक का उपयोग शामिल है। इन प्रयासों से लगभग 600 टन नए (वर्जिन) प्लास्टिक को प्रणाली से हटाए जाने की संभावना है। वर्ष 2018 से अब तक, मदर डेयरी ने उपभोक्ता-उपयोग के बाद उत्पन्न लगभग 53,500 टन प्लास्टिक कचरे का सफलतापूर्वक संग्रहण, पृथक्करण और रिसाइकलिंग किया।

वित्त वर्ष 2024–25, मदर डेयरी के लिए नवाचार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण वर्ष सिद्ध हुआ। इस वर्ष में उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वास्थ्यवर्धक एवं सुविधाजनक विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से 30 से अधिक नवीन उत्पाद लॉन्च किए गए। स्वास्थ्य-जागरूक उपभोक्ताओं के बीच प्रोटीन की बढ़ती महत्ता को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने प्रोमिल्क का शुभारंभ किया, जो एक सरल, दैनिक प्रोटीन उत्पाद है। इसके सेवन हेतु जीवनशैली में किसी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक नहीं है। यह पहल कंपनी के उस मिशन को परिलक्षित करती है जिसके अंतर्गत प्रोटीन खपत को लोकभोग्य बनाकर इसे प्रत्येक वर्ग तक सुलभ कराना है।

उपभोक्ताओं को आकर्षित करने तथा उन्हें नवीन विकल्पों का पता लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, मदर डेयरी ने आइसक्रीम वैरिएंट में विविधतापूर्ण नए वैरिएंट प्रस्तुत किए, जिनमें सेलिब्रेशन पैक्स, सिंगल सर्व्स, कुल्फी, कोन तथा प्रीमियम टब्स सम्मिलित हैं। डेयरी पोर्टफोलियो का भी विस्तार किया गया, जिसमें अग्रणी नवाचार के रूप में भारत का पहला सेट-फॉर्मेट हाई प्रोटीन ग्रीक योगर्ट लॉन्च शामिल है। इसके साथ ही प्रोबायोटिक छाछ, लो-फैट पाउच दही तथा अन्य फंक्शनल एवं इन्डलजेंट उत्पाद शामिल किए गए। इसके अलावा, कंपनी ने विशेष गिर गाय का घी लॉन्च किया, जिसमें प्रामाणिकता सुनिश्चित करने हेतु ट्रेसएबिलिटी फीचर को शामिल किया गया है।

पिछले वर्ष के दौरान मदर डेयरी ब्रांड ने नवजीवंतता का अनुभव किया, जिसमें प्रेम, सुरक्षा एवं करुणा के मूल्यों को आत्मसात किया गया। वित्त वर्ष 2024–25 में, उपभोक्ता विश्वास को और सुदृढ़ करने हेतु कंपनी ने भावनात्मक अभियान "ममता जैसी शुद्ध, मां जैसी ममता – मदर डेयरी, मां जैसी" चलाया। ब्रांड ने अपनी पहुंच को और व्यापक बनाने के लिए आईपीएल, चैंपियंस ट्रॉफी तथा प्रो कबड्डी लीग जैसे प्रतिष्ठित आयोजनों के साथ सहभागिता की, जिससे खेल प्रेमियों के साथ गहरा जुड़ाव स्थापित हुआ और समग्र उपभोक्ता जुड़ाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

इन समन्वित प्रयासों से, मदर डेयरी ने एक विश्वसनीय देशी नाम से अपनी स्थिति को और सुदृढ़ किया, जो गुणवत्ता, नवाचार तथा अटूट उपभोक्ता-केंद्रित दृष्टिकोण का पर्याय है।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, धारा ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत राजस्व की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। साथ ही, कंपनी ने प्रमुख उपभोक्ता बाजारों में डेडिकेटेड मस्टर्ड ऑयल कैटेगरी कैम्पेन प्रारंभ किया, जिसे विभिन्न बीटीएल पहलों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया, जिससे इसकी पहुंच और अधिक प्रभावशाली बनी।

इसी प्रकार, सफल ने वित्त वर्ष 2024–25 में सशक्त प्रदर्शन करते हुए पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत राजस्व वृद्धि दर्ज की।

इस वर्ष सोर्सिंग एवं डिस्ट्रीब्यूशन के विस्तार हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिससे हमारी फार्म-टू-फोर्क वैल्यू चेन और सुदृढ़ हुई। लद्दाख को दिल्ली-एनसीआर से एप्रिकॉट्स एवं सेब की आपूर्ति हेतु

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ मदर डेयरी के गिर गाय के घी को ट्रेसेबिलिटी सुविधा के साथ लॉन्च करते हुए

जोड़ा गया। सफल ने मेघालय अनानास, मैंडरिन एवं अदरक को लॉन्च किया तथा बिहार, तमिलनाडु और ओडिशा में नए सोर्सिंग संबंध स्थापित किए। ये पहलें समावेशी विकास एवं क्षेत्रीय एकीकरण के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। सफल ने अपने वैल्यू-एडेड पोर्टफोलियो का और विस्तार करते हुए इडली-डोसा बैटर लॉन्च किया, जिससे एनसीआर क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए सुविधा और बढ़ी।

वित्त वर्ष के दौरान, सफल की प्रोसेसिंग अवसंरचना में उल्लेखनीय विस्तार हुआ। गुजरात एवं आंध्र प्रदेश में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई, जो फलों, सब्ज़ियों एवं हिमीकृत उत्पादों की प्रोसेसिंग हेतु समर्पित हैं। गुजरात इकाई की आधारशिला माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा रखी गई, जबकि आंध्र प्रदेश इकाई की आधारशिला आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू जी द्वारा रखी गई। ये नई सुविधाएं सफल की प्रोसेसिंग क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएंगी तथा इसके घरेलू एवं वैश्विक विस्तार को सशक्त करेंगी।

पुरस्कार एवं सम्मान:

- मदर डेयरी को दुनिया के अग्रणी स्वतंत्र ब्रांड मूल्यांकन और रणनीति परामर्शदाता कंपनी, ब्रांड फाइनेंस, यूके द्वारा शीर्ष 100 वैश्विक खाद्य और पेय ब्रांडों में शामिल किया गया।
- द एडवरटाइजिंग क्लब द्वारा आयोजित एफी इंडिया अवार्ड्स के 24वें संस्करण में, मदर डेयरी को उसके 'मां जैसी' अभियान के लिए ब्रॉन्ज अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।
- धारा को मिलर्स फॉर न्यूट्रीशन द्वारा 'ऑयल फोर्टिफिकेशन क्वालिटी लीप अवार्ड' से सम्मानित किया गया। मिलर्स फॉर न्यूट्रीशन, एक विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त उद्योग-नेतृत्व वाला सहयोग संगठन है, जो 2009 से ऑयल फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा देने में ब्रांड के निरंतर प्रयासों के लिए प्रदान किया जाता है।

आईडीएमसी लिमिटेड

आईडीएमसी लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1978 में हुई। एक छोटे डेयरी उपकरण निर्माता के रूप में प्रारंभ होकर यह कंपनी डेयरी प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग सॉल्यूशंस उद्योग की एक प्रमुख संस्था के रूप में विकसित हो चुकी है।

कंपनी ने मेटल फैब्रिकेशन एवं प्लास्टिक प्रोसेसिंग में अपनी विशेषज्ञता को सुदृढ़ किया है तथा तकनीकी दक्षता एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण द्वारा विश्वसनीय एवं किफायती समाधान प्रदान किए हैं। इन प्रयासों से डेयरी संयंत्रों की संचालन क्षमता में वृद्धि हुई और राष्ट्र की डेयरी अवसंरचना को मजबूती मिली। वित्त वर्ष में आईडीएमसी ने कुल 882.00 करोड़ रुपये की आय दर्ज की।

इस सफलता में कंपनी की मेटल डिवीजन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने 5,000 लीटर से लेकर 5,00,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले टर्नकी डेयरी प्लांट इंस्टॉलेशन संपन्न किए। इन सुविधाओं में बटर, यूएचटी दूध, आइसक्रीम, दही एवं मिल्क पाउडर की प्रोडक्ट लाइनें शामिल हैं।

कंपनी ने स्वचालित बल्क कल्चर प्रिपरेशन सिस्टम का विकास कर उसकी सफल कमीशनिंग की। इस प्रभाग ने यूनाइटेड किंगडम में 1,000,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले डेयरी संयंत्र हेतु एक निर्यात अनुबंध किया तथा 2,000,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले घरेलू प्रोजेक्ट का कार्यभार भी संभाला, जिसमें 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन बटर यूनिट तथा 3,200 टीआर अमोनिया-आधारित रेफ्रिजरेशन सिस्टम शामिल है। इसके अतिरिक्त, आईडीएमसी ने 50 टीआर से 1,600 टीआर तक की क्षमता वाले अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम की सफल कमीशनिंग भी की।

फार्म इक्विपमेंट डिवीजन ने हेरिंगबोन-टाईप के मिल्किंग पार्लर स्थापित किए तथा डेयरी फार्म उपकरणों की व्यापक श्रृंखला उपलब्ध कराई, जिनमें टीएमआर मिक्सर,पशु झुंड निगरानी हेतु काउ कॉलर टैग, सीमेन स्ट्रॉ के लिए डिजिटल थॉइंग यूनिट्स और स्मार्ट वेट मशीनें शामिल हैं।

प्लास्टिक डिवीजन ने 15,767 मीट्रिक टन पॉलीफिल्म की आपूर्ति की, जिसके माध्यम से दूध, घी, दही एवं छाछ की पैकेजिंग आवश्यकताओं को विविध पैकेजिंग फिल्मों द्वारा पूरा किया गया। इसके अतिरिक्त, इसने मिल्क पाउडर एवं अन्य खाद्य उत्पादों के लिए हाई- बैरियर लैमिनेट्स भी उपलब्ध कराए। डिवीजन ने यूएचटी दूध पैकेजिंग हेतु विशिष्ट बैरियर फिल्मों का अफ्रीकी देशों में निर्यात करके उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपस्थिति को और विस्तार दिया। एनडीडीबी के हीरक जयंती समारोह के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी द्वारा दिल्ली स्थित आईडीएमसी पॉलीफिल्म प्लांट की आधारशिला रखी गई।

आईडीएमसी ने फार्मास्यूटिकल्स एवं बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को संपादित कर अपने व्यावसायिक विस्तार को और गति प्रदान की। कंपनी ने पेनिसिलिन उत्पादन हेतु 200 किलोलीटर क्षमता वाले चार फर्मेंटर्स का निर्माण एवं स्थापना की।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री; सुश्री वर्षा जोशी, अपर सचिव, डीएएचडी, भारत सरकार; डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी और आईडीएमसी लिमिटेड, श्री प्रकाश माहेश्वरी, प्रबंध निदेशक, आईडीएमसी लिमिटेड के साथ आणंद में आईडीएमसी के नए फैब्रिकेशन शेड के उद्घाटन के दौरान

आईडीएमसी बल्क मिल्क कूलर निर्माण सुविधा

भारत में कंपनी ने क्रमशः मध्य क्षेत्र में 100 किलोलीटर और दक्षिणी क्षेत्र में 55 किलोलीटर क्षमता वाले फर्मेंटेशन सिस्टम की सफल कमीशनिंग की। इसके अतिरिक्त, आईडीएमसी ने खुरपका एवं मुंहपका रोग वायरस (FMDV) तथा कम्बाइंड FMDV एवं हैमरेजिक सेप्टीसीमिया (HS) वैक्सीन के उत्पादन हेतु एनिमल वैक्सीन उत्पादन सुविधा स्थापित करने का टर्नकी अनुबंध किया। साथ ही, एंटीबायोटिक उत्पादन में उपयोग होने वाले 10 किलोलीटर एंज़ाइमेटिक रिएक्टर की आपूर्ति हेतु एक एक्सपोर्ट ऑर्डर भी हासिल किया।

आईडीएमसी ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए पश्चिम भारत में 100 टीपीडी क्षमता वाले दो गोबर-आधारित बायोगैस संयंत्रों की सफल कमीशनिंग की। इन संयंत्रों में क्लीनिंग, कंप्रेशन एवं डिस्पेंसिंग सिस्टम्स का एकीकरण किया गया, जिससे बायोगैस उपयोग और संचालन दक्षता को अनुकूलित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, पूर्वी भारत में 300 टीपीडी क्षमता वाला पशु आहार संयंत्र भी स्थापित किया गया।

कंपनी ने डेयरी एवं सहायक क्षेत्रों के लिए उपकरणों की व्यापक श्रृंखला का निर्माण किया। इस उत्पाद पोर्टफोलियो में मिल्क साइलो, क्लीन-इन-प्लेस (CIP) सिस्टम्स, हीटर्स, चिलर्स, पाश्चुरीज़र्स, एसेप्टिक टैंक्स एवं यूएचटी स्टरलाइजेशन यूनिट्स सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने FAT स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट्स, कंटीनिवस बटर मेकिंग मशीन (CBMM), बटर टब फिलिंग सिस्टम्स तथा कंटीनिवस खोआ मेकिंग मशीन (CKMM) जैसी उन्नत तकनीकें भी उपलब्ध कराईं। मानक उत्पादों में आइसक्रीम फ्रीजर्स, फ्रूट फीडर्स, रोटरी एवं लीनियर कप फिलर्स, फ्लो कंपोनेंट्स, बल्क मिल्क कूलर्स तथा स्वदेशी मिल्किंग मशीनें शामिल हैं।

पिछले वित्त वर्ष में, अनुसंधान एवं विकास (R&D) प्रभाग ने विभिन्न उत्पाद विकास पहलों का नेतृत्व करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवधि में 10 KL एवं 25 KL क्षमता वाले नए एसेप्टिक टैंक्स तथा 4.4 KLPH मल्टी-प्रोडक्ट UHT स्टरलाइज़र का निर्माण प्रमुख परियोजनाओं में सम्मिलित रहा। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने मॉडल की नई श्रृंखला की सेंट्रीफ्यूगल पंप्स (CLA-30), उच्च क्षमता वाली वॉल्यूमेट्रिक कप-फिलिंग मशीनें, बड़े प्न्यूमैटिक वाल्व्स तथा 50 KLPH FAT स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट लॉन्च की। एनडीडीबी और सुजुकी आरएंडडी सेंटर इंडिया (SRDI) के साथ एक महत्वपूर्ण सहयोग के तहत 300 लीटर मोबाइल मिल्क कलेक्शन एवं टेस्टिंग सिस्टम का सफल विकास किया गया। कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रति प्रतिबद्धता इस तथ्य से परिलक्षित होती है कि सात उत्पादों के लिए CE सर्टिफिकेशन प्राप्त किया गया, जिससे निर्यात क्षमता और सुदृढ़ हुई। साथ ही, दो पेटेंट एप्लिकेशन फाइलिंग हमारी कंपनी की नवाचार एवं प्रौद्योगिकीय नेतृत्व की निरंतर खोज को रेखांकित करती है।

आईडीएमसी ने बढ़ती बाजार आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अत्याधुनिक फैब्रिकेशन वर्कशॉप स्थापित की, जिसमें हाई-कैपेसिटी क्रेन्स एवं 26 मीटर वर्टिकल क्लीयरेंस की सुविधा उपलब्ध है। अगस्त 2024 में, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन सिंह जी द्वारा उक्त सुविधा का उद्घाटन किया गया। इस इकाई ने कंपनी की डेयरी एवं फार्मास्युटिकल उद्योगों के लिए बड़े आकार के टैंक्स एवं वेसल्स का निर्माण करने की क्षमता को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया। इसके अतिरिक्त, एनडीडीबी की तकनीकी विशेषज्ञता के अंतर्गत रेडी-टू-यूज़ डेयरी कल्चर्स के उत्पादन हेतु एक इकाई का शुभारंभ किया गया, जिससे इस महत्वपूर्ण इनपुट सेक्टर में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को बल मिला।

आईडीएमसी ने एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रीशन को निरंतर सहयोग प्रदान किया, जिसमें गिफ्ट मिल्क पहल में योगदान भी सम्मिलित रहा। कंपनी ने स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों में भी सक्रिय सहभागिता की। दक्षिण भारत के एक प्रमुख मंदिर प्रयोगशाला को घी एवं डेयरी उत्पादों की शुद्धता की उन्नत परीक्षण उपकरण उपलब्ध कराए गए। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में और निवेश करते हुए कंपनी ने चार विनिर्माण इकाइयों में 490 किलोवाट क्षमता वाले रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स स्थापित किए तथा अतिरिक्त 700 किलोवाट क्षमता की स्थापना प्रगति पर है।

इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड

इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में खुरपका एवं मुंहपका रोग (FMD) वैक्सीन के उत्पादन हेतु की गई। इसे 8 अक्तूबर 1999 को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया। बीते चार दशकों में, आईआईएल एक समग्र वन हेल्थ (ONE HEALTH) वैक्सीन उत्पादक के रूप में विकसित हुआ है। गचिबोव्ली (तेलंगाना), शमीरपेट (तेलंगाना) एवं ऊटी (तमिलनाडु) स्थित उन्नत वैक्सीन विनिर्माण सुविधाओं के साथ आईआईएल विश्व के एक अग्रणी वैक्सीन निर्माताओं में से के रूप में उभरा है।

31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, आईआईएल ने 1,453 करोड़ रुपये का टर्नओवर हासिल किया। अन्य आय को सम्मिलित करने पर कुल राजस्व 1,513 करोड़ रुपये दर्ज किया।

आईआईएल, भारत सरकार को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रमुख वैक्सीन आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, जैसे – रोग नियंत्रण कार्यक्रम, पशु रोग नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (ASCAD), सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) आदि। इसके अतिरिक्त, आईआईएल अपने टीकों का निर्यात विश्व के 60 से अधिक देशों में करता है।

वर्तमान में, एफएमडी, एंटी-रेबीज़, पेंटावैलेंट, ब्लू टंग, थिलेरियोसिस, Cysvax, क्लासिकल स्वाइन फीवर, पीपीआर, हेपाटाइटिस -ए, हेपाटाइटिस -बी, टिटनेस टॉक्सॉइड आदि प्रमुख टीके आईआईएल की आय के मुख्य स्रोत हैं। साथ ही, अनेक नवीन उत्पादों के विकास का अंतिम चरण जारी है।

कंपनी की उत्पाद विकास प्रक्रिया सशक्त एवं आशाजनक है। अनुसंधान एवं विकास (R&D) टीम वर्तमान में कई महत्वपूर्ण टीकों के विकास पर केंद्रित है, जिनमें टेट्रावैलेंट मस्टाइटिस वैक्सीन, कुत्तों हेतु टेन-इन-वन कॉम्बिनेशन वैक्सीन, लंपी स्किन डिज़ीज़ वैक्सीन, भेड़ एवं बकरियों में फुट रॉट हेतु वैक्सीन, Td वैक्सीन, टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन, हेक्सावैलेंट वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड जीका वैक्सीन तथा क्यासानूर फॉरेस्ट डिज़ीज़ (KFD) वैक्सीन शामिल हैं। निकट भविष्य में इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रेकाइटिस (IBR), खसरा-रूबेला तथा मछलियों हेतु वैक्सीन लॉन्च करने की योजना है। इस वर्ष की एक उल्लेखनीय उपलब्धि एनडीडीबी के साथ संयुक्त रूप से "षष्ठी" का विकास रहा, जो एक स्वदेशी इन-विट्रो फर्टिलाइज़ेशन (IVF) मीडिया है। साथ ही, प्रभाग नए पोल्ट्री वैक्सीनों के विकास हेतु सहयोग की संभावनाओं का सक्रियता से पता लगा रहा है।

आईआईएल की विदेशी सहायक कंपनी प्रिस्टीन बायोलॉजिकल्स एनज़ेड लिमिटेड, डारगाविले, न्यूज़ीलैंड में वर्ष 2015 में स्थापित की गई। इसका मुख्य कार्य एडल्ट बोवाइन सीरम (ABS) की आपूर्ति करना है, जो एफएमडी एवं विभिन्न वैक्सीनों के उत्पादन हेतु एक महत्वपूर्ण इनपुट है। इस सहायक कंपनी का योगदान भारतीय बाजार के लिए एफएमडी वैक्सीन के सतत् उत्पादन एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है।

मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए राष्ट्र की वैक्सीन सुरक्षा में सबसे बड़ा योगदानकर्ता

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

न्यूजीलैंड के माननीय प्रधानमंत्री श्री क्रिस्टोफर लक्सन ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के विपक्ष के नेता श्री क्रिस हिपकिंस की उपस्थिति में एनडीडीबी और आईआईएल के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह, आईआईएल के एमडी डॉ. के. आनंद कुमार और प्रिस्टीन बायोलॉजिकल्स (एनजेड) लिमिटेड के निदेशक डॉ. विजय दसारी को 'बिज़नेस एक्सीलेंस इन मार्केटिंग' और 'बिज़नेस एक्सीलेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड विथ इंडिया' पुरस्कार प्रदान करते हुए

कंपनी ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित अनेक कृषि मेलों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, ताकि किसानों में जागरूकता को सुदृढ़ किया जा सके। अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पहल के अंतर्गत, आईआईएल देशभर की गौशालाओं में एक लाख से अधिक पशुओं को निरंतर स्वास्थ्य कवरेज प्रदान कर रही है। तेलंगाना राज्य के लक्ष्मापुर गांव में दो तथा कार्कपटला गांव में एक शासकीय विद्यालय को आईआईएल द्वारा गोद लिया गया है, जहां विद्यार्थियों के समग्र कल्याण हेतु बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है तथा यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और नोटबुक उपलब्ध कराए गये हैं।

आईआईएल ने एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रीशन (NFN) की प्रमुख गतिविधियों जिसमें गिफ्टमिल्क (स्कूली बच्चों हेतु) एवं घरेलू बायोगैस संयंत्र को सहयोग दिया है। गत तीन वर्षों में इस सीएसआर गतिविधि से तेलंगाना और तमिलनाडु के क्षेत्रों में 3500 से अधिक स्कूली छात्र एवं लगभग 300 परिवार लाभान्वित हुए हैं।

आईआईएल केरल राज्य में रेबीज उन्मूलन के अभियान में भी सक्रिय रूप से संलग्न है। Compassion for Animals Welfare Association (CAWA) नामक गैर-सरकारी संगठन (NGO) के सहयोग से आईआईएल ने "RABIES FREE KERALA" पहल को वित्तपोषित किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवारा कुत्तों का टीकाकरण, स्कूल बच्चों एवं सरकारी अस्पतालों के रोगियों को परामर्श प्रदान करना तथा सार्वजनिक जागरूकता अभियानों का आयोजन केरल के त्रिवेंद्रम, कोल्लम एवं त्रिशूर जिलों में किया गया।

फरवरी 2025 में, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन जी ने केरल सरकार की पशुपालन, डेयरी विकास मंत्री, श्रीमती जे चिंचुरानी जी और एनडीडीबी और आईआईएल के अध्यक्ष, डॉ. मीनेश शाह के साथ मिलकर कोट्टायम के नगरपालिका अध्यक्ष और सीएडब्ल्यूए टीम को वैक्सीन किट और विशेष रूप से अनुकूलित रेबीज टास्क फोर्स वाहन की चाबी सौंपी।

गत वर्ष, आईआईएल को अनेक विशिष्ट अतिथियों की मेजबानी का गौरव प्राप्त हुआ। इनमें नीति आयोग के सदस्य श्री वी.के. पॉल तथा भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD) की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय शामिल थीं। दोनों अतिथियों ने जनवरी 2025 में IIL द्वारा प्रायोजित "पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड वैक्सीन इनोवेशन" विषयक सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में सहभागिता की।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, आईआईएल को अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनमें टीम मार्कमेन नेटवर्क द्वारा प्रदत्त "मोस्ट प्रेफर्ड वर्कप्लेस अवार्ड", भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा "राष्ट्रीय ऊर्जा प्रबंधन उत्कृष्टता पुरस्कार 2024" तथा दो ईटी री-फार्मा अवार्ड्स में "बायोटेक ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर" और "मेक इन इंडिया इनिशिएटिव" (भारत के प्रथम हेपाटाइटिस-ए वैक्सीन हेतु) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी को आईएमएपीएसी द्वारा आयोजित बायोफार्मा एक्सीलेंस अवार्ड्स इंडिया एडिशन 2025 में "मोस्ट प्रॉमिसिंग वैक्सीन डेवलपमेंट 2025" पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

इंडियन न्यूज़लिंक बिज़नेस अवार्ड्स 2024 में प्रिस्टीन बायोलॉजिकल्स (न्यूज़ीलैंड) लिमिटेड को सम्मान

इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड (IIL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी प्रिस्टीन बायोलॉजिकल्स (न्यूज़ीलैंड) लिमिटेड को इंडियन न्यूज़लिंक के रजत जयंती समारोह और नवंबर 2024 में ऑकलैंड, न्यूज़ीलैंड में आयोजित 15वें वार्षिक इंडियन न्यूज़लिंक बिज़नेस अवार्ड्स के दौरान सम्मान प्राप्त हुआ। इस सहायक कंपनी को 'मार्केटिंग में व्यावसायिक उत्कृष्टता' और 'भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यावसायिक उत्कृष्टता' के लिए पुरस्कार मिले।

न्यूज़ीलैंड के माननीय प्रधानमंत्री श्री क्रिस्टोफर लक्सन ने ये पुरस्कार प्रदान किए। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय विपणन में सहायक कंपनी की मज़बूती और ऑर्गेनिक उत्पादों एवं पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भारत-न्यूज़ीलैंड व्यापार को बढ़ाने में इसकी भूमिका को प्रदर्शित करता है।

एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज

एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (NDS), एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली एक गैर-लाभकारी सहायक कंपनी है, जिसकी स्थापना 2009 में हुई। एनडीएस का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना, उत्पादकत्ता वृद्धि करना, दूध की गुणवत्ता में सुधार करना, पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करना और ग्रामीण डेयरी किसानों को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना है। एनडीएस, डेयरी विकास के समावेशी और कुशल मॉडलों को लागू करके अपने कार्यक्षेत्र का निरंतर विस्तार कर रही है।

वित्त वर्ष 2024-25 में, एनडीएस द्वारा संचालित 23 दूध उत्पादक संगठनों (MPO) के सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप 9,637 करोड़ रुपये का संचयी सकल कारोबार दर्ज किया गया।

वर्ष के दौरान, महाराष्ट्र में मराठवरहाड़ एमपीओ का संचालन एनडीएस की तकनीकी और वित्तीय सहायता से किया गया। सृजनी एमपीओ ने भी एनडीएस के तकनीकी सहयोग से इसी वित्तीय वर्ष में परिचालन शुरू किया।

अपने मैनडेट के अनुरूप, स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (NDS) वर्तमान में चार वीर्य केंद्रों का संचालन कर रही है, जिनके माध्यम से वित्त वर्ष में कुल 425.97 लाख हिमीकृत वीर्य डोज़ों का वितरण किया गया। इसमें अट्ठारह देशी गाय नस्लों से 80.39 लाख डोज़ तथा 8 भैंस नस्लों से 133.43 लाख डोज़ सम्मिलित हैं, जो देशी पशुधन आबादी में आनुवंशिक विविधता और उत्पादकता को बढ़ाने के प्रति एडीएस की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

एनडीएस ने गौसॉर्ट नामक एक अभिनव सेक्स-सॉर्टेड सीमन तकनीक को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिसे स्वदेशी रूप

मापदंड	विवरण
कुल एमपीओ	23
सभी महिला सदस्यता वाले एमपीओ	16
महिला अध्यक्षों द्वारा संचालित एमपीओ	18
आच्छादित गांव	37,000 से अधिक गांव
किसान सदस्य	12 लाख से अधिक
महिला सदस्य	कुल सदस्यों का 77 प्रतिशत
लघुधारक किसान	कुल सदस्यों का 65 प्रतिशत
अंश पूंजी योगदान	242 करोड़ रुपये
प्रतिदिन दूध संकलन	62 लाख किलोग्राम से अधिक

श्री गणेश राम सिंहखुंटिया जी, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ओडिशा सरकार; माननीय श्री गोकुलानंद मलिक जी, माननीय मत्स्यपालन एवं पशु संसाधन विकास, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री, ओडिशा सरकार; डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी और एनडीएस अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ ओडिशा के मयूरभंज में गौ समावेश कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए

गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी को एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह द्वारा एसएजी, बीडज की गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए

से विकसित किया गया और जिसका 5 अक्तूबर, 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा औपचारिक शुभारंभ किया गया। यह अत्याधुनिक तकनीक, अलामाढी सीमन स्टेशन पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD) तथा एनडीडीबी के सहयोग से विकसित की गई है। यह तकनीक मादा बछड़े के जन्म की संभावना को 90 प्रतिशत तक बढ़ाती है। जनवरी 2025 से इसका व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत चौथी तिमाही में 3 लाख डोज़ का उत्पादन किया गया। यह तकनीक सस्टेनेबल डेयरी कृषि और पशु झुंड सुधार पहलों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फरवरी 2025 में, गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी ने एनडीएस द्वारा संचालित विश्व की सबसे बड़ी साबरमती आश्रम गौशाला के सीमन स्टेशन का भ्रमण किया तथा वहां स्वदेशी सेक्स सॉर्टिंग सीमन – गौसॉर्ट के उत्पादन का अवलोकन किया।

पशुधन की गुणवत्ता में सुधार के अपने प्रयासों के तहत, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज़ (NDS) ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, मध्यप्रदेश, झारखंड, पंजाब एवं हरियाणा में किसानों को कुल 6,116 उच्च आनुवंशिक गुण वाले पशुओं का वितरण किया। इन पशुओं में गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, थारपारकर, क्रॉसब्रेड एचएफ, जर्सी, हरियाना, राठी, मुर्रा, पंढरपुरी और जाफराबादी जैसी नस्लें शामिल हैं। ये गाय एवं भैंस नस्लें दूध उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ नस्ल सुधार एवं सस्टेनेबल आजीविका अवसरों के माध्यम से आर्थिक एकीकरण को भी सशक्त बना रही हैं।

एनडीएस ने अपने पशु आहार बिक्री परिचालन के प्रथम पूर्ण वर्ष में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की, जिसमें कुल 255.36 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया गया, जिसमें 1,09,868 मीट्रिक टन की मात्रा शामिल है।

एनडीडीबी ने अलामाढी (तमिलनाडु), अंदेश नगर (उत्तर प्रदेश) और धामरोड (गुजरात) स्थित तीन केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म (CCBF) का प्रबंधन अपने हाथो में लिया। इन संस्थानों को डेयरी इनोवेशन के उत्कृष्टता केंद्रों में परिवर्तित किया गया, जिनका फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर, तकनीक और क्षमता विकास पर रहा। अंदेश नगर CCBF में वर्षभर में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लीडरशिप, विवाद समाधान, उन्नत आईटी एप्लीकेशन, व्यक्तिगत विकास, समय प्रबंधन तथा स्वच्छ दूध उत्पादन, डेयरी वैल्यू चेन, एफएसएसएआई नियमावली और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर विशेष सत्र शामिल थे। इन पहलों का उद्देश्य डेयरी इकोसिस्टम में MPO निदेशक मंडल और फॉर्मर फसिलिटेटर्स के बीच सुशासन, प्रोफेशनलिज्म और विशेषज्ञता को सुदृढ़ करना है।

घरेलू वित्तीय स्थिरता की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, एनडीएस ने अपने विकासात्मक दायरे को डेयरी से आगे बढ़ाते हुए ऐसे कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में विस्तार किया है, जो उत्पादक सदस्यों की वर्तमान पद्धतियों की पूरक हैं। संस्थान ने आंध्र प्रदेश में आम, राजस्थान में सरसों तथा बिहार में मक्के की कृषि मूल्य श्रृंखला की गतिविधियों को शुरू किया। एमपीओ सदस्यों द्वारा पहले से ही उगाई जा रही इन फसलों को उनके मूल्य संवर्धन की महत्वपूर्ण क्षमता और मज़बूत बाज़ार संपर्क के कारण चुना गया।

एनडीडीबी मृदा लिमिटेड

एनडीडीबी मृदा लिमिटेड, जो एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है, की स्थापना 1 जुलाई 2022 को की गई थी। इसका उद्देश्य गोबर प्रबंधन, बायोगैस उत्पादन और ऑर्गेनिक उर्वरक उत्पादन हेतु एकीकृत समाधान विकसित करना एवं लागू करना है। कंपनी की प्रमुख प्राथमिकता नवीकरणीय ऊर्जा पहलों पर रही, जिसमें गोबर को मुख्य फीडस्टॉक के रूप में प्रयोग किया गया। इन पहलों में घरेलू स्तर पर बायोगैस संयंत्रों का विकास, बायो-सीएनजी इकाइयों की स्थापना, डेयरी एवं औद्योगिक कार्यों हेतु बायोगैस आधारित ऊर्जा उपयोग तथा डाइजेस्टेड स्लरी से उत्पादित ऑर्गेनिक उर्वरकों का व्यावसायीकरण सम्मिलित रहा।

एनडीडीबी ने सुजुकी आरएंडडी सेंटर इंडिया प्रा. लि. (SRDI) के साथ एक संयुक्त उद्यम एमओयू किया, जिसके अंतर्गत भारत के विभिन्न स्थलों पर बायोगैस संयंत्रों की स्थापना एवं प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। यह सहयोग गोबर को एक सस्टेनेबल ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कार्बन न्यूट्रलिटी एवं विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संबंधी राष्ट्रीय लक्ष्यों को समर्थन प्रदान करता है।

एनडीडीबी के हीरक जयंती समारोह के अवसर पर, एनडीडीबी मृदा लिमिटेड ने एनसीओएल के साथ समझौता ज्ञापन(MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य जैव-इनपुट की आपूर्ति को सुगम बनाना तथा ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहित करना है।

एनडीडबी मृदा लिमिटेड ने वाराणसी दूध संघ स्थित 100 एमटीपीडी संयंत्र का संचालन निरंतर जारी रखा। इस संयंत्र से लगभग 8.9 लाख घन मीटर बायोगैस का उत्पादन हुआ, जिसका उपयोग डेयरी के स्टीम बॉयलरों में ईंधन के रूप में किया गया। इस पहल के माध्यम से स्थानीय किसानों से गोबर की खरीद पर 151 लाख रुपये से अधिक का निवेश किया गया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन प्राप्त हुआ।

कंपनी ने, एमएनआरई बायोगैस कार्यक्रम के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य किया। डेयरी सहकारिताओं, एमएनआरई तथा किसान-केंद्रित संगठनों के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से 13 राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, में 7,000 से अधिक घरेलू स्तर के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की गई। इन संयंत्रों ने किसानों की पूंजीगत निवेश आवश्यकताओं को कम किया तथा स्थानीय स्तर पर स्वच्छ ईंधन (कुकिंग गैस) तक पहुंच सुनिश्चित की।

बायोगैस स्लरी से उत्पादित "सुधन" ब्रांड के ऑर्गेनिक उर्वरकों की मांग पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रही। इन उर्वरकों ने मृदा स्वास्थ्य संरक्षण एवं पोषक तत्व के रिसाइकलिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

कंपनी ने समावेशी विकास को भी प्राथमिकता दी, जिसके अंतर्गत महिला किसानों की भागीदारी को गोबर प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में प्रोत्साहित किया गया। ये पहलें एनडीडीबी मृदा लिमिटेड के किसान-केंद्रित दृष्टिकोण तथा डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबल ऊर्जा एवं ऑर्गेनिक संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

एनडीडीबी मृदा लिमिटेड की गतिविधियों ने सस्टेनेबल एवं विकेन्द्रीकृत ऊर्जा समाधान विकसित करने के समग्र उद्देश्य को आगे बढ़ाया, जिससे ग्रामीण आजीविका को सशक्त करने और भारत की डेयरी प्रणाली को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला।

एनडीडीबी, आणंद में हीरक जयंती समारोह के दौरान एनडीडीबी मृदा लिमिटेड और एनसीओएल के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान

एनडीडीबी काफ लिमिटेड

एनडीडीबी काफ लिमिटेड, जो एक विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला है, को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। कंपनी ने अपने संचालन के दूसरे वर्ष को सफलतापूर्वक पूरा किया तथा 18.63 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया।

तकनीकी सेवाएं एवं परीक्षण

एनडीडीबी काफ लिमिटेड ने डेयरी उत्पादों, फैट एवं तेल, शहद, रेडी-टू-ईट फूड्स, प्रोसेस्ड एवं ऑर्गेनिक फूड्स, फल एवं सब्ज़ियां, पशु आहार, खनिज मिश्रण तथा विटामिन प्रीमिक्स के लिए वृहद् विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान कीं। आणंद स्थित प्रयोगशाला ने अपनी तकनीकी क्षमताओं का विस्तार करते हुए पितृत्व सत्यापन, बोवाइन डिज़ीज़ डायग्नोसिस, डिटेक्शन ऑफ़ क्रोमोसोमल एब्नॉरमलिटीज़ एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेंडर एस्टीमेशन, ब्रीड प्यूरिटी एनालिसिस तथा गाय एवं भैंसों के लिए जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू इवैल्यूएशन जैसी उन्नत सेवाएं शामिल हैं।

एनडीडीबी काफ लिमिटेड ने एनालिटिकल किट्स और उपकरणों के प्रदर्शन की पुष्टि करते हुए उपकरण निर्माताओं, वितरकों और नवोन्मेषी स्टार्ट-अप को प्रमाण-पत्र प्रदान किए। कंपनी ने ISO/IEC 17025 मान्यता को राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) के माध्यम से निरंतर बनाए रखा। प्रयोगशाला ने खाद्य पदार्थों, कृषि उत्पादों और जल परीक्षण के लिए बीआईएस, एपीडा और ईआईसी की मान्यता भी बनाए रखी। प्रयोगशाला ने एफएसएसआई के अंतर्गत दूध और दूध उत्पादों के लिए राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला (NRL) और रेफरल प्रयोगशाला (RL) के रूप में अपनी भूमिका जारी रखी।

प्रयोगशाला ने देश के पश्चिमी क्षेत्र के लिए एफएसएसआई की 10वीं फूड एनालिस्ट परीक्षा भी आयोजित की।

वर्ष के दौरान, एनडीडीबी काफ लि. ने 100,000 से अधिक सैम्पलों का मूल्यांकन किया, जिसमें रासायनिक, सूक्ष्मजीव संबंधी और आनुवंशिक पैरामीटर्स शामिल थे और कुल 420,000 से अधिक पैरामीटर्स का विश्लेषण किया गया। प्रयोगशाला ने दक्षता परीक्षण सेवाएं भी प्रदान कीं, जिनमें भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 150 से अधिक प्रयोगशालाओं को शामिल किया गया। इन प्रयासों से सम्पूर्ण क्षेत्र में गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance) को मजबूती मिली।

संचालन विस्तार – कोच्चि सुविधा

पिछले वर्ष हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) के अंतर्गत केरल कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (MILMA) ने एर्नाकुलम, कोच्चि स्थित स्टेट सेंट्रल क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के प्रबंधन एवं संचालन को एनडीडीबी काफ लिमिटेड को सौंपा। यह प्रयोगशाला एक क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में एनडीडीबी काफ लिमिटेड की विश्लेषणात्मक क्षमताओं में उल्लेखनीय विस्तार करेगी तथा डेयरी उत्पादों के अलावा मसाले, मत्स्य उत्पाद, चाय, कॉफी, सभी खाद्य एवं कृषि उत्पादों के लिए परीक्षण सेवाएं प्रदान करेगी।

श्री जॉर्ज कुरियन जी, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री, श्री के एस मणि, अध्यक्ष, केरल सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के साथ, एनडीडीबी और एनडीडीबी काफ लिमिटेड के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह और एनडीडीबी काफ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री राजेश सुब्रमण्यम को प्रयोगशाला की चाबी सौंपते हुए

डेयरी सहकारिताओं की प्रगति

डेयरी सहकारी समितियाँ (संख्या में)^

उत्तर

क्षेत्र /राज्य	80-81	90-91	00-01	10-11	20-21	23-24	24-25*
हरियाणा	505	3,229	3,318	7,019	7,837	7,686	7,839
हिमाचल प्रदेश		210	288	740	1,084	1,130	1,214
जम्मू एवं कश्मीर		105	**	**	896	1,294	1,775
लद्दाख						3	24
पंजाब	490	5,726	6,823	7,069	8,539	8,799	9,174
राजस्थान	1,433	4,976	5,900	16,290	21,300	26,493	27,184
उत्तर प्रदेश	248	7,880	15,648	21,793	40,353	38,753	45,244
उत्तराखंड					4,205	4,442	4,573
क्षेत्रीय कुल	**2,676**	**22,126**	**31,977**	**52,911**	**84,214**	**88,600**	**97,027**

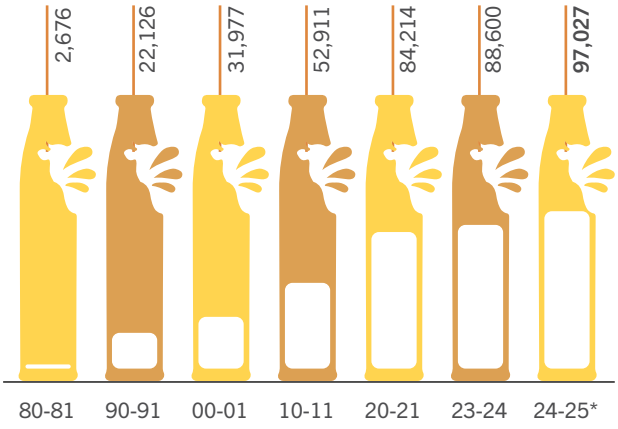

क्षेत्रवार डेयरी सहकारी समितियाँ (उत्तर)

पूर्व

क्षेत्र /राज्य	80-81	90-91	00-01	10-11	20-21	23-24	24-25*
असम		117	125	155	522	1,093	1,555
बिहार	118	2,060	3,525	9,425	26,275	29,405	31,825
झारखंड				53	769	1,228	1,228
मणिपुर						196	196
मेघालय					30	30	18
मिजोरम					42	36	25
नागालैंड		21	74	49	52	52	52
ओडिशा		736	1,412	3,256	6,151	6,523	6,417
सिक्किम		134	174	287	587	690	690
त्रिपुरा		73	84	84	119	168	178
पश्चिम बंगाल	584	1,223	1,719	3,019	3,804	3,968	3,455
क्षेत्रीय कुल	**702**	**4,364**	**7,113**	**16,328**	**38,351**	**43,389**	**45,639**

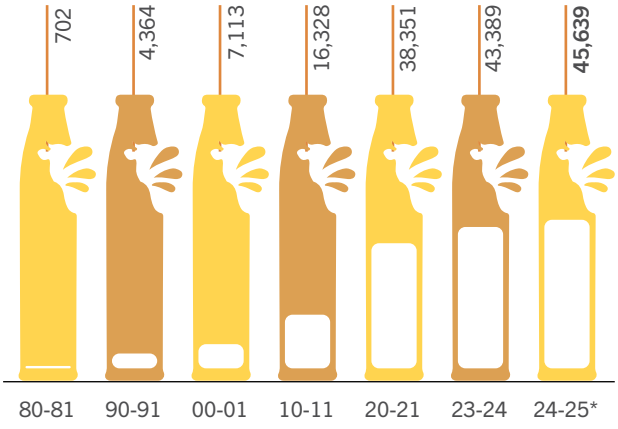

क्षेत्रवार डेयरी सहकारी समितियाँ (पूर्व)

^ डेयरी सहकारिताओं के लिए, यह संगठित (संचयी) है, इसमें पारंपरिक समितियां और पूर्व गठित तालुका संघ शामिल है। 2020-21 के बाद के आंकडों में एमपीसी के क्रियाशील एमपीपी और एमडीएफवीपील के एमपीआई शामिल हैं।

* अनंतिम

** रिपोर्ट नहीं मिली

पश्चिम

क्षेत्र /राज्य	80-81	90-91	00-01	10-11	20-21	23-24	24-25*
छत्तीसगढ				757	1,110	991	997
गोवा		124	166	178	183	174	181
गुजरात	4,798	10,056	10,679	14,347	22,341	23,018	23,497
मध्य प्रदेश	441	3,865	4,877	6,216	10,757	11,641	12,149
महाराष्ट्र	718	4,535	16,724	21,199	22,895	19,993	16,359
क्षेत्रीय कुल	**5,957**	**18,580**	**32,446**	**42,697**	**57,286**	**55,817**	**53,183**

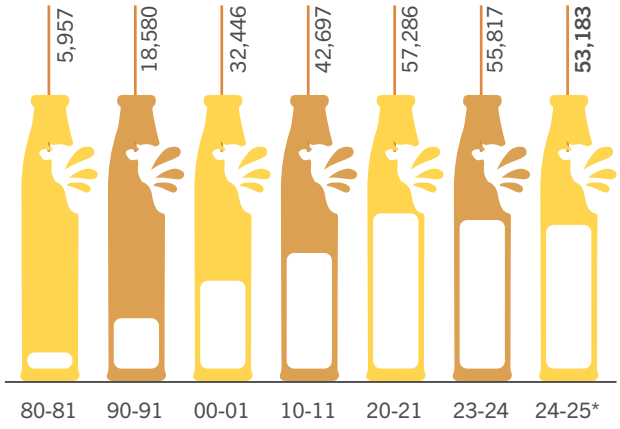

क्षेत्रवार डेरी सहकारी समितियाँ (पश्चिम)

दक्षिण

क्षेत्र /राज्य	80-81	90-91	00-01	10-11	20-21	23-24	24-25*
आंध्र प्रदेश	298	4,766	4,912	4,971	6,458	9,415	9,378
कर्नाटक	1,267	5,621	8,516	12,372	16,721	17,808	18,117
केरल		1,016	2,781	3,666	3,337	3,406	3,406
तमिलनाडु	2,384	6,871	8,369	10,079	10,555	11,428	11,610
तेलंगाना					6,581	6,862	6,879
पुदुचेरी		71	92	102	107	109	102
क्षेत्रीय कुल	**3,949**	**18,345**	**24,670**	**31,190**	**43,759**	**49,028**	**49,492**

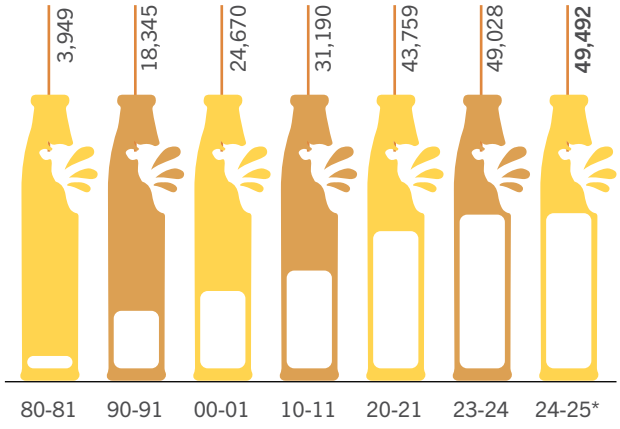

क्षेत्रवार डेयरी सहकारी समितियाँ (दक्षिण)

कुल योग

80-81	90-91	00-01	10-11	20-21	23-24	24-25*
13,284	63,415	96,206	1,43,126	2,23,610	2,36,834	2,45,341

स्रोत: दूध संघ एवं महासंघ, एनडीएस

डेयरी सहकारिताओं की प्रगति

उत्पादक सदस्य (हजार में)

उत्तर

क्षेत्र /राज्य	80-81	90-91	00-01	10-11	20-21	23-24	24-25*
हरियाणा	39	184	185	313	326	328	291
हिमाचल प्रदेश		17	20	32	46	48	49
जम्मू एवं कश्मीर		2	**	**	30	63	78
लद्दाख						0.3	1.1
पंजाब	26	304	370	385	419	402	420
राजस्थान	80	340	436	669	1,044	1,129	1,174
उत्तर प्रदेश	18	392	649	977	1,568	718	879
उत्तराखंड					159	169	175
क्षेत्रीय कुल	**163**	**1,239**	**1,660**	**2,376**	**3,593**	**2,856**	**3,066**

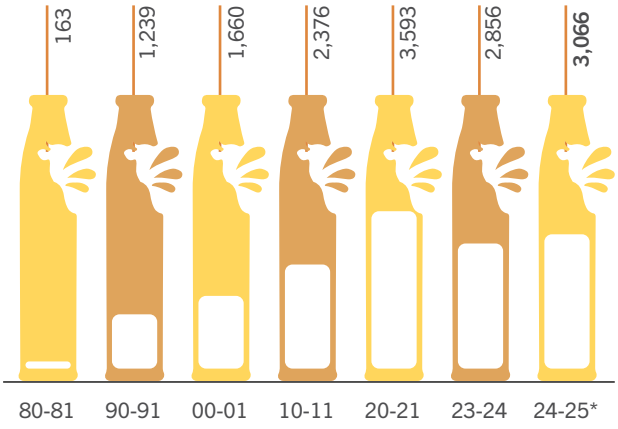

क्षेत्रवार उत्पादक सदस्य (उत्तर)

पूर्व

क्षेत्र /राज्य	80-81	90-91	00-01	10-11	20-21	23-24	24-25*
असम		2	1	4	34	58	88
बिहार	3	100	184	523	1,308	1,420	1,477
झारखंड				1	23	40	55
मणिपुर						4	4
मेघालय					1	1	1
मिजोरम					1	1	1
नागालैंड		1	3	2	2	2	2
ओडिशा		46	111	187	325	336	340
सिक्किम		4	5	10	15	18	18
त्रिपुरा		4	4	6	8	6	6
पश्चिम बंगाल	20	66	114	213	247	204	201
क्षेत्रीय कुल	**23**	**223**	**422**	**946**	**1,964**	**2,088**	**2,192**

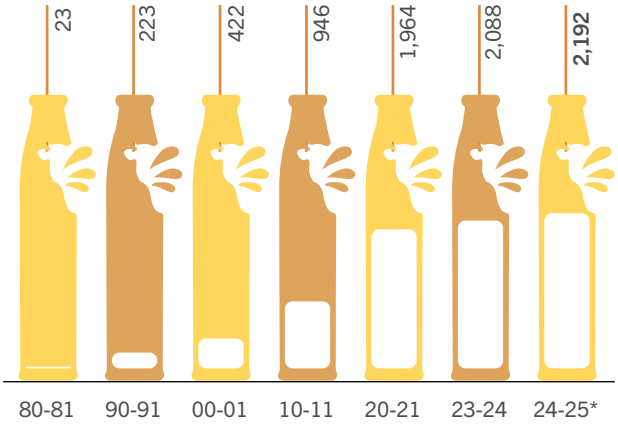

क्षेत्रवार उत्पादक सदस्य (पूर्व)

* अनंतिम

** रिपोर्ट नहीं मिली

2020-21 के बाद के आंकड़ों में एनडीएफवीपीएल की एमपीओ व एमपीजी के क्रियाशील सदस्यों को शामिल किया गया है।

पश्चिम

क्षेत्र /राज्य	80-81	90-91	00-01	10-11	20-21	23-24	24-25*
छत्तीसगढ				31	43	38	38
गोवा		12	18	19	19	19	19
गुजरात	741	1,612	2,147	2,970	3,740	3,667	3,684
मध्य प्रदेश	24	150	242	271	372	407	401
महाराष्ट्र	87	840	1,398	1,818	1,853	1,089	890
क्षेत्रीय कुल	**852**	**2,614**	**3,805**	**5,109**	**6,027**	**5,219**	**5,032**

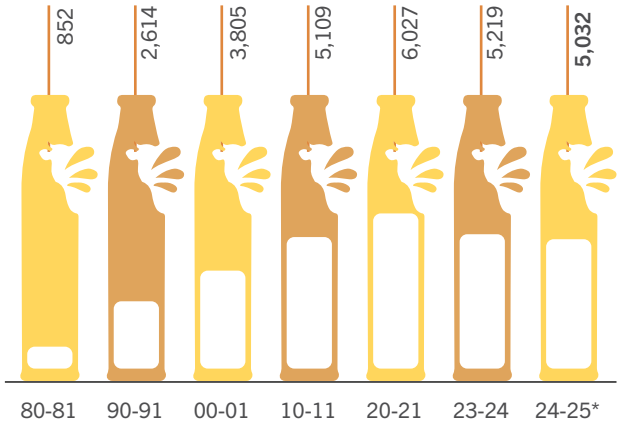

क्षेत्रवार उत्पादक सदस्य (पश्चिम)

दक्षिण

क्षेत्र /राज्य	80-81	90-91	00-01	10-11	20-21	23-24	24-25*
आंध्र प्रदेश	33	561	702	846	661	659	641
कर्नाटक	195	1,013	1,528	2,124	2,633	2,694	2,647
केरल		225	637	851	1,025	1,060	1,067
तमिलनाडु	481	1,590	1,957	2,176	1,983	1,705	1,536
तेलंगाना					258	271	279
पुदुचेरी		17	27	36	42	43	43
क्षेत्रीय कुल	**709**	**3,406**	**4,851**	**6,033**	**6,602**	**6,432**	**6,213**

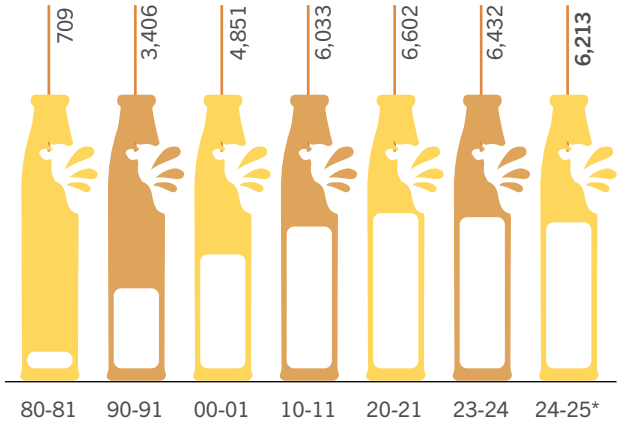

क्षेत्रवार उत्पादक सदस्य (दक्षिण)

कुल योग

80-81	90-91	00-01	10-11	20-21	23-24	24-25*
1,747	7,482	10,738	14,464	18,185	16,596	16,503

स्रोत: दूध संघ एवं महासंघ, एनडीएस

डेयरी सहकारिताओं की प्रगति

दूध संकलन (प्रतिदिन हजार किलोग्राम में)#

उत्तर

क्षेत्र /राज्य	80-81	90-91	00-01	10-11	20-21	23-24	24-25*
हरियाणा	33	94	276	511	590	593	509
हिमाचल प्रदेश		14	24	60	92	98	158
जम्मू एवं कश्मीर		11	**	**	92	158	187
लद्दाख						1	2
पंजाब	75	394	912	1,037	2,155	2,344	2,545
राजस्थान	138	364	887	1,629	3,613	4,702	4,506
उत्तर प्रदेश	64	382	791	504	1,330	1,957	2,028
उत्तराखंड					189	189	212
क्षेत्रीय कुल	**310**	**1,259**	**2,890**	**3,741**	**8,061**	**10,040**	**10,148**

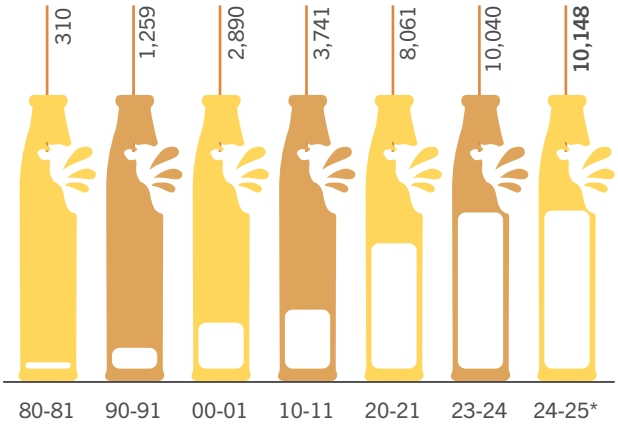

क्षेत्रवार दूध संकलन (उत्तर)

पूर्व

क्षेत्र /राज्य	80-81	90-91	00-01	10-11	20-21	23-24	24-25*
असम		4	3	5	29	52	89
बिहार	3	95	330	1,091	1,505	2,391	2,332
झारखंड				5	134	259	256
मणिपुर						2	1
मेघालय					14	11	10
मिजोरम					5	2	2
नागालैंड		1	3	2	3	3	3
ओडिशा		41	94	276	366	492	514
सिक्किम		4	7	12	40	50	52
त्रिपुरा		3	1	2	7	5	5
पश्चिम बंगाल	31	52	204	273	203	263	260
क्षेत्रीय कुल	**34**	**200**	**642**	**1,666**	**2,305**	**3,530**	**3,525**

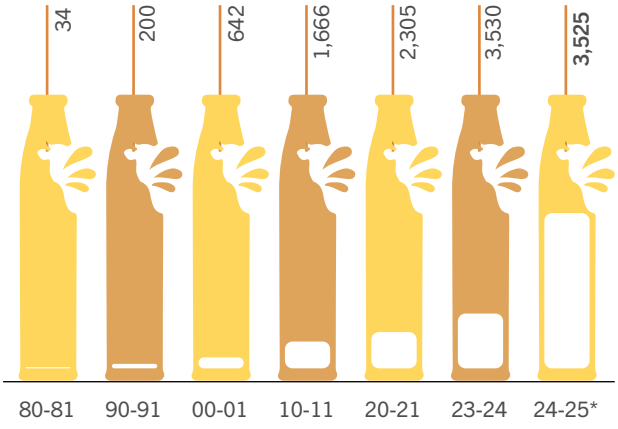

क्षेत्रवार दूध संकलन (पूर्व)

राज्य के बाहर के परिचालन शामिल है

* अनंतिम

** रिपोर्ट नहीं मिली

2024-25 में गुजरात के कुल दूध संकलन में राज्य के बाहर से 8,191 टीकेजीपीडी शामिल है और 2023-24 में यह आंकड़ा 9,027 टीकेजीपीडी था।

2020-21 के बाद के आंकडों में एमडीएफवीपीएल के एमपीजी और एमपीओ का संकलन शामिल है।

पश्चिम

क्षेत्र /राज्य	80-81	90-91	00-01	10-11	20-21	23-24	24-25*
छत्तीसगढ				25	68	69	69
गोवा		16	32	38	55	41	39
गुजरात	1,344	3,102	4,567	9,158	25,237	31,383	31,551
मध्य प्रदेश	68	256	319	588	954	1,191	1,025
महाराष्ट्र	165	1,872	2,979	3,053	3,751	4,081	4,341
क्षेत्रीय कुल	**1,577**	**5,246**	**7,897**	**12,862**	**30,065**	**36,764**	**37,025**

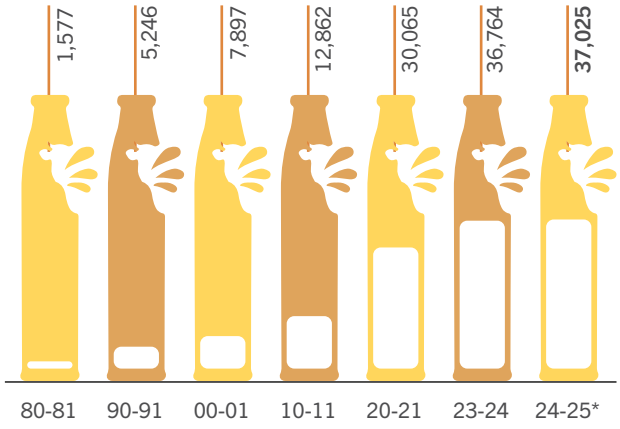

क्षेत्रवार दूध संकलन (पश्चिम)

दक्षिण

क्षेत्र /राज्य	80-81	90-91	00-01	10-11	20-21	23-24	24-25*
आंध्र प्रदेश	79	763	879	1,371	1,742	2,501	2,782
कर्नाटक	261	917	1,887	3,742	7,879	8,310	8,807
केरल		185	646	688	1,388	1,293	1,141
तमिलनाडु	301	1,106	1,618	2,097	3,709	3,043	3,367
तेलंगाना					461	676	734
पुदुचेरी		26	45	35	60	56	47
क्षेत्रीय कुल	**641**	**2,997**	**5,075**	**7,932**	**15,240**	**15,880**	**16,878**

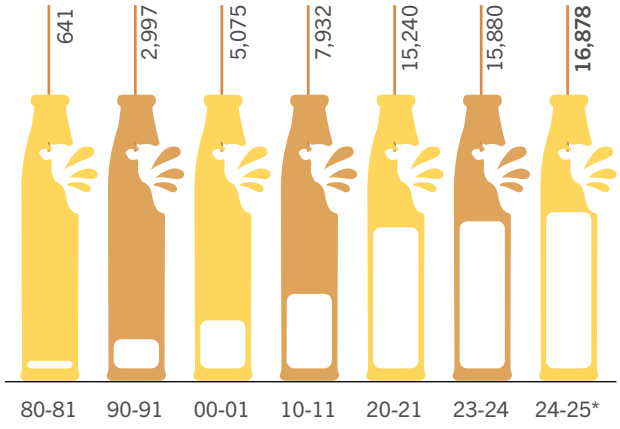

क्षेत्रवार दूध संकलन (दक्षिण)

कुल योग

80-81	90-91	00-01	10-11	20-21	23-24	24-25*
2,562	9,702	16,504	26,202	55,672	66,213	67,575

स्रोत: दूध संघ एवं महासंघ, एनडीएस एवं एमडीएफवीपीएल

डेयरी सहकारिताओं की प्रगति

तरल दूध विपणन (हजार लीटर प्रतिदिन में)#

उत्तर

क्षेत्र /राज्य	80-81	90-91	00-01	10-11	20-21	23-24	24-25*
हरियाणा	2	80	108	362	289	278	274
हिमाचल प्रदेश		15	20	23	25	24	24
जम्मू एवं कश्मीर		9	**	**	99	130	124
लद्दाख						1	3
पंजाब	7	139	420	802	1,013	1,289	1,255
राजस्थान	12	136	540	1,505	2,129	2,989	2,989
उत्तर प्रदेश	1	326	436	380	1,444	2,106	2,247
उत्तराखंड					161	154	158
दिल्ली	697	1,051	1,524	3,050	6,647	7,806	8,062
क्षेत्रीय कुल	**719**	**1,756**	**3,048**	**6,122**	**11,806**	**14,776**	**15,137**

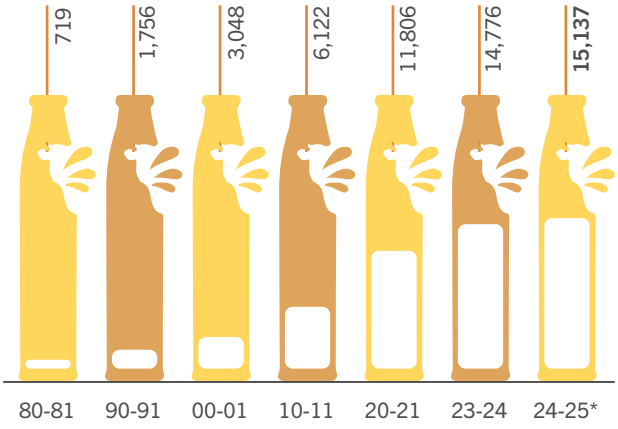

क्षेत्रवार तरल दूध विपणन (उत्तर)

पूर्व

क्षेत्र /राज्य	80-81	90-91	00-01	10-11	20-21	23-24	24-25*
असम		10	7	22	59	83	103
बिहार	8	111	324	454	1,269	1,480	1,533
झारखंड				253	374	423	432
मणिपुर						2	3
मेघालय					13	11	10
मिजोरम					4	3	4
नगालैंड		1	4	3	6	5	7
ओडिशा		65	98	290	324	334	317
सिक्किम		5	7	17	44	51	56
त्रिपुरा		6	7	15	9	7	6
पश्चिम बंगाल	17	26	27	41	83	108	111
कोलकाता	283	526	840	644	1,207	1,323	1,256
क्षेत्रीय कुल	**308**	**750**	**1,314**	**1,739**	**3,392**	**3,830**	**3,837**

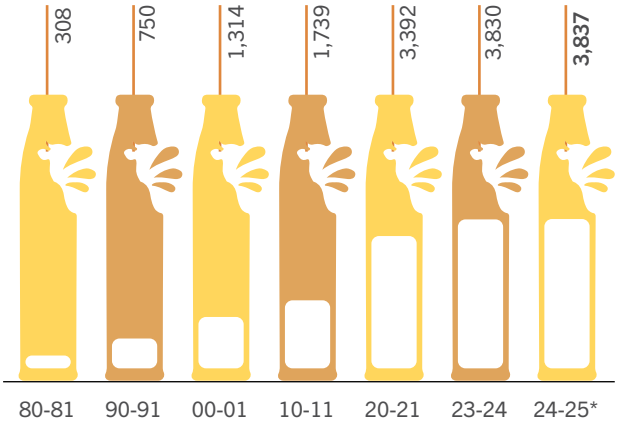

क्षेत्रवार तरल दूध विपणन (पूर्व)

मेट्रो डेरियों तथा राज्य के बाहर के परिचालन शामिल हैं

* अनंतिम

** रिपोर्ट नहीं मिली

2024-25 में, गुजरात की कुल दूध बिक्री 17,079 टीएलपीडी है जिसमें राज्य के बाहर के आंकडे शामिल है और 2022-23 में, यही आंकडा 16,711 टीएलपीडी था।

2020-21 में, यही महाराष्ट्र के दूध संघो द्वारा मुंबई के महाराष्ट्र दूध संघ द्वारा बेची गई मात्रा का विवरण उपलब्ध नहीं है।

2020-21 के बाद के आंकडों में एमपीसी और एमडीएफवीपीएल का संकलन शामिल है।

पश्चिम

क्षेत्र /राज्य	80-81	90-91	00-01	10-11	20-21	23-24	24-25*
छत्तीसगढ				34	176	259	263
गोवा		36	83	69	57	52	48
गुजरात	210	1,052	1,905	3,237	5,663	6,599	6,720
मध्य प्रदेश	39	279	244	495	800	951	932
महाराष्ट्र	18	363	1,178	2,023	1,641	1,931	1,950
मुंबई	950	1,057	1,390	841	2,650	3,029	2,995
क्षेत्रीय कुल	**1,217**	**2,787**	**4,800**	**6,699**	**10,986**	**12,821**	**12,908**

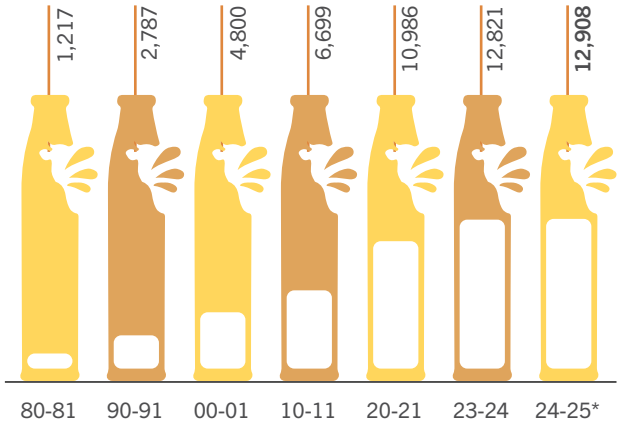

क्षेत्रवार तरल दूध विपणन (पश्चिम)

दक्षिण

क्षेत्र /राज्य	80-81	90-91	00-01	10-11	20-21	23-24	24-25*
आंध्र प्रदेश	19	552	733	1,565	1,346	1,427	1,397
कर्नाटक	166	889	1,501	2,661	4,261	5,311	5,408
केरल		223	640	1,092	1,315	1,623	1,635
तमिलनाडु	109	405	559	989	1,175	1,521	1,567
तेलंगाना					878	969	984
पुदुचेरी		22	43	93	92	92	97
चेन्नई	245	662	725	1,025	1,220	1,488	1,442
क्षेत्रीय कुल	**539**	**2,753**	**4,201**	**7,425**	**10,286**	**12,430**	**12,530**

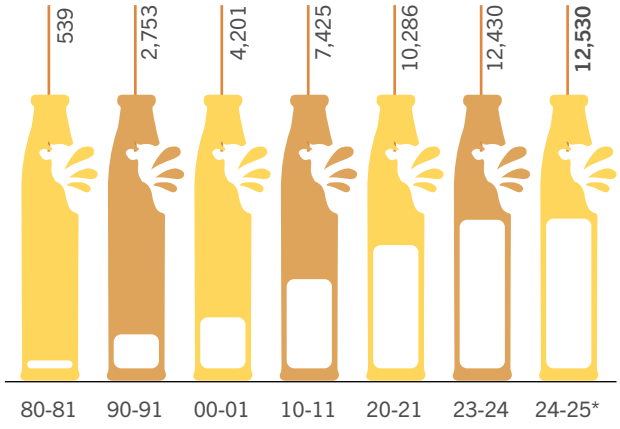

क्षेत्रवार तरल दूध विपणन (दक्षिण)

कुल योग

80-81	90-91	00-01	10-11	20-21	23-24	24-25*
2,783	8,046	13,363	21,985	36,470	43,856	44,412

स्रोत: दूध संघ एवं महासंघ, एनडीएस एवं एमडीएफवीपीएल

डेयरी सहकारिताओं की प्रगति

डेयरी सहकारिताओं की कोल्ड चेन अवसंरचना (क्षमता)*

(मार्च 2025)^

उत्तर

क्षेत्र /राज्य	बीएमसी (टीएल)	चिलिंग केंद्र (टीएलपीडी)	डेयरी संयंत्र (टीएलपीडी)
दिल्ली			1,500
हरियाणा	609	388	8,215
हिमाचल प्रदेश	173	79	180
जम्मू एवं कश्मीर	352		250
लद्दाख			5
पंजाब	2,474	1,132	3,760
राजस्थान	6,710	3,012	5,140
उत्तर प्रदेश	1,813	4,184	5,510
उत्तराखंड	77	60	256
क्षेत्रीय कुल	**12,207**	**8,855**	**24,816**

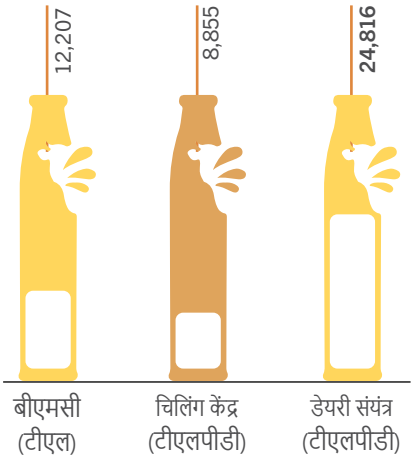

क्षेत्रवार कोल्ड चेन क्षमता (उत्तर)

पूर्व

क्षेत्र /राज्य	बीएमसी (टीएल)	चिलिंग केंद्र (टीएलपीडी)	डेयरी संयंत्र (टीएलपीडी)
असम	199		200
बिहार	2,344	410	4,820
झारखंड	336		840
मणिपुर	8		20
मेघालय	22		80
मिजोरम	4		35
नगालैंड	2		10
ओडिशा	920	125	1,260
सिक्किम	84		105
त्रिपुरा	19		64
पश्चिम बंगाल	425	155	1,279
क्षेत्रीय कुल	**4,360**	**690**	**8,713**

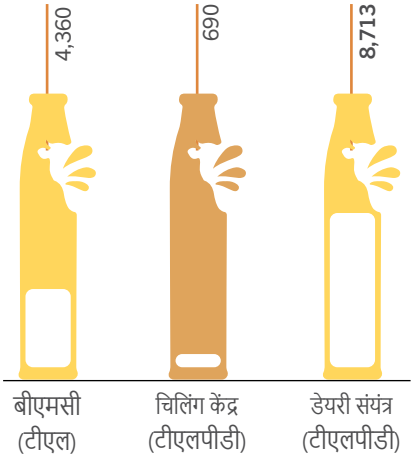

क्षेत्रवार कोल्ड चेन क्षमता (पूर्व)

* अनंतिम

टीएलः हजार लीटर

टीएलपीडीः हजार लीटर प्रतिदिन

^इसमें एमपीओ तथा एमडीएफवीपीएल द्वारा स्वामित्व प्राप्त अवसंरचना को सम्मिलित किया गया है।

पश्चिम

क्षेत्र /राज्य	बीएमसी (टीएल)	चिलिंग केंद्र (टीएलपीडी)	डेयरी संयंत्र (टीएलपीडी)
छत्तीसगढ	129	75	150
गोवा	46		110
गुजरात	31,621	5,820	35,240
मध्य प्रदेश	1,959	676	2,286
महाराष्ट्र	2,559	2,460	14,505
क्षेत्रीय कुल	**36,313**	**9,031**	**52,291**

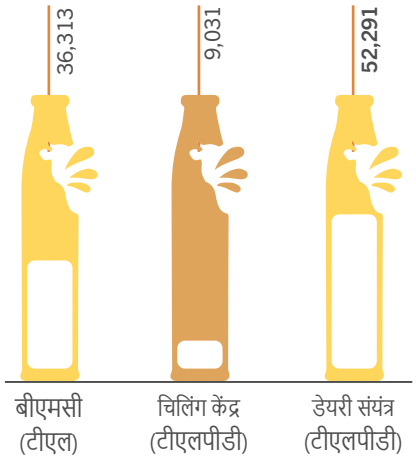

क्षेत्रवार कोल्ड चेन क्षमता (पश्चिम)

दक्षिण

क्षेत्र /राज्य	बीएमसी (टीएल)	चिलिंग केंद्र (टीएलपीडी)	डेयरी संयंत्र (टीएलपीडी)
आंध्र प्रदेश	2,858	1,044	4,105
कर्नाटक	7,461	3,060	11,810
केरल	1,799	30	3,150
तमिलनाडु	3,408	760	4,818
तेलंगाना	860	411	2,135
पुदुचेरी	78		120
क्षेत्रीय कुल	**16,463**	**5,305**	**26,138**

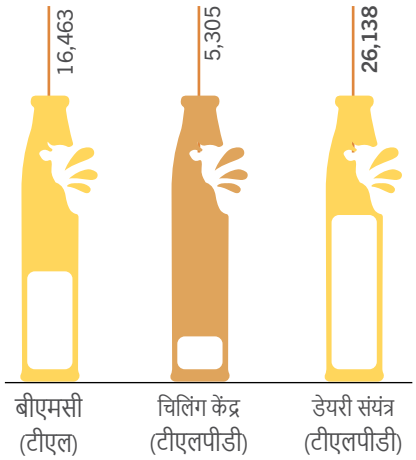

क्षेत्रवार कोल्ड चेन क्षमता (दक्षिण)

कुल योग

69,343
बीएमसी (टीएल)

23,881
चिलिंग केंद्र (टीएलपीडी)

1,11,958
डेयरी संयंत्र (टीएलपीडी)

स्रोत: दूध संघ एवं महासंघ, एनडीएस एवं एमडीएफवीपीएल

आगंतुक

वित्त वर्ष 2024–2025 के दौरान, एनडीडीबी में भारत और विदेश से 2,528 आगंतुक पधारे।

श्री ब्रायन लिंडसे,
निदेशक, डेयरी सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क

श्री ताकाओ सुज़ुकी,
सुज़ुकी मोटर कॉर्पोरेशन तथा श्री केनिचिरो टोयोफुकु,
निदेशक, सुज़ुकी आर एंड डी सेंटर इंडिया

श्री टॉड मैक्ले,
माननीय कृषि मंत्री, न्यूज़ीलैंड; महामहिम श्री पैट्रिक राटा,
उच्चायुक्त, न्यूज़ीलैंड उच्चायोग; सुश्री जूली कॉलिन्स, उप
महानिदेशक, प्राथमिक उद्योग मंत्रालय, न्यूज़ीलैंड; श्री ग्राहम राउज़,
वाणिज्य आयुक्त, न्यूज़ीलैंड ट्रेड एंटरप्राइज़

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन सिंह जी,
माननीय मंत्री, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं
डेयरी तथा पंचायती राज, भारत सरकार

प्रो. एस पी सिंह बघेल,
माननीय राज्य मंत्री, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती
राज, भारत सरकार

श्री हेमंत खंडेलवाल,
माननीय विधायक, बैतूल; डॉ. उमेश चंद्र शर्मा, अध्यक्ष, भारतीय
पशु चिकित्सा परिषद; डॉ. प्रवीण शिंदे, नोडल अधिकारी, मध्य
प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड; तथा श्री मोहन नागर, उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश
जन-अभियान परिषद्

श्री डैनियल श्मिट,
प्रबंध निदेशक, सिमोन फ्रेरे; श्री मिशेल ले कैद्र,
महानिदेशक, सिमोन फ्रेरे; तथा श्री एंटोनी मैसॉन, बिक्री
निदेशक, सिमोन फ्रेरे

श्री सुरेश प्रभु,
पूर्व केंद्रीय मंत्री, अध्यक्ष, आईसीएफए, चांसलर,
ऋषिहुड विश्वविद्यालय तथा रूरल डेवेलपमेंट एंड
एग्रिकल्चरल ट्रांसफ़ॉर्मेशन स्पेशलिस्ट

श्री गोकुलानंद मलिक,
माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), मत्स्य एवं पशु संसाधन विकास, सूक्ष्म,
लघु एवं मध्यम उद्यम, ओडिशा; श्री किशोर चंद्र प्रधानी, अध्यक्ष, ओमफेड,
ओडिशा; तथा श्री विजय अमरुत कुलांगे, आईएएस, प्रबंध निदेशक,
ओमफेड, ओडिशा

श्री तोशिहीरो सुज़ुकी,
प्रतिनिधि निदेशक एवं अध्यक्ष,
सुज़ुकी मोटर कॉर्पोरेशन

प्रोफेसर अदनान ख़ान,
मुख्य अर्थशास्त्री, फ़ॉरेन, कॉमनवेल्थ एवं विकास कार्यालय (FCDO),
यूनाइटेड किंगडम सरकार; तथा श्री स्टीव हिक्लिंग, उप उच्चायुक्त,
गुजरात और राजस्थान

श्री रितेश चौहान,
सचिव, पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार; तथा डॉ.
विकास सूद, प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी
दुग्ध महासंघ (एचपी मिल्कफेड)

आगंतुक

डॉ. स्टेन मॉर्टेनसन,
मुख्य परामर्शदाता, पशु स्वास्थ्य इकाई, डैनिश वेटरिनरी एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन (DVFA); डॉ. कैमिला ब्राश एंडरसन, मुख्य परामर्शदाता, अंतरराष्ट्रीय सहयोग केंद्र, डैनिश वेटरिनरी एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन (DVFA); तथा डॉ. हेले पाल्मो, परामर्शदाता, खाद्य एवं कृषि, रॉयल डैनिश दूतावास, नई दिल्ली

श्री धरमबीर सिंह,
माननीय सदस्य, लोकसभा

श्री एमिल पटेल,
श्री त्रिभुवनदास पटेल के पौत्र, कार्यपालक निदेशक (आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर), प्रबंध निदेशक, एंडरसन कैंसर सेंटर, यूएसए

एम'इकियारा साइमन किरुजा,
अध्यक्ष, मेरु सेंट्रल डेयरी कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड; कामुंडे यूस्टेस किमारु, उपाध्यक्ष, मेरु सेंट्रल डेयरी कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड; रीगी एडिथ नक्था, मानद सचिव, मेरु सेंट्रल डेयरी कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड;

श्री राहुल गुप्ता,
प्रबंध निदेशक, पंजाब राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड (मिल्कफेड)

माननीय वाइक्लिफ़ अंबेट्सा ओपारान्या,
ईजीएच, कैबिनेट सचिव, सहकारी एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास मंत्रालय, गणराज्य केन्या; माननीय टिटस खमाला मुखवाना, सदस्य, राष्ट्रीय विधानसभा, गणराज्य केन्या; श्री विंसेंट मारंगू, निदेशक, सहकारी बैंकिंग विभाग, कोऑपरेटिव बैंक ऑफ केन्या

डॉ. प्रवीण देवरे,
आईएएस, आयुक्त (पशुपालन),
महाराष्ट्र सरकार

श्री एडविन विट्लॉक्स,
कंट्री डायरेक्टर, पीयूएम नीदरलैंड्स

श्री ताकायुकी हागिवारा,
भारत में एफएओ प्रतिनिधि

बिरुकटायेत अस्सेफ़ा,
वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ, वर्ल्ड बैंक; सुश्री करिश्मा वस्ती, वरिष्ठ कृषि अर्थशास्त्री,
वर्ल्ड बैंक; एंडेशॉ अस्सेफ़ा, वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ – पशुधन मूल्य श्रृखंला,
कृषि मंत्रालय, इथियोपिया; कलकिदान वोंडिमु, पशुधन पहचान और
ट्रेसबिलिटी विशेषज्ञ, कृषि मंत्रालय, इथियोपिया; अद्दिसु अबेरा, पशु प्रजनन एवं
आनुवंशिकी विशेषज्ञ, कृषि मंत्रालय, इथियोपिया; और श्री तेस्फाये शेवा,
पर्यावरणीय सुरक्षा विशेषज्ञ, कृषि मंत्रालय, इथियोपिया

श्री आई. वी. राव,
विशिष्ट सदस्य, टेरी; श्री सौविक भट्टाचार्य, वरिष्ठ सदस्य एवं सह
निदेशक, टेरी; सुश्री त्रिनयन कौशिक, अनुसंधान सहयोगी, टेरी;
सुश्री अपर्णा सजीव, अनुसंधान सहयोगी, टेरी; और श्री मिलान सांगवी,
वरिष्ठ प्रबंधक, मारुति सुज़ुकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट

श्री सैमुअल सिग्रिस्ट,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एसआईजी कॉम्बिब्लॉक

आगंतुक

डॉ. आशीष कुमार भूटानी,
सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार; पंकज बंसल, अपर सचिव, सहकारिता मंत्रालय; और श्री संदीप कुमार सिंह, उपसचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

श्री मनोज गुप्ता,
सीईओ, टाटापावर रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड लिमिटेड (TPRMG) और श्री सुगाता मुखर्जी, परिचालन प्रमुख, टाटापावर रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड लिमिटेड (TPRMG)

सुश्री मीरा मिश्रा,
कंट्री डायरेक्टर,आईएफएडी; श्री बिनोद आनंद, सदस्य, उच्च स्तरीय समिति (एमएसपी, कॉरपोरेशन विधीकरण और प्राकृतिक कृषि), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार; और श्री विनीत राय, अध्यक्ष, आविष्कार ग्रुप

डॉ. डेविड ग्राहम,
सीईओ, एनिमल हेल्थ, आयरलैंड; और प्रो. फाल्को स्टाइनबाख, प्रमुख, मैमेलियन वायरोलॉजी, एनिमल एंड प्लांट हेल्थ एजेंसी (APHA), यूके

प्रो. गैरी उडी, एमपीआई,
न्यूज़ीलैंड; प्रो. निकोलस लोपेज, मेसी विश्वविद्यालय, न्यूज़ीलैंड; और डॉ. डेविड हेईमेन, टीआरजी/एबीएस, न्यूज़ीलैंड

एडवोकेट माणिकराव कोकटे,
माननीय कृषि मंत्री, महाराष्ट्र सरकार

एम के पी एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

प्रति
निदेशक मंडल
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

मत

1. हमने राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (''एनडीडीबी'') के संलग्न वित्तीय विवरणों लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 की स्थिति में तुलन पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखों और नकदी-प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सार तथा अन्य स्पष्टीकरण विवरणों (''वित्तीय विवरण'') सहित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां शामिल हैं।

2. हमारे मत में और हमें प्राप्त सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त ये वित्तीय विवरण राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 (''अधिनियम''), जो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (निधि, लेखा और बजट का संचालन) विनियम, 1988 ("विनियमन") के साथ पठित हैं, अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ("ICAI") द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2025 तक एनडीडीबी के कामकाज की स्थिति और तब समाप्त वर्ष के लिए इसके अधिशेष तथा इसके नकदी-प्रवाह का वास्तविक एवं स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करते हैं।

मत का आधार

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों ("SAs") के अनुसार की है । इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा वाले खंड में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में दिया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("ICAI") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार एनडीडीबी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो विनियमन के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी नैतिक जिम्मेदारियां पूरी की हैं। हमारा विश्वास है कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वे हमारे मत - वित्तीय विवरणों को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं ।

अन्य सूचनाएं

4. अन्य सूचनाओं को तैयार करने का दायित्व एनडीडीबी के प्रबंधन और निदेशक मंडल का है जिसमें सूचनाएं जैसे निदेशक मंडल की रिपोर्ट और एनडीडीबी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल अन्य प्रकटन शामिल हैं, परंतु वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य सूचनाएं इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

5. वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन अथवा निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

6. वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में हमारा यह दायित्व है कि हम अन्य सूचना पढ़ें और ऐसा करते समय यह देखें कि अन्य सूचना वित्तीय विवरणों से अथवा लेखा परीक्षा के दौरान हमें प्राप्त हुई जानकारी से किसी महत्वपूर्ण मामले में असंगत तो नहीं है अथवा उसमें अन्यथा कोई महत्वपूर्ण गलत प्रस्तुति तो नहीं दिखती । यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक भौतिक गलत बयान है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

7. प्रबंधन एवं एनडीडीबी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है कि वे विनियम के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार करें, जो एनडीडीबी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी-प्रवाह का वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हों । इस दायित्वों में एनडीडीबी

बी-301, वेस्टर्न एज II, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से दूर,
बोरीवली (पूर्व), मुंबई - 400066, भारत।
वेबसाइट: www.mkps.in | ईमेल: mumbai@mkps.in | दूरभाष: +91 22 35 402 661/579

की परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रख-रखाव करना; उचित लेखा नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और आकलन करना तथा लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे पर्याप्त ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और रखरखाव करना शामिल हैं जिनका परिचालन वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित था कि वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी महत्वपूर्ण गलत प्रस्तुतियों से मुक्त वास्तविक और निष्पक्ष चित्रण करने वाले एक आधार पर तैयार वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए संगत लेखा अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित कर सकें ।

8. वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय, प्रबंधन और निदेशक मंडल एनडीडीबी की क्षमता का आकलन करने के लिए भी जिम्मेदार हैं, जैसा कि वर्तमान सरोकार के रूप में जारी रखने की लागू हो, सरोकार करने और लेखांकन के वर्तमान सरोकार के आधार का उपयोग करने से संबंधित मुद्दों को प्रकट करते हैं, जब तक कि प्रबंधन या तो एनडीडीबी को परिसमाप्त करने या परिचालनों को बंद करने की मंशा नहीं रखती है, या ऐसा करने के अलावा कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं होता है।

9. एनडीडीबी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख-रेख के लिए निदेशक मंडल भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

10. हमारा उद्देश्य इस बात का तर्क पर आधारित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण पूर्णतः धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाले किसी महत्वपूर्ण गलत प्रस्तुतियों से मुक्त हैं। अन्य उद्देश्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा मत शामिल हो। तर्क पर आधारित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानदंडों के अनुसार संचालित लेखा परीक्षा किसी विद्यमान महत्वपूर्ण गलत प्रस्तुतियों का हमेशा पता लगा ही लेगी। गलत प्रस्तुतियां धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब वे व्यक्तिगत रूप से या पूर्ण रूप से इन विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को एक तर्कपूर्ण सीमा तक प्रभावित कर सकती हों।

11. लेखा मानकों के अनुसार, लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में, हम लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय क्षमता का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संदेहवाद बनाए रखते हैं। साथ ही:

11.1 हम धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत प्रस्तुतियों के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, उन जोखिमों के जवाब में लेखा परीक्षा कार्य पद्धतियों की रूपरेखा तैयार करते हैं और उनका कार्यान्वयन करते हैं और महत्वपूर्ण मदों के लिए ऐसा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो मत के लिए आधार प्रदान करने की दृष्टि से पर्याप्त और उपयुक्त हो । धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण गलत प्रस्तुतियों का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से बड़ा होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, गलत मंशा से उपेक्षा करना, गलत प्रस्तुतियां इत्यादि शामिल हो सकते हैं या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना की गई हो सकती है।

11.2 हम लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं । ऐसा मौजूदा परिस्थितियों के लिए उचित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया जाता है न कि एनडीडीबी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर अपना मत व्यक्त करने के लिए ।

11.3 हम प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाई जा रही लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं ।

11.4 हम लेखांकन के 'निरंतर चल रही संस्था' आधार के प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह देखते हैं कि क्या किसी ऐसी घटना या परिस्थिति से जड़ी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो 'निरंतर चलने वाली संस्था' के रूप में एनडीडीबी की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा करती हो । यदि हमारा निष्कर्ष यह होता है कि ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों

की ओर ध्यान आकृष्ट करें, अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपने मत को संशोधित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं. तथापि भविष्यगत घटनाएं या परिस्थितियां एनडीडीबी के 'निरंतर चलने वाली संस्था' नहीं बने रहने का कारण बन सकती हैं ।

11.5 हम प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और उनमें निहित विषय-वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देनों और घटनाओं को इस तरह अभिव्यक्त करते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति का उद्देश्य पूरा हो ।

11.6 हम शासन के प्रभारी व्यक्तियों को, अन्य बातों के साथ-साथ, लेखा परीक्षा के दायरे और समय की योजना तथा उल्लेखनीय लेखा परीक्षा निष्कर्ष संप्रेषित करते हैं जिनमें आंतरिक नियंत्रण में उन महत्वपूर्ण कमियों को शामिल किया जाता है जो हमारी लेखा परीक्षा के दौरान पहचान में आती हैं।

11.7 हम शासन के प्रभारी व्यक्तियों को ऐसा अभिकथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने अपनी निष्पक्षता और हमारी निष्पक्षता को उचित रूप से प्रभावित करने वाले माने जाने वाले सभी संबंधों तथा अन्य विषयों को उन्हें संप्रेषित करने के संबंध में, और जहां प्रयोजनीय हो वहां संबंधित रक्षा के उपायों के बारे में सभी संगत नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है ।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

12. एनडीडीबी का तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा विनियमन के अध्याय VI की अनुसूची "I" और अनुसूची "II" के अनुसार तैयार किया गया है।

जैसा कि इसके अंतर्गत विहित विनियमन के प्रावधानों द्वारा अपेक्षित है, हम आगे रिपोर्ट यह करते हैं कि:

12.1 हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग की है और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

12.2 एनडीडीबी के लेन-देन, जो हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमारे ध्यान में आए हैं, एनडीडीबी की शक्तियों के भीतर रहे हैं।

12.3 हमारे मत के अनुसार, इस रिपोर्ट द्वारा निष्पादित वित्तीय विवरण लेखा बही खातों के अनुरूप हैं।

12.4 हमारे मत के अनुसार, वित्तीय विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

एम के पी एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 302014E/ W101061

वासुदेव सुंदरदास मत्ता
भागीदार
आईसीएआई सदस्यता संख्या: 046953
यूजीआईएनः 25046953BMIOZW2042

स्थानः मुंबई
दिनांक: 1 अगस्त 2025

बी-301, वेस्टर्न एज II, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के सामने,
बोरीवली (पूर्व), मुंबई - 400066, भारत।

वेबसाइट: www.mkps.in | ईमेल: mumbai@mkps.in | दूरभाष: +91 22 35 402 661/579

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ('एनडीडीबी' या 'बोर्ड')

(राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 के अंतर्गत गठित एक निगमित निकाय)

तुलनपत्र

31 मार्च, 2025 तक

मिलियन रुपये में

विवरण	संलग्नक	31.03.2025	31.03.2024
देयताएं			
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड निधि	I	33,465.19	32,972.74
सुरक्षित ऋण	II	17,087.54	17,880.66
चालू देयताएं और प्रावधान	III	10,213.73	8,398.50
आस्थगित कर देयताएं	XVI (नोट 8)	324.48	284.23
योग		**61,090.94**	**59,536.13**
परिसंपत्तियाँ			
नकद और बैंक शेष	IV	9,155.36	6,942.43
वस्तुसूची	V	0.21	0.21
विविध देनदार		229.71	236.40
ऋण, अग्रिम और अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	VI	34,258.83	31,562.04
निवेश	VII	15,638.50	19,130.39
सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	VIII	1,808.33	1,664.66
कुल		**61,090.94**	**59,536.13**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं	XV		
लेखों पर टिप्पणियाँ जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं	XVI		

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम के पी एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 302014E/ W101061

वासुदेव सुंदरदास मत्ता
भागीदार
सदस्यता सं. 046953

स्थान: मुंबई
दिनांक: 1 अगस्त 2025

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से,

मीनेश सी शाह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एस रघुपति
कार्यपालक निदेशक
(ऑपरेशन)

अमित गोयल
ग्रुप प्रमुख
(लेखा)

स्थान: आणंद
दिनांक: 1 अगस्त 2025

आय एवं व्यय लेखा-जोखा

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

मिलियन रुपये में

विवरण	संलग्नक	2024-25	2023-24
आय			
ब्याज		3,566.70	3,351.74
सेवा प्रभार	IX	234.11	382.17
किराया और हायर चार्ज		246.88	257.72
लाभांश		399.00	169.84
अन्य आय	X	299.30	109.82
योग (क)		**4,745.99**	**4,271.29**
व्यय			
ब्याज और वित्तीय प्रभार		1,139.58	1,127.38
पारिश्रमिक एवं कार्मिकों को लाभ	XI	1,287.06	1,248.00
प्रशासनिक व्यय	XII	215.69	203.89
अनुदान		201.61	161.80
अनुसंधान और विकास		93.10	83.96
परिसंपत्तियों का रख-रखाव	XIII	304.31	276.53
प्रशिक्षण खर्च		120.32	53.55
कंप्यूटर खर्च		153.28	57.03
अन्य व्यय	XIV	151.05	274.83
मानक परिसंपत्ति, एनपीए और आकस्मिकता के लिए प्रावधान		200.00	200.00
मूल्यह्रास	VIII	298.27	165.72
योग (ख)		**4,164.27**	**3,852.69**
कर से पहले वर्ष के दौरान अधिशेष (ग) = (क-ख)		**581.72**	**418.60**
घटाइए : कराधान के लिए प्रावधान			
वर्तमान कर		181.20	193.10
आस्थगित कर	XVI (नोट 8)	40.24	4.54
कर के पश्चात् वर्ष के दौरान अधिशेष		**360.28**	**220.97**
घटाइए : विनियोजन-			
विशेष आरक्षित	XVI (नोट 13)	250.53	137.90
सामान्य निधि में ले जाई गई शेष राशि		109.75	83.07
योग (घ) = (ख+ग)		**4,745.99**	**4,271.29**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं	XV		
लेखों पर टिप्पणियाँ जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं	XVI		

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम के पी एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 302014E/ W101061

वासुदेव सुंदरदास मत्ता
भागीदार
सदस्यता सं. 046953

स्थान: मुंबई
दिनांक: 1 अगस्त 2025

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से,

मीनेश सी शाह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एस रघुपति
कार्यपालक निदेशक
(ऑपरेशन)

अमित गोयल
ग्रुप प्रमुख
(लेखा)

स्थान: आणंद
दिनांक: 1 अगस्त 2025

नकदी-प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

मिलियन रुपये में

विवरण	ANNEXURE	2024-25		2023-24	
प्रचालन गतिविधियां से नकदी-प्रवाह					
वर्ष के दौरान कर से पूर्व अधिशेष			**581.72**		**418.60**
समायोजन निम्नलिखित के लिए:					
मूल्यह्रास		298.27		165.72	
मानक परिसंपत्ति, एनपीए और आकस्मिकता के लिए प्रावधान		200.00		200.00	
निवेशों की बिक्री पर (लाभ)/हानि		53.31		124.41	
सावधि जमा एवं बांड पर ब्याज आय को अलग माना जाए		(1,582.05)		(1,789.89)	
लाभांश आय को अलग माना जाए		(399.00)		(169.84)	
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री (लाभ)/हानि को अलग माना जाए		(23.53)		(0.37)	
स्वीकृत परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास की प्रतिपूर्ति		(79.09)		(15.41)	
कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ		151.03		146.63	
बैंक को देय ब्याज तथा वित्तीय प्रभार		59.34		138.37	
बांड तथा राज्य विकास ऋणों पर परिशोधित प्रीमियम		39.16	(1,282.56)	42.42	(1,157.96)
			(700.84)		**(739.34)**
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन नकदी-प्रवाह					
वस्तुसूची में (वृद्धि)/कमी		-		0.10	
विविध देनदारों में (वृद्धि)/कमी		6.69		(53.52)	
ऋणों एवं अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी		(2,656.64)		(7,247.70)	
वर्तमान देयताओं में (वृद्धि/कमी)		1,464.21	(1,185.74)	410.01	(6,891.11)
प्रचालन गतिविधियों से अर्जित/(प्रयुक्त) नकदी-प्रवाह			**(1,886.58)**		**(7,630.45)**
कर वापस किया/(प्रदत)			(279.66)		(287.17)
प्रचालन गतिविधियों से अर्जित/(प्रयुक्त) निवल नकदी-प्रवाह (क)			**(2,166.24)**		**(7,917.62)**
निवेश गतिविधियों से नकदी- प्रवाह					
ब्याज से आय		1,640.34		2019.95	
लाभांश आय		399.00		169.84	
निवेशों (बॉन्डस) की परिपक्वता से प्राप्त लाभ		3,995.92		3,002.09	
निवेशों की खरीद (शेयर)		(596.50)		(30.20)	
90 दिनों से अधिक बैंकों में रखे एफडीआर में कमी/(वृद्धि) (निवल)		(3,657.80)		3,486.19	
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ		24.53		91.42	
स्थायी परिसंपत्ति की खरीद के लिए प्राप्त अनुदान (अनुदान वापस किया)		211.27		3.54	
स्थायी परिसंपत्ति की खरीद		(442.93)		(187.81)	
निवेश गतिविधियों में अर्जित/(प्रयुक्त) निवल नकदी-प्रवाह (ख)			**1,573.83**		**8,555.02**
वित्तीय गतिविधियों से नकदी-प्रवाह					
उधार निधियों की प्राप्ति/(पुन: भुगतान)			(793.12)		(5,278.33)
बैंकों को देय ब्याज एवं वित्तीय प्रभार			(59.34)		(138.37)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी-प्रवाह (ग)			**(852.46)**		**(5,416.70)**
वर्ष के दौरान निवल नकदी-प्रवाह (क + ख + ग)			**(1,444.87)**		**(4,779.30)**
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद समतुल्य			**2,351.87**		**7,131.17**
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य			**907.00**		**2,351.87**
नकद और नकद समतुल्य					
बैंकों के पास शेष:					
सावधि जमा			8,442.07		4,734.18
घटाइए: 90 दिनों से अधिक मूल परिपक्वता सहित जमा			8,248.36		4,590.56
			193.71		**143.62**
चालू/बचत खातों में			713.26		2,208.22
नकद एवं चेक ऑन हैंड			0.03		0.03
योग			**907.00**		**2,351.87**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं	**XV**		-		-
लेखों पर टिप्पणियाँ जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं	**XVI**				

टिप्पणी: नकदी-प्रवाह विवरण लेखा मानक - **3** के नकदी-प्रवाह विवरण में दिए गए 'अप्रत्यक्ष तरीके' से तैयार किया गया है।

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम के पी एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 302014E/ W101061

वासुदेव सुंदरदास मत्ता
भागीदार
सदस्यता सं. 046953

स्थान: मुंबई
दिनांक: 1 अगस्त 2025

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से,

मीनेश सी शाह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एस रघुपति
कार्यपालक निदेशक
(ऑपरेशन)

अमित गोयल
ग्रुप प्रमुख
(लेखा)

स्थान: आणंद
दिनांक: 1 अगस्त 2025

एनडीडीबी निधि

संलग्नक - I

मिलियन रुपये में

विवरण	31.03.2025		31.03.2024	
सामान्य आरक्षित (नोट क)				
पूर्व तुलन-पत्र के अनुसार शेष		3,559.61		3,559.61
स्थायी परिसंपत्तियों के लिए अनुदान (नोट ख)				
पूर्व तुलन-पत्र के अनुसार शेष	27.57		39.44	
जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	212.16		3.54	
घटाइए : मूल्यह्रास की प्रतिपूर्ति	79.98		15.41	
		159.75		27.57
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अन्तर्गत विशेष आरक्षित (अनुलग्नक XVI का नोट 13 देखें)				
पूर्व तुलन-पत्र के अनुसार शेष	1,762.14		1,624.24	
जोड़िए : आय एवं व्यय लेखा से अंतरण	250.53		137.90	
		2,012.67		1,762.14
आय-व्यय का लेखा-जोखा				
पूर्व तुलन-पत्र के अनुसार शेष	27,623.41		27,540.35	
जोड़िए: वर्ष के दौरान विनियोजन के बाद अधिशेष	109.75		83.07	
		27,733.16		27,623.41
योग		**33,465.19**		**32,972.74**

टिप्पणीः

क. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 के अनुसार डेयरी एवं अन्य कृषि आधारित तथा संबद्ध उद्योगों एवं जैविकों को प्रोत्साहित करना, योजना बनाना एवं कार्यक्रमों का आयोजन करना।

ख. लेखा मानक - 12 के अनुरूप - 'सरकारी अनुदानों के लेखे'

सुरक्षित ऋण

संलग्नक - II

मिलियन रुपये में

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
बैंक ओवरड्राफ्ट (बैंकों में सावधि जमा पर लीयन के प्रति सुरक्षित)	666.06	1,316.65
नाबार्ड से ऋण (डीआईडीएफ स्कीम के तहत दिए गए सुरक्षित ऋण)	13,304.72	14,988.26
एनपीडीडी योजना के घटक-बी "सहकारिताओं के माध्यम से डेयरी (DTC)" के लिए ऋण (JICA सहायता प्राप्त परियोजना)	3,083.10	1,573.10
एनपीडीडी योजना का घटक-बी ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज {डीआईडीएफ और "सहकारिताओं के माध्यम से डेयरी (DTC)" (JICA सहायता प्राप्त परियोजना) }	33.66	2.65
योग	**17,087.54**	**17,880.66**

वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

संलग्नक - III

मिलियन रुपये में

विवरण		31.03.2025		31.03.2024
(क)	**वर्तमान देयताएं**			
	अग्रिम एवं जमा		97.63	76.76
	विविध लेनदार (अनुलग्नक XVI का नोट 10 देखें)		259.19	162.29
	अन्य देनदारियां		163.17	116.63
	परामर्श परियोजना के कारण निवल देयता			
	प्राप्त निधियाँ	26,685.23		17,772.40	
	जोड़िए : आपूर्तिकर्ताओं को व्यय हेतु देय	2,031.73		1,084.62	
		28,716.96		18,857.02	
	घटाइए : व्यय हुई राशि	21,849.68		15,738.83	
	आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	1,101.53		216.06	
		5,765.75		2,902.13	
	जोड़िए : एनडीडीबी को देय	218.84		321.16	
	(पर कॉन्ट्रा अनुलग्नक VI देखें)		5,984.59		3,223.29
(ख)	**भारत सरकार की परियोजनाओं के लिए प्राप्त निधिः**			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	1,984.37		2,746.89	
	भारत सरकार से प्राप्त निधि	4,584.09		4,439.84	
	जोड़िए : अर्जित ब्याज आय/(व्यय)	(37.43)		4.44	
	घटाइए : किया गया खर्च	5,527.62		3,802.99	
	घटाइए : अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों को अग्रिम	168.97		1,400.27	
	घटाइए : एनडीएलएम अंशदान अनुदान में अंतरण	193.15		3.54	
			641.29		1,984.37
(ग)	**निम्नलिखित के लिए प्रावधानः**			
	अनर्जक परिसंपत्तियां (संलग्नक XVI का नोट 9 देखें)	582.13		582.08	
	मानक परिसंपत्तियों पर सामान्य आकस्मिकता (अनुलग्नक XVI का नोट 9 देखें)	128.62		122.57	
	आकस्मिकता (संलग्नक XVI का नोट 9 देखें)	2,097.51		1,903.61	
			2,808.26		2,608.26
(घ)	**निम्नलिखित हेतु प्रावधानः**			
	छुट्टी नकदीकरण (संलग्नक XVI का नोट 5 देखें)	136.04		113.67	
	सेवा निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा योजना (अनुलग्नक XVI का नोट 5 देखें)	123.56		113.23	
			259.60		226.90
योग			**10,213.73**		**8,398.50**

नकद और बैंक शेष

संलग्नक - IV

मिलियन रुपये में

विवरण	31.03.2025		31.03.2024	
बैंकों में शेष				
सावधि जमा में (निम्नलिखित नोट क से ग देखें)	8,442.07		4,734.18	
बचत खाते में (नीचे नोट घ देखें)	633.97		2,178.02	
चालू खाते में (नीचे नोट ङ देखें)	79.29		30.20	
		9,155.33		6,942.40
नकद एवं चेक ऑन हैंड		0.03		0.03
योग		**9,155.36**		**6,942.43**

नोट:

सावधि जमा में निम्नलिखित शामिल है -

(क) 5194.30 मिलियन रूपये (पूर्व वर्ष 3170.00 मिलियन रूपये) राशि जो लियन के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट सूविधा प्राप्त करने के लिए बैंक के पास रखी गई है।

(ख) 1204.00 मिलियन रूपये (900.01 मिलियन रूपये) जो डीआईडीएफ योजना के अंतर्गत प्राप्त ऋणों के लिए नाबार्ड के पक्ष में खोले गए डीएसआरए खाते के लिए लियन के अधीन है।

(ग) एनडीएलएम परियोजना के लिए निर्धारित एनडीएलएम परियोजना में एनडीडीबी का शेयर 143.22 मिलियन रूपये (पूर्व वर्ष 313.22 मिलियन रूपये) है।

(घ) भारत सरकार की परियोजनाओं के लिए 349.74 मिलियन रूपये (पिछले वर्ष 350.41 मिलियन रूपये) निधि प्राप्त हुई।

(ङ) भारत सरकार की परियोजनाओं में चालू खातों में 64.17 मिलियिन रूपये (पूर्व वर्ष 16.53 मिलियन रूपये) की निधि प्राप्त हुई।

वस्तु सूची

संलग्नक - V

मिलियन रुपये में

विवरण	31.03.2025		31.03.2024	
स्टोर्स, स्पेयर्स और अन्य	1.36		1.36	
परियोजना उपकरण	3.16		3.16	
	4.52		**4.52**	
घटाइए : अप्रचलन के लिए प्रावधान	4.31		4.31	
		0.21		0.21
योग		**0.21**		**0.21**

ऋण, अग्रिम और अन्य वर्तमान संपत्ति

संलग्नक - VI

मिलियन रुपये में

विवरण		31.03.2025		31.03.2024	
सहकारी संस्थाओं को ऋण एवं अग्रिम					
दूध -	सुरक्षित (निम्नलिखित नोट क एवं ख देखें)	30,312.95		26,513.12	
	असुरक्षित	16.55		3.22	
			30,329.50		26,516.34
तेल -	सुरक्षित	80.00		80.00	
	असुरक्षित (उपार्जित ब्याज सहित)	578.57	658.57	578.57	658.57
सहायक कंपनियों/प्रबंधित इकाइयों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम					
सुरक्षित (निम्नलिखित नोट क एवं ख देखें)		819.67		1,838.19	
असुरक्षित		679.72		606.49	
			1,499.39		2,444.68
कार्मिकों को ऋण एवं अग्रिम					
सुरक्षित		0.06		0.09	
असुरक्षित		8.42		6.31	
			8.48		6.40
उपार्जित ब्याज पर -					
ऋण एवं अग्रिम		1.98		59.52	
सावधि जमा एवं निवेश		383.00		441.28	
			384.98		500.80
आपूर्तिकर्ताओं एवं ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम			33.15		9.42
टर्नकी परियोजनाओं के लेखे पर वसूली योग्य			218.84		321.16
(पर कॉन्ट्रा, संलग्नक III देखें)					
विविध जमा			17.75		17.65
भुगतान किया गया आयकर (निवल प्रावधान)			925.91		827.45
प्रीपेड ग्रेच्युटी (संलग्नक XVI का नोट 5 देखें)			54.74		39.25
अन्य प्राप्तियां (नीचे नोट ग देखें)			127.52		220.32
योग			**34,258.83**		**31,562.04**

नोट :

(क) सुरक्षित ऋण परिसंपत्ति को गिरवी पर रखने और/या स्टॉक/परिसंपत्ति के हाइपोथिकेशन के आधार पर दिए जाते हैं।

(ख) सुरक्षित ऋण और अग्रिम में DIDF योजना के तहत दिए गए 25864.20 मिलियन रुपये (पूर्व वर्ष 23575.75 मिलियन रुपये) और "सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी (DTC)" (JICA समर्थित परियोजना) NPDD योजना के घटक-B के तहत दिए गए 2767.30 मिलियन रुपये (पूर्व वर्ष 1025.94 मिलियन रुपये) शामिल हैं।

(ग) अन्य देय राशियों में FUCs की प्रतीक्षा में 49.86 मिलियन रुपये (पूर्व वर्ष 14.72 मिलियन रुपये) की राशि अनुदान शामिल हैं।

निवेश

संलग्नक - VII

मिलियन रुपये में

विवरण	31.03.2025		31.03.2024	
दीर्घकालीन निवेश (लागत पर):				
सहायक कंपनियों में इक्विटी शेयर (अनकोटेड):				
मदर डेयरी फ्रूट एन्ड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड (MDFVPL)	2,500.00		2,500.00	
आईडीएमसी लिमिटेड (IDMC)	283.90		283.90	
इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड (IIL)	90.00		90.00	
एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (NDS)	2,000.00		2,000.00	
एनडीडीबी मृदा लिमिटेड (नीचे नोट ख देखें)	-		95.00	
एनडीडीबी काफ लिमिटेड	750.00		750.00	
		5,623.90		5,718.90
संयुक्त उद्यम में इक्विटी शेयर (अनकोटेड):				
नॉर्थ ईस्ट डेयरी एंड फूड्स लिमिटेड (निम्नलिखित नोट क देखें)	50.00		50.00	
एनडीडीबी मृदा लिमिटेड (नीचे नोट ख देखें)	251.60		-	
		301.60		50.00
सरकारी कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और बैंकों के बांड (कोटेड) (परिशोधित प्रीमियम के निवल मूल्य पर)		5,854.79		8,306.99
(तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार बांड का कुल बाजार मूल्य 5,983.20 मिलियन रूपये (पूर्व वर्ष 8,441.07 मिलियन रूपये) है)				
राज्य विकास ऋण (कोटेड) (परिशोधित प्रीमियम के निवल मूल्य पर)		3,349.21		4,985.40
(तुलन पत्र की तारीख के अनुसार राज्य विकास ऋण का कुल बाजार मूल्य 3,328.86 मिलियन रूपये (पूर्व वर्ष 4,957.73 मिलियन रूपये) है)				
सहकारिताओं और महासंघों में शेयर (अनकोटेड)	509.10		69.20	
घटाइए: निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान	0.10		0.10	
		509.00		69.10
योग		**15,638.50**		**19,130.39**

सहायक कंपनियों में निवेश का विवरण

सहायक कंपनी का नाम	31.03.2025		31.03.2024	
	शेयर की संख्या	अंकित मूल्य (प्रति शेयर)	शेयर की संख्या	अंकित मूल्य (प्रति शेयर)
मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड (MDFVPL)	25,00,00,070	10.00	25,00,00,070	10.00
आईडीएमसी लिमिटेड (IDMC)	1,21,44,544	10.00	1,21,44,544	10.00
इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड (IIL) (नीचे नोट ग देखें)	5,40,00,042	10.00	5,40,00,042	10.00
एनडीडीबी डेयरी सविर्सेज (NDS)	20,00,00,000	10.00	20,00,00,000	10.00
एनडीडीबी मृदा लिमिटेड (नीचे नोट ख देखें)	-	-	95,00,000	10.00
एनडीडीबी काफ लिमिटेड	7,50,00,000	10.00	7,50,00,000	10.00
	59,11,44,656		**60,06,44,656**	

नोट :

(क) एनडीडीबी और असम सरकार के बीच संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल की गई।

(ख) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, सुजुकी आरएंडडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी प्रदत्त शेयर पूंजी का 26% अंशदान दिया है जिसके बाद एनडीडीबी मृदा लिमिटेड एनडीडीबी का संयुक्त उद्यम बन गया है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2022-23 में, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड (IIL) ने 10 रुपये अंकित मूल्य के 4,50,00,035 बोनस शेयर जारी किए हैं।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

संलग्नक - VIII

मिलियन रुपये में

विवरण	सकल कोष्ठ (लागत पर)				मूल्यह्रास				निवल कोष्ठ	
	01.04.2024 को	जोड़िए	कटौतियाँ/ (समायोजन)	31.03.2025 को	01.04.2024 को	वर्ष के लिए	कटौतियाँ/ (समायोजन)	31.03.2025 को	31.03.2025 को	31.03.2024 को
पूर्ण स्वामित्व (फ्रीहोल्ड) भूमि (नोट 1 से 3 देखें)	412.49	-	-	412.49	-	-	-	-	412.49	412.49
पट्टाधृत (लीज़ होल्ड) भूमि	64.16	-	-	64.16	16.82	0.75	-	17.57	46.59	47.34
भवन और सड़कें	2,072.15	5.64	3.08	2,074.71	1,342.17	59.25	2.10	1,399.32	675.39	729.98
संयंत्र और मशीनरी	10.85	89.02	4.44	95.43	7.01	51.90	4.44	54.47	40.96	3.84
विद्युतीय स्थापन	193.13	5.06	3.00	195.19	147.32	4.64	2.98	148.98	46.21	45.81
फर्नीचर, कंप्यूटर्स एवं अन्य उपकरण	920.61	23.75	0.93	943.43	785.00	28.67	0.93	812.74	130.69	135.61
सॉफ्टवेयर लाइसेंस	277.30	386.88	-	664.18	269.18	128.95	-	398.13	266.05	8.12
रेल दूध टैंकर्स	375.64	-	4.62	371.02	289.69	19.58	4.62	304.64	66.38	85.95
वाहन	32.96	8.14	0.36	40.74	23.28	4.53	0.36	27.45	13.29	9.68
योग	**4,359.29**	**518.49**	**16.43**	**4,861.35**	**2,880.47**	**298.27**	**15.43**	**3,163.30**	**1,698.05**	**1,478.82**
पूर्व वर्ष	***4,535.53***	***155.14***	***331.38***	***4,359.29***	***2,955.09***	***165.72***	***240.33***	***2,880.47***	***1,478.82***	***1,580.44***
पूँजी अग्रिम सहित पूँजीगत कार्य प्रगति पर है									**110.28**	**185.84**
कुल स्थायी परिसंपत्तियाँ									**1,808.33**	**1,664.66**

नोट

1. तमिलनाडु सरकार से मुहंपका एवं खुरपका रोग नियंत्रण परियोजना से संबंधित भू-हस्तांतरण द्वारा प्राप्त की गई है जिसका मूल्य 0.39 मिलियन रूपये है।
2. पूर्ण स्वामीत्व भूमि 17.94 मिलियन रूपये राशि की ऑइल टेंक फार्म, नरेला की भूमि सम्मिलित है। जिसे स्थायी लीज पर प्राप्त किया गया है। और जिसके लिए अभी लीज डीड का निष्पादन करना बाकी है।
3. कृषि एवं बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार से प्राप्त भूमि का मूल्य 65.98 मिलियन रूपये है, जो कन्नामंगला हार्टीकल्चर फार्म में सहायक कंपनी मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। भू-स्वामीत्व का हस्तांतरण अभी लंबित है।
4. यह वृद्धि एनडीएलएम परियोजना हेतु 193.15 मिलियन रुपये की राशि, जो कि 50 प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी है, को शामिल किया गया है।

सेवा शुल्क

संलग्नक - IX

मिलियन रुपये में

विवरण	2024-25	2023-24
प्रशिक्षण शुल्क	19.53	22.71
अधिप्राप्ति एवं तकनीकी सेवा शुल्क	189.17	325.46
परीक्षण प्रभार	-	5.23
परामर्श एवं साध्यता (फीजिबिलिटी) अध्ययन से शुल्क	24.35	27.58
रॉयल्टी एवं प्रक्रिया जानकारी शुल्क	1.06	1.19
योग	**234.11**	**382.17**

अन्य आय

संलग्नक - X

मिलियन रुपये में

विवरण	2024-25	2023-24
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)	23.53	0.37
अन्य ब्याज से आय	49.84	40.98
अतिरिक्त प्रावधान तथा एनपीए का प्रतिलेखन	4.26	0.15
स्वीकृत परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास की प्रतिपूर्ति	79.09	15.41
दूध की बिक्री	3.18	2.47
विविध आय	139.40	50.44
योग	**299.30**	**109.82**

कार्मिकों को पारिश्रमिक और लाभ

ANNEXURE - XI

मिलियन रुपये में

विवरण	2024-25	2023-24
वेतन और मजदूरी (अनुग्रह राशि सहित)	982.24	944.91
भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि तथा उपदान राशि में योगदान	199.39	191.36
स्टाफ कल्याण व्यय	105.43	111.73
योग	**1,287.06**	**1,248.00**

पारिश्रमिक में अनुसंधान एवं विकास व्यय के भाग के रूप में इंगित गए 57.90 मिलियन रूपये (पूर्व वर्ष: 36.50 मिलियन रूपये) शामिल नहीं हैं।

प्रशासनिक व्यय

संलग्नक - XII

मिलियन रुपये में

विवरण	2024-25	2023-24
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	5.48	6.13
संचार प्रभार	8.54	11.60
लेखा परीक्षा शुल्क एवं व्यय (कर सहित)		
लेखा परीक्षा शुल्क	0.91	0.76
आयकर लेखा परीक्षा	0.30	0.22
आऊट ऑफ पॉकेट व्यय	0.04	0.05
	1.25	1.03
विधि शुल्क	6.59	7.47
व्यावसायिक शुल्क	29.69	33.91
वाहन व्यय	7.89	4.99
भर्ती व्यय	0.22	0.15
विज्ञापन व्यय	2.37	5.46
यात्रा एवं वाहन व्यय	115.78	94.90
बिजली एवं किराया	31.61	33.33
अन्य प्रशासनिक व्यय	6.27	4.92
योग	**215.69**	**203.89**

परिसंपत्तियों का अनुरक्षण

संलग्नक - XIII

मिलियन रुपये में

विवरण	2024-25	2023-24
मरम्मत एवं अनुरक्षण		
भवन	214.96	193.44
अन्य	76.51	69.89
दर एवं कर	10.07	10.51
बीमा	2.77	2.69
योग	**304.31**	**276.53**

अन्य व्यय

संलग्नक - XIV

मिलियन रुपये में

विवरण	2024-25	2023-24
प्रीमियम परिशोधन	39.16	42.42
पूर्व अवधि के व्यय	16.81	0.69
निवेश की बिक्री पर हानि	53.31	124.41
अन्य व्यय	41.77	107.31
योग	**151.05**	**274.83**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा है

संलग्नक - XV

1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत परिपाटी तथा भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों (GAAP) के साथ-साथ इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउन्टैन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी बोर्ड पर लागू लेखांकन मानकों का प्रयोग करते हुए संग्रहण आधार पर तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणों को, जब तक अन्यथा न कहा जाए, भारतीय रुपए के निकटतम पूर्णांकित दस लाख में प्रदर्शित किया गया है।

2. आंकलन का प्रयोग

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को आकलन तथा पूर्वानुमान करना पड़ता है जो परिसंपत्तियों तथा देयताओं, राजस्व तथा खर्च और वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण की सूचित राशियों को प्रभावित करते हैं। ऐसे आंकलन तथा पूर्वानुमान, प्रबंधन के वित्तीय विवरण की तारीख पर संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों के मूल्याँकन पर आधारित हैं। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त आंकलन विवेकपूर्ण एवं उचित है; हालांकि, वास्तविक परिणाम इस आकलन से भिन्न हो सकते हैं जिन्हें वर्तमान तथा भविष्य की अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से मान्यता प्राप्त है। ऐसे आकलनों में कोई भी परिवर्तन वर्तमान तथा भविष्य की अवधि में भविष्यलक्षी प्रभाव से मान्य हैं।

3. परिसंपत्तियों का वर्गीकरण तथा प्रावधान

सार्वजनिक वित्तीय संस्था होने के नाते एनडीडीबी परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों का पालन करती है 'जोकि व्यवस्थित रूप से महत्त्वपूर्ण नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एवं डिपॉजिट टेकिंग कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशा-निर्देश, दिसंबर 2016 पर लागू है'। अनर्जक एवं मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान बोर्ड द्वारा अनुमोदित दरों पर किया गया है।

4. राजस्व मान्यता

मानक परिसंपत्तियों पर ब्याज आय में आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार संग्रहण के आधार पर मान्यता दी गई है। अनर्जक परिसंपत्तियों पर ब्याज आय, लागू दिशा-निर्देशों के अनुरूप वर्गीकृत हैं।

बैंक के साथ सावधि जमा एवं बांड्स में निवेश पर ब्याज आय को आनुपातिक समय आधार पर मान्यता दी गई है।

सहकारिता आदि की सेवाओं से आय को आनुपातिक पूरा होने के आधार पर तथा सम्बद्ध अनुबंध की शर्तों के अनुसार मान्य किया गया है।

दूध कमोडिटी की बिक्री का हिसाब परिवहन के समय पर्याप्त जोखिम और ईनाम के आधार पर पण्यवस्तुओं की गोदाम से प्रेषण की तारीख पर किया जाता है।

लाभांश आय का हिसाब आय प्राप्त होने के बिना शर्त अधिकार स्थापित होने पर किया गया है।

अन्य आय को तब मान्यता दी जाती है जब इसके अंतिम संग्रहण में कोई अनिश्चितता नहीं होती।

5. अनुदान

क) स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों को आरंभ में सामान्य निधि के अंतर्गत स्थायी परिसंपत्तियों के लिए अनुदान में क्रेडिट किया जाता है। इस राशि को संबंधित स्थायी परिसंपत्तियां की उपयोगी अवधि के दौरान, ऐसे संपत्तियों पर मूल्यह्रास की प्रतिपूर्ति के रूप में आय और व्यय खाते में व्यवस्थित तरीके से प्रदर्शित किया गया है।

ख) वर्ष के दौरान प्राप्त राजस्व अनुदानों को आय तथा व्यय लेखे में मान्यता दी जाती है।

ग) विशिष्ट परियोजनाओं के लिए प्राप्त अनुदान को परियोजना निधि में क्रेडिट किया जाता है तथा इन परियोजनाओं के लिए धन वितरण में इसका उपयोग किया जाता है।

6. अनुसंधान एवं विकास व्यय

अनुसंधान एवं विकास व्यय को (अधिगृहीत स्थायी परिसंपत्तियों की लागत के अलावा) वर्ष में व्यय के रूप में प्रभारित किया गया है। अनुसंधान तथा विकास के लिए उपयोग की गई स्थायी परिसंपत्तियाँ जिनका अन्य जगह उपयोग हो सकता है उनका बोर्ड की नीति के अनुसार उनके उपयोगी जीवन के बाद मूल्यह्रास किया जाता है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा है

संलग्नक - XV

7. कर्मचारी लाभ

क. परिभाषित योगदान योजनाः भविष्य निधि तथा अधिवार्षिता निधि में योगदान पूर्व निर्धारित दर पर किया जाता है तथा उसे आय और व्यय लेखे में प्रभारित किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित दर और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि योजना के वास्तविक आय के बीच यदि कोई कमी है, तो बोर्ड द्वारा आय और व्यय खाते में डेबिट के रूप में योगदान दिया जाता है।

ख) परिभाषित लाभ योजनाएंः उपदान, मुआवजा अनुपस्थिति तथा सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजनाएं प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करते हुए बोर्ड की देयताएं निर्धारित की जाती हैं जिसमें प्रत्येक सेवा अवधि को गिना जाता है जिससे लाभ हकदारी की अतिरिक्त इकाई में वृद्धि होती है तथा अंतिम दायित्व को निर्धारित करने के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापा जाता है। बीमांकिक लाभ तथा हानियाँ जो स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा वार्षिक तौर पर की जाती हैं, बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित हैं, उन्हें तुरंत आय तथा व्यय लेखा में आय अथवा व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। दायित्व को, छूट दर का प्रयोग करते हुए, अनुमानित भविष्य के नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर मापा गया है। इनका निर्धारण तुलन पत्र की तारीख पर भारत सरकार के बांड पर बाजार लाभ के संदर्भ में किया जाता है, जहाँ सरकारी बॉन्डों की वैधता अवधि तथा शर्तें परिभाषित लाभ दायित्व की वैधता अवधि और अनुमानित शर्तों के अनुरूप हैं।

अनुपस्थिति क्षतिपूर्तिः बोर्ड की कर्मचारियों के लिए अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति लाभ हेतु एक योजना है जिसकी देयता वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

बोर्ड ने भारतीय जीवन बीमा निगम की ग्रुप ग्रैच्यूटी सह लाइफ एशोरेन्स योजना में प्रतिभागिता द्वारा उपदान के पक्ष में इनकी देयताओं को वित्त पोषण प्रदान किया है।

8. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (PPE) तथा मूल्यह्रास

मूर्त स्थायी परिसंपत्तियों को मूल्यह्रास तथा क्षति हानि घटा कर लागत पर लिया जाता है। लागत में खरीद का मूल्य, आयात शुल्क तथा अन्य गैर वापसी कर अथवा उगाही तथा ऐसी कोई प्रत्यक्ष अपसामान्य लागत शामिल होती है जो परिसंपत्ति पर उसके अपेक्षित इस्तेमाल के लिए तैयार करने हेतु खर्च की जाती है।

प्रत्येक 10,000 रुपये से अधिक की लागत वाली पीपीई पर मूल्यह्रास बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर प्रभारित किया जाता है। परिसंपत्ति के पूँजीकरण के वर्ष में पूरा मूल्याह्रास प्रभारित किया जाता है तथा उसके निपटान के वर्ष में मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया जाता। 10,000 रुपये तथा उससे कम राशि की प्रत्येक परिसंपत्ति को क्रय के वर्ष में 100 प्रतिशत मूल्यह्रास किया जाता है। बोर्ड द्वारा विभिन्न श्रेणी की परिसंपत्तियों के लिए अनुमोदित मूल्यह्रास दरें नीचे दी गई हैंः-

परिसंपत्तियां	दर (% में)
फैक्टरी भवन, गोदाम तथा रोड	4.00
अन्य भवन	2.50
कोल्ड स्टोरेज	15.00
विद्युत स्थापन	5.00
कम्प्यूटर (सॉफ्टवेयर सहित)	33.33
कार्यालय तथा प्रयोगशाला उपकरण	15.00
संयंत्र तथा मशीनरी	10.00
सौर उपकरण	30.00
फर्नीचर	10.00
वाहन	20.00
रेल दूध टैंकर	10.00

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा है

संलग्नक - XV

पट्टे पर ली गई जमीन का पट्टे की अवधि तक एमोर्टाइज किया गया है। पट्टे पर ली गई जमीन पर स्थित परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास पट्टे की अवधि से कम होगा या उस परिसंपत्ति की उपयोगी जीवन से कम होगी।

स्थापन/निर्माणाधीन पूँजीगत परिसंपत्तियों को तुलनपत्र में 'पूँजीगत कार्य प्रगति पर' के रूप में दिखाया गया है।

9. परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख पर, परिसंपत्तियों के रखाव मूल्य की परिसंपत्तियों की हानि के लिए समीक्षा की जाती है। यदि इस प्रकार की हानि होने का कोई संकेत मिलता है, तो ऐसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और हानि को मान्य किया जाता है, यदि इन परिसंपत्तियों के रख रखाव की राशि वसूली योग्य राशि से अधिक है। वसूली योग्य राशि शुद्ध बिक्री मूल्य तथा उनके उपयोग के मूल्य से अधिक है। उपयोग मूल्य को, उनके वर्तमान मूल्य में से भविष्य के नकद प्रवाह में छूट के आधार पर निकाला जाता है जो उपयुक्त छूट घटक पर आधारित होती है। जब ऐसा संकेत हो कि लेखा अवधियों से पूर्व किसी परिसंपत्ति के लिए मान्य क्षति हानि अब विद्यमान नहीं है अथवा कम हो गई होगी तो अपसामान्य हानि के ऐसे परिवर्तन को आय तथा व्यय लेखा

10. निवेश

दीर्घकालीन निवेशों को निम्न प्रकार से मूल्यांकित किया गया है:

क) सहायक कंपनियों, सहकारिताओं तथा महासंघों के शेयर - अधिग्रहण की लागत पर;

ख) सरकारी कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों में डिबेंचर/बांड - राज्य विकास ऋण - अधिग्रहण की लागत पर शुद्ध परिशोधित प्रीमियम, यदि कोई हो।

वर्तमान निवेशों को कम लागत अथवा बाजार मूल्य पर निर्धारित किया गया है।

दीर्घकालिक निवेशों को लागत पर निर्धारित किया गया है। यदि अंकित मूल्य से लागत मूल्य अधिक होता है तो अंतर्निहित प्रतिभूति की शेष परिपक्वता अवधि पर प्रीमियम को परिशोधित किया जाता है। इस प्रकार के निवेश का उल्लेख तुलनपत्र में कम परिशोधित प्रीमियम अधिग्रहण मूल्य पर किया गया है।

वर्ष के दौरान किए गए निवेशों के मूल्य में, अस्थायी के अलावा अन्य कमी हेतु प्रावधान कमी का मूल्यांकन किए जाने वाले वर्ष में किया गया है।

11. वस्तुसूची

स्टोर तथा परियोजना उपकरण सहित वस्तु सूचियों को लागत पर अथवा शुद्ध नकदीकरण मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया गया है। लागत को प्रथम आवक, प्रथम जावक आधार पर निकाला गया है। जहाँ कहीं आवश्यक है वहाँ अप्रचलन के लिए प्रावधान किया गया है।

12. विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्रा का लेन-देन, लेन देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित मुद्रा संबंधी वस्तुएं तथा जो तुलन पत्र की तारीख में बकाया हैं उन्हें वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। गैर-मौद्रिक मदों को ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है।

विदेशी मुद्रा लेन-देन में होने वाले विनिमय अन्तर को उनके सामने आने वाली अवधि में आय एवं व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

13. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का लेखांकन

अनुग्रह राशि सहित स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना की लागत, कर्मचारी के सेवा वियोजन अवधि में आय तथा व्यय लेखे में प्रभारित की जाती है। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लेने वाले कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों की सेवा वियोजन अवधि में मासिक लाभ योजना हेतु प्रावधान किया गया है तथा इसका समायोजन भुगतान मिलने पर किया जाता है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा है

संलग्नक - XV

14. आय पर कर

वर्तमान कर, वर्ष के दौरान कर योग्य आय पर देय है जिसका निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

आस्थगित कर समय के अंतर पर मान्य है, यह कर योग्य आय तथा लेखा आय का वह अंतर है जो एक अवधि से उत्पन्न होता है तथा एक अथवा अधिक अनुवर्ती अवधि में परिवर्तन योग्य है।

अनवशोषित मूल्यह्रास तथा अग्रेनीत हानियों के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्य किया गया है यदि यह आभासी निश्चितता है कि ऐसे कर घाटों को दूर करने के लिए भविष्य की पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी। अन्य आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ मान्य हैं जब यदि यथोचित निश्चितता हो कि ऐसी परिसंपत्तियों की वसूली के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय होगी।

15. पट्टे

पट्टा व्यवस्थाएं, जहाँ परिसंपत्ति के स्वामित्व का प्रासंगिक जोखिम और ईनाम पर्याप्त रूप से पट्टेदाता पर निहित है, उन्हें प्रचालन पट्टे के रूप में मान्यता दी गई है। प्रचालित पट्टे के अंतर्गत पट्टा किराया को पट्टा अनुबंधों के संदर्भ में आय एवं व्यय लेखे के रूप में मान्यता दी गई है।

16. प्रावधान तथा आकस्मिकताएं

पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप जब बोर्ड के पास वर्तमान दायित्व होता है तो उस समय प्रावधान को मान्यता दी जाती है तथा यह संभावित है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों का बर्हिगमन अपेक्षित होगा, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता है। प्रावधानों (सेवानिवृत्ति लाभों को छोडकर) को उनके वर्तमान मूल्य में छूट नहीं दी जाती है तथा इन्हें तुलन पत्र की तारीख ङ्कें दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमान प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है। आकस्मिक देयताओं का खुलासा लेखा पर टिप्पणियों में किया गया है।

बोर्ड ने वर्ष 2001-02 के पूर्व के ऋणों तथा अन्य परिसंपत्तियों के संबंध में प्रावधान किया है। अंतर्निहित परिसंपत्तियों के संचालन के आधार पर जिनके लिए ऐसे प्रावधान का सृजन किया गया था, बोर्ड पहचानी गई घटनाओं के आधार पर ऐसे प्रावधानों का पुनः आवंटन/प्रतिलेखन करता है। तदनुसार, बोर्ड अपनी परिसंपत्तियों के मूल्य में संभावित मूल्यह्रास अथवा ऐसी देयता हेतु अप्रत्यशित घटनाओं के लिए वर्तमान आकस्मिक प्रावधान के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान अथवा आवंटन करता है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा है

संलग्नक - XVI

1 संबंधित प्राधिकारियों के अनुरोध पर, एनडीडीबी पश्चिम असम दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, झारखंड राज्य सहकारी दूध उत्पादक महासंघ, जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ, वाराणसी, लद्दाख यूटी डेरी सहकारी महासंघ, पूर्वी असम दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित और मणिपुर दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड का प्रबंधन कर रही है। ये पृथक और स्वतंत्र संस्थाएं हैं और उनके बही खातों का रखरखाव संबंधित प्रधिकारियों द्वारा किया जाता है और अलग से उनकी लेखा परीक्षा की जाती है। इसके अलावा, संबंधित प्राधिकारियों के साथ हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार, बोर्ड केवल जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ, वाराणसी के प्रबंधन को सौंपते समय शुद्ध नकदी हानि को वहन करने के लिए उत्तरदायी है। जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ, वाराणसी के साथ समझौता ज्ञापन की अवधि के अंत में प्रबंधन को सौंपते समय नकद हानि, यदि कोई हो, के लिए आवश्यक प्रावधान किया जाएगा।

2 राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (NDLM) 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)' के अंतर्गत एक परियोजना है, जिसे भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD) तथा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (NDDB) के बीच संयुक्त उद्यम (JV) के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक का 50 प्रतिशत का अंशदान है।

एनडीएलएम परियोजना राजस्व और व्यय (i) एनडीडीबी के शेयर के लिए क्रमशः एनडीडीबी के आय और व्यय खाते में जमा/डेबिट किया गया है और (ii) भारत सरकार के शेयर के लिए, इसे एनडीडीबी की 'भारत सरकार की परियोजनाओं के लिए प्राप्त निधि' में समायोजित किया गया है। जहां तक, एनडीएलएम परियोजना के पूंजीगत व्यय का संबंध है, (iii) एनडीडीबी का शेयर बही खातों में पूरी तरह पूंजीकृत है और मूल्यह्रास एनडीडीबी के आय और व्यय खाते में प्रभारित किया जाता है और (iv) भारत सरकार के शेयर के लिए, इसे 'अचल परिसंपत्तियों के लिए अनुदान' में स्थानांतरित कर दिया जाता है और उस सीमा तक मूल्यह्रास की वार्षिक आधार पर भरपाई की जाती है। निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (Capital Work in Progress - 'CWIP') हेतु भारत सरकार के अंश को 'भारत सरकार की परियोजनाओं के लिए प्राप्त निधि' शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है।

3 आकस्मिक देयताएँ:

3.1. मूल राशि के दावे जो ऋण के रूप में नहीं माने गए : 318.74 मिलियन रुपये (पूर्व वर्ष: 318.74 मिलियन रुपये)

3.2. आयकर की मांग (संबंधित सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत देय ब्याज एवं जुर्माने को छोडकर) 887.76 मिलियन रुपये (पूर्व वर्ष : 1,185.93 मिलियन रुपये)

3.3. सेवा कर मांग 37.23 मिलियन रुपये (पूर्व वर्ष: 916.50 मिलियन रुपये)

3.4. अन्य मांगें

मिलियन रुपये में

विवरण	प्राधिकरण	2024-25	2023-24
भूमि देय राशि का निपटान	भूमि एवं भूमि सुधार विभाग, सिलीगुड़ी	3.94	3.94
इटोला की भूमि के लिए नगरपालिका कर की मांग	तालुका विकास अधिकारी, वडोदरा	4.73	4.73
संपत्ति कर	बृहन मुंबई महानगर पालिका, मुंबई	0.31	0.29

बोर्ड ने 3.1 से 3.4 में उपर्युक्त उल्लिखित मांगों को उपयुक्त फोरम के समक्ष चुनौती दी है। उक्त संबंध में नकद प्रवाह केवल निर्णय का परिणाम/उस फोरम का फैसला आने पर निर्धारित करने योग्य है, जहाँ मांगों को चुनौती दी गई है।

4 खंड जानकारी:

एनडीडीबी राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 के अंतर्गत गठित एक निगमित निकाय है। अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, एनडीडीबी की सभी गतिविधियाँ डेरी/कृषि क्षेत्र के इर्द-गिर्द घूमती हैं जो लेखा मानक-17 के अनुसार "खण्ड रिपोर्टिंग" पर एकल रिपोर्ट करने योग्य खंड है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा है

संलग्नक - XVI

5 **लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) के अनुसार, कर्मचारी भत्ते का प्रकटन निम्नानुसार है:**

कर्मचारी लाभ योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजनाएं

कंपनी योग्य कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान योजनाओं के अंतर्गत भविष्य निधि तथा अधिवर्षिता निधि में अंशदान देती है। इन योजनाओं के अंतर्गत, कंपनी को पे-रोल लागत का एक विशेष प्रतिशत इन लाभों को धन प्रदान करने के लिए देना अपेक्षित है। वर्तमान वर्ष में कंपनी ने लाभ एवं हानि विवरण में भविष्य निधि अंशदान के लिए 87.3 मिलियन रुपये तथा पिछले वर्ष में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष में 81.24 मिलियन रुपये तथा अधिवर्षिता निधि अंशदान में वर्तमान वर्ष में 58.69 मिलियन रुपये तथा 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष में 54.44 मिलियन रुपये मान्य किए है। कंपनी द्वारा इन योजनाओं के लिए देय योगदान की राशि, इन योजनाओं के नियमों में विनिर्दिष्ट दर पर दी जाती है।

परिभाषित लाभ योजनाएं

कंपनी अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ योजनाएं प्रदान करती है:

i. उपदान

ii. सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना (PRMBS)

iii. छुट्टी नकदीकरण

निम्नलिखित तालिका में परिभाषित लाभ योजनाओं को प्रदान निधि की स्थिति तथा वित्तीय विवरण में मान्य राशि दर्शाई गई है:

मिलियन रुपये में

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष		
	उपदान	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजनाएं (पीआरएमबीएस)	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजनाएं (पीआरएमबीएस)	छुट्टी नकदीकरण
नियोक्ता खर्च के घटक						
चालू सेवा लागत	41.72	0.93	38.36	36.93	0.92	33.00
ब्याज लागत	41.15	8.14	49.48	38.77	8.21	46.27
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(43.97)	-	(41.31)	(42.70)	-	(42.64)
बीमांकिक हानि/(लाभ)	18.21	7.43	24.25	26.45	(1.16)	35.64
आय और व्यय में मान्य कुल व्यय	**57.11**	**16.50**	**70.79**	**59.45**	**7.97**	**72.27**
वर्ष के लिए वास्तविक योगदान और लाभ भुगतान						
वास्तविक लाभ भुगतान	(29.19)	(6.17)	(17.24)	(40.99)	(4.20)	(37.68)
वास्तविक योगदान	72.60	-	48.26	46.31	-	6.95
तुलन-पत्र में मान्य निवल परिसंपत्ति/ (देयता)						
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(641.39)	(123.56)	(780.86)	(572.26)	(113.23)	(688.21)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	696.13	-	644.81	611.50	-	574.54
तुलनपत्र में मान्य निवल परिसंपत्ति/(देयता)	**54.74**	**(123.56)**	**(136.04)**	**39.25**	**(113.23)**	**(113.67)**
वर्ष के दौरान परिभाषित लाभ दायित्वों (DBO) में परिवर्तन						
वर्ष के आरंभ में डीबीओ का वर्तमान मूल्य	572.26	113.23	688.21	516.97	109.45	616.91
वर्तमान सेवा लागत	41.72	0.93	38.36	36.93	0.92	33.00
ब्याज लागत	41.15	8.14	49.48	38.77	8.21	46.27
वास्तविक (लाभ)/हानि	15.46	7.43	22.04	20.58	(1.16)	29.71

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा है

संलग्नक - XVI

मिलियन रुपये में

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष		
	उपदान	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजनाएं (पीआरएमबीएस)	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजनाएं (पीआरएमबीएस)	छुट्टी नकदीकरण
प्रदत्त लाभ	(29.19)	(6.17)	(17.24)	(40.99)	(4.20)	(37.68)
वर्ष के अंत में डीबीओ का वर्तमान मूल्य	**641.39**	**123.56**	**780.86**	**572.26**	**113.23**	**688.21**
वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन						
वर्ष के आरंभ में योजित परिसंपत्तियाँ	611.50	-	574.54	569.36	-	568.56
अधिग्रहण समायोजन	-	-	-	-	-	-
योजित परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	43.97	-	41.31	42.70	-	42.64
वास्तविक कंपनी योगदान (उपदान ट्रस्ट/ एनडीडीबी और एलआईसी द्वारा कटौती किए गए शुल्क को छोड़कर दिया गया योगदान)	72.60	-	48.26	46.31	-	6.95
वास्तविक लाभ/(हानि)	(2.75)	-	(2.21)	(5.87)	-	(5.93)
प्रदत्त लाभ	(29.19)	-	(17.08)	(40.99)	-	(37.68)
वर्ष के अंत में योजित परिसंपत्तियाँ	**696.13**	**-**	**644.81**	**611.50**	**-**	**574.54**
योजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ	41.21	-	39.10	36.83	-	36.71
योजित परिसंपत्तियों के घटक इस प्रकार हैः						
सरकारी बांड	-	-	-	-	-	-
पीएसयू बांड	-	-	-	-	-	-
इक्विटी एवं इक्विटी संबंधी निवेश	-	-	-	-	-	-
अन्य	100.00%	-	100.00%	100%	-	100%
वास्तविक धारणाएं						
छूट दर	6.73%	6.73%	6.73%	7.19%	7.19%	7.19%
योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित लाभ	6.73%	NA	6.73%	7.19%	NA	7.19%
वेतन वृद्धि	8.50%	3.00%	8.50%	8.50%	3.00%	8.50%
क्षयण (एट्रीशन)	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
चिकित्सा मुद्रास्फीति	NA	5.00%	NA	NA	5.00%	NA
मृत्यु तालिका	भारतीय आश्वासित जीवन (2012-14) अंतिम मृत्यु दर	भारतीय आश्वासित जीवन (2012-14) अंतिम मृत्यु दर	भारतीय आश्वासित जीवन (2012-14) अंतिम मृत्यु दर	भारतीय आश्वासित जीवन (2012-14) अंतिम मृत्यु दर	भारतीय आश्वासित जीवन (2012-14) अंतिम मृत्यु दर	भारतीय आश्वासित जीवन (2012-14) अंतिम मृत्यु दर

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा है

संलग्नक - XVI

अनुभव समायोजन

मिलियन रुपये में

विवरण	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
उपदान						
डीबीओ का वर्तमान मूल्य	641.39	572.26	516.97	513.59	458.98	449.30
योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(696.13)	(611.50)	(569.36)	(472.74)	(421.34)	(418.09)
वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	54.74	39.25	52.39	(40.85)	(37.64)	(31.21)
सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना (PRMBS)						
डीबीओ का वर्तमान मूल्य	123.56	113.23	109.45	110.75	111.16	81.01
अन्य परिभाषित लाभ योजनाएं (छुट्टी नकदीकरण)						
डीबीओ का वर्तमान मूल्य	780.86	688.21	616.91	615.36	542.14	522.08
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(644.81)	(574.54)	(568.56)	(516.09)	(393.49)	(393.45)
वित्तपोषित स्थिति [अधिशेष / (घाटा)]	(136.04)	(113.67)	(48.35)	(99.27)	(148.65)	(128.63)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
लंबी अवधि की प्रतिपूरक अनुपस्थिति की बीमांकिक पूर्वधारणाएं		
छूट दर	6.73%	7.19%
उपदान योजित परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	6.73%	7.19%
योजित अवकाश नकदीकरण परिसंपत्ति पर संभावित प्रतिलाभ	6.73%	7.19%
वेतन वृद्धि	8.50%	8.50%
क्षयण (एट्रीशन)	1.00%	1.00%

छूट दर कर्तव्यों की अनुमानित अवधि के लिए तुलन प की तारीख के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों के मौजूदा बाजार लाभ पर आधारित है।

भविष्य की वेतन वृद्धियों के अनुमान में मुद्रास्फिति, वरिष्ठता, पदोन्नती, वेतन वृद्धि तथा अन्य सम्बद्ध घटकों को माना गया है।

बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान किए जाने वाले योगदान निर्धारित नहीं किए गए हैं।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा है

संलग्नक - XVI

6 **लेखामानक 18 के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए संबंधित पार्टी तथा उनसे लेन-देन का प्रकटीकरण**

क) संबंधित पार्टी तथा उनका संबंध

1) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां

आईडीएमसी लिमिटेड
इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड
मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड
एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज
प्रिस्टिन बायोलॉजिकल (NZ) लिमिटेड (इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
एनडीडीबी काफ लिमिटेड

2) अन्य उद्यम जहाँ प्रबन्ध तंत्र का उनके प्रबन्धन में महत्वपूर्ण प्रभाव है

पश्चिम असम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
पशु प्रजनन अनुसंधान संगठन (भारत)
आनंदालय एजुकेशन सोसायटी
झारखंड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड
एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रीशन
वाराणसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
लद्दाख यूटी डेयरी सहकारी महासंघ लिमिटेड
पूर्वी असम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
एनडीडीबी मृदा लिमिटेड
महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित
मणिपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड

3) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

डॉ. मीनेश शाह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा है

संलग्नक - XVI

ख) संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन

(इटेलिक में दिये गए आँकड़े पिछले वर्ष के हैं।)

मिलियन रुपये में

विवरण	ब्याज से आय	इक्विटी शेयरों की खरीद	स्थायी संपत्तियों की खरीद	अन्य वस्तुओं की खरीद	लाभांश	किराया (आय)	अन्य आय	अनुदान	अन्य व्यय	चालू खाते का शेष बकाया डे./(क्रे.)	ऋण शेष बकाया डे./(क्रे.)	वितरित ऋण	चुकाया ऋण/समायोजित		ऋण शेष बकाया डे./(क्रे.)
													ऋण शेष	बकाया	
	ब्याज	इक्विटी	स्थायी संपत्तियों	अन्य खरीद	लाभांश	किराया	अन्य आय	अनुदान	अन्य व्यय	चालू खाता	अग्रिम	वितरित ऋण	ऋण शेष	ब्याज	ऋण शेष
आईडीएमसी लिमिटेड	4.67	-	-	-	60.72	0.93	9.30	-	0.23	0.59	-	279.05	38.96	4.67	325.40
	7.64	-	-	-	*60.72*	*0.53*	*0.16*	*0.05*	*0.10*	*0.02*		*243.23*	*157.92*	*7.64*	*85.31*
इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड	40.97	-	-	-	150.01	29.40	10.73	-	7.21	3.32	-	-	121.66	40.97	433.18
	51.34	-	-	-	*108.00*	*29.38*	*43.80*	-	*7.38*	*(0.39)*		*728.45*	*173.61*	*51.34*	*554.84*
मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड	115.04	-	-	-	187.50	145.77	96.42	-	-	41.68	-	1,107.53	2,276.79	115.04	-
	89.52	-	-	-	-	*130.97*	*19.57*		*3.25*	*84.15*		*1,407.29*	*238.03*	*89.52*	*1,169.26*
एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज	-	-	-	-	-	10.61	21.50	-	1.19	7.70	-	-	55.40	-	307.50
	-	-	-	-	-	*13.28*	*5.10*	-	*0.26*	*12.93*		*418.30*	*55.40*	-	*362.90*
एनडीडीबी काफ लिमिटेड	-	-	-	-	-	0.41	58.50	-	3.62	75.04	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	*0.41*	*69.23*	-	*11.55*	*120.44*		-	-	-	-
योग	**160.68**	**-**	**-**	**-**	**398.23**	**187.12**	**196.45**	**-**	**12.25**	**128.33**	**-**	**1,386.58**	**2,492.81**	**160.68**	**1,066.08**
	148.50	**-**	**-**	**-**	***168.72***	***174.57***	***137.86***	***0.05***	***22.54***	***217.15***	**-**	***2,797.27***	***624.96***	***148.50***	***2,172.31***

मिलियन रुपये में

विवरण	ब्याज से आय	इक्विटी शेयरों की खरीद	स्थायी संपत्तियों की खरीद	अन्य वस्तुओं की खरीद	लाभांश	किराया (आय)	अन्य आय	अनुदान	अन्य व्यय	चालू खाते का शेष बकाया डे./(क्रे.)	ऋण शेष बकाया डे./(क्रे.)	वितरित ऋण	चुकाया ऋण/ समायोजित ऋण शेष	चुकाया ऋण/ समायोजित बकाया	ऋण शेष बकाया डे./(क्रे.)
अन्य उद्यम जहां प्रबंधन का उनके प्रबंधन पर महत्वपूर्ण प्रभाव है															
पश्चिम असम दूध उत्पादक सहकारी संघ लि.	-	-	-	-	-	0.02	2.85	11.78	0.06	0.11	-	15.84	-	-	30.11
	0.09	-	-	-	-	*0.14*	*0.92*	*14.70*	*0.02*	*0.03*	-	*80.00*	*80.00*	*0.09*	*14.27*
पशु प्रजनन अनुसंधान संगठन	-	-	-	-	-	0.19	0.03	-	-	0.09	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	*0.60*	-	-	*0.29*	-	-	-	-	-
आनन्दालय शिक्षा सोसाइटी	-	-	-	-	-	0.52	0.13	-	0.03	0.05	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	*0.48*	*0.13*	-	*0.02*	*0.01*	-	-	-	-	-
झारखंड राज्य सहकारी दूध उत्पादक महासंघ लिमिटेड	-	-	-	-	-	0.14	3.83	0.05	0.01	0.19	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	*0.17*	*2.08*	*2.09*	*0.01*	*1.12*		-	-	-	-
वाराणसी दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.48	5.60	-	(0.68)	115.65	122.87	129.65	-	248.65
	-	-	-	-	-	*0.01*	*0.04*	*23.90*	*0.54*	*(0.43)*	-	*280.00*	*37.13*	-	*255.43*
लद्दाख यूटी डेयरी सहकारी महासंघ	0.35	-	-	-	-	-	0.01	29.12	0.11	-	29.30	-	-	0.35	-
	-	-	-	-	-	-	-	*3.32*	-	-		-	-	-	-
नॉर्थ ईस्ट डेयरी एंड फूड्स लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-			-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
एनडीडीबी मृदा लिमिटेड	0.45	156.60	-	-	-	0.04	14.26	38.10	1.16	5.52	-	-	-	0.45	-
	-	-	-	-	-	*0.03*	*12.27*	*12.00*	*8.86*	*5.76*		-	-	-	-
पूर्वी असम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	16.72	-	-	4.84	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित	0.24	-	-	-	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	0.24	-
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	1.03	-	(0.04)	-	-	-	-	-
मणिपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	-	-	-	-	-	0.00	0.06	21.67	-	0.02	4.76	-	-	-	-
योग	**1.04**	**156.60**	**-**	**-**	**-**	**0.91**	**21.67**	**124.07**	**1.37**	**5.27**	**154.55**	**138.71**	**129.65**	**1.04**	**278.76**
	0.09	**-**	**-**	**-**	**-**	***0.83***	***16.04***	***56.01***	***9.45***	***6.78***	**-**	***360.00***	***117.13***	***0.09***	***269.70***

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा है

संलग्नक - XVI

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक को पारिश्रमिक

	मिलियन रुपये में
डॉ. मीनेश शाह	7.10
	7.00
योग	**7.10**
	7.00

नोट: केवल उन संबंधित पक्षों का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिनके साथ चालू और/या पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान लेनदेन हुआ है।

7 लेखा मानक 19 के अनुसार, 'लीज़'(पट्टे) का प्रकटीकरण (संदर्भ संलग्नक VIII देखें):

निम्नलिखित परिसंपत्तियों के लिए बोर्ड के द्वारा पट्टादाता (लेसर) के रूप में लीज व्यवस्था संचालन:

(क) पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों की प्रकृति

मिलियन रुपये में

परिसंपत्तियों की श्रेणी	31 मार्च 2025 को परिसंपत्तियों का सकल मूल्य	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	31 मार्च 2025 को संचित मूल्यह्रास
भवन एवं रोड #	1632.68	42.23	1162.50
	1633.00	*42.52*	*1120.58*
बिजली स्थापन #	28.07	0.88	27.14
	30.16	*0.89*	*28.34*
फर्नीचर, फिक्स्चर, कंप्यूटर्स एवं कार्यालय उपकरण	8.67	0.00	8.67
	8.7	*0.00*	*8.70*
रेल दूध टैंकर	340.87	16.55	287.34
	345.49	*16.55*	*275.40*
योग	**2010.29**	**59.66**	**1485.65**
	2017.35	***59.96***	***1433.02***

स्टाफ क्वार्टर तथा कोल्ड स्टोरेज शामिल हैं।
(इटैलिक में लिखे गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।)

पट्टेदाता (लीज़ी) को पूर्व नोटिस देकर इन व्यवस्थाओं को रद्द किया जा सकता है।

(ख) लीज़ प्रबंधों से संबंधित आरंभिक प्रत्यक्ष लागत को लीज़ प्रबंध के वर्ष के आय एवं व्यय लेखा में प्रभारित किया गया है।

(ग) महत्वपूर्ण लीज़ प्रबंध:

अनुबंध के नवीनीकरण अथवा निरस्तीकरण के विकल्प के साथ, उपर्युक्त सभी परिसंपत्तियों को सहायक कंपनियों, महासंघों तथा अन्य को लीज़ पर दिया गया है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा है

संलग्नक - XVI

8 आस्थगित कर परिसंपत्तियों को लेखा मानक 22 - 'आय पर कर गणना' के अनुसार माना गया है। विवरण इस प्रकार है:

मिलियन रुपये में

विवरण	1 अप्रैल 2024 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च 2025 को अंत शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ/(देयताएं):			
मूल्यह्रास	1.86	3.39	5.25
	(7.04)	*8.90*	*1.86*
भुगतान के आधार पर स्वीकार्य व्यय	167.29	23.32	190.61
	149.32	*17.97*	*167.29*
उपदान	(9.88)	(3.90)	(13.78)
	(13.19)	*3.31*	*(9.88)*
स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना	0.00	0.00	0.00
	0.01	*(0.01)*	*0.00*
विशेष आरक्षित निधि	(443.50)	(63.06)	(506.56)
	(408.79)	*(34.71)*	*(443.50)*
योग	**(284.23)**	**(40.25)**	**(324.48)**
	(279.69)	***(4.54)***	***(284.23)***

(इटैलिक में लिखे गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।)

नोट:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के परिपत्र सं. आरबीआई/2013-14/412 डीबीओडी सं.बीपी.बीसी.77/21.04.018/2013-14 दिनांक 20 दिसंबर 2013 में बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष रिजर्व पर आस्थगित कर दायित्व सृजित किया है।

9 लेखा मानक 29 के अनुसार-'प्रावधान, आकस्मिक देयताओं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण' निम्न प्रकार है:

मिलियन रुपये में

विवरण	अलाभकर परिसंपत्तियाँ (NPA)	मानक परिसंपत्तियों पर सामान्य आकस्मिकता	आकस्मिकता	कुल
आरम्भिक शेष	582.08	122.57	1,903.61	2,608.26
	559.34	*93.67*	*1,755.25*	*2,408.26*
वर्ष के दौरान आकस्मिकता से निर्मित	0.05	6.05	193.90	200.00
	22.74	*28.90*	*171.61*	*223.25*
वर्ष के दौरान वापस किया गया/ संचालन	-	-	-	-
	-	-	*(23.25)*	*(23.25)*
अंत शेष	**582.13**	**128.62**	**2,097.51**	**2,808.26**
	582.08	***122.57***	***1,903.61***	***2,608.26***

(इटैलिक में लिखे गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा है

संलग्नक - XVI

10 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार बोर्ड के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 28.84 मिलियन रूपये (पूर्व वर्ष 14.22 मिलियन रूपये) के विभिन्न लेनदार रहें और उन संस्थाओं को जिन्हे माइक्रो, स्मॉल एंड मिडियम इन्टरप्राइज डेवलेपमेंट एक्ट, 2006 के अंतर्गत माइक्रो और स्मॉल इन्टरप्राइज के रूप में वर्गीकृत किया गया है पर, कोई बकाया नही है।

11 ऋण और अग्रिम से ब्याज में 2,303.59 मिलियन रूपये (पूर्व वर्ष 1,723.53 मिलियन रुपये) और दीर्घावधि से 854.36 मिलियन रुपये (पूर्व वर्ष 1,144.55 मिलियन रुपये) शामिल हैं।

12 सभी लाभांश दीर्घावधि निवेश से प्राप्त होते हैं।

13 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-04 (निर्धारण वर्ष जिसमें एनडीडीबी आयकर अधिनियम, 1961 के दायरे में आया) से विशेष रिजर्व निर्मित किया गया है। जैसा कि एनडीडीबी का मानना है यह उक्त धारा के तहत कटौती की जाने की पात्रता रखता है। हालाँकि, निर्धारण वर्ष 2003-04 और उसके बाद के वर्षो के लिए आयकर अधिकारियों ने इस तरह के दावे को अस्वीकार कर दिया। एनडीडीबी ने विभिन्न अपीलीय मंचों पर इसका विरोध किया। माननीय उच्च न्यायालय, गुजरात ने मामले का फैसला आयकर विभाग के पक्ष में दिया। एनडीडीबी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की। यह मामला अब निराकरण हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है। एनडीडीबी प्रबंधन का मानना है कि आयकर के संबंध में कैश ऑउट फ्लो की कम संभावना है और यह विशेषज्ञ विधिक मत पर आधारित है यह एक उचित केस है; तदनुसार, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान एनडीडीबी बही खाते में विशेष रिजर्व निर्मित करना निरंतर जारी रखा है और उक्त दावे को कर प्रावधान के लिए पात्र माना है।

14 वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पूंजीगत कार्य की कुल पूंजी प्रतिबद्धता 95.88 मिलियन रुपये (पूर्व वर्ष 22.73 मिलियन रुपये) है।

15 वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित पूंजी निवेश की परिकल्पना की गई है:

कंपनी का नाम	मिलियन रुपये में	अभ्युक्ति
भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड	209.90	अतिरिक्त शेयर पूंजी

16 गत वर्ष के आँकड़ें आवश्यकतानुसार पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित किए गए हैं।

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम के पी एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 302014E/ W101061

वासुदेव सुंदरदास मत्ता
भागीदार
सदस्यता सं. 046953

स्थान: मुंबई
दिनांक: 1 अगस्त 2025

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से,

मीनेश सी शाह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एस रघुपति
कार्यपालक निदेशक
(ऑपरेशन)

अमित गोयल
ग्रुप प्रमुख
(लेखा)

स्थान: आणंद
दिनांक: 1 अगस्त 2025

एनडीडीबी के अधिकारी

प्रधान कार्यालय, आणंद

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक

मीनेश सी शाह
बीएससी (डीटी), पीजीडीआरडीएम
विज्ञान में डॉक्टरेट की मानद उपाधि

मुख्य कार्यपालक का कार्यालय

राजेश कुमार
वरिष्ठ प्रबंधक, बीए (इको), पीजीडीआरएम

हृदय बी दर्जी
वैज्ञानिक-II, बीटेक (डीटी), एम.टेक (डीटी)

रेणु शर्मा
उप प्रबंधक, बीबीए (मार्केटिंग एवं सेल्स), पीजीडीआरएम

रिदम
उप प्रबंधक, बीटेक (डीटी)

प्रबंध निदेशक

मीनेश सी शाह
बीएससी (डीटी), पीजीडीआरडीएम
विज्ञान में डॉक्टरेट की मानद उपाधि

प्रबंध निदेशक का कार्यालय

राजेश सिंह
वरिष्ठ प्रबंधक, बीसीए, पीजीडीएम (मार्केटिंग एवं वित्त)

निकित बंसल
प्रबंधक, बीकॉम, सीए, पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

कार्यपालक निदेशक

एस रघुपति
एमकॉम,
आईसीडब्ल्यूए, पीजीडीआरडीएम

एस राजीव
बीटेक (औद्योगिक इंजीनियरिंग), पीजीडीआरएम

कार्यपालक निदेशक का कार्यालय

वत्सल पटेल
प्रबंधक, बीई (मैक.)

वरिष्ठ महाप्रबंधक

वी श्रीधर
बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी (पशु पोषण), एमबीए

आर ओ गुप्ता
बीवीएससी, एमवीएससी (मेड)

ए वी रामचंद्र कुमार
बीई (कंप्यूटर इंजीनियरिंग), पीजीडीएम

एस एस सिन्हा
बीई (इलेक्ट)

लेखा

अमित गोयल
उप महाप्रबंधक, बीकॉम, सीए

विनय गुप्ता
वरिष्ठ प्रबंधक, बीकॉम, आईसीडब्ल्यूए, पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

चिराग के सेवक
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (गणित), पीजीडीसीए, पीजीडीटीपी, आईसीडब्ल्यूए, पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

आशुतोष के मिश्र
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (ईएंडआई), पीजीडीबीए (वित्त)

रश्मि प्रतीश
प्रबंधक, एमकॉम, आईसीडब्ल्यूए

स्वप्निल ठाकर
प्रबंधक, एमकॉम, सीए,
पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

रविंद्र जी रामदासिया
प्रबंधक, एमकॉम, सीए, सीएस, पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

कमलकांत आर परमार
उप प्रबंधक, बीकॉम, सीए

पंकज सैन
उप प्रबंधक, एमकॉम, सीए, सीएस

दर्शन एन प्रजापति
उप प्रबंधक, बीकॉम, सीएमए

केतनकुमार डी पटेल
उप प्रबंधक, बीकॉम, सीएमए

बिलावथ शिवुडू नाइक
उप प्रबंधक, बीकॉम, सीएमए

सागर वी पांडेय
उप प्रबंधक, बीकॉम, सीए

प्रशासन

धीरूभाई सी परमार
वरिष्ठ प्रबंधक, एमकॉम, एलएलबी (सामान्य), एमएसडब्ल्यू, पीजीडी-एचआरएम

आर पी डोडामणि
प्रबंधक, बीकॉम, एलएलबी

नयनकुमार डी काथावाला
उप प्रबंधक, बीकॉम, एमएचआरएम, एलएलबी

प्रशासन - उपयोगिता

रुपेश ए दर्जी
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (इलेक्ट)

बिभाष बिस्वास
प्रबंधक, डिप्लो. (सिविल), डीबीएम

पशु प्रजनन

पशु प्रजनन - अनुसंधान एवं विकास

सुजीत साहा
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (कृषि), एमएससी (डेयरी), पीएचडी (पशु आनु. एवं प्रजनन), पीजीडीआईएम, एमबीए (ऑपरेशन प्रबंधन)

ए सुधाकर
वरिष्ठ प्रबंधक, बीवीएससी, एमवीएससी, पीएचडी (पशु प्रजनन)

स्वप्निल जी गज्जर
प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच,
एमवीएससी (पशु आनु. एवं प्रजनन)

सिद्धार्थ एस लायक
प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच,
एमवीएससी (एलपीएम), पीएचडी (एलपीएम)

करुप्पनासामी के
प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी (वेट. गायनेक. एवं ऑब्सटेट्रिक्स)

कर्मराज आर जैसवार
वैज्ञानिक I, बीएससी, एमएससी (माइक्रोबायोलॉजी), जैव सूचना विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स

संकेत प्रकाश पाटिल
उप प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच,
एमवीएससी (पशु प्रजनन, गायनेक एवं ऑब्स.)

कथन भानुभाई रावल
उप प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच,
एमवीएससी (वेट. गायनेक एवं ऑब्स.),
पीएचडी (वेट. गायनेक एवं ऑब्स.)

पशु प्रजनन - क्षेत्रीय परियोजनाएं

एन जी नाई
वरिष्ठ प्रबंधक, बीवीएससी, एमवीएससी (पशु प्रजनन), पीएचडी (पशु आनु. एवं प्रजनन)

पराग आर पंड्या
वरिष्ठ प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच,
एमबीए (एचआरएम)

वी पी भोसले
वरिष्ठ प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच,
एमवीएससी (मेड)

एम एल गवांडे
वरिष्ठ प्रबंधक, बीवीएससी, एमवीएससी (पशु चिकित्सा)

समता डे
वरिष्ठ प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच,
एमवीएससी (वेट. गाइनेक एंड ऑब्स्ट)

शिराज एम शेरसिया
प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच, एमबीए (एग्री बिज.)

अतुल सी महाजन
प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी (पशु आनु. एवं प्रजनन), पीएचडी (पशु आनु. एवं प्रजनन)

मयंककुमार जे. पटेल
उप प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी (एनिमल रिप्रोडक्शन, गायनेक एवं ऑब्स.)

सुनीलभाई जे. परमार
उप प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी (वेट. गायनेक एवं ऑब्स.)

पशु स्वास्थ्य

ए वी हरि कुमार
उप महाप्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी (माइक्रो)

पंकज दत्ता
प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी (माइक्रो)

श्रोफ सागर आई
प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी (माइक्रो), पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

केशांक एम दवे
उप प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी (वेट. एपिडर्मिलॉजी एवं प्रीव. मेड.)

एनडीडीबी अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद

पोनन्ना एन एम
वैज्ञानिक III, बीएससी (कृषि), एमएससी (एग्री माइक्रो), पीएचडी (बायोटेक)

के एस एन एल सुरेंद्र
वैज्ञानिक II, बीएससी, एमएससी (बायोटेक)

अमितेश प्रसाद
वैज्ञानिक II, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी (वेट. माइक्रो)

विजय एस बाहेकर
वैज्ञानिक II, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी (वेट. माइक्रो)

संदीप कुमार दाश
वैज्ञानिक II, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी (माइक्रो), पीएचडी (वेट. माइक्रो)

पशु पोषण

राजेश शर्मा
उप महाप्रबंधक, एमएससी (कृषि), पीएचडी (एग्रो)

एन आर घोष
वरिष्ठ प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच, एमएससी (पशु पोषण)

मयंक टंडन
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी, एमएससी (कृषि पशु पोषण), पीएचडी (पशु पोषण)

भूपेंद्र टी फोंदबा
वैज्ञानिक III, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी, पीएचडी (पशु पोषण)

चंचल वाघेला
प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी (पशु पोषण)

विनोद उइके
प्रबंधक, बीएससी (कृषि), एमएससी (कृषि विज्ञान)

हार्दिककुमार बी नलियापरा
उप प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच, मवीएससी (पशु पोषण), पीएचडी (पशु पोषण)

निधि
उप प्रबंधक, बीएससी (ऑनर्स) (कृषि), एमएससी (बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी), पीएचडी(बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)

अनिल
उप प्रबंधक, बीएससी (ऑनर्स) (कृषि), एमएससी (कृषि विज्ञान)

सहकारिता सेवाएं

सीमा माथुर
वरिष्ठ प्रबंधक, एमए (अंग्रेजी)

हृषिकेश कुमार
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (भौ.), पीजीडीआरएम

हेमाली भारती
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (पावर इलेक्ट), एमबीए (वित्त)

विशाल कुमार मिश्रा
वरिष्ठ प्रबंधक, बीए, एमए (एसडब्ल्यू)

डेंजिल जे डायस
प्रबंधक, बीटेक (डीटी), एमटेक (डीटी)

रविनारायण भट वी
उप प्रबंधक, बीई (मैक.), पीजीडीआरएम

सीएस-एनएफएन

स्मृति सिंह
वरिष्ठ प्रबंधक, बीए (अंग्रेजी), पीजीडीएम (मार्केटिंग एवं एचआर)

काजल दक्षेश जोशी
उप प्रबंधक, बीकॉम, एमएसडब्ल्यू

सहकारिता प्रशिक्षण

अनिंदिता बैद्य
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (बॉट), पीजीडीआरडी

टी प्रकाश
प्रबंधक, एमए (डेव. एडमिन), पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

राहुल आर
प्रबंधक, बीटेक (सीएस), एमबीए (सिस्टम)

सुनीतकुमार वी गौतम
उप प्रबंधक, बीई (मैक), पीजीडीआरएम

अजितकुमार संपतराव तंदाले
उप प्रबंधक, बीएससी (कृषि), एमएससी (कृषि विज्ञान)

अभियांत्रिकी सेवाएं

एस तालुकदार
महाप्रबंधक, बीई (मैक.), एमआईई

पी रमेश
उप महाप्रबंधक, बीई (मैक.), पीजीसीपीएम

के एस पटेल
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (सिविल), एमबीए (मासंवि एवं वित्त)

मिहिर बी बगरिया
वरिष्ठ प्रबंधक, डीसीई, बीई (सिविल), एमबीए (वित्त)

मनोज गोठवाल
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (सिविल)

सुब्रता चौधरी
वरिष्ठ प्रबंधक, डीसीई, एएमआईई (सिविल)

धवल ए पंचाल
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (इलेक्ट)

भूषण पी कापशिकर
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (सिविल)

सचिन गर्ग
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (इलेक्ट), पीजीडीबीए

निकेश वी मोरे
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (इंस्ट्रू. एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग)

डी बी लालचंदानी
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (मैक), एमबीए (ऑपरेशन)

सुनंदा कुमार एन
प्रबंधक, बीटेक (मैक), एमटेक (मैट. साइंस एंड टेक)

पी बालाजी
प्रबंधक, बीई (सिविल)

आदित्य शर्मा
वरिष्ठ प्रबंधक, बीटेक (सिविल), एमटेक (सीपीएम)

अभिषेक गुप्ता
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (मैक.)

सुधीर कुमार गंगल
वरिष्ठ प्रबंधक, डीसीई, बीई (सिविल)

श्रेयस जैन
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (इलेक्ट्रिकल)

प्रकाश ए मकवाना
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (इलेक्ट)

बलबीर शर्मा
वरिष्ठ प्रबंधक, डीईई, बीटेक (इलेक्ट) पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

अक्षय मंडोरा
प्रबंधक, बीई (मैक.)

प्रतीक के अग्रवाल
प्रबंधक, बीई (सिविल)

विवेक जैसवाल
प्रबंधक, बीई (सिविल)

सुमीत शेखर
प्रबंधक, बीई (मैक.)

सचिन ए सरवैया
प्रबंधक, बीई (मैक.)

अलर्क एस कुलकर्णी
प्रबंधक, बीटेक (इंस्ट्रू.),
एमटेक (बायोटेक)

राहुल कुमार
प्रबंधक, बीटेक (इलेक्ट्रिकल)

सत्यबान बेहेरा
उप प्रबंधक, डिप्लोमा (सिविल), बीटेक (सिविल)

मानसी वाई गोस्वामी
उप प्रबंधक, बीई (मैटलर्जिकल एवं मैटेरियल इंजीनियरिंग), पीजीडीआरए

मानसी बिष्ट
उप प्रबंधक, बीएससी (ऑनर्स) (कृषि), पीजीडीआरएम

1.5 लाख लीटर प्रतिदिन का स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र व मूल्य वर्धित उत्पाद इकाई, ढंगवार, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

अभिषेक सिंघल
प्रबंधक, बीटेक (सिविल)

120 मीट्रिक टन प्रतिदिन का डेयरी व्हाइटनर/बेबी फूड मिल्क पाउडर प्लांट और यूएचटी प्लांट, दूधसागर डेयरी, महेसाणा, गुजरात

शैलेंद्र मिश्रा
वरिष्ठ प्रबंधक, डिप्लो. (सिविल),
डिप्लो. (कंस्ट्रू. टेक)

150 टन प्रतिदिन पशु चारा संयंत्र, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा, राजस्थान

जय नागर
प्रबंधक, बीई (सिविल)

अंशुल चौरसिया
प्रबंधक, बीई (मैक.), पीजीडीओएम

2.35 लाख लीटर प्रतिदिन फर्मेन्टेड उत्पाद संयंत्र, अमृतसर, पंजाब

गौरव सिंह
प्रबंधक, बीटेक (सिविल)

50 हजार लीटर प्रतिदिन का डेयरी संयत्र, राजसमंद, राजस्थान

जसदेव सिंह
वरिष्ठ प्रबंधक, बीटेक (इले.), एमटेक (पावर इंजीनियरिंग), पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

कृष्ण देव
प्रबंधक, बीटेक (सिविल),
एमटेक (जियोटेक्निकल)

5 लाख लीटर प्रतिदिन की स्वचालित डेयरी संयंत्र परियोजना, अरिलो, ओडिशा

सौम्य रंजन मिश्रा
प्रबंधक, बीई (इलेक्ट.)

अमूलफेड-II, राजकोट, गुजरात

निकुंजकुमार एन परमार
प्रबंधक, बीई (सिविल)

संतोष पाटीदार
प्रबंधक, बीई (सिविल)

बनास पशु प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र (COE-BBBRC), भीलड़ी, बनासकांठा, गुजरात

आशीष रवि
प्रबंधक, बीटेक (सिविल),
पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

पशु आहार संयंत्र, हाजीपुर, साबरकांठा, गुजरात

तुषार एस चवान
प्रबंधक, बीई (मैक)

अपशिष्ट उपचार परियोजना (ईटीपी) (चरण-II), साबर डेयरी, हिम्मतनगर, गुजरात

नीरव पी सक्सेना
उप प्रबंधक, बीई (मैक), एमई (कैड/कैम)

हैदराबाद डेयरी परियोजना स्थल, हैदराबाद, तेलंगाना

प्रदीप लायक
वरिष्ठ प्रबंधक, बीटेक (इलेक्ट)

मेगा डेयरी, नागपुर, महाराष्ट्र

धीरज बी टेमभुर्णे
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (सिविल)

दूध उत्पाद संयंत्र परियोजना, बरौनी, बिहार

सुरजीत के चौधरी
प्रबंधक, बीई (मैक.)

5 लाख लीटर प्रतिदिन का नया दूध प्रसंस्करण संयंत्र एवं 15 लाख लीटर प्रतिदिन ईटीपी, मोहाली, पंजाब

तारक राजनी
प्रबंधक, बीई (सिविल)

नया पशु वैक्सीन संयंत्र, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, कारकापटला, तेलंगाना

बिभु प्रसाद जेना
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (सिविल)

सैयद अब्दुल राशिद
प्रबंधक, बीई (मैक.)

एसएजी, अहमदाबाद

बलराम निबोरिया
प्रबंधक, बीटेक (सिविल)

वैक्सीन उत्पादन संयंत्र, ब्रह्मपुर, ओडिशा

आशुतोष सामल
प्रबंधक, बीटेक (सिविल)

वित्त

टी टी विनयागम
उप महाप्रबंधक, बीई (कृषि), पीजीडीआरएम

चिंतन खाखरियावाला
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (केम.), एमबीए (वित्त)

कल्पेशकुमार जे पटेल
वरिष्ठ प्रबंधक, बीबीए, एमकॉम(एसीसीजी एवं वित्त प्रबंधन), एसीएमए,एसीएस

रोहन बी बुच
प्रबंधक, बीकॉम, एमबीए (वित्त)

शिल्पा पी बेहेरे
प्रबंधक, बीएमएस, पीजीडीआरएम

संजीता भाटी
उप प्रबंधक, बीएमएस, पीजीडीआरएम

वैशाली जैन
उप प्रबंधक, बीकॉम (ऑनर्स), पीजीडीआरएम

अनुराग जोसेफ कुजूर
उप प्रबंधक, बीकॉम, एमबीए (वित्त)

मानव संसाधन विकास

एस एस गिल
उप महाप्रबंधक, बीएससी (जियो), एमएसडब्ल्यू,पीएचडी (एसडब्ल्यू), डिप्लो. (ट्रेनिंग एवं डेव.)

मोहन चंदर जे
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (मैक.), एमटेक (मासंवि)

राकेश बी
प्रबंधक, बीए, एमएसडब्ल्यू, पीजीडी-एचआरएम

समीर डुंगडुंग
प्रबंधक, बीकॉम, पीजीडीएम-एचआरएम

प्राची जैन
उप प्रबंधक, बीबीए (जनरल बिजनेस मैनेजमेंट), एमएचआरएम

हिंदी कक्ष

जनार्दन मिश्र
प्रबंधक, एमए (हिंदी), एमफिल (अनुवाद प्रौद्योगिकी), जनसंचार एवं संप्रेषणी हिंदी में पीजीडी

आईडीएफ एवं कोडेक्स

आदित्यकुमार पी जैन
उप महाप्रबंधक, बीएससी (डीटी), एमएससी (डेयरिंग)

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

एस करुनानिधि
उप महाप्रबंधक, डीईई, सीआईसी

आर के जादव
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (भौ.), एमसीए, पीजीडीएम

सुप्रिय सरकार
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (गणित), एमसीए, पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

विपुल गोंडलिया
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (इलेक्ट्रॉनिक्स)

बी सेंथिल कुमार
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी, पीजीडीसीए, बीएड, एमसीए, एमबीए

रीतेश के चौधरी
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (कंप्यू. विज्ञान), पीजीडीबीएम, पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

राकेश आर मानिया
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (ईसीई)

अशोक कुमार साहनी
प्रबंधक, बीई (सीएसई)

सोहेल ए पठान
प्रबंधक, बीई (आईटी), एमई (सीएसई)

जय वाई बारोट
प्रबंधक, बीटेक (कंप्यू. इंजीनियरिंग)

निकिता आर मेस्वानिया
उप प्रबंधक, बीई (कंप्यू. इंजीनियरिंग)

तुषार साहेबराव पाटिल
उप प्रबंधक, बीई (कंप्यू.)

नवाचार और परियोजना प्रबंधन (आईपीएम) प्रकोष्ठ

मुकेश आर पटेल
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी, एमएससी (कृषि)

विनय ए पटेल
प्रबंधक, बीटेक (बायोमेड), एमबीए (मार्केटिंग)

प्रकाशकुमार ए पंचाल
प्रबंधक, बीटेक (डीटी), एमएससी (आईसीटी-एआरडी), पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

सिंजिनी गुहा
उप प्रबंधक, बीटेक (ईसीई), पीजीडीआरएम

श्रेयश जैसवाल
उप प्रबंधक, बीबीए (बिजनेस एडमिन), पीजीडीआरएम

आंतरिक लेखा परीक्षा

धारा एन लखानी
उप महाप्रबंधक, एमकॉम, एसीएमए

विधि

संजीवी नागराजन
वरिष्ठ प्रबंधक, एमएससी (रसायन विज्ञान), एलएलबी

पल्लवी ए जोशी
प्रबंधक, बीकॉम, एलएलबी

प्रखर द्विवेदी
उप प्रबंधक, बीए-एलएलबी (ऑनर्स)

मार्केटिंग सेल

हर्षेंद्र सिंह
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (इलेक्ट एवं पावर इंजीनियरिंग), एमबीए (मार्केटिंग)

आर मजूमदार
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (कृषि), पीजीडीआरएम

विष्णु देठ जी
प्रबंधक, बीटेक (सीएस), पीजीडीआरएम

शाज़लीन मांज़ूर
उप प्रबंधक, बीए-एलएलबी (ऑनर्स), एलएलएम (कॉर्पोरेट बैंकिंग एवं बीमा कानून), पीजीडीआरएम

राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (एनडीएलएम)

आर के श्रीवास्तव
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (गणित), पीजीडीसीए, एमसीए

रनमल एम अम्बालिया
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (कंप्यूटर इंजीनियरिंग), पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

बी वसंत नाईक
प्रबंधक, बीटेक (सीएस एवं आईटी), एमटेक (सीएसई)

मीतेश सी पटेल
प्रबंधक, बीई (आईटी)

उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास

जितेंदर सिंह
वैज्ञानिक III, बीएससी, एमएससी (माइक्रो), पीएचडी (डेयरी माइक्रो)

सौगता दास
वैज्ञानिक II, बीटेक (डीटी), एमएससी (डेयरी माइक्रो)

विशालकुमार बी त्रिवेदी
वैज्ञानिक II, बीटेक (डीटी), एमटेक (डीटी), पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

ललिता मोदी
वैज्ञानिक II, बीटेक (डीटी), एमटेक (डीटी)

अमरलापुदी मोनिका रोज़
वैज्ञानिक-I, बीटेक (डीटी), एम.टेक (डेयरी सूक्ष्मजीव), पीएच.डी (डेयरी माइक्रो)

अमित प्रकाशचंद्र तिवारी
वैज्ञानिक-I, बीएससी, एमएससी (माइक्रो बायोलॉजी)

जनसंपर्क, संचार एवं आतिथ्य

अभिजीत भट्टाचारजी
महाप्रबंधक, बीएससी, एलएलबी, पीजीडीआरडी

बसुमन भट्टाचार्य
उप महाप्रबंधक, बीएससी (बॉट), एमए (पत्रकारिता), डिप्लो. इन सोशल कॉम (फिल्म मेकिंग)

दिव्यराज आर ब्रह्मभट्ट
वरिष्ठ प्रबंधक, बीए (अंग्रेजी), पीजीडीबीए, एमबीए (पीआर)

आकांक्षा एल कुमार
उप प्रबंधक, बीए (अंग्रेजी), एमए (पत्रकारिता एवं मास कॉम), पीजीडी (पत्रकारिता)

निखिल वी कल्याणपाद
उप प्रबंधक, बीएमएम, एमबीए (संचार प्रबंधन)

प्रणव जिग्नेश अवसत्थी
उप प्रबंधक, एमए (पत्रकारिता एवं जनसंचार)

गुरशरण दीप सिंह हंसरा
उप प्रबंधक,
बीटेक (एग्री इंजीनियरिंग), एम.टेक (मृदा एवं जल अभियांत्रिकी), पीजीडीएम (जनसंचार)

क्रय

कृष्णा एसवाई
उप महाप्रबंधक, बीई (मैक.), एमटेक (उत्पाद प्रबंधन)

सौगत भार
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (मैक.)

मोहम्मद नसीम अख्तर
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (मैक.)

भद्रसिंह जे गोहिल
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (मैक.)

निधि त्रिवेदी
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (बॉट), एमएसडब्ल्यू

विपुल एल सोलंकी
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (ईसीई),
पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

नीलेश के पटेल
प्रबंधक, बीई (प्रोडक्शन)

हिमांशु के रत्नोत्तर
प्रबंधक, बीई (प्रोडक्शन),
पीजीडी (ऑपरेशन प्रबंधन)

दिनेश के घांची
उप प्रबंधक, बीटेक (इलेक्ट्रिकल)

पार्थ प्रकाशभाई मैयाद
उप प्रबंधक, बीटेक (इलेक्ट्रिकल)

झनकृत के वसावड़ा
उप प्रबंधक, बीई (मैक.)

ऋषभकुमार एस शाह
उप प्रबंधक, बीई (मैक.)

जयदीपकुमार पी वाधेल
उप प्रबंधक, बीई (मैक.)

गुणवत्ता आश्वासन

एस डी जैसिंघाणी
उप महाप्रबंधक,
बीएससी (डीटी), पीजीडीएचआरएम

नवीनकुमारा एसी
प्रबंधक, बीटेक (डीटी),
एमटेक (डेयरी माइक्रो)

दीक्षा सिंह
उप प्रबंधक, बीटेक (डीटी)

नीलराजसिंह एम जादव
उप प्रबंधक, बीटेक (डीटी)

क्षेत्रीय विश्लेषण और योजना

जिग्नेश जी शाह
उप महाप्रबंधक, बीई (इलेक्ट), एमबीए,
पीएचडी (प्रबंधन), डिप्लोमा (निर्यात प्रबंधन)

अनिल पी पटेल
वरिष्ठ प्रबंधक, एमएससी (कृषि),
पीजीडीएमएम

मेना एच पाघडार
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी, एमसीए

सर्वेश कुमार
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (कृषि एवं एएच),
एमएससी (डेयरी इको), पीएचडी (डेयरी
इको), पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

बिश्वजीत भट्टाचारजी
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (कृषि), एमएससी
(एग्री इको), पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

आयुष कुमार
प्रबंधक, बीटेक (जेनेटिक इंजीनियरिंग),
पीजीडीएम

रीति
प्रबंधक, बीएससी (जू.),
पीजीडीएम (वित्त एवं मार्केटिंग)

आभास अमर
प्रबंधक, बीबीए, पीजीडीएम

श्वेता एन रामटेके
प्रबंधक, बीपीटीएच, पीजीडीआरएम

सक्षम गर्ग
उप प्रबंधक, बीई (औद्योगिक अभियांत्रिकी
एवं प्रबंधन), पीजीडीआरएम

क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु

जी किशोर
महाप्रबंधक, बीवीएससी, एमएससी (डेयरिंग,
पशु आनु. एवं प्रजनन)

शशिकुमार बी एन
उप महाप्रबंधक, बीई (ईईई),
पीजीडीआरडीएम

एम एन सतीश
वरिष्ठ प्रबंधक, एमएससी (सांख्यिकी)

बी वी महेशकुमार
वरिष्ठ प्रबंधक, एमएससी (कृषि)

एस एस न्यामगोंडा
वरिष्ठ प्रबंधक, एमएससी (एग्रो), सीआईसी

एम एल गवांडे
वरिष्ठ प्रबंधक, बीवीएससी, एमवीएससी
(वेट. मेड)

लता सिरिपुरापु
वरिष्ठ प्रबंधक, बीकॉम, पीजीडीबीए (वित्त)

रजनी बी त्रिपाठी
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (बॉट), एमएसडब्ल्यू,
पीजीडीआईआरपीएम

निधि नेगी पटवाल
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी, एमएससी (रसायन),
पीजीडीआरएम

थुंगय्या सालियान
प्रबंधक, बीए, एमएसडब्ल्यू, पीजीडी-
एचआरएम, पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

कृष्णा एम बेउरा
प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच, एमबीए
(ग्रामीण प्रबंधन)

दिव्या टीआर
प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी
(एनीमल रिप्रो. गायनेक. एवं आब्स.)

निम्मी तोपनो
प्रबंधक, बीकॉम, पीजीडीएम-एचआरएम

पृथ्वी पातनेनी
प्रबंधक, बीटेक (सिविल), एमटेक (क्यूएम)

जगदीश नायका
प्रबंधक, बीटेक (डीटी), एमटेक (फूड टेक)

फ्रेडरिक सेबास्टियन
प्रबंधक, एमए (डेव. स्टडी), पीजीडीडीएम,
पीजीसीएमआरडीए

इंदु एस
उप प्रबंधक, एमए (अर्थशास्त्र),
पीजीडीआरएम

इशिता
उप प्रबंधक, बीएससी (कृषि), पीजीडीआरएम

मालथी एन
उप प्रबंधक, बीटेक (बागवानी),
पीजीडीआरएम

त्रिवेंद्रम

रोमी जैकब
उप महाप्रबंधक, एमएससी (कृषि)

अंजना साहू
उप प्रबंधक, बीई (इलेक्ट), पीजीडीआरएम

रिया जॉर्ज
उप प्रबंधक, बीएससी (ऑनर्स) (कृषि),
पीजीडीआरएम

ज़ोया छेत्री
उप प्रबंधक, बीटेक (फूड टेक्नोलॉजी एवं
मैनेजमेंट), पीजीडीआरएम

इरोड

ए क्रितिगा
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (कृषि),
एमए (ग्रामीण विकास)

हैदराबाद

यू सुंदरा राव
वरिष्ठ प्रबंधक, डीईई, बीटेक (ईईई)

चैन्नई

एस ए अनुषा
उप प्रबंधक, बीवीएससी, एमवीएससी (वेट.
पब्लिक हेल्थ)

क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता

आर सौंदराराजन
उप महाप्रबंधक, एएमआईई (मैक.)

सब्यसाची रॉय
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (कृषि) ऑनर्स,
एमएससी (कृषि), पीजीडीआरडी, पीएचडी
(कृषि)

कौशिक रॉय
वरिष्ठ प्रबंधक, बीटेक (इले.)

चैताली चटर्जी
वरिष्ठ प्रबंधक, बीए, एमए (तुलनात्मक
साहित्य)

रबिंद्र के बेहेरा
प्रबंधक, बीई (सिविल)

दर्श के वोरा
प्रबंधक, बीएससी (माइक्रो), एमएससी (पर्यावरण विज्ञान), जीआईएस सर्टिफिकेट, पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

चंदन सिंह
प्रबंधक, बीएससी (जू.), पीजीडीएम (मार्केटिंग एवं वित्त)

श्रेष्ठा
प्रबंधक, बीसीए, पीजीडीएम (एचआर एवं मार्केटिंग)

ऋतुराज बोरा
प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी

सुरभि पवार
प्रबंधक, बीबीए, पीजीडीएम-आरएम

गौतम कुमार झा
प्रबंधक, बीई (सिविल)

संदीप कुमार
उप प्रबंधक, बीएसी (ऑनर्स), कृषि, एमएससी (एग्रोनॉमी)

अंकित सुबर्णो
उप प्रबंधक, बीए (ऑनर्स), पीजीडीआरएम

पटना

आशुतोष सिंह
वरिष्ठ प्रबंधक, एमए (इको.), पीएचडी (इको.), पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

पदम वीर सिंह
प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी (पशु पोषण)

भुवनेश्वर

लक्ष्मी नारायण सारंगी
वैज्ञानिक-II, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी (वेट. माइक्रो), पीएचडी

क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई

वी श्रीनिवास
महाप्रबंधक, बीई (सिविल)

गोपाल के नारंग
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (सिविल), डीआईपी-एमसीएम

स्वाति श्रीवास्तव
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (भौ.), पीजीडीआरएम

धर्मेन्द्र के बेहरा
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (मैक.), एमबीए (मार्केटिंग एवं सिस्टम)

रोहन बी बुच
प्रबंधक, बीकॉम, एमबीए (वित्त)

कुणाल किशोर जाधव
उप प्रबंधक, बीएससी (कृषि), पीजीडीआरएम

भोपाल

सुभांकर नंदा
प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी (पशु पोषण)

क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा

राजेश गुप्ता
महाप्रबंधक, बीएससी, एमएसडब्ल्यू

एस के नासा
उप महाप्रबंधक, बीई (सिविल)

दिग्विजय सिंह
वरिष्ठ प्रबंधक, एमएससी (कृषि), पीएचडी (एग्रो.)

अरुण चंडोक
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी, पीजीडी (आईआरपीएम), डीसीएस, एमबीए

एम के राजपूत
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी, बीई (फूड इंजीनियरिंग एंड टेक)

पंकज एल शेरसिया
वैज्ञानिक III, बीवीएससी, एमवीएससी (पशु पोषण), पीएचडी (पशु पोषण)

संजय कुमार यादव
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी, एमबीए (आरडी)

संदीप धीमान
वरिष्ठ प्रबंधक, बीकॉम, एमए (एसडब्ल्यू)

मनोज कुमार
प्रबंधक, बीटेक (मैक.)

मनोज कुमार गुप्ता
प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी (वेट. माइक्रो)

जितेंद्र सिंह राजावत
प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच, एग्री बिज. प्रबंधन में पीजीडी

आशीष सिजेरिया
प्रबंधक, बीई (इलेक्ट्रॉनिक्स), पीजीडीआरएम

बृजेश कुमार
प्रबंधक, बीटेक (सिविल)

जयपुर

प्रीतेश जोशी
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (मैक.), पीजीडीआरएम

अलका चौधरी
प्रबंधक, बीएससी (ऑनर्स) (कृषि), एमएससी (एग्रोनॉमी)

चंडीगढ़

धनराज खत्री
वरिष्ठ प्रबंधक, बीए, एमए (एसडब्ल्यू)

रुमिनपाल सिंह बाली
प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी (एनिमल रिप्रो. गायनेक. एवं आब्स.)

शिवम
उप प्रबंधक, बीएससी (ऑनर्स) (कृषि), पीजीडीआरएम

लखनऊ

मोहम्मद राशिद
वरिष्ठ प्रबंधक, बीए, पीजीडीडीएम

क्षेत्रीय प्रदर्शन और प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी)

ईआरडीटीसी, सिलीगुड़ी

कमलेश प्रसाद
प्रबंधक, डीएमएलटी, बीएससी, बीवीएससी एवं एएच, पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

रमेश कुमार
प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी (एलपीएम)

मानसिंह प्रशिक्षण संस्थान, महेसाणा

हितेंद्रसिंह राठौड़
प्रबंधक, डीईई

शैलेष एस जोशी
प्रबंधक, बीई (मैक.)

दुष्यंत देसाई
प्रबंधक, बीटेक (डीटी), पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

हिमांशुकुमार एन सरवैया
उप प्रबंधक, बीटेक (डीटी)

भूमितकुमार एच बालधा
उप प्रबंधक, बीटेक (डीटी)

एनआरडीटीसी, जालंधर

सत्यपाल कुर्रे
प्रबंधक, डीफार्म, बीवीएससी एवं एएच, एमबीए

एसआरडीटीसी, इरोड

टी पी अरविंद
वरिष्ठ प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी (वेट माइक्रो)

महासंघों, संघों, प्रबंधित इकाइयों / परियोजनाओं में प्रतिनियुक्ति/ सेकेंडमेंट/ तैनाती

औरंगाबाद दुग्ध संघ, औरंगाबाद

सुरेश पहाड़िया
वरिष्ठ प्रबंधक, बीटेक (डीटी), एमएससी (डेयरिंग), पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

पवन कुमार डांगी
उप प्रबंधक, बीएससी (ऑनर्स) कृषि, पीजीडीएम (एग्री बिज. मेनेजमेंट)

बनास डेयरी, बायो-सीएनजी, दामा

जयेश धनराज चव्हाण
उप प्रबंधक, बीटेक (रासायनिक), पीजीडीआरएम

बीकानेर दूध संघ, बीकानेर

शुभम गुलाटी
उप प्रबंधक, बीएससी कृषि, पीजीडीएम (कृषि व्यवसाय प्रबंधन)

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी डेयरी महासंघ (सीजीसीडीएफ), रायपुर

सैकत सामंता
वरिष्ठ प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी (पशु पोषण), पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

काहनू सी बेहेरा
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (कृषि), पीजीडीआरएम

सतेन्द्र सिंह गुर्जर
प्रबंधक, बीई (मैक.), पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

अनिल एम अद्रोजा
प्रबंधक, बीई (आईटी)

एलन सेवियो एक्का
प्रबंधक, बीएससी (आईटी), पीजीडीएम-आरएम

रमेश कुमार
उप प्रबंधक, बीकॉम, सीए

विजिता सिंह
उप प्रबंधक, बीकॉम, पीजीडीआरएम

पूर्वी असम दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (ईअमूल), जोरहट

प्रीतम के सैकिया
वरिष्ठ प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी (पशु पोषण), पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

गोवा स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड, कुर्ती

नवीन कुमार
वरिष्ठ प्रबंधक, एमएससी (पर्यावरण विज्ञान), एमटेक (पर्यावरण विज्ञान एवं अभियांत्रिकी), एमएससी (ईएनएम एमओडी एवं एमजीएमटी), पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दूध उत्पादक महासंघ लिमिटेड, शिमला

प्रवीण शर्मा
उप प्रबंधक, बीटेक (डीटी), पीजीडीआरएम

अब्दुल रकीब अब्दुल हलीम
उप प्रबंधक, बीटेक (डीटी)

झारखंड दूध महासंघ (जेएमएफ), रांची

जयदेव बिश्वास
महाप्रबंधक, बीएससी (केम), पीजीडीआरडी, पीजीडीएचआरएम

नितिन एम शिंकर
उप महाप्रबंधक, बीई (मेटलर्जी), पीजीपीबीए (पी एंड ओ प्रबंधन)

एम गोविंदन
उप महाप्रबंधक, एमए (एसडब्ल्यू), एमबीए

टी सी गुप्ता
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (ऑनर्स), एमएससी (कृषि), पीएचडी (एग्रो.)

मिलन कुमार मिश्रा
वरिष्ठ प्रबंधक, बीकॉम, पीजीडीडीएम

शैली तोपनो
वरिष्ठ प्रबंधक, बीए (ऑनर्स), एमए (एसडब्ल्यू)

सौरभ कुमार
प्रबंधक, बीटेक (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार), पीजीडीएम

प्रियंका तोप्पो
प्रबंधक, बीकॉम, पीजीडीआरएम

संजय नंदी
प्रबंधक, बीकॉम, आईसीडब्ल्यूएआई, पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

अरुण मारुति वड्डाट्टी
उप प्रबंधक, बीएससी (कृषि), पीजीडीआरएम
कर्नाटक ऑयल फेडरेशन, बेंगलुरु

जी सी रेड्डी
प्रबंध निदेशक (केओएफ), एमएससी (सांख्यिकी), एमफिल (जनसंख्या अध्ययन)

केसीएमएमएफ, एर्णाकुलम

आसिफहुसैन मैयुदीन कुरैशी
उप प्रबंधक, बीटेक (डीटी), एमटेक (डेयरी केमिस्ट्री)

लद्दाख दूध महासंघ (एलएमएफ), लेह

मनोजकुमार बी सोलंकी
प्रबंधक, बीटेक (डीटी), एमटेक (डेयरी केम)

शुभम कम्बोज
उप प्रबंधक, बीटेक (डीटी), पीजीडीआरएम

मिजोरम दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, आइजॉल

हर्ष वर्धन
प्रबंधक, बीटेक (इलेक्ट्रो), पीजीडीएम (वित्त)

महाराष्ट्र राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित (एमआरएसडीएमएम), मुंबई

ए एस हातेकर
महाप्रबंधक, एमएससी (कृषि)

नरेंद्र एच पटेल
उप महाप्रबंधक, बीई (मैक.)

अरिजीत मोंडल
उप प्रबंधक, बीएससी (औद्योगिक मत्स्य एवं मत्स्यिकी), एमएससी (मत्स्य विज्ञान), पीजीडीआरएम

उंडावल्ली महेश
उप प्रबंधक, बीएससी (ऑनर्स) (कृषि), पीजीडीआरएम

प्रमोद कुमार
उप प्रबंधक, बीटेक (डीटी), पीजीडीआरएम

ऋत्विककुमार जे शर्मा
उप प्रबंधक, बीटेक (डीटी)

राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल), दिल्ली

तुषार कांति पात्रा
वरिष्ठ प्रबंधक, बीकॉम, आईसीडब्ल्यूए

रुबेन पापांग
उप प्रबंधक, बीए (ऑनर्स) (अर्थशास्त्र), पीजीडीआरएम

नॉर्थ ईस्ट डेयरी एंड फूड्स लिमिटेड (एनईडीएफएल), गुवाहाटी

एस बी बोस
प्रबंध निदेशक (एनईडीएफएल), बीई (मैक.), पीजीडीआरडीएम

विपिन नामदेव
वरिष्ठ प्रबंधक, एमकॉम, पीजीडीसीए, आईसीडब्ल्यूए

करन शर्मा
उप प्रबंधक, बीएससी (केम.), पीजीडीआरएम
क्षेत्रीय तिलहन उत्पादक सहकारी समिति संघ लिमिटेड (आरओजीसीएसयूएल), चित्रदुर्ग)

एम जयकृष्ण
उप महाप्रबंधक, एमए (इको), एमफिल (इको), पीएचडी (इको)

क्षेत्रीय तिलहन उत्पादक सहकारी समिति संघ लिमिटेड (आरओजीसीएसयूएल), रायचूर

हलनायक ए एल
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (कृषि विपणन एवं सहकारिता), एमएससी (एग्री इको)

वाराणसी दूध संघ, वाराणसी

एस चंद्रशेखर
उप महाप्रबंधक, बीई(मैक.)

अरविंद कुमार
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (कृषि), एमएससी (एग्री मार्केटिंग एंड कॉपरेशन), पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

एस महापात्रा
वरिष्ठ प्रबंधक, बीए (मनो.), एलएलबी, पीजीडीएम (एचआरएम)

पी वी सुब्रह्मण्यम
वरिष्ठ प्रबंधक, बीबीएम, एमबीए (वित्त)

राहुल त्रिपाठी
वरिष्ठ प्रबंधक, बीकॉम, एमबीए (वित्त)

आलोक प्रताप सिंह
वरिष्ठ प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी (पशु पोषण)

भरत सिंह
प्रबंधक, बीटेक (मैक.)

हरेन्द्र पी सिंह
प्रबंधक, बीटेक (डीटी), एमएससी (डेयरी केम), पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

साकिब खान
प्रबंधक, एमसीए

अरविंद कुमार यादव
प्रबंधक, बीटेक (मैक.), एमबीए (इन्फ्रा)

हितेंद्रकुमार बी रावल
प्रबंधक, बीटेक (डेयरी एंड फूड टेक), एमटेक (डीटी)

जीलकुमार आर राठौड़
उप प्रबंधक, बीटेक (ईई), पीजीडीआरएम

विदर्भ मराठवाड़ा डेयरी विकास परियोजना, नागपुर

सचिन एस शंखपाल
प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी (पशु पोषण), पीएचडी (पशु पोषण)

सचिन कुमार
उप प्रबंधक, बीएससी (आनर्स)(कृषि) पीजीडीआरएम

मिथिला डी वदुरकर
उप प्रबंधक, बीएससी (आनर्स) (कृषि), पीजीडीडीएम

पश्चिम असम दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (वामूल), गुवाहाटी

एस के परिदा
उप महाप्रबंधक, बीई (इलेक्ट)

गुलशन कुमार शर्मा
वरिष्ठ प्रबंधक, बीए, डिप्लो. (होटल प्रबंधन)

कुलदीप बोरा
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (बायोटेक), पीजीडीडीएम

प्रशांत नायडु वी जी पी
उप प्रबंधक, बीटेक (एरोस्पेस इंजीनियरिंग), पीजीडीआरएम

दीपक कम्बोज
उप प्रबंधक, बीएससी (ऑनर्स) कृषि, पीजीडीआरएम

कृष्ण बल्लभ चौधरी
उप प्रबंधक, बीए (ऑनर्स) सोशल वर्क, पीजीडीआरएम

सहायक कंपनियों और सहयोगी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर

आईडीएमसी लि., वी यू नगर

चंद्र प्रकाश
उप महाप्रबंधक, बीटेक(मैक.)
एनडीडीबी काफ लिमिटेड, आणंद

राजेश सुब्रमण्यम
प्रबंध निदेशक (एनसीएल),
बीई (केमिकल इंजी), पीजीडीआरएम

राजेश नायर
वरिष्ठ महाप्रबंधक, बीएससी, एमएससी (एन. केम), पीएचडी (केम)

राजीव चावला
वरिष्ठ वैज्ञानिक, बीएससी, एमएससी (पशु पोषण), पीएचडी (पशु पोषण), एमबीए (मार्केटिंग)

एस के गुप्ता
वैज्ञानिक III, एमएससी (कृषि)

स्वगतिका मिश्रा
वैज्ञानिक III, बीएससी (बॉट), एमएससी (माइक्रो)

अमोल एस खाड़े
वैज्ञानिक II, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी (पशु आनु. एवं प्रजनन)

स्वाति एस पाटिल
वैज्ञानिक II, बीएससी (फूड टेक एवं मैनेजमेंट) एमएससी (फूड टेक)

पुदोता रोहित कुमार
वैज्ञानिक II, बीएससी (केम),
एमएससी (फूड केम)

निहिर हितेशकुमार सोनी
वैज्ञानिक I, बीई (फूड प्रो. टेक), एमटेक (खाद्य सुरक्षा और क्यूएम)

कैलाश चंद्र बेहेरा
वैज्ञानिक I, एमएससी (खाद्य और पोषण विज्ञान)

वर्षा शर्मा
वैज्ञानिक I, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी (पोषण)

निलय यादव
वैज्ञानिक I, बीटेक (बायो टेक), एमटेक (केमिकल टेक)

भव्य मेहरा
वैज्ञानिक I, एमएससी (जैव रसायन)

एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, दिल्ली

पंकज सिंह
वरिष्ठ प्रबंधक, एमएससी (कृषि),
पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

अमोल एम जाधव
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (मैक.),
पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

कार्तिक पटेल
उप प्रबंधक, बीकॉम, सीए
एनडीडीबी मृदा लिमिटेड,आणंद

संदीप भारती
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी,पीजीडीडीएम

के बी प्रताप
वरिष्ठ प्रबंधक, बीआईबीएफ (इंट. बिजनेस), पीजीडीडीएम

ब्रजेश साहू
वरिष्ठ प्रबंधक, बीकॉम, सीए

भीमाशंकर शेटकर
प्रबंधक, बीई (प्रोड), पीजीडीआरडीएम

चंद्रशेखर के डाखोले
प्रबंधक, बीवीएससी एवं एएच, एमवीएससी (पशु पोषण), पीजीडीएम (आरएम-एक्स)

मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड (एमडीएफवीपीएल), दिल्ली

जे टी चारी
उप प्रबंध निदेशक (एमडीएफवीपीएल)
बीई (इलेक्ट्रिकल), पीजीडीआरडीएम

इंस्टीट्युट ऑफ रुरल मैनेजमेंट (इरमा), आणंद

आर अरुमुगम
वरिष्ठ प्रबंधक, एमकॉम

शब्दावली

एएईटीआई - अनिल अग्रवाल पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान

एएयू - आणंद कृषि विश्वविद्यालय

एबीआईपी - तीव्र नस्ल सुधार कार्यक्रम

एबीआईपी आईवीएफ-ईटी - तीव्र नस्ल सुधार कार्यक्रम, इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन एवं भ्रूण प्रत्यारोपण

एबीआईपी आईवीएफ - तीव्र नस्ल सुधार कार्यक्रम, इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन

एबीआईपी-एसएसएस - सेक्स्ड और सेक्स-सॉर्टेड वीर्य के माध्यम से तीव्र नस्ल सुधार कार्यक्रम

एबीएस - एडल्ट बोवाइन सीरम

ए हेल्प - पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य एवं विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट

एएचआईडीएफ - पशुपालन अवसंरचना विकास निधि

एआई - कृत्रिम गर्भाधान

एकेएफ - आगा खॉ फाउंडेशन

एएलडीए - असम पशुधन विकास एजेंसी

एएमसीएस - स्वचालित दूध संकलन प्रणाली

एएमसीयू - स्वचालित दूध संकलन इकाई

एएमआर - एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस

एएमयू - एंटीमाइक्रोबियल यूसेज

अमूल डेयरी - कैरा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड

एएमवी - ऑल फॉर मेडिकल वियतनाम

एएनएएस - पशु पोषण परामर्श सेवाएं

एपीएआरटी - असम कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना

एपीईडीए - कृषि एवं प्रससंकरण खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण

एपीएचए - यूके - एनिमल एंड प्लांट हेल्थ एजेंसी यूके

एआरआईएएस - असम ग्रामीण बुनियादी ढांचा और कृषि सेवा समिति

एएससीएडी - पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता

बीएआईएफ - बायफ विकास अनुसंधान फाउंडेशन

बनास डेयरी - बनासकांठा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड

बीबीएसएसएल - भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड

बरौनी डेयरी - देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड

बीवीडी - गोवंशीय वायरल डायरिया

बीवीडीवी - गोवंशीय वायरल डायरिया वायरस

बीजीसी - गोवंशीय जेनिटल कैम्पिलोबैक्टीरियोसिस

बॉयोसीएनजी - बॉयो- कम्प्रैस्ड नेचुरल गैस

बीआईएस - भारतीय मानक ब्यूरो

बीएमसी - बल्क मिल्क कूलर

बीएमसीयू - बल्क मिल्क कूलर यूनिट्स

बीएमएफ - नस्ल वृद्धि फार्म

बीओएम - बिल ऑफ मटेरियल

बीओएचवी-1 - बोवाइन हर्पीसवायरस टाईप 1

बीओएचवी-5 - बोवाइन हर्पीसवायरस टाईप 5

बीयूएचवी-1 - बुबलाइन हर्पीसवायरस टाईप 1

बीपीएससीएल - बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड

बीएसएल - जैव-सुरक्षा प्रयोगशालाएं

बीटीएल - बिलो द लाइन

सीएसी - कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमेटी

सीएएस-एमएमपी - दूध एवं दूध उत्पादों के लिए अनुरूपता मूल्यांकन योजना

सीएडब्ल्यूए - कंपैशन फॉर एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन

सीबीबीओ - क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन

सीबीडीसी - सेन्ट्रल बैंक डिजीटल करैंसी

सीबीजी - कम्प्रैस्ड बॉयोगैस

सीबीएचएफ - क्रासब्रीड ऑफ होल्स्टीन फ्रीज़ियन

सीबीजेवाई - जर्सी संकर नस्ल

सीबीएमएम - सतत् मक्खन निर्माण मशीन

सीसीबीएफ - केन्द्रीय मवेशी प्रजनन फार्म

सीएफपी - पशु आहार संयंत्र

सीएफएसपी एंड टीआई - केंद्रीय हिमिकृत वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान

सीजीसीडीएफ - छत्तीसगढ़ सहकारी डेयरी महासंघ

सीएफयू - कॉलोनी-फॉर्मिंग यूनिट

सीआईआई - कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री

सीआईवीएफ - चारूसैट इनोवेटिव वेंचर्स फाउंडेशन

सीआईपी - क्लीन-इन-प्लेस

सीएलए - सेंट्रीफ्यूगल पंप

सीकेएमएम - सतत् खोआ निर्माण मशीन

सीएनए - केंद्रीय नोडल एजेंसी

सीएनजी - कम्प्रैस्ड नेचुरल गैस

सीओई - उत्कृष्टता केन्द्र

कोविड-19 - 2019 नोवेल कोरोनावायरस

सीआरपी - बछड़ी पालन कार्यक्रम

सीएसई - विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र

सीएसआर - कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

सीडब्ल्यूआईपी - चालू पूंजीगत कार्य

डीएएचडी - पशुपालन एवं डेयरी विभाग

डीएवीएसी - डालैट पाश्चर वैक्सीन कंपनी लिमिटेड

डीबीओ - डीफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन

डीबीटी - डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर

डीसीएएम - वैकल्पिक उपायों द्वारा रोग नियंत्रण

डीसीएस - डेयरी सहकारी समिति

डीएफसीसीआईएल - डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

डीआईडीएफ - डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि

डीएमएफ - डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट

डीएनए - डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड

डीओआरबी - डी-ऑइल्ड राइस ब्रैन

डीपीएमसीयू - डाटा प्रोसेसर आधारित दूध संकलन इकाई

डीपीआर - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

डीआरओ - डेयरी रूट ऑप्टिमाइज़र

डीएसएफ - डेयरी सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क

डीटीसी - सहकारिताओं के माध्यम से डेयरी

डीवीएफएए - डेनिश वेटनरी एंड फूड एडमिनिट्रेशन

ईअमूल - पूर्वी असम दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड

ईबीएल - एन्ज़ूटिक बोवाइन ल्यूकोसिस

ईजीएच - एल्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन हार्ट

ईआईए - अंतिम कार्यान्वयन एजेंसी

ईआईसी - निर्यात निरीक्षण परिषद्

एलिसा - एंजाइम लिंक्ड इम्युनोसॉर्बेंट एशे

ईपीपी - खाली मटर के छिलके

ईआरपी - एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग

ईएसजी - पर्यावरण, सामाजिक और शासन

ईटी - भ्रूण प्रत्यारोपण

ईटीपी - एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट

ईटीटी - भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक

ईवीएम - एथनो-वेटनरी मेडिसिन

एफएओ - संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन

एफसीडीओ - विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय

एफडीयू - चारा प्रदर्शन इकाई

एफएमडी - खुरपका एवं मुंहपका रोग

एफएमडीवी - खुरपका एवं मुंहपका रोग वायरस

एफपी - फिल्टर पेपर

एफपीओ - किसान उत्पादक संस्था

एफएसडी - हिमीकृत वीर्य डोज

एफएसएसएआई - भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

जीएएपी - जेनेरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स

गडवासु - गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय

जीबीआरसी - गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र

जीबीवी - जीनोमिक प्रजनन मूल्य

जीसीएमएमएफ - गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ लिमिटेड

जीडीटी - ग्लोबल डेयरी ट्रेड

जीएचजी - ग्रीनहाउस गैस

जीआईएस - भौगोलिक सूचना प्रणाली

जीएमपी - उत्तम निर्माण पद्धतियां

जीओए - असम सरकार

जीओआई - भारत सरकार

जीओएम - महाराष्ट्र सरकार

जीडब्ल्यूएएस - जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज

एचए - हेक्टेयर

एचएसीसीपी - हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट

एचएफसीबी - क्रॉसब्रेड होल्स्टीन फ्रीजियन

एचजीएम - उच्च आनुवंशिक गुण

एचपी मिल्कफेड - हिमाचल प्रदेश राज सहकारी दूध उत्पादक महासंघ लि.

एचएस - रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया

आईए - कार्यान्वयन एजेंसी

आईबीआर - संक्रामक गोवंशीय राइनोट्रेकाईटिस

आईबीएससी - संस्थागत जैव सुरक्षा समिति

आईसीएआई - भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

आईसीआरआईएसएटी - इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स

आईसीएआर - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

आईसीएआर - इंटरनेशनल कमेटी ऑफ एनिमल रिकॉर्डिंग

आईसीएआर-एनबीएजीआर - आईसीएआर-राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो

आईसीएफए - इंडियन चैंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर

आईसीएस - आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आईडीए - इंडियन डेयरी एसोसिएशन

आईडीएफ - अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ

आईडीएफ आरडीसी - आईडीएफ क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन

आईडीएफ डब्ल्यूडीएस-2024 - अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ का विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन-2024

आईडीएफ डब्ल्यूडीएस-2027 - अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ का विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन-2027

आई-डीआईएस - इंटरनेट पर आधारित डेयरी सूचना प्रणाली

आईडीएमसी - इंडियन डेयरी मशीनरी कंपनी लिमिटेड

आईईसी - अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन

आईएफएडी - अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष

आईएफपीआरआई - अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान

आईएफएफसीओ - इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड

आईआईएल - इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड

आईएलआरआई - अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान

आईएनसी-आईडीएफ - अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ की भारतीय राष्ट्रीय समिति

इरमा - इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद

आईएस - भारतीय मानक

आईएसओ - अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन

आईवीईपी - इन विट्रो भ्रूण उत्पादन

आईवीएफ - इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन

आईवीपीएम - इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी प्रीवेंटिव मेडिसीन

आईवीआरआई - भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान

आईवाईसी - अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष

जीका - जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी

जेएमएफ - झारखंड दूध महासंघ

जेएसआईए - झारखंड राज्य कार्यान्वयन एजेंसी

जीवी - संयुक्त उद्यम

जेवाईसीबी - संकर नस्ल जर्सी

केडीसीएमपीयूएल - कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि.

केसीएमएमएफ - केरल सहकारी दूध विपणन संघ

केएफडी - क्यासानूर फॉरेस्ट डिज़ीज़

केजी - किलोग्राम

केएल - किलो लीटर

केएलडी - किलोलीटर प्रतिदिन

केएलपीएच - किलो हजार लीटर प्रतिघंटा

केओएफ - कर्नाटक सहकारी तिलहन उत्पादक संघ

कृभको - कृषक भारती सहकारी लिमिटेड

केवीके - कृषि विज्ञान केंद्र

केडब्ल्यूपी - किलोवाट पीक

एलएएचडीसी - लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद्

एलसीएफ - लीस्ट कास्ट फार्मूलेशन

एलडीसीएफ - लद्दाख डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड

एलएचएंडडीसी - पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण

एलआईसी - भारतीय जीवन बीमा निगम

एलआईसी - लाइवस्टॉक इम्प्रूवमेंट कॉर्पोरेशन

एलकेजीपीडी - लाख किलोग्राम प्रतिदिन

एलएलपीडी - लाख लीटर प्रतिदिन

एलएमएफ - लद्दाख दूध महासंघ

एलएमआईसी - निम्न और मध्यम आय वाले देश

एलएमपी - तरल दूध प्रसंस्करण

एलएसएचडीसीपी - पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम

एलएसडी - लम्पी त्वचा रोग

एमएएफएसयू - महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय

मैत्री - ग्रामीण भारत के बहुउद्देश्यीय एआई तकनीशियन

एमएआईटी - मोबाइल एआई तकनीशियन

एमडीसीएस - बहु-उद्देश्य डेयरी सहकारी समिति

एमडीएफवीपीएल - मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड

एमडीएल - मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स

महेसाणा डेयरी - महेसाणा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड

मिल्मा - केरल सहकारी दुग्ध विपणन संघ

एमआईएस - प्रबंधन सूचना प्रणाली

एमआईटी, महेसाणा - मानसिंग प्रशिक्षण संस्थान, महेसाणा

मिल्कफेड - पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड

एमएलएसटी - मल्टी-लोकस सीक्वेंस टाइपिंग तकनीक

एमएनआरई - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

एमओसी - सहकारिता मंत्रालय

एमओयू - समझौता ज्ञापन

एमपी - मध्य प्रदेश

एमपीएसीएस - बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां

एमपीसीएस - दूध उत्पादक सहकारी समितियां

एमपीओ - दूध उत्पादक संस्था

एमआर - मीजल्स रूबेला

एमआरएसडीएमएम - महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित

एमएसपी - न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल

एमएसपी - न्यूनतम समर्थन मूल्य

एमटी - मीट्रिक टन

एमटीसी - माइक्रो प्रशिक्षण केंद्र

एमटीपीडी - मीट्रिक टन प्रतिदिन

एमयू - दूध संघ

एमडब्ल्यू - मेगावाट

नाबार्ड - राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

एनएबीएल - राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड

एनएडीसीपी - राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम

नेफेड - भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड

एनबीएजीआर - राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो

एनबीसीसी - नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन

एनबीजीसी-आईबी - राष्ट्रीय बोवाइन जीनोमिक केंद्र - स्वदेशी नस्लों के लिए

एनबीएचएम - राष्ट्रीय मधुमक्खीपालन एवं शहद मिशन

एनसीसीएफ - भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित

एनसीडीसी - राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

एनसीडीएफआई - नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लि.

एनसीईएल - राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड

एनसीओएल - राष्ट्रीय कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड

एनसीआर - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

एनसीआरपीबी - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

एनसीटी - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

एनडीडीबी - राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

एनडीडीबी-एसपीईएफ - एनडीडीबी सस्टेन प्लस एनर्जी फाउंडेशन

एनडीईआरपी - एनडीडीबी डेयरी ईआरपी

एनडीएफ - न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर

एनडीएलएम - राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन

एनडीपी I - राष्ट्रीय डेयरी योजना I

एनडीपी II - राष्ट्रीय डेयरी योजना II

एनडीआरआई - राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान

एनडीएस - एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज

एनईडीएफएल - नॉर्थ ईस्ट डेयरी एंड फूड्स लिमिटेड

एनईआर - पूर्वोत्तर राज्य

एनएफडीबी - राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड

एनएफएन - एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रीशन

एनएफपी - न्यूबुटो फिल्टर पेपर

एनएफएसएम - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

एनआईएबी - राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान

एनआईएएच - राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान

नीति आयोग - राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था

एनआईवीईडीआई - राष्ट्रीय पशु रोग जानपदिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान

एनएलएम - राष्ट्रीय पशुधन मिशन

एनएमआरपी - राष्ट्रीय दुग्ध रिकॉर्डिंग कार्यक्रम

एनपीडीडी - राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम

एनपीसीआई - भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

एनआरएल - राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला

एनजेड - न्यूजीलैंड

ओडीए - कार्यालयीन विकास सहयोग

ओएच - वन हेल्थ

ओएल - राजभाषा

ओएलआईसी - राजभाषा कार्यान्वयन समिति

ओमफेड - ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड

ओएनजीसी - तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड

ओपीयू - ओवम पिक-अप

ओपीयू-आईवीईपी - ओवम पिक-अप -इन विट्रो भ्रूण उत्पादन

ओपीयू-आईवीईपी- ईटी - ओवम पिक-अप -इन विट्रो भ्रूण उत्पादन एवं प्रत्यारोपण

पीए - प्रतिभागी एजेंसी

पीएसीएस - प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां

पीबीएनएल - प्रिस्टीन बायोलॉजिकल्स एनजेड लिमिटेड

पीसीडीएफ - प्रादेशिक सहकारी डेयरी फेडरेशन

पीसीएस - प्राथमिक सहकारी समितियां

पीसीआर - पॉलिमराइज्ड चेन रिएक्शन

पीजीएस - भागीदारी गारंटी प्रणाली

पीआई - प्रतिभागी संस्थान

पीएमयू - परियोजना निरीक्षण ईकाई

पीएनबी - पंजाब नेशनल बैंक

पीओआई - उत्पादक स्वामित्व वाली संस्था

पीपीई - संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

पीपीआर - पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स

पीआरएमबीएस - सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना

पीएस - वंशावली चयन

पीएसबी - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

पीएसयू - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

पीटी - संतति परीक्षण

क्यूसीआई सर्कल - गुणवत्ता नियंत्रण चक्र

क्यूसीआई - भारतीय गुणवत्ता परिषद

क्यूपीआर - तिमाही प्रगति रिपोर्ट

क्यूआर - त्वरित प्रतिक्रिया

आरबीआई - भारतीय रिर्जव बैंक

आरबीपी - आहार संतुलन कार्यक्रम

आरडीए - अनुशंसित आहार भत्ता

आरएफआईडी - रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन

आरजीएम - राष्ट्रीय गोकुल मिशन

आरएल - संदर्भ प्रयोगशाला

रो-रो - रोल-ऑन/रोल-ऑफ

आरपीपीओआई - री-वाइटलाइज़िंग प्रॉमिसिंग प्रोड्यूसर्स ओन्ड इंस्टिट्यूशन्स

आरयूसी - रेडी-टू-यूज कल्चर

एसए - लेखापरीक्षा मानक

साबर डेयरी - साबरकांठा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड

सैक-इसरो - अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

एसएजी-एसआर - एसएजी-स्लो रिलीज

एसएआई प्लेटफार्म - सतत कृषि पहल प्लेटफार्म

सेल - स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

एससीएडीए - पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं डेटा अधिग्रहण

एससीआई - शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

एससीएस - सुरभि चयन शृंखला

एसडीसीएफपीओ - डेयरी सहकारिताओं और किसान उत्पादक संस्थाओं को समर्थन

एसडीजी - सतत् विकास लक्ष्य

सेवा - स्व-नियोजित महिला संघ

श्रीजा एमएमपीसीएल - श्रीजा महिला दूध उत्पादक कंपनी लिमिटेड

एसकेयू - स्टॉक कीपींग यूनिट

एसएमएलयू - सुदंरबन सहकारी दूध एवं पशुधन उत्पादक संघ लिमिटेड

एसएमपी - स्किम्ड मिल्क पाउडर

एसएनएफ - सॉलिड नॉट फैट

एसओपी - मानक प्रचालन प्रक्रिया

एसआरडीआई - सुजुकी आर एंड डी सेन्टर इंडिया प्रा. लिमिटेड

एसएस - वीर्य केन्द्र

एसएसएमएस - वीर्य केन्द्र प्रबंधन प्रणाली

एसएस एंड एसएम - सीरो-सर्विलांस और सीरो-मॉनिटरिंग

एसटी - सिकवेन्स टाईप

सुमूल डेयरी - सूरत तापी जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड

टीएजी - उष्णकटिबंधीय पशु आनुवंशिकी

टीसीएमपीएफ - तमिलनाडु को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड

टीडीयू - ट्रांस डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी

टीडीएन - कुल पाच्य पोषक तत्व

टीईआरआई - द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्युट

टीकेजीपीडी - हजार किलोग्राम प्रतिदिन

टीएलपीडी - हजार लीटर प्रति दिन

टीएमआर - संर्पूण मिश्रित आहार

टॉलिक - नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

टीओटी - प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

टीपीआरएमजी - टाटा पावर रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड लिमिटेड

टीआर - रिफ्रिजरैशन टन

टीआरजी - तकनीकी संदर्भ समूह

टीएसडीडीसीएफएल - तेलंगाना स्टेट डेयरी डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड

टीटीएल - टास्क टीम लीडर

यूडीआईएन - विशेष दस्तावेज पहचान संख्या

यूएचटी - अल्ट्रा हाई टेम्परेचर

यूआईपी - सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम

वीएडीपी - मूल्य वर्धित डेयरी उत्पाद

वीबीएमपीएस - ग्राम आधारित दूध संकलन प्रणाली

वीएमडीडीपी - विदर्भ मराठवाड़ा डेयरी विकास परियोजना

वीआरएस - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

वामूल - पश्चिम असम दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड

डब्ल्यूओएएच - विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन

डब्ल्यूआर 2.0 - श्वेत क्रांति 2.0

कृतज्ञता ज्ञापन

- दूध महासंघ, डेयरी सहकारी दूध उत्पादक संघ और दूध उत्पादक संगठन
- भारत सरकार का मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, जलशक्ति मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और नीति आयोग
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें
- एनडीडीबी की सहायक कंपनियां - मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड, आईडीएमसी लिमिटेड, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज़, एनडीडीबी मृदा लिमिटेड और एनडीडीबी काफ लिमिटेड
- इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, आनंदालय एज्यूकेशन सोसायटी तथा विद्या डेयरी
- बहुराज्यीय सहकारी समितियां - नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, कृषक भारती सहकारी लिमिटेड और भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड
- बहु-क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, डेयरी सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क, डेयरी एशिया, वैश्विक डेयरी प्लेटफॉर्म, अंतर्राष्ट्रीय पशु रिकार्डिंग समिति और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जैसे संस्थान शामिल हैं।
- आईसीएआर-राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
- भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन और निर्यात निरीक्षण परिषद; और
- सभी हितधारक

मुख्यालय
आणंद 388 001
दूरभाष: (02692) 260148/260149/260160
फैक्स: (02692) 260157
ई-मेल: anand@nddb.coop

कार्यालय
VIII ब्लॉक,
80 फीट रोड, कोरमंगला,
बेंगलुरू 560 095
दूरभाष: (080) 25711391/25711392
फैक्स: (080) 25711168
ई-मेल: bangalore@nddb.coop

डी के ब्लॉक, सेक्टर II,
सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता 700 091
दूरभाष: (033) 23591884/23591886
फैक्स: (033) 23591883
ई-मेल: kolkata@nddb.coop

वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे,
गोरेगांव (पूर्व), मुंबई 400 063
दूरभाष: (022) 26856675/26856678
फैक्स: (022) 26856122
ई-मेल: mumbai@nddb.coop

प्लॉट सं. ए-3, सेक्टर-1,
नोएडा 201 301
दूरभाष: (0120) 4514900
फैक्स: (0120) 4514957
ई-मेल: noida@nddb.coop

www.nddb.coop